राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का बाइसवां दिवस [संख्या: 12

गुरुवार,
16 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। होली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, विराजिये। प्रश्नकाल। मास्टर मामन सिंह यादव।

भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के टोल प्लाजा का अन्यत्र स्थानान्तरण

298. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद व नगरपालिका क्षेत्र की सड़कों पर टोल प्लाजा लगाया जा सकता है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रिडकोर टोल प्लाजा नगरपरिषद भिवाड़ी व नगरपालिका तिजारा की सीमा में लगा हुआ है? यदि हां, तो उक्त टोल प्लाजा द्वारा कितनी सीमा तक के निवासियों के टोल कर से मुक्त रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त टोल प्लाजा को उक्त स्थान से अन्यत्र स्थान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी हां। राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में जारी फीस नोटिफिकेशन दिनांक 29.05.2015 के अनुसार राजस्थान राज्य राजमार्ग का भाग, स्थाई पुल, बाई पास या सुरंग

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

नगरपालिका या शहरी क्षेत्र की सीमा के भीतर या ऐसी सीमा से 2 किलोमीटर पर बनाया जाता है जो मुख्य रूप से इस नगरपालिका के निवासियों या शहरी क्षेत्र के उपयोग के लिए हो तो टोल प्लाजा को नगरपालिका या शहरी क्षेत्र की सीमा या सीमा से 2 किलोमीटर दूरी के भीतर भी स्थापित किया जा सकता है। फीस नोटिफिकेशन दिनांक 29.05.2015 परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। रिडकोर द्वारा अलवर-भिवाड़ी सड़क पर स्थापित तीन टोल प्लाजा (1) पापड़ी किमी. 163/000, (2) तिजारा टोल प्लाजा किमी. 193/000 एवं (3) भिवाड़ी टोल प्लाजा 221/480 में से दो टोल प्लाजा तिजारा व भिवाड़ी क्रमश: नगरपालिका तिजारा एवं नगर परिषद भिवाड़ी की सीमा में आते हैं।

अलवर-भिवाड़ी सड़क परियोजना की अधिसूचना दिनांक 18.06.2008 को जारी की गयी थी, तत्समय टोल प्लाजा की नगरपालिका/नगर परिषद से दूरी के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया हुआ था। अधिसूचना दिनांक 18.06.2008 परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

रिडकोर द्वारा संचालित टोल प्लाजा से 20 किमी. की परिधि में आने वाले स्थानीय ट्रैक्टर, ट्रोलियों को जो कृषि उत्पाद ले जा रही हों एवं कृषि कार्य हेतु पंजीकृत हों, को अधिसूचना दिनांक 07.06.2008 के अनुसार टोल दरों से मुक्त रखा गया है। अधिसूचना दिनांक 07.06.2008 परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। रिडकोर द्वारा संचालित मेगा हाईवे अलवर से भिवाड़ी सड़क मार्ग पर अधिसूचना दिनांक 18.06.2008 के अनुसार उपयोक्ता शुल्क का संग्रहण किया जा रहा है। उक्त परियोजना का अनुबन्ध पूर्व में ही हो जाने के कारण भिवाड़ी एवं तिजारा टोल प्लाजाओं को अन्यत्र स्थापित/स्थानान्तरित किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी-

(मास्टर मामन सिंह यादव)

अलवर स्टेट हाईवे 2008 में कम्पलीट हो गया था। 2008 में नोटिफिकेशन तो हो गया था लेकिन टोल का स्थान 2011 में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया। 2011 में जैसे ही टोल निर्धारित किया गया तो नगर परिषद, भिवाड़ी और नगरपालिका, तिजारा में जनता का एजिटेशन हुआ और 3-4 बार बहुत भारी आंदोलन हुए। हमारे बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं के मुकदमे बने जो अभी हमारी सरकार ने उन दोनों मुकदमों को हटाया है। उसके विरोध के कारण तब वो वहां पर बंद कर दिया। उसके 8 महीने बाद जनवरी, 2012 में फिर वो टोल वहां पर जबर्दस्ती, जनता के विरोध के बावजूद और जन विरोधी नीति के कारण पूर्ववर्ती सरकार ने वहीं पर स्थापित कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, नियम में भी यही है, 2015 के विधान में यह आ चुका है कि नगर परिषद और नगरपालिका क्षेत्र में टोल का निर्धारण नहीं हो सकता तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप नियम और जनहित को ध्यान में रखते हुए पूर्व सरकार की जनविरोधी नीति के तहत उन्होंने जबरदस्ती बिना किसी कानून-कायदे के टोल लगा दिया उसको हटाने का विचार रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी और तिजारा की स्ट्रेच, जब 40 किलोमीटर का आपके प्रावधान है जबकि उसकी दूरी केवल 28 किलोमीटर है और दोनों जगह वहां पर टोल आते हैं।

तीसरी बात, यह है कि यहां पर पास की जो व्यवस्था है उसमें भिवाड़ी और तिजारा हरियाणा क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र हैं और 90 प्रतिशत वाहन एचआर, हरियाणा नम्बर के हैं तो उनका कोई पास नहीं बनाया जाता है। 2 लाख की आबादी में इनकी रिडकोर कम्पनी के द्वारा केवल 45 पास बनाये गये हैं तो क्या वहां के लोगों के एड्रेस, आई.डी. प्रूफ और स्थानीय निवासियों के राशन कार्ड के अनुसार बनाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि यह जनहित में है और पूरे राजस्थान में टोल की रोज झगड़ेबाजी रहती है इसलिए इसमें कुछ सुधार करने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह जो सड़क है इसको 2004 में आरएसआरडीसी मेंटेन करती थी और जो वर्तमान में स्थान निर्धारित किए हुए हैं इन्हीं जगहों पर पहले टोल थे। तत्पश्चात् 2008 में जब इसको फोरलेन बनाने के लिए रिडकोर को दिया तब उस समय नगरपालिका क्षेत्र में कोई टोल लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है इसके नियम नहीं थे और नियम नहीं होने की वजह से, प्रावधान नहीं होने की वजह से वो जो आरएसआरडीसी से स्थानान्तरित होकर रिडकोर को यह सड़क फोरलेन के रूप में आई तो उन्हीं स्थानों पर टोल लग गये। उसके बाद में अभी हमने स्टेट हाईवे एक्ट पास किया उसमें भी प्रोविजन किये। जो रूल्स 2015 में बनाये उनमें हमने यह प्रोविजन किया है कि नगर निकाय सीमा क्षेत्र से 5 किलोमीटर क्षेत्र तक टोल नहीं लग सकता लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं तो हम 2 किलोमीटर सीमा तक भी टोल लगा सकते हैं जैसे कोई टनल बन गया हो, कोई ब्रिज बन गया हो और उस क्षेत्र में टोल लगाना आवश्यक है तो लगाया जा सकता है इसलिए यह तो नहीं है कि टोल कानूनन गलत लगा है। चूंकि यह एग्रीमेंट हुआ था 2008 में और उसके बाद 2009 में नगरपालिका का नोटिफिकेशन हुआ और नगर परिषद का बाद में हुआ। मेरा निवेदन यह है कि जो माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है यह 85 किलोमीटर जो सड़क है उसमें एक स्ट्रेच 45 किलोमीटर का है और दूसरा स्ट्रेच 40 किलोमीटर का है तो इस 45 किलोमीटर में इन्होंने दो टोल लगा रखे हैं, एक भिवाड़ी टोल प्लाजा और एक तिजारा टोल प्लाजा। इन दोनों में से एक जगह अगर टोल दे देते हैं यानी इस 45 किलोमीटर के क्षेत्र में दोनों में से एक जगह टोल दे देते हैं तो दूसरी जगह नहीं देना पड़ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा स्ट्रेच अलवर साइड में है जो 40 किलोमीटर का है और उसमें जो पापड़ी टोल प्लाजा है उस पर टोल देना जरूरी है। मेरा निवेदन यह है कि इसमें तीन में से दो पर और विशेष रूप से भिवाड़ी और तिजारा में से किसी एक पर देकर कोई भी व्यक्ति जो इसको यूज कर रहा है, जा सकता है।

जहां तक हरियाणा नम्बर की गाड़ियों का और स्थानीय लोगों को पास

(श्री युनुस खान)

देने की बात है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पास का प्रोविजन भी किया हुआ है। 300 रुपये देकर अनलिमिटेड टाइम तक कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ-जा सकता है और स्थानीय लोगों को 20 किलोमीटर के रेडियस में यह छूट दी हुई है। दूसरा, हरियाणा नम्बर की गाड़ियों और वोटर आई.डी. की बात आपने कही है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति राजस्थान में टैक्स भी नहीं दे रहा है, हरियाणा के नम्बर यूज कर रहा है तो उसके लिए तो सरकार विचार नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 40 किलोमीटर का अन्तर आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जबकि वो दूरी 28 किलोमीटर है। इसके अलावा जो आपको अधिकारियों ने सूचना दी है कि दो जगह में से एक जगह टोल लिया जाता है, इसके बारे में मैं निश्चित रूप से सदन के बीच में कह रहा हूं कि दोनों जगह से टोल लिया जाता है। भिवाड़ी भी पर्ची कटती है और तिजारा भी पर्ची कटती है तो इस पर भी गौर फर्माया जाए।

दूसरा, टोल पर रोज झगड़े होते हैं और जैसे ही किसी सम्मानित व्यक्ति या किसी भी नागरिक के साथ झगड़ा-फसाद होता है तो वो कहते हैं कि हमारे टोल का कोई कर्मचारी नहीं है इसलिए ड्रेस की व्यवस्था करने का माननीय मंत्री महोदय विचार रखते हैं कि ड्रेस होनी चाहिए?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): और यह जो टोल की सीमा आपके नोटिफिकेशन में है.....

श्री अध्यक्ष: विराजिये, आपका प्रश्न आ गया।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): नहीं आया साहब। उस नोटिफिकेशन में यह है कि वही नगर परिषद या नगरपालिका के लिए ही केवल वो कार्य है जैसे पुल या सड़क पर यह तो 200 किलोमीटर की सड़क है, गंगापुर सिटी तक जाती है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, आपका प्रश्न आ गया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। बहुत लम्बा हो गया। जवाब दे रहे हैं आपका।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): एक प्रश्न रह गया है, साहब, फिर सारा जवाब दे देंगे। एक प्रश्न यह है कि जनता के कार्य के लिए और बाकी जन-प्रतिनिधियों के लिए टोल नि:शुल्क कर रखा है लेकिन पंचायती राज के कर्मचारी जैसे प्रधान हैं, जिला पार्षद और नगरपालिकाओं के चेयरमैन हैं इनको जनहित के कार्यों के लिए जिले में आना पड़ता है तो कृपा करके मंत्री महोदय यह विचार रखते हैं कि इनको जिले में आने जाने के लिए नहीं, केवल अपने जिले में उनको टोल की छूट होनी चाहिए? यह कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): और टोल को तो निश्चित रूप से हटा ही दो, मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो टोलकर्मी हैं, उनकी ड्रेस के बारे में बात कही है, वह तो हम निर्देशित कर देंगे कि इस तरीके से भविष्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन प्रतिनिधि के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करे। यह शिकायतें आती रहती हैं। इस बात से मैं सहमत हूं कि ये शिकायतें आती रहती हैं। कई बार हमारे एमएलए साहिबान भी जाते हैं, कार्ड दिखाते हैं तो उस समय विभिन्न टोलकर्मी चाहे वह एनएच हो, एनएचएआई हो, आरएसआरडीसी हो, रिडकोर हो, किसी का भी टोल हो, उनके व्यवहार के लिए यह शिकायतें आती हैं कि सही नहीं रहता है। उसके लिए तो हम लिखित में भी निर्देशित कर देंगे। इस तरह की शिकायतें भविष्य में आएंगी तो उन टोलकर्मियों के खिलाफ राज्य सरकार सख्ती से कार्यवाही करेगी और ड्रेस लगाने के भी निर्देश देगी।

जहां तक आपने बात कही है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि इसमें एक 45 किलोमीटर का स्ट्रैच है और एक 40 किलोमीटर का स्ट्रैच है। 85 किलोमीटर में दो ही टोल हैं और अगर इस तरीके की कोई बात है, माननीय सदस्य के साथ में जो रिडकोर कम्पनी है, उनके उच्चाधिकारियों को बैठाकर, और अन्य भी सदस्यों की कोई शिकायतें आएंगी तो उनका हम निस्तारण करेंगे, निवारण करेंगे।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): मंत्री महोदय, जन प्रतिनिधियों वाली बात के बारे में बता दें। जिला पार्षद और प्रधान, चेयरमैन हैं, उनके बारे में...

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक, रामहेत सिंह। विराजिये विराजिये, विराजिये विराजिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। यह भिवाड़ी-तिजारा दो टोल होने के बाद किशनगढ़बास आकर जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, वहां से यह सीधा कोटपूतली को निकलता है और मेरे खैरथल नगरपालिका में भी अन्दर वार्ड नम्बर 17 और वार्ड नम्बर 24 के बीच में टोल लगाया हुआ है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जब प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, अब तक काम चल रहा है तो, मंत्री महोदय, यह बताइये कि यह टोल कब से शुरू होगा? आपने 182 करोड़ रुपये सैंक्शन किये, उसमें से आपने 40 करोड़ रुपये बचा लिये, आज तक भी नाली नहीं है, आप खुद मानते हो। आपके सामने आपकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और उसमें आपने खुद ने माना। आपके अधिकारियों ने जवाब दिया कि खैरथल के अंदर 20 फुट, 25 फुट अंदर रास्ता है, उसका बाईपास बनना जरूरी है और जो 5.4.2013 को आपकी आरएसआरडीसी की मीटिंग हुई, उसके बिन्दु में लिखा है, उसमें उससे पहले बाईपास था खैरथल-किशनगढ़बास में। आपने उसको डैफर्ड किया है। 2013 का डैफर्ड मामला बाईपास खैरथल और किशनगढ़बास का, यह कब तक डैफर्ड रहेगा? आप टोल ले रहे हो, आपका काम पूरा नहीं हुआ तो क्या आप काम पूरा करने से पहले टोल लगा सकते हैं? नगरपालिका में यह जो टोल लगा हुआ है, इसको हटायेंगे क्या? बाईपास खैरथल-किशनगढ़बास कब तक आप सैंक्शन करेंगे? यह आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़बास से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इनके क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क है, उसके बारे में, एक तो खैरथल और किशनगढ़बास के बाईपास की बात कही। उस एग्रीमेंट को हम देख लेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। जो 5.4.2013 को एग्रीमेंट हुआ, उसमें बाईपास का प्रावधान था तो निश्चित रूप से सरकार बाईपास को बनाएगी। वैसे भी माननीय सदस्य के साथ जो बैठक हुई थी, उसमें इन दोनों जगहों पर बाईपास की आवश्यकता है। सरकार इस पर विचार करेगी और वार्ड नम्बर 17 और 24 के लोगों से जो टोल लिया

(श्री युनुस खान)

जा रहा है या टोल वहां स्थापित किया है, उसका एक बार परीक्षण करवा लेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि यह टोल कब शुरू होगा? क्या प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले या काम पूरा होने के बाद शुरू होगा या जब सरकार के जंचेगी, तभी लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रोजेक्ट अगर 80 प्रतिशत पूरा हो जाता है तो उस पर टोल लगाया जा सकता है। इसके लिए मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करके माननीय सदस्य को अवगत करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, टोल टैक्स से संबंधित सवाल है, अलवर जिले में सबसे ज्यादा टोल टैक्स के गेट हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 2015 में टोल टैक्स दिल्ली रोड पर गुड़गांवा सीमा तक, हरियाणा सीमा तक नौगांवा से आगे खत्म हो जाना चाहिए लेकिन उसको 2018 तक कर दिया और एक टोल गेट के बीच में सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी है। भाला टोल गेट और बंडवापूत और दूसरे टोल गेट के बीच में सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी है। यह दोनों कारण से ये टोल गेट हटने चाहिए।

साथ में मेरा सुझाव है जो मामनसिंह यादव, हमारे माननीय विधायक तिजारा ने दिया, ड्रेस कोड के साथ में उनके ऊपर पुलिस की तरह नेम प्लेट भी हो और आई-कार्ड भी हो क्योंकि 17 झगड़े टोल गेटों पर हमारे अलवर जिले में हुए हैं और जनता पर फौजदारी केस लगे हैं। खैरथल में भी हुआ, तिजारा में भी हुआ, मेरे यहां भी हुआ और बानसूर वाले टोल पर हुआ। मेरा निवेदन यह है कि उनका ड्रेस कोड भी हो और नेम प्लेट भी लगी हो। क्या नाम है उस कर्मचारी का और पुलिस से वेरीफिकेशन करवाकर आई-कार्ड बने। इसके बारे में मंत्री महोदय क्या कहेंगे? 20 किलोमीटर पर टोल है और 35 किलोमीटर पर टोल है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, अब आप कहिये, क्या कहना चाहते हैं?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसकी डीपीआर बनती है और डीपीआर बनते वक्त और उसकी स्वीकृति के तहत टोल के डेस्टीनेशन तय हो जाते हैं। यह बात सही है कि 40 किलोमीटर तक टोल नहीं लगाया जाता। तो, उसमें मेरा पहले भी निवेदन था और अभी भी यही है कि अगर मान लीजिये, उसकी लम्बी दूरी है तो दो टोल लगाये जा सकते हैं लेकिन 40 किलोमीटर तक टोल एक बार ही पे किया जाएगा और रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस सड़क का मुद्दा उठाया है। इस सरकार के आने के बाद में आपसे व्यक्तिश: चर्चा हुई है और आपने लिखकर भी दिया। जो टोल निर्धारित था, हमने कंसेसेनियर से बात करके उसका स्थान भी बदलवाया है, जिससे आपके क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिली है।

जहां तक ड्रेस का सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं दो चीजों के लिए सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा। एक तो टोलकर्मियों का व्यवहार है, उसकी बार-बार शिकायतें आती हैं, चाहे वह एनएच हो, एनएचएआई हो, आरएसआरडीसी हो, रिडकोर हो, उनके उच्च प्रबन्धन को बुलाकर हम पाबंद करेंगे। भविष्य में इस तरह की शिकायत आएगी तो राज्य सरकार सख्ती से उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी और ड्रेस कोड हम लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: शंकरसिंह राजपुरोहित। तीसरा पूरक प्रश्न, श्री शंकरसिंहजी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही पूछना चाहूंगा। मंत्री महोदय, आप एक बहुत बड़े डायनामिक मंत्री हैं। आप भी गुजरात की तर्ज पर यह जो छोटे-छोटे फोर-व्हीलर्स जाते हैं, इनको टोल फ्री करेंगे? मतलब जो गुड्स वाहन हैं, बसेज हैं, उन पर लगे, लेकिन जो छोटे व्हीकल हैं, कार वगैरह हैं, इनको टोल फ्री करने की मंशा रखते हैं? या उन पर कोई रोड टैक्स बढ़ा दीजिये। बार-बार की ये झंझटें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उनको आधा-आधा घंटा वहां खड़ा रहना पड़ता है तो, जैसे गुजरात ने किया है, वैसा आप भी करने की मंशा रखते हैं? एक ऐतिहासिक काम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन है कि मेरे किशनगढ़ नगरपरिषद के दोनों तरफ सात-सात किलोमीटर में टोल लगा हुआ है। नगरपरिषद के सात किलोमीटर उधर...

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। यह नहीं। आप जवाब दीजिये। आप इनके सवाल का जवाब दीजिये। तीसरा पूरक प्रश्न उनका था, उनका जवाब दीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग कंसेसनियर हैं, अलग-अलग सड़कें बनी हुई हैं। उसी के अनुसार टोल लिया जाता है। मेरा आपसे यह निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो माननीय सदस्य ने इश्यू उठाया है, यह भारत सरकार के स्तर पर, उच्च स्तर पर चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में उसमें राजस्थान भी सम्मिलित है, जो टोल है उस पर वाहन खड़े रहते हैं, उसमें फ्यूल का बहुत बड़ा नुकसान होता है तो उसकी क्या विधि अपनाई जाए और कामर्शियल व्हीकल के अलावा भी लिया जाए या नहीं लिया जाए, माननीय नितिन गडकरीजी जो केन्द्रीय मंत्री हैं, उनके स्तर पर यह विचार चल रहा है और राज्य सरकार उसको कैसे एडजस्ट करे, तो उसका भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा और पोजिटिव नतीजा आएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हीरालाल नागर। (व्यवधान) नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री हीरालाल नागर। नहीं, मामनसिंहजी, ऐसा नहीं।

कोटा भामाशाह मण्डी में एयरक्रास वेयरहाउस का निर्माण

299. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा संभाग में वर्तमान वर्ष में कितने हैक्टेयर में लहसुन की बुवाई की गयी है? जिलेवार लहसुन की बुवाई का रकबा एवं अनुमानित उत्पादन सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त संभाग में लहसुन बुवाई के बढ़ते रकबे को देखते हुए केन्द्रीय मसाला बोर्ड एवं प्रदेश मसाला बोर्ड से लहसुन खरीद करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल नागर)

(3) क्या सरकार उक्त संभाग में लहसुन के बढते रकबे को देखते हुए भामाशाह मण्डी में एयरक्रास वेयरहाउस निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति कोटा एवं फल सब्जी मण्डी समिति कोटा द्वारा हाड़ौती में लहसुन की बम्पर पैदावार को देखते हुए विपणन की व्यवस्था हेतु क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) कोटा संभाग में वर्तमान वर्ष 2016-17 में 1.38 लाख हैक्टेयर में लहसुन की बुवाई की गयी है। कोटा संभाग में जिलेवार लहसुन की बुवाई का रकबा एवं अनुमानित उत्पादन परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत मसाला बोर्ड द्वारा लहसुन सहित अन्य मसालों की उत्पादकों से खरीद का कार्य न कर मसालों के उत्पादन व निर्यात प्रोत्साहन का कार्य किया जाता है। प्रदेश में पृथक से कोई अन्य मसाला बोर्ड गठित नहीं है।

(3) भामाशाह मण्डी प्रांगण में स्थान का अभाव होने के कारण मण्डी में एयरक्रास वेयरहाउस का निर्माण किया जाना संभव नहीं है।

(4) भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा एवं कृषि उपज मण्डी समिति (फल-सब्जी) कोटा द्वारा लहसुन पैदावार को देखते हुए की गयी व्यवस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक, श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): मंत्री महोदय, हाड़ौती में अत्यधिक मात्रा में किसानों के द्वारा लहसुन उत्पादन करने से पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कितना उत्पादन हुआ तथा उसका कितना मूल्य रहा एवं कितना रकबा बढ़ा और क्या बढ़े हुए उत्पादन से भावों में जो कमी आयी है, दस हजार से, बारह से, चौदह हजार रुपये क्विंटल पर बिकने वाला लहसुन आज की तारीख में बाइस सौ से चौबीस सौ रुपये क्विंटल मंडी में बिक रहा है। इस लहसुन

(श्री हीरालाल नागर)

से हाड़ौती के किसानों को नुकसान हो रहा है। एक लाख से अधिक किसानों के परिवार और तीन से चार लाख मजदूर परिवार इस लहसुन से जुड़े हुए हैं। करीब चार से पांच लाख परिवारों को लहसुन की पैदावार से आय अर्जित होती है, तो क्या इन परिवारों को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, हाड़ौती का व्यापार भी कृषि पर ही आधारित है और बहुत बड़ा लहसुन का भी योगदान है जिसका लागत मूल्य भी करीबन पच्चीस हजार रुपये प्रति बीघा आ रहा है मंत्री महोदय, तो किसानों का बाइस रुपये-चौबीस रुपये में जो लहसुन आज बिक रहा है मंडी में, क्या उस पर सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत केन्द्र को प्रस्ताव भेज कर एमआईएस स्कीम के तहत लहसुन की खरीद करने की कोई योजना रखती है? यदि हां, ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न बहुत लंबा हो गया, संक्षिप्त कीजिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): तो कब तक? इस पर सहमति दें और केन्द्र से एमएसपी समर्थन मूल्य पर भी लहसुन को उस सूची में डाला जाए, ताकि लहसुन का समर्थन मूल्य घोषित करके उस पर खरीद प्रारंभ की जा सके। मंत्री महोदय, सदन को अवगत कराए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता के द्वारा निश्चित रूप से जो चिन्ता व्यक्त की गयी है वास्तव में कोटा डिवीजन का यदि हम पिछले तीन साल का देखते हैं तो 2015-16 में 52,286 हैक्टेयर में फसल की बुआई की गयी थी और जहां प्रोडक्शन का सवाल था 2,82,439 मैट्रिक टन के लगभग प्रोडक्शन हुआ। 2016-17 की यदि बात करें तो ढाई गुना से ज्यादा किसानों के द्वारा लहसुन की फसल बोई गयी। लगभग 1,38,231 हैक्टेयर में किसानों के द्वारा कोटा संभाग में फसल बोई गयी है और अनुमानित प्रोडक्शन उसका 7,87,000 मैट्रिक टन के लगभग निश्चित रूप से होगा।

यह बात भी सही है कि अभी जो बाजार भाव है चूंकि उत्पादन कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन यदि हम देखें तो 27 से 29 रुपये पर किलो के हिसाब से उसकी बुआई का खर्चा किसान को उठाना पड़ता है, लेकिन यह बिलकुल सही है कि पूरे प्रदेश की यदि हम बात करते हैं लहसुन के बारे में तो 2015-16

(श्री प्रभू लाल सैनी)

में लगभग 69,099 हैक्टेयर में बुआई थी लेकिन अब बढ़ कर 1,51,773 हैक्टेयर में उसकी बुआई हुई और प्रोडक्शन का जहां तक सवाल है 8,43,000 मैट्रिक टन के लगभग लहसुन की पैदावार होगी। कुछ मंडियों के 1 मार्च से लेकर 14 मार्च तक के कुछ आंकड़ें हमने जुटाये हैं और इन मंडियों में वर्तमान में जो लहसुन के भाव चल रहे हैं वो मैक्सिमम 1 तारीख को 6 हजार रुपये क्विंटल थे, 2 तारीख को 5,500 रुपये थे, 3 तारीख को 6,000 रुपये थे और 14 तारीख यदि हम देखें तो 5,250 मैक्सिमम थे। लेकिन अगर मिनीमम को हम देखें माननीय अध्यक्ष महोदय, तो 4 हजार से 3 हजार और उन्तीस सौ तक अलग-अलग मंडियों में उसके भाव आ रहे हैं।

आपने एक सवाल यह भी किया कि क्या इंटरवेंशन सरकार करना चाहती है, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम 2011-12 में चूंकि लागू हुई थी, एक साल चूंकि यह पेरीसेबिल आइटम है, खरीदने के बाद इसके खराब होने की गुंजाइश बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी भाव चूंकि तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखें तो ठीक हैं। यदि भाव गिरते हैं तो निश्चित रूप से सहकारिता विभाग और हम मिल कर कोशिश करेंगे भारत सरकार की इंटरवेंशन ऑफ मार्केट एमआईएस स्कीम लागू हो जाए जिसमें कि 50 परसेंट पैसा भारत सरकार की वहन करना पड़ता है और 50 परसेंट पैसा राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। यदि किसानों के हित में बहुत बड़ा फैसला लेने की जरूरत पड़ेगी माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम लोग एमआईएस के अन्तर्गत प्रस्ताव भेज कर भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने समर्थन मूल्य पर खरीद के बारे में जो मैंने पूछा था उस पर कुछ नहीं बताया। मंत्री महोदय अपने जवाब में स्वीकार कर चुके हैं कि कोटा में भामाशाह मंडी में स्थान उपलब्ध नहीं है, वहां एयर क्रोस वेयरहाउस खोले जाने की संभावना कम है। क्या सरकार, प्याज के भंडारण पर वेयरहाउस बनाने पर केन्द्र सब्सिडी देता है, उसी तर्ज पर सूची में लहसुन को भी सम्मिलित करते

(श्री हीरालाल नागर)

हुए उसके भंडारण के लिए वेयरहाउस पर किसानों को सब्सिडी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह बताया कि मसाला बोर्ड मसाला श्रेणी में आने वाली फसलों का ही निर्यात में प्रोत्साहन करता है। लहसुन को निर्यात स्टोरेज प्रोसेस करने व कोटा में निर्यात प्रोसेस स्टोरेज डिहाइड्रेट करने के लिए रियायती दर पर वहां इस तरह का कोई निर्यात प्रोसेसिंग पार्क घोषित करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और इनके लिए कोई तकनीकी उपलब्ध कराने के बारे में भी सरकार कोई विचार रखती है क्या, ताकि किसानों को जो व्यापारी हमारी उपज खरीदते हैं उससे उनको प्रोसेसिंग भी मिल सके, उसका स्टोरेज हो सके। निश्चित रूप से बहुत बड़ी आवश्यकता आज हाड़ौती में कोटा हो, झालवाड़ हो, सभी जगह पर यह उत्पादन हो रहा है और आम किसान इससे जुड़ा हुआ है तो इसके बारे में प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग हाउस और इसके निर्यात का विचार रखती है सरकार?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिये हैं, आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन है चूंकि अभी पहली बार, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने पहली बार लहसुन को, पहले यह वेजीटेबल में अकेले सब्जी मंडियों में बिकता था, लेकिन अबकी बार इसको मसाला मंडी यानी कि सारी अन्य जो मंडियां हैं उनमें इसकी अनुमति दी है। कोटा में जहां तक आपने कहा कि हमने पूरी कोशिश करके लहसुन की पूरी व्यवस्था क्रय-विक्रय करने के लिए भामाशाह मंडी में भी की है और फल-सब्जी मंडी में भी की है। दोनों मंडियों में समुचित व्यवस्था सीसी प्लेटफार्म बना कर हम लोगों ने की है और कवर्ड प्लेटफार्म भी हम लोगों ने लिये हैं। निश्चित रूप से किसान के हित में हम लोग काम करेंगे।

दूसरा आपने सरकार द्वारा इसके प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन बनाने की बात की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है अभी राजस्थान में मसाला फसलों पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन बने हुए हैं और

(श्री प्रभू लाल सैनी)

खास तौर से बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर की बात करें तो वहां पर जीरे का एक्सपोर्ट जोन बना हुआ है और इसी प्रकार धनिये का भी एक्सपोर्ट जोन कोटा संभाग में बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से आज यह घोषणा करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से लहसुन पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन बनेगा। इसमें चार जिलों को जोड़ कर जहां सबसे अधिक पैदावार होती है उनमें प्रोसेसिंग से लेकर, वैल्यू एडिशन से लेकर हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स उपलब्ध कराने के लिए नयी तकनीक को लागू करके किसानों की आमदनी हम कैसे बढ़ाएं इसके पूरे प्रयास किये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री मंगलराम (कठूमर): मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मंत्री जी ने नहीं बताया है।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं। हो गया। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, लहसुन का रकबा हाड़ौती में पिछले सात सालों से जबर्दस्त बढ़ा है और सरकार के पास यह अनुभव है कि लागत की तुलना में लाभ किसान को नहीं मिल पा रहा है। 2010 में पिछली सरकार के समय हाड़ौती में तीन किसानों ने आत्महत्या की। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन हालातों में बाजार हस्तक्षेप योजना या समर्थन मूल्य पर खरीद का भारत सरकार को कोई अविलम्ब प्रस्ताव भेज कर उस पर कोई निर्णय कराने की स्थिति है क्या ? ताकि किसान को उसकी लागत की तुलना में लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है समर्थन मूल्य के बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि जो भी पेरीसेबल क्रोप्स होती हैं, कम समय में खराब होने वाली फसलों के प्रोक्योरमेंट करने का काम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत किया जाता है, ताकि किसान को उसका उचित मूल्य मिले।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

जहां तक माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि समर्थन मूल्य में इसको जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजेंगे, तो मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे विभाग के द्वारा प्रिंसिपल सैक्रेटरी, एग्रीकल्चर के द्वारा भी हम लोगों ने ऐसी कुछ क्रोप्स हैं, 22.04.2015 को हमने पहले से ही प्रस्ताव भिजवाये हैं। उन प्रस्तावों में हम लोगों ने कोशिश की है कि ग्वार, मोठ, चौला, जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, अरंडी, एलोवेरा और मेहंदी, यह हमारे राजस्थान के ऐसे उत्पाद हैं जो एमएसपी में सम्मिलित नहीं है। इनको सम्मिलित कराने के लिये भारत सरकार को हम लोगों ने 22.4.2015 को प्रस्ताव भिजवाया था। उसके रिप्लाई में भारत सरकार ने यह कहा कि समर्थन मूल्य पर हम उन्हीं जिन्सों को सम्मिलित करते हैं जो एक तो पेरिसेबल नहीं हो और दूसरा उनका यह कहना था कि जिस फसल का सामूहिक उपयोग पूरे भारत वर्ष में किया जाता हो। तीसरा उन्होंने कहा था जिसकी सैल्फ लाइन यानी शीघ्र खराब होने वाली फसलें नहीं हो और जिन फसलों को खाद्य पोषण सुरक्षा की दृष्टि से सम्मिलित किया गया हो, ऐसी क्रॉप्स को ही भारत सरकार के द्वारा एमएसपी के अंतर्गत पूरे देश को ध्यान में रखते हुए घोषणा की जाती है। फिर भी जो माननीय सदस्य ने कहा उस पर निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे, जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया है कि किसानों के हित में राजस्थान सरकार को जो भी फैसला लेने की जरूरत होगी, वह हम लेंगे। इंटरवेंशन स्कीम के तहत भाव गिरने के बाद अगर इंटरवेंशन करना पड़ेगा जैसा कि 2010-11 में हुआ था उसमें 6281 मैट्रिक टन के लगभग प्रोक्योरमेंट हुआ था। उस प्राक्योरमेंट में लगभग 698.82 लाख रुपये का नुकसान हुआ था क्योंकि पेरिसेबल होने से वह खराब हुआ था, फिर भी किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग भारत सरकार से आग्रह करेंगे। 50 प्रतिशत अनुदान देने की स्थिति में सहकारिता विभाग और हम संयुक्त रूप से प्रयास कर के इंटरवेंशन करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री प्रताप सिंह।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा और मंत्री जी जानते भी हैं कि लहसुन की पैदावार हाड़ौती में छीपाबड़ौद क्षेत्र से शुरू हुई है। छीपाबड़ौद में हाड़ौती का

(श्री प्रताप सिंह)

सबसे अधिक लहसुन मंडी में आता है क्योंकि वहां पर लहसुन के लिये स्पेशल मंडी है। वहां पर किसानों को माल बेचने की समुचित व्यवस्था है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या यह सही है कि मंडी जितने क्षेत्र में बनी हुई है और जिस प्रकार से आज लहसुन आ रहा है, उस हिसाब से वह छोटी पड़ रही है? मंडी ने प्रस्ताव भी भेजा है कि मंडी को और जमीन दी जाए, उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है, मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है कि छीपाबड़ौद में लहसुन की स्पेशल मंडी सरकार के द्वारा बनाई गयी थी और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट का जो काम होना था, वह भी सरकार के द्वारा करवाया गया था। जहां तक माननीय सदस्य जानना चाहते हैं इन्होंने जो प्रस्ताव भेजा है, उसको मैं निश्चित रूप से दिखवा लूंगा, अभी मेरे ध्यान में वह विषय नहीं है कि इनके कौन कौन से प्रस्ताव आये हैं। यदि मंडी समिति के पास राशि उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से उस पर शीघ्र कार्यवाही करके उसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा कोटा भामाशाह मंडी के विस्तार की योजना बनाई गयी थी। इसके लिये राज्य सरकार ने भामाशाह मंडी के पास की भूमि का सर्वे भी करवा लिया था लेकिन उसके बाद भामाशाह मंडी के विस्तार के लिये कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। इसी प्रकार फल सब्जी मंडी का जो प्रांगण है चन्द्रेसल वह हमारे कोटा शहर के बहुत अंदर घनी आबादी के मध्य में है और उसके लिये हमने प्रस्ताव दे रखा है। चन्द्रेसल में फल सब्जी मंडी का टर्मिनल बनाने की योजना तैयार पड़ी है उसके लिये राज्य सरकार के अभी तक क्या प्रयास हुए हैं। साथ ही प्रदेश की मंडियों को ई प्लेटफार्म से जोडने की योजना बनाई गयी थी, अभी तक कितनी मंडियों को इसके तहत डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ कर ऑनलाइन कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा साउथ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चूंकि भामाशाह मंडी एक शहर में बसी हुई मंडी है और निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट के आवागमन से किसानों को काफी समस्या उठानी पड़ती है। इस बात को सरकार ने भी गंभीरता से लिया है, उसके लगी हुई फोरेस्ट की जो लैंड है उसके लिये कंसल्टेंट नियुक्त हो चुके हैं, कई बार हम लोगों ने मीटिंग कर ली है। रेवेन्यू, फोरेस्ट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अधिकारियों के द्वारा मीटिंग भी की जा चुकी है, वह प्रक्रियाधीन है। हम लोग निश्चित रूप से शीघ्र ही उसका प्रस्ताव बनाकर डाइवर्जन के लिये राज्य सरकार को और राज्य सरकार के बाद लखनऊ भिजवाएंगे ताकि लैंड का डाइवर्जन हो जाएगा तो निश्चित रूप से उस मंडी को एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाने के जो प्रयास माननीय मुख्य मंत्री जी कर रही हैं, उसको हम लोग गति देंगे।

दूसरा प्रश्न आपने कहा कि लहसुन के बारे में आपका किस प्रकार का प्रयास रहेगा, निश्चित रूप से इस पर काफी बड़ा मैंने अपना वक्तव्य दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा यही प्रयास होगा कि किसानों को वाजिब दाम मिले और यह कैसे सुनिश्चित हो इसके सारे प्रयास सरकार की तरफ से हम लोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री हीरालाल दरांगी।

झाड़ोल के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

300. श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की पंचायत समिति झाड़ोल, फलासिया व कोटड़ा में विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पदों में से कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभागीय रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरा लाल दरांगी)

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित संचालन हो रहा है तथा उक्त केन्द्रों पर नियमित पोषाहार, टीकाकरण व अन्य सुविधाएं निर्बाध रूप से मिल रही हैं? यदि हां, तो किस प्रकार? यदि नहीं, तो सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हेतु क्या प्रयास कर रही है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती अनिता भदेल): (1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल (फ.) के तहत पंचायत समिति झाड़ोल, फलासिया व कोटड़ा में महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत, रिक्त पदों का विवरण व कब से रिक्त चल रहे हैं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालयों में विभिन्न रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थी अथवा संबंधित विभाग से कार्मिक उपलब्ध होने पर पदस्थापन किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग को राज्य में बाल विकास परियोजना अधिकारी के 100 पदों एवं सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के 26 पदों हेतु अर्थना की गयी है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। लिपिक ग्रेड-द्वितीय (कनिष्ठ लिपिक) के 19 पदों को भरने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग को अर्थना भेजी गयी है। विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय (लेखाकार)/कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों पर पदस्थापन के लिए निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को अनुरोध किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों की परीक्षा के उपरान्त 795 अभ्यर्थियों को अन्तिम रूप से चयन हेतु पात्र माना गया। नियुक्ति से पूर्व प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किये जाने के कारण नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये जा सके। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 01.02.2017 को खारिज किया गया। वर्तमान में प्रकरण विधिक परीक्षण हेतु प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

उक्त विधानसभा क्षेत्र में भी उक्तानुसार कार्मिक उपलब्ध होने पर रिक्त पदों पर सतत प्रक्रिया के तहत पदस्थापन किया जा सकेगा।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(3) जी हां। विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्रों पर नियमित पोषाहार दिया जा रहा है तथा एमसीएचएन दिवस पर टीकाकरण किया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्रों की गुणवत्ता सुधार हेतु किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "र" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक, मिस्टर दरांगी।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में पोषाहार की गुणवत्ता सुधार के लिये कितनी बार निरीक्षण किया गया, कितने सैम्पल लिये गये और उसकी क्या रिपोर्ट आई, नेगेटिव आई या पोजिटिव आई, उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि झाड़ोल में कितनी बार निरीक्षण हुए और कितनी बार उसकी रिपोर्ट आई है तो, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि हमने निदेशालय स्तर पर सभी डिप्टी डाइरेक्टर्स और सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी, जो हमारे पर्यवेक्षक हैं, उनको निर्देश जारी किये हैं कि वह हर गुरुवार को जिस दिन पोषाहार का वितरण होता है, उस दिन सभी मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ डिप्टी डाइरेक्टर्स से लेकर जो भी कर्मचारी हैं, वह सघन निरीक्षण करेंगे और माह में दो बार अधिकारी आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। गुरुवार को जिस दिन पोषाहार का वितरण होता है उस दिन व्हाट्स एप ग्रुप बनाकर, निदेशालय स्तर पर व्हाट्स एप ग्रुप बनाया गया है, सूचनाओं को समय पर ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है।

आपने परीक्षण की बात कही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि विभाग द्वारा हमने राज्य स्तर पर कुछ प्रयोगशालाओं को एनलिस्ट किया है, उन प्रयोगशालाओं के माध्यम से समय-समय पर पोषाहार की गुणवत्ता की जांच की जाती है। अभी तक पोषाहार की गुणवत्ता की जो हमने जांच की है उसमें कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

तीसरा मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहती हूं कि हमने स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पोषाहार का वितरण हो, यह भी निर्देश जारी किये हैं और साथ ही साथ गुरुवार को जिस दिन पोषाहार वितरण होता है उसके दो दिन पूर्व ही पोषाहार केन्द्र पर पहुंच जाये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हां यह पोषाहार बटने वाला है। साथ ही साथ जहां पर पोषाहार का निर्माण होता है, चाहे गर्म पोषाहार हो जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपूर्ति की जाती है, चाहे टीएचआर है, वह पोषाहार कहां बन रहा है, किन कंडीशंस में बन रहा है, उसके भी हमने निर्देश जारी किये हैं कि विभाग के अधिकारी स्वयं जहां निर्मित होता है, वहां जाकर देखे। और उस पोषाहार को किस क्वालिटी के साथ बनाया जा रहा है, उसका भी ध्यान रखें। ये सारी व्यवस्थाएं हमने विभाग के स्तर पर की हैं और आपने जो बात की है कि आप और क्या-क्या करने वाले हैं? तो हमने ये सारी व्यवस्थाएं पोषाहार की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए की है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाल विकास परियोजना में काफी पद रिक्त हैं। प्रदेश में 750 अभ्यार्थियों की नियुक्ति का माननीय हाई कोर्ट का 1 जनवरी, 2017 को फैसला आने के बाद.. माननीय मंत्री महोदया ने जवाब दिया कि जांच चल रही है तो किस बात की जांच चल रही है व प्रदेश में आज तक कुल कितने पद रिक्त हैं?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो बात कही है। एक तो आपने एन.टी.टी. के टीचर्स की बात उठाई है कि 795 एनटीटी के अभ्यर्थी मिले हैं, उसके विधिक परीक्षण की बात मैंने कही थी। क्योंकि हाई कोर्ट का एस.बी.सी. के लिए जो स्थगन आया है, उसके कारण यह विधिक परीक्षण में गयी है और जैसे ही विधिक परीक्षण पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम इनका पदस्थापन करेंगे।

आपने एक बात कही है कि मेरे विभाग में कितने पद रिक्त चल रहे हैं। मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि उदयपुर जिले की जब मैं बात करूंगी तो उदयपुर में उप निदेशक का

(श्रीमती अनिता भदेल)

एक पद है और एक वहां पर कार्यरत है। सी.डी.पी.ओ. की चौदह पोस्ट हैं। चौदह पोस्ट के अगेंस्ट वहां ग्यारह लोग कार्यरत हैं। ए.सी.डी.पी.ओ. की आठ पोस्ट हैं, लेकिन एक भी ए.सी.डी.पी.ओ. का पदस्थापन नहीं है। सारी पोस्टें वेकेंट हैं। पर्यवेक्षकों की 123 पोस्टों के अगेंस्ट 78 पद भरे हुए हैं, 45 पद खाली हैं। कार्यालय अधीक्षक की एक पोस्ट है और एक पोस्ट भी भरी हुई है। सहायक कार्यालय अधीक्षक की पांच पोस्ट हैं, उनके अगेंस्ट चार पोस्ट भरी हुई हैं, एक पोस्ट खाली है। यू.डी.सी की आठ पोस्ट हैं, उनके अगेंस्ट छह पोस्ट भरी हुई हैं, दो पोस्ट खाली हैं और इसी प्रकार से एल.डी.सी. की 17 पोस्ट के अगेंस्ट 13 पोस्ट भरी हुई हैं, 4 पोस्ट खाली हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का निवेदन हैं कि उनकी झाड़ोल परियोजना में एल.एस. की पोस्टों के अगेंस्ट एक पद भरा हुआ है, बाकी की पोस्ट खाली हैं। इसके बाद मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहती हूं कि आपकी जो एल.एस. की पोस्ट है, उसको हम शीघ्र ही भर देंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्रीमती द्रोपती। यह झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र से है।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): यह पूरे प्रदेश का मामला है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। इस एरिये की बात कीजिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश का है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: I will not allow. श्री रामलाल शर्मा। यह झाड़ोल का है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आपने जो वेकेंसी निकाल दी, उन वेकेंसियों के बाद में वार्डों का जो पुनर्गठन हुआ है। वार्डों के पुनर्गठन के बाद उन वेकेंसियों को आप दुरूस्त करोगी? क्योंकि पुनर्गठन के बाद काफी वार्ड चेंज हो गये।

श्री अध्यक्ष: चलो बैठिए।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है,

(श्रीमती अनिता भदेल)

पहले तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि हम परियोजना स्तर पर कोई वेकेंसी नहीं निकालते हैं। ये जितने पद हैं, ये स्टेट के पद हैं, मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद हैं। यह प्रश्न मंत्रालयिक कर्मचारियों से संबंधित पूछा गया है। आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बारे में बात करे रहें है। आपको भी मैं बताना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो पद हैं, उनकी विभाग के उप निदेशक के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की जाती है और जिस वार्ड में वेकेंसी होती है, उस वार्ड के आधार पर वह विज्ञप्ति जारी की जाती है। आपका निवेदन हैं चूंकि हर पांच साल बाद चुनावों में वार्डों का परि-सीमांकन चेंज हो जाता है। कभी वार्ड नं. 4 था, कभी 5 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है और उसका क्षेत्र भी बदल जाता है। आपने जो प्रश्न किया है, निश्चित रूप से वर्तमान में जो परि-सीमांकन है, उस परि-सीमांकन के आधार पर ही वार्डों की विज्ञप्ति निकाली जाएगी और यह मैंने आपको पहले भी आश्वस्त किया था। आज भी मैं यहां आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि वर्तमान में जो वार्ड की परिसीमा है, उस परिसीमा के आधार पर ही विज्ञप्ति निकाली जाएगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। तीसरा पूरक प्रश्न, श्री देवेन्द्र कटारा। झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र का है।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय, झाड़ोल से ही संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि झाड़ोल और झाड़ोल के आसपास के जितने भी आंगनबाड़ी सेन्टर हैं, उनमें पोषाहार वितरण एस.एच.जी. ग्रुप के माध्यम से होना होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है। इसके बाद भी झाड़ोल और झाड़ोल के आसपास के सभी क्षेत्रों में ठेकेदारों के माध्यम से पोषाहार वितरण हो रहा है और वह भी गुणवत्तायुक्त नहीं है। क्या माननीय मंत्री महोदया, इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश-निर्देश हैं, उनके तहत कार्यवाही करना चाहेंगी?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि यह पोषाहार का वितरण स्वयं सहायता समूह से न होकर ठेकेदार के माध्यम से हो रहा है। यदि आपकी जानकारी में कोई इस प्रकार का विषय आया है कि ठेकेदार के

(श्रीमती अनिता भदेल)

माध्यम से हो रहा है, आप मुझे बताएंगे तो निश्चित रूप से हम उसका निस्तारण करेंगे, पर मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगी कि मेरे पास पूरे उदयपुर संभाग की सूची है, झाड़ोल और उसके आस-पास के क्षेत्र की कि किस एस.एच.जी. के माध्यम से किस-किस आंगनबाड़ी पर पोषाहार की सप्लाई हो रही है और वे लगभग तीस-पैंतीस एस.एच.जी हैं, जिनके माध्यम से यह हो रहा है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगी। उदयपुर के कोटड़ा के आंगनबाड़ी सैक्टर 1st में आंगनबाड़ी केंद्र एक - कोटड़ा, झाझर बाड़ा, सरली, नान और गमारो का फलां। इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर चेहर माता कोटड़ा, एस.एच.जी. है, उसके माध्यम से पोषाहार की सप्लाई हो रही है। स्वयं सहायता समूह गरीब नवाज कोटड़ा के नाम से है, जिसके द्वारा कोटड़ा के कोटड़ा 3rd, कोटड़ा 4th, कोटड़ा 5th केंद्रों पर सप्लाई हो रही है और इसी प्रकार से पांच स्टार कोटड़ा, बादशाह समूह कोटड़ा, सांवरिया कलस्टर, मण्डवा, राधाकृष्ण, एस.एच.जी. समूह कोटड़ा। इस प्रकार से जो एस.एच.जी. हैं, उनके माध्यम से सप्लाई हो रही है। फिर भी आप यदि बतायेंगे कि ये आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिन पर एस.एच.जी. के माध्यम से नहीं होकर किसी ठेकेदार के माध्यम से हो रही है, तो मैं निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही कराने के लिए आपको आश्वस्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। अगला सवाल श्री भजन लाल जाटव।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर विषय है। प्रश्न करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय क्या है कि मेरे पास प्रश्न का जो उत्तर आया है, वह अतारांकित में आया है।

श्री अध्यक्ष: इसमें आया क्या? इसका है आपका।

श्री भजन लाल (वैर): इसी से है। इसका जो जवाब आया है, मेरे पास अतारांकित में आया है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न करें।

वैर में जारी खनन पट्टे

301. श्री भजन लाल (वैर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भजन लाल)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र वैर में सरकार द्वारा खनन पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां किस-किस ग्राम में व किस-किसको तथा कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) खनन क्षेत्र में क्रैशर लगाने के क्या मानदण्ड निर्धारित है? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में लगे क्रैशर सरकार के मानदण्डों के अनुसार लगे हुए हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में खनन व क्रैशरों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोई उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खान (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र वैर में सरकार द्वारा खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी सूची ग्राम, नाम व अवधि सहित परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) खनन पट्टाधारी खनन पट्टे की संविदा की शर्तों के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र में क्रैशर लगा सकता है। क्रैशर की स्थापना एवं संचालन हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से कन्सेन्ट टू एस्टेब्लिश व कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त करना अनिवार्य है। क्रैशर लगाने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शिका जारी की गयी है। वर्तमान में लागू मार्गदर्शिका दिनांक 15.10.2014 एवं संशोधन दिनांक 30.04.2015 एवं 18.06.2015 की प्रति क्रमश: परिशिष्ट अ, ब एवं स पर उपलब्ध है।

(3) वैर विधान सभा क्षेत्र में स्थापित स्टोन क्रैशर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी मार्गदर्शिका में क्रैशर की स्थापना हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्थापित किए गये हैं, तथापि 7 स्टोन क्रैशरों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है। इन सभी उद्योगों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट- द एवं य पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, खान)

(4) खनन पट्टाधारी द्वारा खनन के दौरान पर्यावरण सुरक्षा हेतु किये जाने वाले उपायों का प्रावधान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 34 में किया गया है, जिसकी पालना करने हेतु पट्टाधारी बाध्य है नियमों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा खनन इकाइयों एवं स्टोन क्रैशर उद्योगों को समुचित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने हेतु बाध्य किया जाता है। प्रदूषण की जांच के लिए खनन इकाइयों एवं स्टोन क्रैशर उद्योगों का राज्य मण्डल द्वारा जारी मार्गदर्शिका में उल्लिखित समयावधि के अनुसार निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग किए जाने का प्रावधान है। दोषी पाए गए उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में 7 स्टोन क्रैशर उद्योगों को अपर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के कारण वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31(ए) के अन्तर्गत बंद कराने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'य' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: आपके पास तारांकित प्रश्न का जवाब नहीं आया है क्या?

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा ....

श्री अध्यक्ष: मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो।

श्री भजन लाल (वैर): हां बिलकुल, इसमें क्या है कि मेरे को जवाब दिया गया है वह अतारांकित लिखकर दिया गया है। यह तारांकित नहीं है। अतारांकित है। कहीं न कहीं इसमें तथ्य छुपाए गये हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब वही है न?

श्री भजन लाल (वैर): इसमें जो अधिकारी है उनकी मिली भगत से उन तथ्यों को छुपाया गया है। जवाब आया है वह मेरे पास अतारांकित आया है।

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, तारांकित का जवाब है या अतारांकित का है?

श्री भजन लाल (वैर): जो जवाब दिया गया है अतारांकित है। अतारांकित दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: तारांकित ही है। गलती से अतारांकित हो गया। आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में जिन खानों के निर्धारित हैक्टेयर में सरकार द्वारा पट्टे जारी किए गये हैं, क्या यह सही है कि उसकी कई गुना ज्यादा भूमि पर खनन किया जा रहा है?

नम्बर दो, वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में एक भौड़ागांव है उसमें 124 हैक्टेयर का खनन है, उसके उपरान्त उसमें खनन किया जा रहा है। साथ में वहां की 252 बीघा चारागाह है उसमें अवैध खनन हो रहा है। मंत्री जी 2016-17 में वैर विधान सभा क्षेत्र में कितने खनन पट्टे जारी किए गये हैं, वह बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुल 2154 क्रेशरों के पट्टे हमने जारी किए हैं। भरतपुर जिले में 299... ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): माननीय मंत्रीजी, मैं वैर की बात कर रहा हूं। वैर, ओनली वैर।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): ...(व्यवधान)...34 क्रैशरों के पट्टे जारी किए गए हैं।

श्री भजन लाल (वैर): इसमें जवाब नहीं है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अब सुन लो, प्यार से सब बता दूंगा।

श्री भजन लाल (वैर): मंत्री जी, इसमें कुछ भी जवाब नहीं है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): सुन तो लो।

श्री भजन लाल (वैर): मैं क्या सुनूं? ...(व्यवधान)... जब इसमें जवाब ही नहीं है कोई। न तो 34 खानों का कहीं जिक्र है। इसमें जवाब ही नहीं दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): आप सुनिए।

श्री भजन लाल (वैर): इसमें जवाब ही नहीं दिया गया है। ...(व्यवधान)... मैं इसमें क्या सुनूं, इसमें सुनने के लिए कुछ दिया नहीं गया। पर्यावरण का इसमें कहीं कुछ नहीं दिया गया। मैं इसमें क्या सुनू।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं आपको बता रहा हूं न। माननीय अध्यक्ष महोदय, खनन का पट्टा अलग विषय है, यह क्रैशरों का प्रश्न है।

श्री भजन लाल (वैर): मेरा खनन पट्टे का प्रश्न है। कितने खनन पट्टे ...(व्यवधान)... आप ध्यान से पढ़े। मेरा फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, आप एक बार देखें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): वर्तमान में पांच खनन पट्टे जो क्रेशर हेतु आपके यहां जारी किए गये हैं, ठीक है न। पांच खनन पट्टे आपके क्रेशरों के स्वीकृत है। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): मैंने इसमें फर्स्ट में ही लिखा है कि कितने खनन पट्टे जारी किए गये। इसमें फर्स्ट में ही क्वेश्चन है। पहले नम्बर पर ही है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं आपको कह रहा हूं न, ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): उसका कहीं जिक्र तक नहीं है इसमें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): आपके क्रेशरों के लिए पांच खनन पट्टे जारी किए गये हैं।

श्री भजन लाल (वैर): जिक्र नहीं है, कितने खनन पट्टे जारी किए गये? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब इसमें आया है, बिलकुल गलत है। बिलकुल गलत जवाब इसमें दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं पांच खनन पट्टे जारी किए गये हैं।...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): कहीं पर भी इसमें खनन पट्टे नहीं दर्शाये गये हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ठीक तरीके से जवाब दें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण मण्डल क्रेशर के लाइसेंस जारी करते हैं। हम तो केवल ...(व्यवधान)...

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

पूरी विधान सभा के अंदर 96 खनन पट्टे हैं, लेकिन पांच खानों के पट्टों में क्रेशर है। 96 टोटल है लेकिन क्रेशर केवल पांच में ही हैं। बाकी क्रेशर जरूरी नहीं कि खनन पट्टे में लगे। क्रेशर लगाने के लिए तहसीलदार के यहां आवेदन होता है। भू रूपान्तरण के बाद तहसीलदार उसको प्रदूषण मण्डल के पास भेजता है। प्रदूषण मण्डल ने वहां के क्षेत्रीय अधिकारी को पाबंद कर रखा है कि वह इसके लिए अपनी स्वीकृति जारी करें। उसमें कुछ शर्ते होती हैं। प्रदूषण मण्डल की जो शर्ते हैं 1500 मीटर, वह गांव से दूर होगा, उसके अंदर पक्का रास्ता होना चाहिए, उसके अंदर जो दूर जाएगी उसकी दीवार बननी चाहिए, उसके अंदर 33 प्रतिशत...(व्यवधान)... उसको लगानी है, वह सारी, जब वह ईसी जारी करते हैं तो फिर वह अपना क्रेशर लगाता है, क्रेशर लगाने के बाद फिर उसका इंस्पैक्शन होता है। फिर उसको सीटीओ जारी करते हैं कि अब इसको चला सकते हो, फिर वह चलाता है। अगर कोई भी क्रेशर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। जहां तक इसकी कार्यवाही का सवाल है, इनके वैर विधान सभा क्षेत्र में 31 अवैध प्रकरण पकड़े गये। आठ लाख जुर्माना हुआ। चार एफआईआर अवैध खनन के अंदर हुई है। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ क्या रहा हूं, प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न का उत्तर मैं पूछ रहा हूं, जवाब कुछ और दे रहे हैं। मेरे को कहना चाह रहे हैं कि इसमें 35 खनन पट्टे जारी किए गये हैं। अतारांकित सवाल है उसमें आया है 89 पट्टे दिए गये हैं। यह कह रहे हैं 35 आए हैं। जवाब दे रहे हैं 89 पट्टे हैं। किसका सही मानूं मैं? ...(व्यवधान)...मंत्रीजी का सही है, मेरे पास जवाब आया वह सही है, यह है क्या?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, 96 पट्टे खनन के जारी है जिनमें 5 खान पट्टों के अंदर क्रेशर लगा हुआ है, बाकी खनन के अलग है। अब बताओ, और क्या पूछना है ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): बिलकुल गलत जवाब है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): 35 क्रेशर ...(व्यवधान)... लगे हुए हैं। खान पट्टे 96.....

श्री भजन लाल (वैर): इन्होंने जो 7 पट्टों का जिक्र किया है ...(व्यवधान)... मंत्रीजी को पता ही नहीं है, ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): 96 खान पट्टे हैं, पांच खान पट्टों में क्रेशर लगे हुए हैं, यह जो 34 हैं यह क्रेशर लगे हुए हैं, आपने क्रेशरों का पूछा है।

श्री भजन लाल (वैर): मैं यही कह रहा हूं आपको। 89 तो क्रेशर लगे हुए हैं। मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूं और क्या कहना चाह रहा हूं। आपने जो जवाब दिया है वह 89 का दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): जवाब को दिखवा लेंगे साहब ...(व्यवधान)... गलत हो तो चैक ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): आप कह रहे है 35 दिए गये हैं। इसमें 89 हैं। आपके जवाब में 89 हैं। तो इनका सही मानू या यह सही मानू?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं आपको जो कह रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): यह तो जवाब दें, आपको कुछ पता ही नहीं ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): पहले सुन लो आप ...(व्यवधान)... देखिए, आपने क्रेशर पूछे थे, वैर विधान सभा क्षेत्र में 96 खनन पट्टे हैं।

श्री भजन लाल (वैर): मैं कह रहा हूं क्रेशर आपने 35 बताई। ...(व्यवधान)... क्रैशर 89 हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): 34 क्रैशर लगे हुए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): क्रेशर 89 है। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 क्रेशर है उसमें इन्होंने जो नोटिस जारी किए हैं वह मेरे प्रश्न लगने के ....

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिए, जवाब आ गया ...(व्यवधान)... जितना है उतना।

श्री भजन लाल (वैर): 7 क्रेशर...

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक जितना जवाब है वह आ गया ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): मेरा बहुत अहम मुद्दा है, वहां लोग आंदोलन कर रहे हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मुद्दा है। वहां पर लोग सांस, दमे की बीमारी से मर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि वहां की फसल नष्ट हो रही है, उसके ऊपर कम से कम ढाई सौ क्रेशर चल रही हैं। डेढ सौ क्रेशर अवैध हैं। आप निरीक्षण करिए। उच्च स्तरीय उसकी जांच करवाईये। वहां पर किसानों का बुरा हाल है। उनकी फसल बर्बाद हो गयी। आए दिन वहां पर दमे की बीमारी से मौत होती है। यह किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह मेरा मुद्दा नहीं, आम किसान, गरीब जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: खतम हो तो आप ...(व्यवधान)... विराजिये

श्री भजन लाल (वैर): क्रेशरों में वहां पर पोल्यूशन में, पर्याप्त पोल्यूशन का होता है, कितने वहां पर हास्पिटल खोले, कितने वहां पर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई, वहां पर कितने किसानों की मौत हुई ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये।

श्री भजन लाल (वैर): कितनों को वहां पर मुआवजा मिला।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये।

श्री भजन लाल (वैर): कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैर से आने वाले विधायक पूछ रहे हैं 34 क्रेशर वहां स्वीकृत थे। उसमें पांच तो बंद कर दिए, जो सही नहीं चल रहे थे। 7 में नोटिस दिया हुआ है। नोटिस के अंदर अगर वह दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको भी बंद कर देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न, गोविन्द सिंह डोटासरा ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): इसमें 89 है, मैं कह रहा हूं 89...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आ गया जितना जवाब था ...(व्यवधान)... गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री भजन लाल (वैर): मैं टेबल करता हूं ...(व्यवधान)... यह आपका है, यह टेबल करूंगा और टेबल करने के बाद ...(व्यवधान)... इसमें 89 है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): 7 को हमने प्रदूषण का नोटिस दे दिया है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): उसमें वह गलत पाए जाएंगे तो उनको बंद कर देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, अब विराजिये। ...(व्यवधान)... नहीं, यह नहीं। जितना जवाब था आ गया, इससे संतुष्ट नहीं है तो आप उनसे बात कर लीजिए। ...(व्यवधान)... नहीं, यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता।

श्री भजन लाल (वैर): गलत है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: गलत भी आया है तो दूसरी प्रक्रिया है ...(व्यवधान)... आप विराजिये। नो, इनका वक्तव्य नहीं जाएगा अब। गोविन्द सिंह डोटासरा, पूरक प्रश्न। नहीं, नहीं ...(व्यवधान)... अंकित नहीं हो।

श्री भजन लाल (वैर): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे बार बार कह रहा हूं कि खानों के अंदर क्रेशर लगना जरूरी नहीं है। केवल पांच ऐसी खानें हैं जिनमें क्रेशर की अनुमति ली है। बाकी अलग-अलग है खान से ...(व्यवधान)... मैंने आपको दस बार बता दिया कि प्रदूषण बोर्ड ने 34 क्रेशरों को स्वीकृति दी है। पांच बंद हैं और 7 में प्रदूषण के कारण नोटिस दिया हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): और उनमें बंद कर देंगे ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): 000

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): 89 पट्टों में क्रेशर नहीं है। ...(व्यवधान)...

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त।

बधाई एवं आभार

अनिता भदेल, श्रीमती, राज्य मंत्री को राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई

माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें। मैं एक बधाई संदेश आपके सामने पढ़ रहा हूं।

माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2017 को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती अनिता भदेल को प्रदेश में बालिका लिंगानुपात में हुई वृद्धि और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में नवाचारों के लिये 'राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार' प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुरस्कार-स्वरूप महिला एवं बाल विकास विभाग को एक लाख रुपये की नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

श्रीमती अनिता भदेल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री को राष्ट्रपति महोदय द्वारा 'राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार' से सम्मानित किये जाने पर मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की भी एक बधाई है, उत्तर प्रदेश के चुनावों की, उत्तराखण्ड के चुनावों की, गोवा के चुनावों की, मणिपुर के चुनावों की, उसको भी बता दें। ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पंजाब में कौन देगा। पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में। गोवा में क्या किया आपने। मणिपुर में क्या किया। ...(व्यवधान)...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): पंजाब की दे दो, माननीय अध्यक्षजी, पंजाब की दे दो, पंजाब की, पंजाब की दिलवा दो। ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पंजाब में क्या हालत हुई आपकी। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वहां पर भी सरकार बनाई। ...(व्यवधान)... आपके कालिख पोत दी। आपके मंसूबे पर पानी फेर दिया। ...(व्यवधान)...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): भारत माता की जय। जय-जय श्रीराम। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: डेढ़ साल बाकी है। ...(व्यवधान)... डेढ़ साल बचा है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): 11 तारीख को क्या हुआ। 11 तारीख को बताएंगे। क्या बताओगे, 11 को, अब बताओ। ...(व्यवधान)... सूपड़ा साफ।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): भारत माता की जय हो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): 11 तारीख का जवाब दो, 11 तारीख की कह रहे थे, 11 को बताएंगे। अब सूपड़ा साफ, चुपचाप हो गये। क्या हुआ। खुद तो डूबे और सपा को भी ले डूबे। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): सारी जगहों पर हमारी सरकार बन गयी। केवल एक मात्र जगह वहां बचे हो, बाकी सब जगह हमारी सरकार बनी है। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से सबको बधाई।

श्री अध्यक्ष: विराज जाइये। आसन अपने पैरों पर है, विराज जाइये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में मोबाइल टावर लगाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से कोटा के नयापुरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवन को नियमों के विपरीत उम्मेद क्लब संस्था को दिए जाने से सरकार को हुई राजस्व हानि के सम्बन्ध में।

3. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी खातेदारी, चारागाह व सिवाय चक भूमि से किसानों द्वारा निजी उपयोग के लिए मिट्टी उठाने पर सरकार द्वारा पैनल्टी वसूल किए जाने से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आसन पैरों पर है। माननीय अध्यक्षजी, आप व्यवस्था पढ़ रहे हैं और देखिये, वह माननीय सदस्य, मैं कहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें। स्थान ग्रहण करें।

4. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में।

5. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से पैरा टीचरों एवं प्रबोधकों की सेवा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

6. श्री मानिक चन्द सुराना एवं श्री भंवर सिंह सदस्य की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सुकमा में नक्सली हिंसा में शहीद श्री जगदीश विश्नोई के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से सहायता की घोषणा करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्री मेवाराम जैन, श्री सुखराम विश्नोई, श्री मानिक

(श्री अध्यक्ष)
चन्द सुराना एवं श्री भंवर सिंह को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बायतू में पेट्रोलियम परिशोधन के लिये रिफाइनरी की स्थापना करने के सम्बन्ध में।
2. श्रीमती सोनादेवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के सीमावर्ती ग्रामों के किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के सम्बन्ध में।
3. डा. प्रेमचन्द बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दूदू में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।
4. श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से बालोतरा उप खण्ड मुख्यालय पर डिस्कॉम का उप भण्डार खोले जाने के सम्बन्ध में।
5. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये खेल नीति का समयबद्ध पालन किये जाने हेतु।
6. श्री दलीचंद डांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही निरस्त कर उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
7. श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
8. श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में रेलवे स्टेशन के पास मुख्य सड़क के रेलवे क्रासिंग पर प्रस्तावित अण्डर ब्रिज के स्थान पर ओवर ब्रिज निर्माण स्वीकृति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री किशनाराम, सदस्य की ओर से भारतीय कौशल विकास विश्वविद्‌यालय, जयपुर विधेयक, 2017 की अनुसूची 2 में क्षौरकार एवं ब्यूटीपार्लर विषय को शामिल करने व श्रम विभाग में क्षौरकार कार्य करने वालों को क्षौरकार आर्टिजन के रूप में शामिल करने के सम्बन्ध में।

10. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से विद्‌यार्थी मित्रों को तत्काल स्थायी नियुक्ति देने के सम्बन्ध में।

11. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में परिवीक्षा काल में अन्य विभाग में समान कैडर व समान पद पर नियुक्त होने पर पूर्व विभाग के परिवीक्षा काल को नवीन परिवीक्षा अवधि में जोड़ने के सम्बन्ध में।

12. श्रीमती द्रोपती, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की ग्राम पंचायत खरलिया के गांव थिराजवाला में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्‌वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 16 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 48 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्‌वारा 4 पर्चियां निकाल गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री शुभकरण चौधरी - तहसील उदयपुरवाटी की ग्राम पंचायत धमोरा, सिंगनौर एवं पोषाणा को तहसील उदयपुरवाटी के स्थान पर उप तहसील गुढ़ागौड़जी में शामिल करने के सम्बन्ध में।
2. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा - नागौर शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री मान सिंह - गंगापुरसिटी महुकला अण्डर पास खोलने के सम्बन्ध में।
4. श्री कन्हैयालाल - समर्थन मूल्य पर चना व सरसों की खरीद किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री मेवाराम जैन।

सूचना

सांचौर में वर्षा से क्षतिग्रस्त ईसब की फसल

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सांचौर में बरसात होने से पूरा का पूरा ईसब झड़ गया, कम से कम सर्वे करवाया जाए। मेरे सांचौर में ही नहीं, बाड़मेर में जहां-जहां बरसात हुई, ईसब के लिये मान लीजिये एक इंच बरसात हुई तो भी वह झड़ जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय आपदा राहत मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है। पूरे तहसील में अकाल है चितलवाना, सांचौर में, ऊपर से बरसात से ईसब जल गया है। इसका सर्वे करवाया जाए और किसानों को मुआवजा दिलाया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन की एक बात करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, पहले आप अपना ये पढ़िये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह आपका जो स्थगन प्रस्ताव है, उस पर बोलिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पहले यह बोल लूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, नहीं। इधर-उधर नहीं, स्थगन प्रस्ताव।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बाड़मेर कन्या महाविद्यालय का क्रमोन्नयन

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव के तहत आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। बाड़मेर जिला मुख्यालय, जो बार्डर एरिये पर आया हुआ है और जहां 26 लाख की पापूलेशन है, वहां कन्या महाविद्यालय है। वहां की बालिकाएं शिक्षा से पिछड़ी हुई हैं। अभिभावक बड़ी मुश्किल से उस कालेज में पढ़ने भेजते हैं। माननीय अध्यक्ष

(श्री मेवाराम जैन)

महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर के महाविद्यालय में करीबन 600 बालिकाएं पढ़ रही हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। इधर-उधर नहीं घूमें, बातचीत न करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): वे बालिकाएं, बी.ए. पास करके आगे पढ़ने जा नहीं पा रही हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस महाविद्यालय को पी.जी. कालेज में कन्वर्ट करें, ताकि वहां की बच्चियां बाहर जोधपुर जाने के लिये मजबूर न हों और वहीं बाड़मेर में अध्ययन करने के लिये कालेज मिले। इसके लिए कई बार धरने, प्रदर्शन हुए, आपने अभी कुछ अप-ग्रेड भी किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस कन्या महाविद्यालय को अप-ग्रेड कर पी.जी. कालेज कराएं। बाड़मेर में आपको पता है कि तेल के भंडार है, वहां पर दुनियाभर के खनिज पदार्थ हैं। इतनी रॉयल्टी प्रदेश को मिल रही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाएं ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): महिला मुख्य मंत्री के रहते हुए बच्चियों के लिए आप यह घोषणा करेंगे, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पांड करेंगी?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो कन्या महाविद्यालय बाड़मेर में स्नातक है, उसको स्नातकोत्तर करवाने की मंशा है। वह इसे क्रमोन्नत करवाना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि अभी वहां पर जो कन्या महाविद्यालय है, इसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों ही संकाय संचालित हो रहे हैं 1997 से और अभी बाड़मेर का जो राजकीय महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में पी.जी. क्लासेज हैं। हमारे पास-हिस्ट्री, पोलिटिकल साइंस, ए.बी.एसटी. और केमिस्ट्री, इन चारों सब्जैक्ट्स के अंदर ऑलरेडी पी.जी. क्लासेज हैं और 194 विद्यार्थी, जिसमें से 121 छात्र

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

और 70 के करीब छात्राएं हमारी वहां पर पी.जी. के अंदर अध्ययनरत हैं। इसलिए अभी फिलहाल तो हमारा नहीं है कि हम कन्या महाविद्यालय को पी.जी. में करें, लेकिन फिर भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर बाद में विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री सुखराम विश्नोई।

पैराटीचर्स एवं प्रबोधकों की पदोन्नति व स्थानांतरण

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पैराटीचर को प्रबोधक बने 17-18 साल हो गये। प्रबोधक बने, उससे पहले पैराटीचर थे, उन पैराटीचर का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल को प्रबोधक कार्यकाल की सेवा में जोड़ा जाए ताकि उसे प्रमोशन का फायदा मिले। उसके बाद प्रबोधक के अंदर कोई ग्रेड नहीं है, जबकि टीचर्स में ग्रेड है। बराबर पढ़ाते हैं, उसी स्कूल में पढ़ाते हैं। प्रबोधक का फर्स्ट और सैकिण्ड कोई ग्रेड तय किया जाए ताकि उन्हें भी प्रमोशन का फायदा मिले।

साथ ही, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि प्रबोधक के प्रमोशन की कोई व्यवस्था नहीं की। टीचर्स की व्यवस्था है, सैकिण्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड बाकायदा परंतु प्रबोधक के कोई ग्रेड की व्यवस्था नहीं है तो ग्रेड की व्यवस्था की जाए। साथ ही, कई ऐसे प्रबोधक अब रिटायर होने के कगार पर हैं, तो उनकी समय सीमा, कार्य सीमा तय नहीं, चार-पांच साल में रिटायर हो जाएंगे तो उनको भी रेगुलर टीचर की तरह 9, 18 और 27 साल का जो फायदा मिलना चाहिए वह फायदा भी पैराटीचर को मिले ताकि उनका परिवार भी सक्षम हो जाए, वह भी मजबूत रहे।

साथ ही, मेरा आपसे निवेदन है कि जब से इनकी नियुक्ति हुई है, नियुक्ति के बाद में इनकी पेंशन का कोई आधार नहीं रखा है। तनख्वाह कम मिल रही है, पेंशन नहीं मिलेगी तो बुढ़ापे में वह जीवन किस तरह से यापन करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि उनकी भी पेंशन की व्यवस्था की जाए ताकि उनका परिवार बुढ़ापे में बिलकुल व्यवस्थित तरीके से चले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है,

(श्री सुखराम विश्नोई)

कि पैराटीचर या प्रबोधक कहें, इनका कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है मतलब, पूरे शिक्षकों में ट्रांसफर की व्यवस्था पर प्रबोधक जहां पर लगा है, वहीं लगा हुआ है, इन प्रबोधकों का ट्रांसफर भी जिले से बाहर हो, तहसील से बाहर हो, ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि प्रबोधक फायदा उठा सकें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में और 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को शिक्षा मिले, इसके लिए 1999 से लेकर 2002 के बीच में पैराटीचर्स की भर्ती की गयी मुझे यह कहते हुए मन में बड़ी पीड़ा है कि उस समय इनकी सरकार ने केवल उनको 1200 रुपये पर नियुक्त किया और 1200 रुपये तो शायद न्यूनतम वेतन से भी कम होता है? अब उसके बाद जब हमारी सरकार आयी तो पहले हमने इनका मानदेय बढ़ाया लेकिन 2008 के अंदर जिला परिषदों के माध्यम से हमने इन प्रबोधकों का एक नया पद सृजित किया कैडर, जिसके अंतर्गत 24726 पदों पर हमने नियुक्ति की। इनके समय नियुक्ति जो 34 हजार की हुई, उसमें बाद में कुछ लोग छोड़कर चले गये, 24726 पदों पर नियुक्ति की गयी और उसके बाद लगभग 4642 इस समय केवल पैराटीचर्स ही काम कर रहे हैं। उसमें भी 2060 तो ऐसे हैं जो केवल 12वीं उत्तीर्ण हैं। उस समय जितने लोग बी.एड. थे या उनको अनुभव था, उन सबको प्रबोधक और प्रबोधक का ग्रेड जो थर्ड ग्रेड का टीचर का ग्रेड है, वही प्रबोधक का ग्रेड है।

इनकी पदोन्नति के लिए हमने वरिष्ठ प्रबोधक का पद सृजित कर रखा है। उस 9 साल का जैसे जिसको अनुभव होगा वैसे ही इनमें से वरिष्ठ प्रबोधक बनें सकेंगे और उसमें इनका जो पांच हजार से आठ हजार का ग्रेड है, वह इनको मिलेगा। अभी चूंकि, 2008 में बने हैं, सभी को साढ़े आठ वर्ष का अनुभव है, जैसे ही छह महीने बाद इनको 9 वर्ष का अनुभव हो जाएगा तो इनको वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नति दे दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

सुकमा (छत्तीसगढ़) के नक्सली हमले में शहीद जगदीश विश्नोई को आर्थिक परिलाभ

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ में नोखा तहसील के ग्राम जेगला के रहने वाले जगदीश विश्नोई जो वहां नक्सली हिंसा में शहीद हो गये हैं, उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए हमारे जिले के, हमारे संभाग के डिवीजनल कमिश्नर और आई.जी. गये थे। जिनके पार्थिव शरीर को जब पंचतत्व में विलीन किया गया तब हमारे अर्जुनराम मेघवाल, राज्य वित्त मंत्री, वहां के प्रतिष्ठित लोग, रामेश्वरजी डूडी, नेता प्रतिपक्ष व अन्य माननीय सदस्य, विश्वनाथ मेघवाल वहां पर उपस्थित थे।

भारत सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया है और एक करोड़ रुपये की राशि उनके परिवार को देने की घोषणा की है।

मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब उनको भारत सरकार ने शहीद का दर्जा दे दिया है तो राज्य सरकार भी उनको शहीद मानते हुए शहीदों को जो भी एक मुरब्बा सिंचित जमीन, उनके परिवार में एक को नौकरी और जो भी परिलाभ दिये जा सकते हैं, वह परिलाभ भी तत्काल दिये जाने की घोषणा गृह मंत्रीजी करें, यह मेरा आपके माध्यम से सदन को निवेदन है और माननीय गृह मंत्रीजी को निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। गृह मंत्रीजी, रेस्पांड करेंगे क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सैनिक कल्याण विभाग के मंत्रीजी करेंगे।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): भंवरसिंहजी, आप भी बोल दो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, सेम इश्यू है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक ही है, आप और बोल लें आपका भी है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 मार्च को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में सी.आर.पी.एफ. के 12 जवान शहीद हो गये थे, जिसमें बीकानेर जिले के जेगला गांव के नोखा निवासी हैड-कांस्टेबल जगदीश विश्नोई की नक्सलियों से लड़ते हुए मृत्यु हो गयी थी।

(श्री भंवरसिंह)

दिनांक 13 मार्च को धुलंडी के दिन जगदीश विश्नोई की राजकीय सम्मान के साथ, हजारों लोगों की उपस्थिति में अंत्येष्टि की गयी। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद के परिजनों व वीरांगनाओं को आर्थिक पैकेज देने की केन्द्र सरकार के द्वारा घोषणा की गयी है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकार के द्वारा जो वर्तमान पैकेज है, उसमें संसोधन किया जाए क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा अभी पिछले दिनों ही शहीदों के परिजनों को और वीरांगनाओं को एक करोड़ रुपये दिये गये। हरियाणा सरकार के द्वारा भी 50 लाख रुपये देने की घोषणा की गयी है। उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार भी शहीदों के परिजनों को अन्य जो पैकेज है, उसके साथ-साथ एक करोड़ रुपये की नकद सहायता दी जाए। नोखा नगरपालिका क्षेत्र में शहीद जगदीश चंद्र विश्नोई की प्रतिमा लगायी जाए और उसके जो पैतृक गांव है जेगला, वहां पर जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उस विद्यालय का नाम शहीद जगदीश चंद्र विश्नोई के नाम से रखा जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से पूरे सदन की तरफ से यह मांग करना चाहूंगा कि शहीदों के सम्मान में जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की सरकारों ने पैकेज बढ़ाये हैं, उसी तरह से हमारे 12 शहीदों में से एक शहीद राजस्थान का है जिसने खुद शहीद होते-होते दो जो नक्सली थे, उनको मार गिराया। ऐसे वीर शहीद की याद में एक पहल सरकार के द्वारा की जाए और पैकेज बढ़ाया जाए, यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं हमारे लाड़ले बहादुर जगदीश विश्नोई, जिन्होंने हंसते-हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर किया दुश्मन को खत्म करते हुए, उनको हृदय से श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूं। आपने उनकी सहायता के लिये राजस्थान सरकार से मांग की है। इसके लिये लूणकरणसर और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है, सन् 1999 के बाद में कारगिल पैकेज के तहत जो सहायता है, उसी के अनुसार सरकार पूरी तौर से उनकी

(श्री अमराराम)

मदद करेगी, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आपने मूर्ति लगाने की बात कही, वह भी सही है और आपने स्कूल या हॉस्पिटल हो, जहां भी जनता को उचित लगे, उन पर जगदीश जी विश्नोई का नाम लगे, उसके लिये भी हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ ही अनुकम्पा में एक व्यक्ति को नौकरी भी देंगे और जब सी.आर.पी.एफ. के हैड क्वार्टर से हमारे सैनिक कल्याण विभाग में जो भी कागजात आएंगे, जो भी पूरा पैकेज होगा, हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे हमारे कलक्टर ने एक लाख रुपये वहां दे दिये होंगे और 20 लाख रुपये जो उस पैकेज के अंदर है, नकद एकमुश्त में 20 लाख रुपये देना। अगर वह 20 लाख रुपये न ले तो उसके परिवार वालों को हम 25 बीघा जमीन नहरी क्षेत्र में देंगे और यदि वह यह भी न लेना चाहे और मकान लेना चाहे तो 20 लाख रुपये का मकान जो हाउसिंग बोर्ड का होगा, जो भी उचित हो, वहां भी वह ले सकते हैं। इस प्रकार से हम पूरी कोशिश करेंगे।

इसके अलावा अल्प बचत योजना की मासिक आय योजना में माता-पिता के नाम से 3 लाख रुपये की सावधि जमा, शहीद की विधवा व उसके पुत्र या अविवाहित पुत्री को राज्य सरकार के नियमों के तहत नियोजन, राजकीय विद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग में नि:शुल्क शिक्षा, इस प्रकार के पैकेज हम देंगे और किसी प्रकार से सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे, यह मैं आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: 295 के तहत विशेष उल्लेख। श्री कैलाश चौधरी। ...(व्यवधान)...नहीं, मानिक जी, आप बैठिये। सरकार की तरफ से आ गया जवाब, अब नहीं। आप विराजिये, आप विराजिये। आपने मांग उठायी और सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। और कुछ हो तो आप चिट्ठी लिख देना। मानिक जी, मैं निवेदन कर रहा हूं आप चिट्ठी लिख देना।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो पहले से ही चल रहे हैं। हरियाणा और केन्द्र सरकार ने पैकेज बढ़ाया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इस विषय को आप कंट्रोवर्सी में मत डालिये। आप बैठिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन। बहुत अर्जेण्ट मामला है।

श्री अध्यक्ष: नो इन्फोर्मेशन, बैठिये। श्री कैलाश चौधरी, 295.

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बायतू में पैट्रोलियम परिशोधन हेतु रिफाइनरी की स्थापना

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के तहत बाड़मेर के बायतू विधान सभा क्षेत्र में पैट्रोलियम परिशोधन के लिये रिफाइनरी की स्थापना करवाने के संबंध में निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान में पैट्रोलियम पदार्थों के अथाह भंडार मिले हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पश्चिमी राजस्थान में पैट्रोलियम पदार्थों की खोज और अन्वेषण करने के लिये अनुमति ही नहीं दी थी। जबकि पश्चिमी राजस्थान से सटे पाकिस्तान में 80 के दशक से ही तेल का दोहन किया जा रहा है। पैट्रोलियम पदार्थों का अन्वेषण और खोज करने की अनुमति देने के पीछे किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के इरादे से काम किया हुआ प्रतीत हो रहा है।

वाजपेयी जी के शासन काल में पश्चिमी राजस्थान में पैट्रोलियम भंडारों की खोज एवं अन्वेषण करने की अनुमति प्रदान की थी, जिससे बाड़मेर व जैसलमेर में तेल व गैस भंडार मिले हैं। बाड़मेर जिले का मंगला तेल कुआं विश्व का सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला कुआं है। मंगला तेल कुए के समकक्ष कई कुए बाड़मेर बेसिन में मौजूद हैं। इन कुओं में तेल का दोहन किया जा रहा है, जिससे करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है।

अपनी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान वसुन्धरा राजे जी ने बाड़मेर की बायतू तहसील के लीलाला में रिफाइनरी स्थापित करने के लिये जमीन सहित सभी तैयारियां पूर्ण कर ली थीं। उस समय कांग्रेस के जन-प्रतिनिधि बायतू में रिफाइनरी स्थापित करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कई बार धरना-प्रदर्शन भी किये। राज्य और केन्द्र में कांग्रेस की सरकारों के बावजूद बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने संबंधी पांच साल में कार्यवाही नहीं की गयी। 2013 के विधान सभा के चुनाव नजदीक आते देख कांग्रेस सरकार ने आचार संहिता के सिर्फ 10 दिन पहले पचपदरा के सांभरा में रिफाइनरी का शिलान्यास कर दिया गया।

तत्कालीन अशोक गहलोत जी की सरकार ने एच.पी.सी.एल. के साथ रिफाइनरी के लिये एक एम.ओ.यू. किया, जिसमें सरकार द्वारा एच.पी.सी.एल.

(श्री कैलाश चौधरी)

को 56 हजार करोड़ रुपये 15 वर्ष तक बिना ब्याज, पानी, बिजली, जमीन आदि की व्यवस्था करने सहित सभी मूलभूत सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जानी थी तथा राज्य सरकार की मुनाफे में मात्र 26 प्रतिशत की भागीदारी ही होगी। एच.पी.सी.एल. के साथ बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने के लिये किया गया एम.ओ.यू. राज्य की जनता और सरकार के लिये घाटे का सौदा था, जिस पर माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी द्वारा समीक्षा करके रिफाइनरी स्थापित करने के बारे में विचार किया जा रहा है, जोकि एक स्वागत योग्य कदम है। मैं आशा करता हूं कि बाड़मेर में जल्दी ही रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सोना देवी।

रायसिंहनगर के सीमावर्ती ग्रामों के किसानों की समस्याएं

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के अन्तर्गत सीमावर्ती किसानों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किये जाने बाबत् प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के अन्तर्गत सीमावर्ती ग्राम कांकूसिंह वाला, लखा हाकम, खाटा, 43 पी.एस., 75 एन.पी. के किसानों को फसल जैसे सरसो, नरमा, कपास आदि बोने नहीं दिया जाता है। इन किसानों को दिन में 10 बजे से 3.00 बजे तक ही फसल की देखरेख, पानी देने की समय सीमा में पाबन्द किया जाता है, जिससे रात्रि में अपनी फसल के लिये वे कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ग्राम पंचायत ख्यालीवाला (5 एफ.डी.) व संगराना के किसानों के किसानों को तो थ्री फेस सिंचाई सुविधा बहुत ही कम दी जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में दूषित पेयजल सप्लाई हो रहा है जिससे विभिन्न बीमारियां फैल रही हैं। फसल खराब होने व कम बुआई होने के कारण हो रहे नुकसान का मुआवजा भी किसानों को कभी नहीं दिया गया। गंगनहर की एफ.एफ.ए. माइनर, भोमपुरा माइनर, करणी जीबी माइनर को टेल का पूरे हिस्से का पानी भी नहीं मिल रहा है जिससे किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है तथा वे पलायन को मजबूर हो रहे हैं। इन गांवों में मोबाइल नेटवर्क भी सही तरह से काम नहीं करता है। आजादी के 70 वर्षों बाद भी किसानों की समस्याएं जस की तस हैं।

(श्रीमती सोनादेवी)

अत: प्रक्रिया के नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत निवेदन करती हूं कि किसानों की उक्त ज्वलन्त समस्याओं का निराकरण अतिशीघ्र किया जाए व किसानों के लिये विशेष पैकेज दिया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द बैरवा।

दूदू में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र दूदू जिला जयपुर में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के संबंध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत सूचना प्रेषित कर रहा हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू (जयपुर) में स्थानीय विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूदू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित है। दूदू कस्बे से 28 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांभर लेक एवं 38 किलामीटर की दूरी पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर) स्थित है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में दो महाविद्यालय शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है। ग्रामीण जनसंख्या अनुसूचित जाति होने के कारण इस वर्ग के अभिभावक लम्बी दूरी के कारण से अपने बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं। स्थानीय दूरी एवं निजी महाविद्यालयों की फीस भी उनके सामर्थ्य में नहीं है। दूदू में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के मादपण्डों की पूर्ति हो रही है लेकिन संसाधनों का अभाव बता कर अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं के साथ अन्याय हो रहा है। राज्य सरकार सबको शिक्षा प्रदान करने की नीति पर कार्य कर रही है।

अत: उक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति के लिए सूचना प्रेषित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीरसिंह भायल। (अनुपस्थित) श्रीमती शकुन्तला रावत।

(12.31 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु खेल नीति की पालना

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं।

महोदय जी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान की खेल नीति बनी हुई है। जो खिलाड़ी राजस्थान राज्य का निवासी है, यदि कोई खिलाड़ी ओलम्पिक, एशियाड एवं कॉमनवैल्थ, इन खेलों में भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है या मैडल जीतता है तो सरकार उसको नहरी सिंचित क्षेत्र में तथा आवासीय क्षेत्र में जमीन आबंटित करती है। ऐसे खिलाड़ी राजस्थान की पहचान बनते हैं और इनको प्रोत्साहन देने हेतु बनी हुई खेल नीति का समयबद्ध तरीके से पालन होना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार के खेल विभाग में ऐसी कई महिला खिलाड़ियों के जमीन आबंटन हेतु आवेदन 2 वर्षों से सरकार के पास विचारार्थ लम्बित पड़े हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के द्वारा खेल के क्षेत्र में किये गये उनके व्यक्तिगत एवं सामूहिक परिणामों की उपलब्धियां शून्य हो जाती हैं। ऐसे में प्रोत्साहन सम्बन्धी समस्त प्रावधानों का खिलाड़ियों के हित में तथा उदीयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु उचित समयानुसार पालना करके प्राप्त आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जबकि हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु करोड़ों में राशि दी जाती है।

अत: माननीय मुख्यमंत्री महोदया से निवेदन है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए उनकी मांगों को तुरन्त पूरा करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दलीचन्द जी।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, you don't have to react on this. श्री दलीचन्द जी। ...(व्यवधान)...

मावली में उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण का निरस्तीकरण

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में तहसील गिर्वा की ग्राम पंचायत लकड़वास के राजस्व गांव सामेता, धामधर में 200 बीघा उपजाऊ कृषि भूमि को आर.एस.एम.एम. द्वारा अधिग्रहण के लिए कार्यवाही सन् 2001 से चल रही है, जिसके विरोध में इन ग्राम पंचायत के प्रभावित किसानों द्वारा अनेक बार धरना दिया है।

राजस्व ग्राम सामेता, धामधर की कृषि राजस्व रिकार्ड में सिंचित व बारानी प्रथम के रूप में दर्ज है, जो उपजाऊ भूमि की श्रेणी में आती है। किसानों ने जगह-जगह पर कुए व ट्यूबवैल खोद रखे हैं, जो विद्युतीकृत हैं तथा इनसे सिंचाई के माध्यम से रबी व खरीफ की फसलें पैदा की जाती है। इस क्षेत्र में चना, सरसों, जौ, तारामीरा आदि वाणिज्यिक फसलों की प्रचुर मात्रा में खेती की जाती है। इस क्षेत्र के निवासियों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है।

आर.एस.एम.एम. द्वारा इस क्षेत्र में खनन ब्लास्टिंग के कारण अनेक मकानों में दरारें आ गयी हैं। खनन के कारण श्मशान का रास्ता एवं सड़क मार्ग पूर्णत: क्षतिग्रस्त हैं। ब्लास्टिंग के कारण अनेक पशु मर गये हैं।

यहां की आबादी लगभग दो हजार की है, जो पक्के एवं कच्चे मकानों में आबाद हैं। अधिग्रहण प्रभावित क्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत, सामेता में 73 बच्चे अध्ययनरत हैं। सामेता आंगनबाड़ी केन्द्र पर 3 से 6 वर्ष के 18 बच्चे पंजीकृत हैं, 0 से 5 वर्ष के 41 बच्चे हैं। धामधर आंगनबाड़ी केन्द्र पर 22 बच्चे पंजीकृत हैं, 0 से 5 वर्ष के 68 बच्चे हैं।

प्रशासन व आ.एस.एम.एम. द्वारा समाचार पत्रों में बारबार खबरें प्रकाशित कर अधिग्रहण की कार्यवाही से क्षेत्र के लोगों को भयभीत किया जा रहा है जिस कारण यहां के नागरिक भय के साये में जीवन-यापन कर रहे हैं। वर्षों से धरने पर बैठे रहे किसानों की मांगों के प्रति प्रशासन द्वारा किसी

(श्री दलीचन्द डांगी)

भी प्रकार की सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है।

अत: इस कृषि प्रधान देश के अन्नदाता किसान की मार्मिक पीड़ा को समझते हुए उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही को सरकार निरस्त कर या धामधर व सामेता के विस्थापितों को उचित मुआवजा देकर उनके पुनर्वास के लिए कृषि भूमि एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। किसानों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से किसानों के प्रति हमारी संवेदनशील सरकार न्यायोचित कार्यवाही कर किसानों को बेघर होने से बचाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयराम जाटव।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष जी, कागज रह गया था, प्लीज। सॉरी, सॉरी।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, यह अगर आप लोगों ने आदत डाल ली तो मेरे ख्याल से ...

अलवर ग्रामीण में पेयजल समस्या

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में ग्रामीणों को पीने के पानी हेतु संचालित जनता जल योजनाओं की राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी दी थी। कई ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने जनता जल योजना, सेक्ट्रीफोर्म योजना, राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल योजना, इन योजनाओं को संचालित करने हेतु ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव व कार्य योजना की कार्यवाही नहीं की, ना ही स्कीमों के संचालन की सहमति प्रदान की है। स्कीमों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करोड़ों रुपये खर्च कर बोरिंग खोद कर टंकियों का निर्माण करा कर छोड़ दिया। सरपंचों की बिना मेहरबानी के बिजली के कनेक्शन नहीं हो रहे। ग्रामीणों के पीने के पानी की

(श्री जयराम जाटव)

व्यवस्था पर संकट पैदा हो गया है। कई स्कीमों के बिजली के लाखों रुपये के बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। इस कारण स्कीमों से बिजली कनेक्शन काट दिये हैं या काटने की बिजली विभाग की कार्यवाही चल रही है। माह मार्च, 2017 में बिजली के बिल जमा नहीं हुए तो कनेक्शन काट दिये जाएंगे। ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कहना है कि हमारे पंचायतों के बैंक खातों में इतनी राशि नहीं है जो हम बिजली का बिल जमा करा सकें।

माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि उक्त स्कीमों को विभाग द्वारा संचालित कराने की व्यवस्था कर ग्रामीणों को पीने का पानी मुहैया करने का श्रम प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन लालजी।

बिलाड़ा में ओवरब्रिज निर्माण

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के नगरपालिका बिलाड़ा में तहसील कार्यालय, एस.डी.ओ. कार्यालय, ए.डी.जे., ए.सी.जे.एम., राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उप पंजीयन कार्यालय, राजकीय रैफरल चिकित्सालय/सार्वजनिक निर्माण विभाग/पंचायत समिति कार्यालय/विद्युत वितरण कार्यालय एवं अन्य समस्त कार्यालय रेलवे स्टेशन के पास से गुजरने वाली शहर की एक मात्र मुख्य सड़क है तथा पूर्व में इस सड़क पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर अण्डर ब्रिज स्वीकृत था।

लेकिन किसी कारणवश अंडर ब्रिज इस रेलवे क्रॉसिंग पर नहीं बन पाया तथा रेलवे ने इस क्रॉसिंग को बंद करके इससे 1 किलोमीटर दूरी पर दूसरा क्रॉसिंग बनाया। जिसके कारण 50 मीटर की दूरी पार करने के बजाय 2 किलोमीटर दूरी के रास्ते को पार करना पड़ता है। रेलवे द्वारा निर्मित बुरी तरह से टूटी सड़क के कारण कई रोगियों की मौतें हो चुकी हैं। रेल विभाग इस पूर्व निर्मित रेलवे क्रॉसिंग का रास्ता बार-बार बंद कर देता है एवं इससे परेशान लोग कई बार धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं।

(श्री अर्जुन लाल)

मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री से निवेदन करूंगा कि उक्त रेलवे क्रॉसिंग स्थल के पास शहर के गंदे पानी का नाला गुजरता है, जिसके कारण प्रस्तावित अंडर ब्रिज में पानी घुस जाने के कारण कई दिनों तक पानी भरा रहेगा एवं एक मात्र मुख्य रास्ता बंद हो जाने से आमजन को परेशानी रहेगी। अत: प्रस्तावित अंडर ब्रिज के स्थान पर ओवर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति प्रदान करावें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री किशनाराम।

भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर में क्षौरकार एवं ब्यूटीपार्लर विषयों का अध्ययन

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि दिनांक 7 मार्च, 2017 को सदन में भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पारित किया गया था। जिसकी अनुसूची 2 में विनिर्माण, संनिर्माण, अवसंरचना, लोक स्वास्थ्य, व्यवसाय प्रबंधन, व्यापार, घरेलू कार्य, घर की देखभाल, सौंदर्य की देखभाल, दुग्ध उद्योग, वस्त्र, हस्तशिल्प, खिलौना, डिजाइन, आभूषण, फर्नीचर एवं अन्य संकायों में व्यक्तियों को अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु पात्र माना गया है। लेकिन इस अनुसूची में क्षौरकार (केश कला) एवं ब्यूटी पार्लर कला से संबंधित विषय को शामिल नहीं किया गया है तथा ना ही श्रम विभाग में केश कला एवं ब्यूटी पार्लर से संबंधित श्रमिकों को इस श्रेणी में रखा गया है। जिसकी वजह से सैन/नाई समाज के इस उद्योग को बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। इस उद्योग को विकसित करने एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु सरकार ने केश कला बोर्ड का भी गठन किया है।

अत: आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त अनुसूची 2 में क्षौरकार एवं ब्यूटी पार्लर एवं श्रम विभाग में क्षौरकार के कार्य करने वाले लोगों को क्षौरकार आर्टिजन के रूप में शामिल कर उन्हें प्रमाण पत्र एवं उक्त संकाय में अध्ययन हेतु शामिल कर अनुगृहित करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

विद्यार्थी मित्रों को स्थायी नियुक्ति

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि प्रदेश में जुलाई, 2008 तक लगभग 24,163 विद्यार्थी मित्रों को नियुक्ति दी गयी थी। उसके बाद 5 वर्ष से भी अधिक समय तक कार्य करने के बाद 13 सितम्बर, 2013 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विद्यार्थी मित्रों को हटाने के आदेश दिए थे, परन्तु हटाया नहीं। लेकिन वर्तमान सरकार ने 30 अप्रैल, 2014 को समस्त विद्यार्थी मित्रों को हटा दिया। जिसके बाद इन विद्यार्थी मित्रों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया और तब से यह विद्यार्थी मित्र हक की लड़ाई के लिए आंदोलित हैं। अभी तक आर्थिक तंगी की वजह से 50 से अधिक विद्यार्थी मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। हाल ही में ली गयी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में किसी भी प्रकार का स्पष्ट निर्देश नहीं होने तथा इस भर्ती में हुई पूरी मनमानी की वजह से, एक बार फिर विद्यार्थी मित्रों के सामने संकट खड़ा हो गया है। अभी तक सरकार विद्यार्थी मित्रों के प्रति गंभीर नहीं है।

राज्य सरकार ने जो ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती ली, उसमें केवल असत्य दिखावा करके विद्यार्थी मित्रों को नियुक्ति देने का वादा किया। जबकि उस भर्ती में कितने विद्यार्थी मित्रों का चयन हुआ या नहीं हुआ, यह सोचनीय बिन्दु है। वर्तमान सरकार ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने की बात कही। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों के जहां भी आंदोलन हुए, वहां पर सरकार ने उन्हें नियमित करने का आश्वासन देकर आंदोलन और धरने को समाप्त करवाया। विधान सभा में भी कई बार आश्वस्त किया तथा इनकी स्थाई नियुक्ति हेतु मंत्रिमंडल उप समिति का गठन करके ठोस और कारगर रास्ता निकालने की भी बात कही। मगर उसके बावजूद विद्यार्थी मित्रों की मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है, जिसकी वजह से विद्यार्थी मित्रों में शासन के प्रति गहरा रोष व्याप्त है।

अत: मैं सरकार का इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के हजारों विद्यार्थी मित्रों के हितों का संरक्षण करते हुए उन्हें सीधी स्थाई नियुक्ति के आदेश किए जाएं, ताकि उनके सामने खड़ा

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बेरोजगारी का संकट दूर हो सके और प्रदेश में उनकी नियुक्ति से स्टॉफ की कमी भी कुछ हद तक दूर हो सके। साथ ही ग्राम पंचायत सहायकों की बिना नियमों एवं मापदंडों के ली गयी भर्ती को निरस्त किया जाए और पुन: नए सिरे से इस भर्ती को लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिह डोटासरा।

प्रदेश में समान कैडर समान पद पर नियुक्ति को नवीन परिवीक्षा अवधि में जोड़ना

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि राजस्थान सेवा नियम के अनुसार विभिन्न भर्तियों के माध्यम से चयनित कोई राज्य कर्मचारी यदि विभाग में निर्धारित कैडर व पद पर कार्यरत है और वह अन्य विभागीय भर्ती में समान कैडर व समान पद पर चयनित किया जाता है एवं उसका पूर्व विभाग में परिवीक्षा काल (02 वर्ष) पूर्ण नहीं हाता है तो उक्त कर्मचारी को अपने नवीन विभाग में उसी पद के लिए पुन: परिवीक्षा काल से गुजरना पड़ता है जो कर्मचारी वर्ग के हित में नहीं है। इस हेतु राजस्थान सेवा नियम के प्रथम खंड के नियम 26-4-क में वर्णित है कि 'यदि कार्मिक द्वारा एक सेवा के प्रोबेशन काल को पूर्ण किए बिना किसी नवीन पद को ग्रहण किया जाता है तो उसके पूर्ववर्ती सेवा काल (परिवीक्षा काल) को नवीन सेवा के संदर्भ में नहीं गिना जाएगा'। जिसके अनुसार यह नियम केवल नवीन पद के लिए सारगर्भित है, न कि नवीन विभाग के समान पद के लिए। जबकि कर्मचारी पूर्ववर्ती विभाग में समान कैडर और समान पद पर परिवीक्षाधीन होकर अन्य नवीन विभाग में उसकी कैडर और उसी पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसके पूर्ववर्ती परिवीक्षा काल को नवीन विभाग में समायोजित किया जाना चाहिए।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित कर निवेदन है कि राजस्थान सेवा नियमों में अस्पष्टता को दूर कर उक्त प्रकार के परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के पूर्ववर्ती परिवीक्षा काल को नवीन विभाग में समान कैडर व समान पद पर समायोजित कर उनको राहत प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

पीलीबंगा के ग्राम थिराजवाला में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरलिया के गांव थिराजवाला में उप स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत खरलिया से थिराजवाला की दूरी लगभग 5 किलो मीटर है। थिराजवाला के नजदीक में चक 17 एल.जी.डब्ल्यू., चक 14 एल.जी.डब्ल्यू., 5 एस.जी.आर., चक 7 एस.जी.आर., 18 एल.जी.डब्ल्यू. हैं। ये चक आबादी के चक हैं एवं इन चकों की विभिन्न ढाणियां भी हैं। इन चक, ढाणियों के पास में लगभग 10 किलो मीटर की दूरी तक कोई उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने की वजह से आमजन को बहुत परेशानी होती है।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करती हूं कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरलिया के गांव थिराजवाला में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करवाकर आम जन को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय। श्री शुभकरण चौधरी। एक मिनट, आप विराजो।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलो।

सूचना

सुखोई विमान गिरने से क्षतिग्रस्त ढाणियां

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि कल बाड़मेर में एक सुखोई विमान गिरा। जिसमें पायलट तो बच गये। वह 3 ढाणियों पर गिरा, वह 3 ढाणियां जलकर के राख हो गयीं। इसमें 3 व्यक्ति घायल हुए जो अस्पताल में भर्ती हैं। उनके पैरों में तथा कई अन्य जगहों पर चोट है, जले हैं। वहां पर गाय, भेड़, बकरियां भी खतम हो गयीं।

(श्री मेवाराम जैन)

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनको एक पैसा नहीं मिला। वह आपदा में आ नहीं रहा। जिला कलेक्टर से भी बात हुई। पूरी ढाणियां जल गयीं। मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें कुछ करें।

श्री उपाध्यक्ष: पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से आपकी सूचना सरकार तक जानी थी। इसके बाद इसमें सरकार जो भी ठीक समझेगी, वह करेगी। पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय। श्री शुभकरण चौधरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

उदयपुरवाटी की कतिपय ग्राम पंचायतों का गुढ़ागौडजी में समायोजन

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में एक उप तहसील गुढ़ागौड़जी भी बनी है। उस उप तहसील गुढ़ागौड़जी के पास में धमौरा, सिंगनौर और पोसाणा, 3 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जो उप तहसील से 3, 5 और 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं। पर, ये तीनों की तीनों ग्राम पंचायतें तहसील में सम्मिलित हैं जहां से उनकी दूरी अठारह, बाइस और छब्बीस किलोमीटर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सदन में गत बार भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था, मुझे इस बात का पूरा विश्वास मिला था कि इन ग्राम पंचायतों को उप तहसील में जोड़ दिया जाएगा किंतु आज तक इन ग्राम पंचायतों को उप तहसील में जोड़ा नहीं गया है। वहां के लोगों में इससे बड़ा आक्रोश है। तहसील में जाने के लिए उन्हें बड़ी दिक्कत महसूस होती है। उप तहसील का गठन भी इसलिए किया गया था कि लोगों को आवागमन में सुविधा हो जाए, नजदीक में उनका काम हो जाए, उनका राजस्व रेकार्ड उप तहसील में नजदीक ही संधारण हो जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि इन तीन ग्राम पंचायतों को उप तहसील में तहसील से काट कर कब तक जोड़ दिया जाएगा?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि तहसील उदयपुरवाटी में कुल 40 पटवार सर्कल है। इनमें उन्नीस

(श्री अमराराम)

पटवार सर्कल उदयपुरवाटी में हैं और उप तहसील के अंदर गुढ़ागौड़जी में इक्कीस पटवार सर्कल हैं। जैसी कि आपने चिंता व्यक्त की है, पहले भी आपने मामला उठाया, मैंने कलेक्टर से प्रस्ताव मंगवा दिया, भौगोलिक दृष्टि से आप सही मानते हैं कि इन चारों गांवों जो धमोरा, सिंगनौर, पोसाणा और पौंख, ये चार जो आपके वहां आरआई सर्कल हैं इनको उप तहसील गुढ़ा गौड़जी में शामिल कराना चाहते हैं क्योंकि इनमें से कोई दो किलोमीटर की दूरी पर है, कोई चार किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन एक तरफ उप तहसील में तो पच्चीस आरआई सर्कल जाएंगे और तहसील में पन्द्रह ही रहेंगे, फिर भी इस प्रकार के नजदीक जो उदयपुरवाटी के होंगे उनको वहां शामिल करेंगे लेकिन यह जो चारों गांव हैं इनको गुढ़ागौड़जी में शामिल करने के लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हबीबुर्रहमान अशरफी।

नागौर शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का अभाव

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नागौर शहर में रामदेव पित्ती चिकित्सालय का संचालन हो रहा था, उसके बाद सरकार ने 300 बैड स्वीकृत करके बीकानेर रोड पर एक भवन बनाया जो पंडित जवाहर लाल नेहरू ट्रोमा सेंटर के नाम से है और उसको राज्य सरकार ने जुलाई, 2015 में नागौर शहर के रामदेव पित्ती चिकित्सालय को बीकानेर रोड पर बने हुए भवन में शिफ्ट कर दिया। वर्तमान में यहां रोगियों के लिए 300 बैड लगे हुए हैं मगर राज्य सरकार यहां पर सुविधाएं बिलकुल डेढ़ सौ बैड के हिसाब से ही दे रही है। वहां पर अभी तक डाक्टरों की संख्या 41 पोस्ट स्वीकृत हैं जिसमें से 36 डाक्टर काम कर रहे हैं जिनमें से 3 डाक्टर अनुपस्थित चल रहे हैं, सरकार इस चिकित्सालय को 300 बैड का दर्जा क्यों नहीं दे रही है? नागौर शहर की आबादी करीब सवा लाख के पार हो चली है, यह अस्पताल पूरे जिले का अस्पताल हो चुका है, जेएलएन राजकीय अस्पताल के आउटडोर में प्रतिदिन 1100 मरीज इलाज के लिए आते हैं जिनमें से औसतन 60-70 मरीजों की स्थिति देखते हुए उन्हें भर्ती किया जाता है। इसके अलावा यहां रोजाना करीब 40-50 महिलाओं की

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

डिलीवरी भी हो रही है, साथ में 7-8 सिजेरियन ऑपरेशन भी हो रहे हैं।

नागौर जिले के पुराने राजकीय पित्ती अस्पताल में मरीजों की व्यवस्था नहीं होने से अनेक मरीज प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं। पुराने अस्पताल भवन में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो एक कच्ची बस्ती में पीएचसी चल रही थी लेकिन अब उसकी बिल्डिंग तैयार हो गयी उसको हमने डेह रोड पर जो पित्ती अस्पताल से दो किलोमीटर दूर है वहां पर शिफ्ट कल कर दी गयी है। इसलिए मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि नियमानुसार यहां दो अरबन पीएचसी खोलें क्योंकि नागौर में मेडिकल कालेज खोलने की योजना बनाई जा रही है सरकार की, जिसके नियमानुसार यहां दो अरबन पीएचसी होना जरूरी है। इसी तरह पुराने अस्पताल भवन में सैटेलाइट या अरबन पीएचसी शुरू करके मरीजों को राहत दी जा सकती है। यहां पर एक अरबन पीएचसी की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जेएलएन हॉस्पिटल में डाइलिसिस की मशीनें भेज दी, वहां पर उसका काम भी शुरू हो गया, 100 बैड की जो लेबर बिल्डिंग है, पूरा इसी का है, वह भी तैयार हो गया है, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि उसका भी आप आकर उद्घाटन कर दें और मेरे यहां नागौर शहर में एक अरबन सीएचसी की आज यहां घोषणा करें क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और यह तीन किलोमीटर पर आ गयी है, सिटी के लोग इतनी दूर जाने में हिचकिचाते हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मंत्रीजी, एक तो दे ही दो।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): वह तो देनी ही है, राजकुमारजी।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): एक तो ले लो।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): हां, दे दो। धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागौर शहर में अभी डेढ़ सौ शय्याओं का राजकीय जिला

(श्री कालीचरण सराफ)

चिकित्सालय, नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देहली दरवाजा और लोहारपुरा डिस्पेंसरी संचालित हैं। जिला चिकित्सालय में 100 शय्याओं की एमसीएच यूनिट निर्माणाधीन है जो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगी। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत नागौर में एक नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देहली दरवाजा क्षेत्र में स्वीकृत किया गया है जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अस्थायी तौर पर पुराने जिला चिकित्सालय भवन में संचालित किया जा रहा है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नागौर शहर और लोहारपुरा डिस्पेंसरी में निम्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आउटडोर सेवाएं, प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना। शहर की जनसंख्या न्यूनतम पांच लाख होने पर, ढाई लाख की जनसंख्या पर एक शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। नागौर शहर की जनसंख्या अभी एक लाख पांच हजार होने के कारण शहरी सामुदायिक केन्द्र वहां अभी खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। आपने जो पीएचसी के लिए कहा है उसको मैं दिखवाउंगा और यदि नोर्म्स में आएगा तो निश्चित रूप से खोल देंगे।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): वहां पहले से जनसंख्या है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने बताया कि नोर्म्स में आएगा तो निश्चित रूप से खोल देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मान सिंहजी।

गंगापुरसिटी में महुकलां अण्डरपास निर्माण

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि गंगापुर सिटी स्थित महुकलां अंडरपास बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, एक तरफ पूर्व में महु गांव है, पश्चिम की ओर गंगापुर शहर है, दिल्ली-मुम्बई ब्रॉडगेज पर हर बीस मिनट में एक गाड़ी गुजरती है और इन चालीस सालों में लगभग 120 जानें जा चुकी हैं, पिछले लम्बे समय से वहां पर अंडरपास की मांग चल रही थी। 2013 में तत्कालीन सरकार ने आनन-फानन में बजट में घोषणा की और वहां पर उसका शिलान्यास भी कर दिया लेकिन जब चुनावों के बाद में हमने पता

(श्री मान सिंह)

किया तो रेलवे ने हमको सूचना दी कि हमारे पास में सरकार का कोई इस प्रकार का प्रपोजल नहीं है और सरकार से हमारा कोई इस प्रकार का सहमति पत्र भी नहीं है। अगर सरकार ने अपने स्तर पर इस प्रकार की कोई घोषणा की है तो रेलवे उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। कुल मिलाकर यह हुआ कि ढाक के तीन पात निकले और कांग्रेस की सरकार ने घोषणा करके वाहवाही लूटने की कोशिश की लेकिन वह उसको अमली जामा नहीं पहना पाए। सच्चाई यह है कि महुकलां का अंडरपास नहीं बनने से गंगापुर की जनता और चालीस गांवों की जनता परेशान है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि 2014 के अंदर हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध किया और उन्होंने वस्तुस्थिति जानकर इस बारे में कदम बढ़ाने की बात कही थी। जैसी मुझे जानकारी मिली है, इस बारे में इसका बजट अब चूंकि बढ़ गया है और रेलवे तथा डीएलबी विभाग के तहत नगरपरिषद, गंगापुर सिटी को इसका तखमीना बनाने के लिए कहा था, नगरपरिषद, गंगापुर सिटी और रेलवे के टैक्नीकल विभाग ने इसका जो तखमीना बनाया है वह लगभग 910 लाख रुपये का हो गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने इसे मेरे गले की हड्डी बनाई है यह तो घोषणा करके चले गये, चालीस साल तक इन्होंने इसको निकाल लिया लेकिन अब वास्तव में इस समस्या से निजात दिलाने का काम आप करेंगे, ऐसी मेरी आपसे विनती है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो समस्या रखी है, इसके बारे में गंगापुर सिटी महुकलां आरयूबी के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति आरटीआईडीएफ, राजस्थान यातायात आधारभूत विकास निधि द्वारा दिनांक 20.04.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जारी कर दी गयी है।

(13.00 बजे)

इस आरयूबी के निर्माण हेतु पश्चिम-मध्य रेलवे को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। रेलवे को तखमीना प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय द्वारा दिनांक 2.8.2016 को पत्र लिखा गया। रेलवे द्वारा दिनांक 26.12.2016

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

को इसका तखमीना पेश किया गया जिसके अनुसार इसकी लागत 910.44 लाख है। आप 910 करोड़ बोल रहे हैं, 910 लाख है। लागत राशि को रेलवे को जारी करने की स्वीकृति हेतु पत्रावली वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को भेज दी गयी है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त तखमीने के आधार पर राशि रेलवे को जारी कर दी जाएगी, तत्पश्चात कार्य प्रारंभ हो सकेगा। कार्य प्रारंभ होने के पश्चात दो माह में कार्य पूर्ण होने की पूरी संभावना है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कन्हैयालालजी।

चना व सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदने के कांटे लगा दिये हैं। लेकिन अभी भी जिस तरह से महीने भर से राजस्थान की सभी मण्डियों में सरसो की आवक हो रही है, छोटे किसान 400-500 रुपये क्विंटल के कम भाव पर बेच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कब तक ये खरीद चालू करा देंगे? पहले भी माननीय सदस्यों ने 5-7 बार सदन में यह मामला उठाया था। राज्य सरकार केन्द्र सरकार से परमिशन लेकर कब चालू करेगी, क्योंकि छोटे किसान काफी परेशान हैं। जिस तरह से शादी का सीजन चालू होने वाला है, किसान औने-पौने दामों में सरसों व चने को बेचेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको चालू कराने की कृपा करें।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पीएसएफ योजना के तहत शीघ्र ही चने की खरीद की जाएगी और राजफैड के 5 केन्द्रों पर यह खरीद 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी, बीकानेर, देई, केकड़ी, नोखा और श्रीमाधोपुर। इसके अलावा एफसीआई के द्वारा भी यह खरीद की जाती है। नैफेड अपनी समितियों के माध्यम से भी खरीद करता है। जहां तक सरसों खरीद की बात है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने भारत सरकार से भी आग्रह किया है कि पूर्व की भांति कार्यशील पूंजी हमें उपलब्ध कराएं और पूर्व की भांति ही मण्डी एवं वैट टैक्स की राशि का वहन भी भारत सरकार द्वारा किया जाए, बारदाने की व्यवस्था की जाए। मैं माननीय सदस्य को विश्वास

(श्री अजय सिंह)

दिलाता हूं कि इसके लिए कुछ अधिकारी भी एक-दो दिन में दिल्ली भेजे जा रहे हैं और शीघ्र ही इसके बारे में उचित निर्णय किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। आबकारी विभाग।

श्री राजपाल सिंह।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

अधिसूचना

आबकारी विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आबकारी विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या:एफ.4(6)वित्त/आब/2017 दिनांक 8 मार्च, 2017 जिसके द्वारा राजस्थान फोरेन लिकर (ग्रांट ऑफ होलसेल ट्रेड एण्ड रिटेल ऑफ लाइसेंस) रूल, 1956 में संशोधन किया गया हैं; एवं
2. अधिसूचना संख्या:एफ.4(6)वित्त/आब/2017 दिनांक 8 मार्च, 2017 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड का प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2015-16

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के नियम-46 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2015-16 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

समिति प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति (क्रम संख्या 3)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2016-2017, समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। डा. फूलचन्द भिण्डा।

याचिका

विराटनगर में नगरपालिका भवन निर्माण

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में नगरपालिका भवन का निर्माण करवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूसिंहजी।

शेरगढ़ में 33/11 केवी सब स्टेशनों के कार्य

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में स्वीकृत 33/11 केवी सब-स्टेशनों के कार्य प्रारम्भ करवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री छोटूसिंहजी।

जैसलमेर में पर्यटन विकास के नये मार्गों एवं स्थलों का विकास

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में पर्यटन विकास के नये मार्ग एवं स्थल विकसित करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

कोटपूतली को जिले का दर्जा

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली को जिला बनाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा।

जमवारामगढ़ के ग्रामों में सी.सी. रोड निर्माण

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम इन्द्रगढ़ के राधेश्याम खोड़ा की ढाणी से साईवाड़ भानपुर मेन रोड़ तक सीसी रोड़ बनाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुनलालजी।

बिलाड़ा में उप तहसीलों का क्रमोन्नयन

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कतिपय उप तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोज कुमारजी।

सादुलपुर में सदर थाने का गठन

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर (जिला-चूरू) में सदर थाने का गठन किये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर के नारायणपुरा में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बानसूर के नारायणपुरा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोले जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017। राजपाल सिंह जी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अनुमति से राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18। श्री प्रहलाद गुंजल।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को राज्य की यशस्वी मुख्यमंत्रीजी ने चौदहवीं विधान सभा का चौथा बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है। कई माननीय सदस्यों ने उस पर चर्चा करते हुए इस बजट के सभी सकारात्मक पहलू इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब राज्य की मुख्यमंत्रीजी सदन में बजट प्रस्तुत कर रही थी तो उन्होंने बजट प्रस्तुत करते समय सदन के माध्यम से जो पक्ष राजस्थान के सामने रखने का प्रयास किया और ऐसा केवल इस बजट में नहीं, लगातार पिछ्ले 3 बजटों में उन्होंने राजस्थान की वित्तीय स्थिति की चर्चा की। पिछ्ली सरकार के 5 साल में राज्य की आर्थिक स्थिति कितनी विकृत हो चुकी थी, यह सबके सामने है। सरकार संभालने के बाद लगातार इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने पैरा नम्बर 3 में पढ़ा है कि "प्रदेश के सुनियोजित और समग्र विकास की आधारशिला के रूप में दिसम्बर, 2013 में प्रस्तुत किये गये विजन 2020 को आधार मानते हुए प्रदेश निरन्तर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। विरासत में मिली चरमराई अर्थव्यवस्था, अकुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण प्रगति का यह सफर अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहा है।" जो प्रदेश के आर्थिक हालात हैं वे आज भी प्रदेश के विकास की रफ्तार में एक चुनौती बनकर खड़े हैं। मैं समझता हूं जिस सच्चाई के साथ लगातार राज्य की मुख्यमंत्री जी चार साल से काम कर रही हैं वह अपने आपमें एक मिसाल है। इन चुनौतियों भरे माहौल में भी उन्होंने किस प्रकार से एक बेहतर वित्तीय प्रबन्धन राजस्थान को देने का प्रयास किया और विगत तीन वर्षों में कर राजस्व में 57 प्रतिशत की वृद्धि की। जहां 2014-15 में वास्तविक आंकड़ों में राज्य सरकार को 58 हजार 479

(श्री प्रहलाद गुंजल)

करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ वहीं 2017-18 के अनुमानों में 91 हजार 747 करोड़ का राजस्व इकट्ठा करने का अनुमानित लक्ष्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सबके बाद भी एक गम्भीर सवाल हम सबके सामने है कि अगर हम आज ईमानदारी के साथ राज्य के वित्तीय हालातों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं तो पिछली सरकार ने बिजली कम्पनियों पर 80 हजार करोड़ का कर्जा कर दिया और राजस्थान की बिजली कम्पनियां डूब न जाएं, वह राजस्थान का आम बिजली उपभोक्ता जिसके प्रति सदन और सरकार, सबकी जिम्मेदारी है, उसके सामने कोई बिजली संकट खड़ा न हो जाए, 62 हजार करोड़ रुपये का कर्जा राज्य की मुख्य मंत्री जी ने सरकार के ऊपर लिया। उन्होंने हर बार इस बात को रखा, पिछले बजट में भी रखा, इस बार भी रखा कि राज्य की वित्तीय स्थिति बिजली कम्पनियों का भार सहित और भार रहित यह है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सबके बाद भी लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज रुक नहीं रहा है, कर्ज लगातार बढ़ रहा है। पिछली सरकार ने 1 लाख 24 हजार करोड़ का कर्जा कर दिया, 80 हजार करोड़ बिजली कम्पनियों पर हो गया, तीन सालों में लगातार कर्ज का मीटर चलता रहा। फिर कोई अगली सरकार आये और यह मौका पाये, कर्जा लगातार बढ़ रहा है। हमको विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर हमने बिजली कम्पनियों से 62 हजार करोड़ का कर्जा राज्य सरकार पर ले लिया, पिछली सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया, ब्याज का मीटर चलता रहेगा, फिर अगली सरकार आएगी और हमको कठघरे में खड़ा करने का प्रयास करेगी। इन सबके बीच में आखिर हम लोग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर, कठघरे में खड़ा करने के बजाय यह हालात पैदा क्यों हो रहे हैं, कभी इस दिशा में जाने का प्रयास नहीं किया, कभी इस दिशा में गंभीर चिंतन करने का प्रयास नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हम इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, हम राजस्थान के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे।

आज विकास कितनी ही रफ्तार पकड़े लेकिन राज्य की वित्तीय व्यवस्था कर्ज आधारित व्यवस्था हो गयी है। इस कर्ज आधारित व्यवस्था में हमको तय करना पड़ेगा कि कर्ज हम ले रहे हैं, स्टेटों की मजबूरी हो गयी, पूरे

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हिन्दुस्तान में सभी प्रांतों की कमोबेश यही स्थिति है, लेकिन उस कर्ज का आउटपुट क्या आ रहा है? जब तक इस विषय में विचार नहीं करेंगे, हम समाधान के रास्तों पर नहीं पहुंच पायेंगे। इसीलिए पहली बार राज्य की मुख्य मंत्री जी ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आर्थिक सेवाओं पर 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है कि राज्य के वित्तीय हालातों में सुधार हो और बजट को 38 हजार 651 करोड़ से बढ़ाकर 61 हजार 847 करोड़ रुपये का कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह क्रांतिकारी पहल है और इस दिशा में हमको जाना ही पड़ेगा। यह विचार करना पड़ेगा, यह चिंतन करना पड़ेगा। हर 5 साल बाद मतदाता सरकार बदलता है। गवर्नर स्पीच पर जब माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दे रही थीं तब उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में स्थायित्व लाने के लिए 5 साल में सरकारें बदलने की परम्परा बन्द होनी चाहिए। सरकार बदलने की परम्परा बन्द करने के लिए हमको सम्पूर्ण जवाबदेही के साथ काम करना पड़ेगा और काम किस दिशा में?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 69-70 सालों से लगातार केन्द्र का, स्टेट का, सबका बजट सदन में पेश होता है और जब हम बजट पेश करते हैं तो हमारे केन्द्र में राजस्थान का आम आदमी होता है। आखिर हम करना क्या चाहते हैं ? जिस राजस्थान के आम आदमी के लिए हम बजट पेश करना चाहते हैं, क्या उधार लेकर उसको संतुष्ट करना चाहते हैं या उधार लेकर उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ाना चाहते हैं, यह सवाल आज गंभीर सवाल बनकर खड़ा हुआ है। पिछली सरकार ने सरकार जाते समय फ्लैगशिप योजनाओं के नाम पर, हम 500 रुपये की पेंशन दे देंगे, हम 750 रुपये की पेंशन दे देंगे, हम घी का डिब्बा दे देंगे, हम दाल-चीनी दे देंगे, इस नाम पर जो जनता के उधार लिये हुए धन की बर्बादी की वो राजस्थान के लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता नहीं था, वो बर्बादी का रास्ता था। जब तक हम इस बर्बादी के रास्ते को नहीं रोकेंगे, जब तक हम तय नहीं करेंगे कि क्या आखिर हमारी जवाबदेही केवल उधार का पैसा लेकर मतदाता के प्रति उदार भाव या उसको संतुष्ट करके करेंगे और जब तक उसको आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाने की हमारी कोई क्रांतिकारी योजना नहीं हो तब तक हर बजट आएगा और हमारे सामने ये सवाल खड़े रहेंगे इसलिए, माननीय

(श्री प्रहलाद गुंजल)
उपाध्यक्ष महोदय, गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करने की जरूरत है। हम बजट पेश करते हैं और सदन की जिम्मेदारी खतम। यह बजट जो सदन पेश करता है, जिम्मेदारीपूर्वक इस स्टेट की ब्यूरोक्रेसी उस पर काम करती है? लगातार घाटा क्यों बढ़ता जा रहा है? जवाबदेही पिछली सरकार की होगी, जवाबदेही हमारी सरकार की होगी। क्या हमने तय किया कि जो कर राजस्व इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है, कर राजस्व में लीकेज रोकने के लिए जो जिम्मेदारी एजेंसियां हैं, इस सदन द्वारा पारित प्रस्तावों को इम्प्लीमेंट करके राजस्थान की जनता के हित में काम करने की जिम्मेदार एजेंसी का काम है, कभी हमने मॉनीटरिंग करने का प्रयास किया? हर बार एक नया प्रयोग।

फीडर सुधार कार्यक्रम के नाम पर राजस्थान में हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ, क्या बिजली कम्पनियों का घाटा रुक गया? अगर इसी प्रकार से हम अधिकारी वर्ग की जवाबदेही तय करने के बजाय उनके बनाये हुए प्रस्तावों पर इस सदन की मोहर लगाते चलेंगे और यह सदन ब्यूरोक्रेसी के द्वारा तय किए गये प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेगा तो हम एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने की राजनीति में उलझे रहेंगे और जवाबदेही तय नहीं करेंगे तो हम राजस्थान के उस आम आदमी के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पायेंगे जो हमको लोक-कल्याणकारी सरकार मानकर वोट देता है, एक उम्मीद और विश्वास के साथ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार इस सदन में कहने का प्रयास किया है कि जो मतदाता हमको मत देता है, मत के बदले हमसे वो रिश्वत नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, भीख नहीं मांगता, उस मत के बदले आत्मनिर्भरता चाहता है, राजस्थान का समग्र विकास चाहता है। पर हमने क्या कर दिया? वोट के बदले हम उसको घी देंगे, वोट के बदले हम उसको दाल-चावल देंगे, उस वोट के बदले हम उसको सीएफएल देंगे, उस वोट के बदले हम उसको साड़ी देंगे। ये जो परम्पराएं इस सदन में स्थापित हो गयी हैं, ये जो सरकारों ने परम्परा स्थापित कर दी हैं उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम साड़ी देकर, सीएफएल, घी देकर क्या राजस्थान के समाज में आत्मनिर्भरता ला

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सकते हैं ? जिस उम्मीद और विश्वास के साथ राजस्थान की जनता ने इन सरकारों को चुना है उस विश्वास पर खरा उतर सकते हैं? ये जो परम्परा पिछली सरकार ने डाली उसका दण्ड राजस्थान की जनता ने इस रूप में दिया कि आज मुख्य मंत्रीजी जब गवर्नर स्पीच पर भाषण कर रही थीं तब कहा कि इस राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे छोटा विरोध बैठा हुआ है जो उनकी नीतियों के कारण बैठा हुआ है। लेकिन आज हमको उन सारी चीजों से सबक लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर राजस्थान को कैसे ले जाएं, इस दिशा में विचार करना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट के पैरा नम्बर 96 में 'स्वस्थ धरा-खेत हरा', यह जो नारा दिया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय पूरे हिन्दुस्तान में इस पर सार्थक काम हो रहा है। स्वस्थ धरा - खेत हरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई वित्त मंत्रियों के स्टेटमेंट पढ़े हैं, जेटली जी से लेकर चिदम्बरम तक, मानसून अच्छा तो देश की जी.डी.पी. में ग्रोथ होगी। अभी पिछले दिनों एक लेख आया कि नोटबंदी के बाद भी इन चार महीनों में जीडीपी में स्थायित्व रहा, अच्छा कृषि उत्पाद रहा। उसका कारण हम सब लोग जानते हैं। अच्छा मानसून इस देश की अर्थव्यवस्था में कुछ मजबूती देता है, अच्छा मानसून इस देश की जीडीपी को बढ़ाता है। इस हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत जनता की परचेजिंग पावर को बढ़ाता है। फिर क्यों नहीं हमने किसान केन्द्रित योजनाओं के आधार पर इस प्रदेश में आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास किया? पहली बार प्रधान मंत्रीजी ने यह नारा दिया और मुख्य मंत्रीजी ने इस दिशा में काम प्रारंभ किया। धरती की उर्वरा क्षमता बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि उसकी जांच हो। किसान के साथ सरकार सहभागी बनकर खड़ी हो और उसकी जांच होकर उसमें किस प्रकार के लवणीय मिश्रण की आवश्यकता है। भारत के किसान ने पिछले 60 सालों में सरकारों के भरोसे नहीं, अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से इस धरती की उर्वरा क्षमता को बढ़ाया है। अपने आपको आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया है लेकिन एक सेचुरेशन के बाद उस उर्वरा क्षमता को बनाये रखने का दायित्व सरकार का जो बनता है, उस दिशा में मुख्य मंत्रीजी और प्रधान मंत्रीजी आगे बढ़ रहे हैं और प्रधान मंत्रीजी ने सपना देखा है कि किसान की आमदनी दुगुनी कैसे हो? किसान की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आमदनी दुगुनी करने का एकमात्र चारा यह है कि आने वाले कुछ सालों में भारत के किसान की आमदनी दुगुनी कैसे हो और भारत के किसान की आमदनी दुगुनी करने के लिए हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा।

बिजली पर कई बार सदन में चर्चा होती रही लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, हम किसान की आत्मनिर्भरता को बनाये रखने के लिए पानी-बिजली का समुचित इंतजाम करें और जब मैं पानी-बिजली की बात कर रहा हूं तो इस प्रदेश ने बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाई है। मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। बिजली का उत्पादन बढ़ा है लेकिन आज भी राजस्थान के किसान की कतार समाप्त नहीं हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने आने वाले दो साल में राजस्थान के किसानों को एक लाख बिजली के कनेक्शन देकर राजस्थान के किसान की आत्मनिर्भरता के रास्ते को मजबूत करने का प्रयास किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्जेंट राजस्थान में कई एमओयू किये हैं और नवीन जीएसएस, 220, 132, 33 केवीए, मैं उन पर नहीं जाना चाहता। बजट घोषणा पत्र में, बजट में मुख्य मंत्रीजी ने इसका उल्लेख किया है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना जरूर कहना चाहता हूं कहीं न कहीं हमें इस दिशा में जाना पड़ेगा कि राजस्थान के किसान को हम बिजली दें। उसकी आत्मनिर्भरता बनाये रखने के लिए हम पानी का समुचित इंतजाम करें और इस बजट में व्यापक रूप से सिंचाई परियोजनाओं पर पैसा खर्च करने का प्रावधान राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पानी, बिजली, सड़क जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जो इस बजट में प्रावधान किये हैं, वे राजस्थान को निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता और विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। कई सारे प्रावधान इसमें किये हैं। मैंने यह जरूर कहा है कि हमारी जिम्मेदारी केवल लोगों को संतुष्ट करने की ही नहीं, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाने की भी है लेकिन उसके बावजूद भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सच्चाई को जानते हैं कि बढ़ती हुई आबादी के संतुलन में संसाधनों का अभाव और कर्जे की मात्रा को देखते हुए सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है।

मुख्य मंत्रीजी ने भामाशाह बीमा योजना लागू की। सारा राजस्थान

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जानता है। यह अपने आपमें एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। आजादी के बाद गम्भीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को राहत देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिक्की के आंकड़े कहते हैं कि इस मुल्क में चार प्रतिशत लोग गम्भीर बीमारी से अपना इलाज कराते-कराते बीपीएल हो गये। उनके घर बिक गये, उनके मकान बिक गये, उन्होंने अपने आपको गिरवी रख दिया, घरेलू नौकर बना दिया और इतना ही नहीं, उन चार प्रतिशत बीपीएल के अलावा ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने गम्भीर बीमारी से त्रस्त होकर इलाज के अभाव में आत्महत्या कर लीं, ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। 30,000 रुपये से लेकर तीन लाख रुपये तक का इलाज गम्भीर बीमारियों का और अब आपको किसी सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पताल में मिल सकेगा। जहां केवल गरीब आदमी उसके सामने जाकर झांक सकता था, अब उसमें प्रवेश करके इलाज भी करा सकता है। मैं इसके लिए राज्य की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हम सब जानते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेहत के बिना काम संभव नहीं है...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को जगाओ। सरकार सो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा थोड़े ही संभव है कि ऐसा वक्ता हो और कोई सो जाए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सेहत के बिना प्रगति संभव नहीं है और यह शाश्वत सत्य केवल मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की सच्चाई है। जिन देशों का स्वास्थ्य कमजोर है, वहां की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, हमारा प्रदेश स्वस्थ रहे, प्रदेश के लोगों की सेहत ठीक रहे। प्रदेश के लोगों की कार्यक्षमता ठीक रहे, इसलिए मुख्य मंत्रीजी का यह एक महत्वाकांक्षी कदम है।

दूसरी बहुत महत्वपूर्ण योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोग कहते हैं कि यह आंध्रप्रदेश की तर्ज पर लाई गयी है, तमिलनाडु की तर्ज पर लाई गयी है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री प्रहलाद गुंजल)

निवेदन करना चाहता हूं कि यह आज की जरूरत बन गयी है। साढ़े तीन दशक के अंदर जब से दुनिया में भूमण्डलीयकरण का दौर आया, शहरीकरण का प्रभाव समाज और जीवन पर कायम हो गया और इसके चलते हुए गांव शहरों में पलायन कर गये और गांवों का शहरों में पलायन करने के बाद, शहरों में रोजगार का संकट आ गया। न केवल रोजगार का संकट आ गया, रहवास का संकट भी आ गया और इसीलिए जो राजस्थान का पुरुषार्थी व्यक्ति है, जो आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है, कई बार पर्याप्त रोजगार न मिलने के कारण वह भूखे सोना मंजूर कर लेता है, लेकिन भीख नहीं मांगता। ऐसे लोगों को कम कीमत पर खाना मिलेगा, कम कीमत पर आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ उसको खाना मिले, नाश्ता मिले, यह प्रबंध करके राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने एक क्रांतिकारी पहल की है। मजाक नहीं किया। हमने देखा, 2011 के यूपीए के शासनकाल में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के आंकड़े आये और प्लानिंग कमीशन ने कहा कि 27 रुपये गांवों में और 33 रुपये शहरों में कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता, तब कांग्रेस के लोगों ने मजाक किया। जब देश के बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार और राजनैतिक लोगों ने कहा, 27 रुपये में दो लोग खाना नहीं खा सकते, तब कांग्रेस के लोगों ने कहा, पार्लियामेंट में बयान दिया, अखबारों में बयान दिया, आओ, दिल्ली में 10 रुपये में, मुम्बई में पांच रुपये में हम खाना खिला देंगे। यह मजाक किया था और मजाक भी कब किया, जिस समय यूपीए के प्रधान मंत्रीजी ने राज्यों के मुख्य मंत्री और सांसदों की बैठक फाइव स्टार होटल में ली, तो पर प्लेट 7,000 रुपये का खर्चा आया, तब उस पार्टी के लोगों को इस हिन्दुस्तान के गरीब आदमी का स्तर पांच रुपये और दस रुपये खाने का लगा था। यह उसका सरासर मजाक था। राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने उनके आत्मसम्मान की चिंता की है, उनके स्वाभिमान की चिंता की है। वह गरीब आदमी जिसकी जेब अलाउ नहीं करती, वह रोजगार को तलाशते-तलाशते गांवों से पलायन करके शहर के किनारे चला गया। वह डिवाइडर पर सोता है। धरती की गोद में और आसमान की छत के नीचे सोता है। अगर उसके पास पर्याप्त पैसे का प्रबन्ध नहीं हुआ, दिन में रोजगार नहीं मिला तो वह शाम को भूखा नहीं सोएगा। दिन में रोजगार मिलेगा, तब शाम का चूल्हा जलेगा, तब पेट भरेगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अब यह बात राजनैतिक लोग भाषणों में न कहे। अगर दिन में किसी को रोजगार न मिला, शाम को चूल्हा न जला तो उसका पेट कम पैसों में राजस्थान की सरकार भरने की जिम्मेदारी लेती है और राजस्थान के कई जिलों में अन्नपूर्णा रसोई योजना प्रभावी तरीके से काम कर रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसीलिए मैं इसके लिए राज्य की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे राजस्थान की परम्परा है। लोग धर्मादा चलाते हैं, भण्डारे चलाते हैं। उसके बावजूद भी स्वाभिमानी व्यक्ति कई बार मुफ्त का खाना पसंद नहीं करता और इसलिए देर से चलाई लेकिन बहुत प्रभावकारी योजना, राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने निश्चित रूप से इस राज्य के हित में चलाई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत क्रांतिकारी काम हुए हैं। "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना" में पहली बार राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या पर सख्ती के साथ राजस्थान की सरकार पेश आई है। पिछले दस सालों में जितने केस नहीं बने होंगे, पिछले तीन सालों में उतने ज्यादा रेड करके केस बनाये गये हैं और उसका परिणाम यह हुआ कि लगभग साठ हजार से अधिक बालिकाओं को बचाया गया कन्या भ्रूणों में और राजस्थान में जैण्डर संतुलन अब धीरे-धीरे बढ़ने, ठीक होने की दिशा में चल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई सारे क्रांतिकारी कदम राज्य की मुख्यमंत्रीजी ने बढ़ाये हैं। कौशल विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर केवल राज्य की मुख्यमंत्रीजी ही नहीं भारत के प्रधानमंत्रीजी और पूरी सरकार काम कर रही है और कई बार इस सदन में चर्चा हुई कि कौशल विकास इस राष्ट्र की जरूरत है। हिन्दुस्तान के अन्दर पिछली सरकारें देश के पढ़े-लिखे नौजवान को बेरोजगार और राष्ट्रीय समस्या कह कर अपमानित करती थीं। जब से राजस्थान में भाजपा का राज आया, केन्द्र में मोदीजी का राज आया, उस पढ़े-लिखे नौजवान को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में सृजित करने का प्रयास किया और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य की मुख्यमंत्रीजी को, पिछले विधान सभा सत्र में अप्रेन्टिस एक्ट लेकर आये। हाथ का हुनर होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, रोजगार मुट्ठी में होना चाहिए। पढ़ने के बाद, डिग्री के बाद भी उसको किस तरीके से कुशल प्रशिक्षक बनाया जाए

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इस पर सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया और आज इसी सत्र में एक निजी क्षेत्र में और एक सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट विश्वविद्यालय लाकर सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। इतना ही नहीं जयपुर के नीमराणा में जापान इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है जो विश्व के नवीनतम तकनीकी ज्ञान से राजस्थान के युवाओं को प्रशिक्षित करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बजट में हम कर्जे को लेकर कितनी चर्चा कर रहे हैं। अब हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों की आर्थिक स्थिति कर्ज पर आधारित खड़ी हो गयी, लेकिन उसमें से कैसे बेहतरीन प्रबंधन करें, उसमें से कैसे राजस्थान की जनता की आत्मनिर्भरता का रास्ता बनायें, उसमें से कैसे राजस्थान के नौजवान को कुशल कामगार बनाकर किस तरीके से रोजगार उसकी मुट्ठी में हो, इस दिशा में प्रयास करें। मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक कदम राज्य की मुख्यमंत्रीजी ने उठाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाये हैं। नरेगा में मैं कह रहा हूं भारत के प्रधानमंत्रीजी ने कहा, साठ साल बाद उनका विजन है, उनका चिन्तन है। हालांकि नरेगा में राजस्थान ने देश में अपना एक विशिष्ट स्थान पाया है। हम यह भी मानते हैं कि नरेगा के कारण राजस्थान का पलायन रुका है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि हमने साठ साल बाद राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट लाकर इस हिन्दुस्तान के लोगों को गड्ढ़े खोदने के लिए तैयार किया है। अगर हम आत्मचिन्तन करते, मूल्यांकन करते कि साठ साल में भारत कहां पहुंचा है तो आज हम आत्मसम्मान के साथ कह पाते कि हम दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में जाकर खड़े हो गये। हमारे यहां के गरीब से गरीब आदमी की परचेजिंग पावर एक लिमिट से ज्यादा है तब हमको फख्र होता कि डैमोक्रेसी की व्यवस्था में जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें पचासों सालों तक जनादेश दिया है हमने उस जनादेश का सम्मान किया है। इससे बड़ा जनादेश का अपमान क्या होगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साठ साल बाद यह चिन्तन हो कि हिन्दुस्तान के लोगों के सामने रोजगार की गारंटी कैसे दी जाए और रोजगार की गारंटी का एक्ट पास करने के बाद लोगों को गड्ढ़े खोदने में लगाओ, लोगों को मिट्टी उठाने में लगाओ, मिट्टी उठाना, गड्ढ़े खोदना कोई

(श्री प्रहलाद गुंजल)

शर्म की बात नहीं है यह स्वावलम्बन है, पुरुषार्थ है। खेत में वर्षों तक काम करता रहा है, यह हमारा सनातन वर्क है। परंपरागत, वंशानुगत वर्क है, लेकिन सरकार को वोट देते समय लोक कल्याणकारी सरकार से उम्मीद करता है व्यक्ति उसकी आत्मनिर्भरता सुदृढ़ होनी चाहिए और उसकी आत्मनिर्भरता सुदृढ़ होने के सम्पूर्ण उपाय सरकार करे इस बारे में गंभीर चिन्तन होना चाहिए। नरेगा में सौ रुपये की मजदूरी, इसका गंभीर चिन्तन नहीं किया और इसलिए प्रधानमंत्रीजी ने विकल्प तय किया कि हम कुशल कामगार बनाएंगे, हम कुशल कामगार के साथ कौशल प्रशिक्षण बढ़ा कर देश की नौजवान पीढ़ी को इस रूप में तैयार करेंगे कि आत्मनिर्भरता का रास्ता स्वयं चुन ले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्रीजी ने इस बजट में कोटा के मेडिकल कालेज को तीस करोड़ रुपये का योगदान दिया है। तीस करोड़ रुपये की राशि मेडिकल कालेज के लिए दी है, मुख्यमंत्रीजी ने तीस करोड़ रुपये न्यू मेडिकल कालेज के द्वितीय तल को बनाने का इस बजट में प्रावधान किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने आठ करोड़ का प्रावधान किया है कि किडनी ट्रांसप्लांट जैसे काम अब कोटा के मेडिकल कालेज में हो। लेकिन मुझे तकलीफ है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों ने किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्रीजी से यह पढ़वा लिया कि कोटा के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय की दो यूनिट्स बाद में मेडिकल कालेज में शिफ्ट कर दी जाएंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हिन्दुस्तान की परम्परा रही है विश्वविद्यालय और चिकित्सालय क्रमोन्नत होने चाहिए अवनत नहीं होने चाहिए। विश्वविद्यालय और चिकित्सालयों में विश्व स्तरीय तकनीक आनी चाहिए उनका डिमोशन नहीं होना चाहिए। मैं जिस महाराव भीम सिंह चिकित्सालय की बात कर रहा हूं न जाने कितने दशकों से लाखों लोगों को जीवन दिया है और लाखों लोगों को जीवन ही नहीं दिया उसने न केवल अमीर का इलाज किया, फटी जेब भी अगर कोई व्यक्ति आया तो कोटा महाराव भीम सिंह चिकित्सालय ने उसका इलाज किया है। कोटा उसकी प्रगति की मन्नत मांगता है, दुआ करता है कि महाराव भीम सिंह चिकित्सालय आगे बढ़ना चाहिए, उसमें और उन्नति होनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने बजट में कहलवा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दिया कि महाराव भीम सिंह चिकित्सालय की दो इंडोर यूनिट मेडिकल कालेज में शिफ्ट कर दी जाएंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगा आपके माध्यम से कि बजट पर जब माननीय मुख्यमंत्रीजी अपना जवाब देंगी तो निश्चित रूप से इस विषय में कोटा की जनता को भरोसा देंगी कि कोटा का महाराव भीम सिंह चिकित्सालय जिसके लिए लोग मन्नत मांगते हैं, दुआ मांगते हैं वह अवनत नहीं होगा व बढ़ेगा और बढ़ना ही नहीं चाहिए बल्कि मैं एक विश्वास के साथ कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि कोटा का महाराव भीम सिंह चिकित्सालय कमजोर होने के बजाय सुदृढ़ होना चाहिए। कोटा राजस्थान का सबसे तीव्र गति से बढ़ता हुआ प्रदेश है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2001 और 2011 सेन्सस आपके सामने रख रहा हूं 2001 के बाद 2011 में जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आपकी राजधानी की रही है 31 परसेंट, जोधपुर की रही है 23 परसेंट, उदयपुर की रही है 15 परसेंट, अजमेर की रही है 11 परसेंट और परसेंटेज ऑफ ग्रोथ 2001 के बाद 2011 के सेन्सस मेरे कोटा शहर की रही है 44.3 प्रतिशत, जो इस गति से बढ़ रहा है, देश की राजधानी की रफ्तार से बढ़ रहा है और केवल आबादी नहीं वहां पर प्रचुर मात्रा में पानी है, बिजली है, संसाधन है। वह एनसीआर का मैग्नेट सिटी है विकल्प के रूप में और उस काउंटर मैग्नेट सिटी में हम सुविधाएं बढ़ाने की बजाय घटाने की बात करें तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी चिन्ताजनक बात कुछ नहीं हो सकती। आबादी का फ्लो केवल वहां बढ़ नहीं रहा है, इसके अलावा इस मुल्क से दो लाख से ज्यादा बच्चे आबादी के अलावा वहां आकर रहते हैं। वहां आकर बसते हैं। इन तमाम लोगों की चिकित्सकीय सुविधा के बारे में हमको गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और जब तक हम इस पर गंभीरतापूर्वक बात नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि कोटा के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। आने वाले समय में जिस प्रकार से एसएमएस मेडिकल कालेज के अलावा जयपुरिया अस्पताल में मेडिकल कालेज की बात है, कोटा का महाराव भीम सिंह चिकित्सालय कोटा की बढ़ती हुई ग्रोथ के हिसाब से एक नये मेडिकल कालेज की मांग करता है

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कोटा में, न कि उसके किसी विभाग को बंद करके उसको कमजोर करने की। महाराव भीम सिंह चिकित्सालय कोटा की आस्था का केन्द्र है, श्रद्धा का केन्द्र है। सैंकड़ों सालों से आज सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति इस शहर का पैदा हुआ है उसने महाराव भीम सिंह चिकित्सालय को वहां की सबसे बड़ी चिकित्सा इकाई के रूप में देखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी मेडिकल कालेज की बिल्डिंग में 400 बैड स्वीकृत होंगे, महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में 434 बैड के अगेंस्ट 700 बैड की क्षमता से काम कर रहे हैं। अच्छा होता कि हम उसकी बैड क्षमता बढाने की बात करते। बजट में बहुत सारी घोषणाएं की हैं, अच्छी घोषणाएं की हैं लेकिन इन सबके बाद हमारा कदम सुधारवादी होना चाहिये, प्रगतिशील होना चाहिये। मेडिकल यूनिवर्सिटीज के संस्थानों का अवमूल्यन प्रगति का सूचक नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा महाराव भीम सिंह चिकित्सालय को निश्चित रूप से मजबूत किया जाना चाहिये।

कोटा में 850 करोड़ की पेयजल योजनाओं की घोषणा की, उस पर तुरंत काम प्रारंभ होना चाहिये। पिछली सरकार में इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए। 400 कालोनीज ऐसी हैं जो बिना पानी के तरस रही हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एनसीआर से लोन लेकर काम आगे बढ़ने का जो अनाउंसमेंट किया है वह स्वागत योग्य कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार सवाल उठाया है, कोटा की अदालत छोटी पड़ने लगी है। मैंने मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को भी सुझाव दिया है कि पास में ही सेंट जोंस स्कूल जो बंद हो गया, अदालत की चार गुणा से अधिक की कैपेसिटी की जमीन है, उसको एक्वायर कर कोटा की अदालत का विस्तार किया जाना चाहिये। जब वह एक्वायर होगा कोटा की डिस्ट्रिक्ट अदालत का विस्तार होगा, हमारे पास गुंजाइश होगी। जो कोटा लगातार पिछले 20 सालों से हाई कोर्ट ब्रांच की मांग कर रहा है, हमारे पास उसकी भी उस जगह गुंजाइश होगी। निश्चित रूप से इस दिशा में भी सकारात्मक प्रयास होने चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुछ

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आधारशिला और बूंदी की एक मस्जिद के विकास के लिये टूरिज्म की दृष्टि से घोषणा की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम जिस कोटा में रहते हैं उस कोटा के नंद ग्राम में मथुराधीश जी का स्थान है। हिन्दुस्तान का सारा पुष्टिमार्ग यह जानता है कि नाथद्वारा में जो धार्मिक टूरिज्म इस राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है वह नाथद्वारा की पीठ पुष्टिमार्गीय संप्रदाय में द्वितीय नंबर की पीठ है और इस मुल्क में अगर पुष्टिमार्गीय प्रथम पीठ कोई है तो वह कोटा का मथुराधीश मंदिर है। उसके डवलपमेंट पर अगर 100 करोड़ रुपये भी सरकार घोषित करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस रोज मथुराधीश को प्रथमेश के रूप में इस मुल्क में स्थापित करने की बात होगी, धर्म की खेती जिसको हम कहते हैं कोटा के लिये आध्यात्म एक रोजगार का जरिया बन जाएगा। धार्मिक टूरिज्म इतना बढ़ जाएगा नाथद्वारा से 10 गुना ज्यादा, इस दिशा में माननीय मुख्य मंत्री जी को निश्चित रूप से घोषणा करनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर स्मार्ट सिटी में भी आगे आ गया। अमृत योजना में कवर है। शहर में बहुत बडी पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं। एयरपोर्ट की जरूरत है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम कोटा की जयपुर से कनेक्टिविटी करेंगे लेकिन कोटा अब एयरपोर्ट को लेकर बहुत बेचैन है। बहुत उत्सुकता हो रही है, अब उस शहर को एयरपोर्ट चाहिये। इसदिशा में जितना जल्दी हो गंभीरतापूर्वक प्रयास होने चाहिये और शहर की पार्किंग व्यवस्था को लेकर जो कुछ भी किया जा सकता है, निश्चित रूप से किया जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय और आपके सामने इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं हम सब लोग सदन में आते हैं आसन की तरफ तो झांकते हैं लेकिन आसन के आस पास झांकने की कोशिश नहीं करते। हिन्दी में लिखा है सभा में या तो प्रवेश न किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए क्योंकि वहां न बोलना और गलत बोलना दोनों स्थितियों में मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है। मैं इस बात के लिये राज्य की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दूंगा कि जब-जब भी उन्होंने बजट पेश किया सैद्धांतिक रूप से इन चुनौतियों को स्वीकार किया कि राज्य की आर्थिक स्थिति विकट है और इन विकट स्थितियों में से हमको किस तरीके से अपना रास्ता बनाना है, पूरे राजस्थान को इससे रूबरू कराने का प्रयास किया। लेकिन हमारा दायरा बहुत सीमित हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जब चर्चा करते हैं तो फिर हमारा दायरा केवल चर्चा में एक दूसरे को कठघरे में खड़ा करना रह गया। एक दूसरे की कमजोरियां निकालने में रह गया। राजस्थान के इस सदन की परम्पराएं खतम हो रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गौरवशाली परम्पराओं का प्रदेश है। विजय सिंह पथिक और कुमार आनंद इस राजस्थान के नहीं थे लेकिन इस राजस्थान के हित में लड़े तो यहां के लोगों ने उनको नेता माना, सम्मानित किया और 70 साल बाद जब उन लोगों के बलिदान और त्याग के आधार पर देश में लोकतंत्र आया तो व्यावहारिक और सैद्धांतिक रूप से हमने इस लोकतंत्र के पक्ष को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया। केवल हमारी बहस का दायरा, हमारी चर्चा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तक सीमित हो गयी। हमारी बहस और हमारी चर्चा का दायरा क्या हमसे पढवाया जा रहा है, किस पर हमसे चर्चा करवाई जा रही है, जवाबदेही केवल हमारे ऊपर लेने तक सीमित रही, लेकिन वर्किंग एजेंसीज के लिये जवाबदेही है इसकी पालना सख्ती से करवाने का कभी प्रयास नहीं किया और उसका परिणाम क्या हुआ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रति लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है। जनतंत्र में इन इमारतों का, इन इबादतों का स्थान मजबूत रहेगा तो जनतंत्र मजबूत रहेगा, भरोसा कमजोर होगा तो जनतंत्र कमजोर होगा और यह सारी व्यवस्था लोगों के विश्वास पर टिकी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी लचर व्यवस्था, हमारे दायरे में बोलने की व्यवस्था, इसके बाद दुनिया के कई देशों में एक सर्वे हुआ है। दुनिया में प्रजातांत्रिक देशों की इस दुर्बलता से निराश जनता अब ताकतवर शासक चाहती है। यहां तक कह दिया कि हमें ऐसे दुर्बल प्रजातंत्र से तानाशाह मंजूर है, यह दुनिया के कई देशों के एक सर्वे में आया है। हमारे यहां के लोगों

(श्री प्रहलाद गुंजल)

की भी मानसिकता कुछ इस तरह की बनती जा रही है। यह हम सब लोगों के लिये एक सबक है, हम सब लोगों के लिये चुनौती है, एक सीख है कि हम सब लोग मिलकर इस सदन में चर्चा करते समय, फैसले करते समय उस गरिमा को, उस मर्यादा को, इस राजस्थान की सनातन परम्पराओं को, इस सदन की परम्पराओं को मजबूत कैसे बनाएं और न केवल मजबूत बनाएं, वह मतदाता जो हमको लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में जनादेश देकर इस सदन में भेजता है, उसके विश्वास को कैसे जिंदा रखे। इस दिशा में जब तक चर्चा नहीं होगी, केवल स्कोरिंग हमारी चर्चा का आधार बनेगा, एक दूसरे को कठघरे में खड़ा करना हमारी चर्चा का आधार बनेगा, हमारे प्रति विश्वास में कमी आती रहेगी और विश्वास में कमी लोकतंत्र के लिये घातक है। इन संकेतों से हमको रूबरू होकर सावधान होने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य सचेतक की पर्ची आ गयी है, संक्षिप्त करें। मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया। सदन की गरिमा की और प्रदेश के चुनौती पूर्ण हालातों से हम सब लोग मिलकर निपटें। इस जनतंत्र की, सदन की, सरकार की साख बने और जनता का विश्वास, भरोसा बना रहे इसके लिये सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रताप सिंहजी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बजट के बारे में विस्तार से कोटा उत्तर से आने वाले माननीय विधायक ने अपनी बात को बहुत ही जोरदार तरीके से रखा। मैं भी उनकी बात का समर्थन करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस बात के लिये धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इस बजट में उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा जो भी फ्लेगशिप योजनाएं चलाई हुई हैं उनका समायोजन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है ताकि राजस्थान की जनता का भला कर सके, राजस्थान प्रगति की तरफ अग्रसर हो सके।

(श्री प्रताप सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राजस्थान सरकार की जो फ्लेगशिप योजनाएं हैं, चाहे वह भामाशाह योजना हो, चाहे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हो, रिसर्जेंट राजस्थान हो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना हो, अन्नपूर्णा भंडार योजना हो, आरोग्य राजस्थान योजना हो, इन सभी योजनाओं के माध्यम से हमारी मुख्य मंत्रीजी ने हमारे प्रदेश की जनता की बहबूदी और राजस्थान के विकास के लिए भरपूर परिश्रम करके राजस्थान को आगे बढ़ाने की जो चेष्टा की है, उसके लिए मैंने आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वसुन्धराजी के बारे में एक बात सब जानते हैं और जब आपस में बातचीत होती है तो अक्सर यह जिक्र भी करते हैं कि वसुन्धराजी जो कहती हैं, वह करती हैं। निश्चित रूप से, इस बजट और पिछले जो तीन बजट यहां पर पेश किए हैं, उनके माध्यम से उन्होंने जो भी कहा है, वह सब करने की चेष्टा की है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम आलोचना के लिए आलोचना तो कर सकते हैं, पर मेरा आप सभी को सुझाव है कि आप आलोचना ही नहीं करें, कोई अच्छे सुझाव भी दें ताकि आपके सुझावों के माध्यम से सरकार हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने की चेष्टा करे।

साथ ही साथ, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा और मैं बजट की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हूं या भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूं। मैं राजस्थान का एक नागरिक होने के नाते भी इस बजट की तारीफ कर रहा हूं कि यह बजट राजस्थान की जनता की बहबूदी के लिए बहुत ही शानदार बजट है। यह बजट प्रदेश के सात करोड़ से अधिक लोगों के सपनों का धरातल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा और मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी का इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने राजस्थान के सभी विधान सभा क्षेत्रों को कुछ-न-कुछ देने का प्रयास किया है।

माननीय मुख्यमंत्रीजी भी यदि वाही-वाही लूटना चाहती, जिस प्रकार से पिछली सरकार के समय हुआ। जिस प्रकार से अभी प्रहलादजी बता रहे थे कि कम्बल, साड़ी बंटे। इस प्रकार की घोषणाएं या इस प्रकार का काम

(श्री प्रताप सिंह)

मुख्यमंत्रीजी भी कर सकती थीं, पर मुख्यमंत्रीजी ने ऐसा नहीं करके राजस्थान की बहबूदी के लिए, ठोस परिणाम आएं, इस प्रकार का बजट पेश किया है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा।

आप सभी जानते हैं कि पिछले शासन में हमारा राजस्थान बीमारू प्रदेश की श्रेणी में खड़ा हो गया था। माननीय मुख्यमंत्रीजी का इस बात के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने फिर से राजस्थान को बीमारू प्रदेश की श्रेणी में से हटाकर अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया और मुझे खुशी है कि आज हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है। राजस्थान के लोग ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के लोग हमारे राजस्थान की तारीफ करने लगे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की फ्लेगशिप योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई हैं। भामाशाह योजना है। भामाशाह योजना के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है। घर की मुखिया महिला को कई प्रकार की आर्थिक सहायता मिल रही है और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि अब तक 1 करोड़ 38 लाख परिवारों के 5 करोड़ 2 लाख लोगों का नामांकन किया जा चुका है। कुल 6 करोड़ 458 रुपये का अमाउंट लोगों के खातों में सीधा ट्रांसफर हुआ है। निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि इससे हमारे जो बी.पी.एल. या गरीब श्रेणी के लोग हैं, उनको फायदा मिलेगा। जो बिचौलिए, जिस प्रकार गरीब लोगों तक सरकार सहायता पहुंचाती थी और पहुंचाती नहीं थी, निश्चित रूप से ये सब काम ऑनलाइन करके गरीबों की मदद की है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ भामाशाह योजना के तहत लोगों को रोजगार भी मिला है। आज ई-मित्र, माइक्रो एटीएम जगह-जगह स्थापित हुए हैं। करीब 23 हजार 500 से अधिक लड़के इस माइक्रो एटीएम से जुड़ कर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं और मुझे जानकारी है कि इस प्रकार के माइक्रो एटीएम से लड़के करीब पांच से छह हजार रुपए महीना कमा रहे हैं, निश्चित रूप से इससे हमारे नौजवानों को भी आर्थिक संबल मिला है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री प्रताप सिंह)

यही नहीं, भामाशाह स्वास्थ्य योजना। भामाशाह स्वास्थ्य योजना में हमारी जो गंभीर बीमारियां थीं, इसमें करीब 1 हजार 715 बीमारियों को शामिल किया गया है। प्रदेश की 70 प्रतिशत के करीब की आबादी को इसमें कवर किया गया और 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता गरीबों को जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं थे, उनको दी गयी। मुझे बताते हुए खुशी है कि यह मात्र सरकारी औषधालयों या सरकारी हॉस्पिटल तक ही सीमित नहीं है, करीब 494 सरकारी और 633 निजी अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा गया है और करीब 300 करोड़ रुपये की चिकित्सा सुविधा अब तक हमारे राजस्थान के लोगों को उपलब्ध कराई गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान में पेयजल के पानी की और सिंचाई के पानी की बहुत अधिक आवश्यकता है और कमी भी है। माननीय मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे बीच में राजस्थान के लोगों के लिए घोषित किया है और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि जहां पर भी इस योजना के माध्यम से, जिसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं, विधायकों से भी फंड लिया है, एम.पी. से भी फंड लिया है, दानदाताओं से भी आग्रह किया है। हमारे सरकारी कर्मचारियों ने भी मदद की है। सम्पूर्ण रूप से सब की मदद लेते हुए, इस योजना की निश्चित रूप से जितनी तारीफ की जाए, कम है। मैंने स्वयं देखा है कि जहां पर कभी पानी नहीं रुकता नहीं था, आज वहां पर पानी भरा हुआ है। जगह-जगह एनिकट बने हुए हैं और कई जगह तो आदमी उस पानी को, जो कि जल स्वावलम्बन योजना के माध्यम से रुका है, उससे सिंचाई भी करने लगे हैं। मवेशियों को गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता था, आज उस पर भी रोक लगी है। मैं समझता हूं कि इसका जितना ज्यादा विस्तार किया जाए, राजस्थान के हित में होगा। इससे पेयजल समस्या का भी समाधान होगा, हमारे मवेशियों के पीने के पानी की समस्या का भी समाधान होगा और खेती के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा। राजस्थान का काफी बड़ा भू-भाग डार्कजोन घोषित हो गया है। इससे निश्चित रूप से हमको फायदा मिलेगा। इसलिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री प्रताप सिंह)

यही नहीं, हमारे यहां खाद की समस्या है। पिछली हुकूमत के समय क्या हुआ, आप सब लोग जानते हैं। किसानों पर लाठियां बरसाई गयी। उसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्रीजी ने किसानों की चिंता करते हुए इस वर्ष भी 1 लाख 50 हजार मैट्रिक टन यूरिया, 20 हजार मैट्रिक टन डी.ए.पी. का अग्रिम भंडारण किया जाएगा, इस प्रकार की घोषणा की है। इससे निश्चित रूप से किसानों को फायदा मिलेगा।

(14.00 बजे)

बिजली के कनेक्शन की घोषणा भी बहुतायत में हुई है। करीब दो वर्षों में एक लाख कनेक्शन देने की घोषणा की है। किसानों को इससे भी बहुत फायदा मिलेगा। जो जरूरतमंद लोग थे, उनको भी समय पर बिजली मिल सकेगी। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी से यही निवेदन है कि समयबद्ध कार्यक्रम चला कर, किसानों को समय पर कनेक्शन मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से इसका फायदा किसानों को और अधिक होगा।

सड़कों के मामले में भी, कई प्रकार के काम हुए हैं। पांच साल में जितना कांग्रेस की हुकूमत ने खर्च नहीं किया उससे ज्यादा हमने तीन वर्षों में खर्च किया है। ग्रामीण गौरव पथ की योजना इतनी सक्सेस योजना है, इसको सभी सराहते हैं। इसमें भी जितना संभव हो सके और अधिक बजट दिया जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी सब गांवों में गौरव पथ बन सकें, इस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए।

मिसिंग लिंक के माध्यम से भी कई गांवों को आपस में जोड़ा जा रहा है। इनकी भी बहुत आवश्यकता थी। कई गांवों के बीच आने-जाने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, मिसिंग लिंक बनने के बाद हमारे राज्य के लोगों को फायदा मिलेगा।

'सशक्त युवा, सशक्त राजस्थान,' इस प्रकार की धारणा लेकर हमारी माननीय मुख्यमंत्रीजी चलती है। इसी बात को लेकर उन्होंने स्किल डवलपमेंट पर, कौशल विकास पर, बहुत अधिक ध्यान दिया है। उसी का नतीजा है कि एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जामड़ोली में स्किल यूनिवर्सिटी खोलने

(श्री प्रताप सिंह)

की घोषणा की है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। यहां पर आपस में रेवेन्यू के मुकदमे भी भारी तादाद में है। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने किसान की पीड़ा को समझते हुए, गांव के लोगों की पीड़ा को समझते हुए, 'न्याय-आपके-द्वार' अभियान चलाया। मुझे बताते हुए खुशी है कि इस अभियान के तहत 69 लाख 89 हजार रेवेन्यू प्रकरणों का निस्तारण किया गया और 523 ग्राम पंचायतों को रेवेन्यू केस से पूर्णतया मुक्त किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं, आप भी खेती से जुड़े हुए हो। औसत देखो तो एक रेवेन्यू केस के पीछे चार साल लग जाते हैं। इतने लाखों मुकदमे निस्तारण करने से राजस्थान के किसान का कितना तो पैसा बचेगा, कितना समय बचेगा, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद दूंगा।

पोस मशीन, बाबूबाल जी भी यहां पर बैठे हैं। पोस मशीन से वितरण, ठीक है, अच्छी व्यवस्था है, इसका हम सब भी स्वागत करते हैं। पर, जहां पर नैटवर्क पूरा नहीं आता, वहां पर अंगूठे लगाने में दिक्कत आती है। हमारा कम्प्यूटर काम नहीं करता है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर जो भी इस प्रकार के टैक्नीकल आदमी है उनसे आप कोशिश करके नैटवर्क प्राब्लम की समस्या का निदान कराए ताकि किसान यह नहीं कह सके कि मैं राशन की दुकान पर गया उन्होंने हमको राशन देने से मना कर दिया, मेरा तो अंगूठा नहीं लगा, मेरी और कोई बात नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र का निवेदन करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की करीब पौने दो सौ किलोमीटर सीमा पर मेरा क्षेत्र लगा हुआ है। कई जगह इस प्रकार की हैं जहां नैटवर्क प्रोब्लम है। नैटवर्क प्रोब्लम होने की वजह से वहां के निवासियों को राशन नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान देकर जो भी निस्तारण हो सके, करवाने की चेष्टा करें।

अन्नपूर्णा भण्डार के माध्यम से मल्टी ब्राण्ड, हमारे शहरों में मॉल में मिलता है, इसको ग्रामीण मॉल कह सकते हैं। करीब 45 तरह के 150 मल्टी

(श्री प्रताप सिंह)

ब्राण्ड उत्पादन अन्नपूर्णा भण्डारों के माध्यम से मिल रहे हैं। इससे भी हमारे गांव के लोगों को फायदा मिलेगा।

भामाशाह रसोई योजना, भामाशाह रसोई योजना का जिस प्रकार से प्रहलादजी जिक्र कर रहे थे, यह सबसे पहले तमिलनाडू की मुख्यमंत्रीजी ने वहां पर शुरू की और काफी सक्सेज भी हुई, इस प्रकार का समाचार पत्रों के माध्यम से हमको पढ़ने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई योजना को राजस्थान में भी लागू किया। पहले कुछ शहरों में लागू किया। अब पूरे राजस्थान के लिए लागू किया। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस प्रकार योजनाएं जो तहसील मुख्यालय हैं, चाहे वह नगरपालिकाएं भी नहीं हैं, तो वहां पर भी इस प्रकार की योजना चालू करवाने की चेष्टा करेंगे, इस प्रकार का मेरा सुझाव है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में छीपाबड़ौद हरनावदा शाहजी को मिलाकर एक अलग मण्डी की घोषणा की। इसके साथ ही छपड़ा से कुम्भराज एक सड़क है जो मध्यप्रदेश से जोड़ती है, काफी बुरी स्थिति में थी, मोटरेबल भी नहीं थी, उसके अपग्रेडेशन के लिए भी उन्होंने काफी बजट इस बजट के माध्यम से दिया।

आपके माध्यम से मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे यहां पर रखना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मांग है, कालेज को सरकारी दर्जा देने की। मैं मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद तो दूंगा कि एक स्ववित्त पोषित कालेज छबड़ा का था, उन्होंने उसको तो पिछले बजट में सरकारी दर्जा दे दिया। छीपाबड़ौद में स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह सिंघवी महाविद्यालय है, वह भी स्व वित्त पोषित कालेज है। कांग्रेस हुकूमत के समय इसको सरकारी दर्जा मिल गया था, पर पता नहीं किन कारणों से यह वापस स्व वित्त पोषित कालेज कर दिया गया। मेरा माननीय मुख्यमंत्रीजी से निवेदन है कि छबड़ा क्षेत्र के गरीब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, वहां की बच्चियों की भावना को ध्यान में रखते हुए, छीपाबड़ौद के कालेज को भी सरकारी कालेज का दर्जा दिलवाने का कष्ट करेंगे। यहां पर सब प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर है, खाली सरकार घोषणा कर दे।

(श्री प्रताप सिंह)

माननीय मुख्यमंत्रीजी ने परवन डैम के लिए एक हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें क्षेत्र के 12-14 गांव डूब में आते हैं। जनसंख्या के हिसाब से भी काफी बड़ा भू-भाग डूब में आता है। खेती की जमीन के हिसाब से भी काफी बड़ा भू-भाग डूब में आता है इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि उनको आज के भाव से जितना अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके, दिलवाने की चेष्टा करे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पूरे बारां जिले की एक दिक्कत है कि वहां पर फोरेस्ट की एन ओ सी नहीं मिलने की वजह से काफी सड़कें रुकी पड़ी हैं। किशनगंज शाहबाद में भी है, छबड़ा छीपाबड़ौद में भी है, और भी क्षेत्रों में है। यहां तक कि नेशनल हाइवे रोड़ भी फोरेस्ट एन ओ सी नहीं मिलने की वजह से रुका पड़ा है। अगर समय रहते फोरेस्ट की एन ओ सी मिल जाती है तो विकास में हमारे क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ेगा और वहां के लोगों को राहत मिलेगी।

छबड़ा थर्मल मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। वहां एल एंड टी कम्पनी काम कर रही है। एल एंड टी ने काफी एन्सलरी, छोटे कांट्रेक्टर को, सबलैट काम किए हुए हैं, उनमें काफी तादाद में मध्यप्रदेश के और अन्य प्रदेशों के लोग, बच्चे वहां आकर काम करते हैं। मेरा यही निवेदन है कि अगर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिले तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के लोगों का फायदा होगा।

यहां पर पीएचईडी मंत्री नहीं हैं, पर उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्रीजी ने स्वयं ने घोषणा की और मुझे बताते हुए दुख है कि करीब एक-डेढ़ वर्ष गुजर गया, मैंने सभी माध्यम से कोशिश की, उन्होंने घोषणा की थी सिंदूरियादह और एक कछावन से पीएचईडी स्कीम की। अगर वह वाइबल नहीं है तो उसका स्कोप छोटा कर दो, पर विभाग के लोग पता नहीं क्यों आनाकानी करते हैं। शायद मंत्रीजी का पूरा ध्यान नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि इसका स्कोप छोटा कर दो। पर माननीय मुख्य मंत्रीजी के मुंह से बात निकली है तो निश्चित रूप से इसको पूरा करायें।

(श्री प्रताप सिंह)

इसके साथ-साथ ही छबड़ा-छीपाबड़ौद रोड का करीब ढाई किलोमीटर रोड बाकी बचा हुआ है, उसको पूरा करवा दें। गूघोर-पावर्ती रोड पर, गूघोर में पार्वती पुलिया पर पुल बनवा दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां हरनावदा शाहजी एक जी.एस.एस. है। जी.एस.एस. के माध्यम से मिनी बैंक चलता है। उस मिनी बैंक में लोगों ने रेकरिंग डिपोजिट के माध्यम से करीब एक करोड़ 36 लाख से भी अधिक की राशि उसमें जमा कराई है। लोग पिछले एक-डेढ़ साल से घूम रहे हैं। न तो उनको वापस पैसा मिल रहा है, न उनको कोई संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। इस ओर भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय निश्चित रूप से कार्यवाही कराएंगी, इस प्रकार का निवेदन है। यह मोटी-मोटी बातें, मैंने आपके सामने रखी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि हम जन प्रतिनिधि हैं। जन प्रतिनिधि होने के नाते हमारे पास सब तरह के लोग आते हैं। कोई अच्छे भी आते हैं, कोई बुरे भी आते हैं। अगर किसी की समस्या है, हम किसी को फोन करते हैं और अन्यथा लेता है तो निश्चित रूप से हमको उसका दु:ख होता है। अभी कल-परसों की ही घटना है। हमारे किशनगंज के विधायक श्री ललित मीणा, उन्होंने किसी काम के लिये पुलिस को फोन किया। पुलिस को फोन करके यह कहा कि इसका यह काम वाजिब है, इसको कर दीजिये, अगर गलत है तो मत कीजिये। पर इसकी सुन तो लीजिये। मुझे बताते हुए दु:ख है कि बारां जिले के पुलिस वालों ने उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज की। निश्चित रूप से यह हम सब जन प्रतिनिधियों का अपमान है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आप तुरन्त इस पर कार्यवाही करेंगे। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

आखिर में, कोटा कोचिंग का जिक्र करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करुंगा। कोटा कोचिंग में, जिस प्रकार से अभी प्रहलादजी बता रहे थे, हम सब लोग जानते हैं, ये रमेशजी भी वहां कोटा में ही बड़े हुए हैं। करीब डेढ़ से दो लाख बच्चे पूरे हिन्दुस्तान से आकर वहां रह रहे हैं। वे अच्छी कोचिंग लेते है। अच्छी-अच्छी जगह उनका प्लेसमेंट भी होता है। वे देश का नाम भी कर रहे हैं। मैं उसके लिये कुछ नहीं कहना चाहता हूं। पर कई क्रिमिनल भी

(श्री प्रताप सिंह)

उनके साथ-साथ वहां पर आ जाते हैं। कई लोग, बड़े घरों के लड़के मौज-मस्ती के लिये वहां आ जाते हैं और कोटा का वातावरण खराब कर रहे हैं। इसलिये आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि उनका आइडेंटीफिकेशन और लैण्डलोर्ड जो उनको रखता है, उसका भी आइडेंटीफिकेशन आप निश्चित रूप से करवायें। अभी 08 तारीख की वहां पर इस प्रकार की घटना है। उसके लिये तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि वे स्वयं मेरे से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने पर्सनल पेन लिया। हालांकि उनको बजट के ऊपर प्रेस कांफ्रेंस करनी थी, दूसरे काम भी करने थे। पर उन्होंने सब छोड़कर, उसके लिये प्राथमिकता दी और उस काम को निपटाया, मुलजिमों को बरामद करवाया, उनको पकड़वाया। उसके लिये धन्यवाद देते हुए, फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोचिंग कहीं कोटा के लिये नासूर नहीं बन जाए, इसलिये समय रहते इसका निदान करना आवश्यक है। हर आठ दिन में एक मौत होती है, सुसाइड होती है। इन सब पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नरपतसिंहजी राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बजटिंग पैटर्न में परिवर्तन किया। 62 हजार करोड़ का उदय योजना का कर्ज, 24 हजार करोड़ के ब्याज की देनदारी, उसके बाद भी सभी विभागों में योजना के अनुसार राशि दी। कुछ डिपार्टमेंट्स में काफी कम दी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में इससे बैटर बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

प्लानिंग कमीशन 28 फरवरी, 1950 को लागू किया गया। उस समय के वित्त मंत्री, भारत सरकार, जॉन मथाई ने पार्लियामेंट में कहा, "It is necessary to undertake planned development in view of the existing programme of development and our existing schemes of development. The geographical and economic facts on which the existing programme is based no longer hold good and the

(श्री नरपत सिंह राजवी)

financial resources on which the existing programme is based are no longer valid." हमारे प्रधान मंत्रीजी ने, मेरे ख्याल से सबसे पहला निर्णय होगा कि प्लानिंग कमीशन को स्क्रेप किया और नीति आयोग का गठन किया।

इसी प्रकार फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन 22 नवम्बर, 1951 में संविधान के आर्टिकल 280 के आधार पर एस्टेब्लिश हुआ। पहले से आठवें वित्त आयोग तक केवल 28 प्रतिशत टैक्सेज का डिविजीबल पूल में हिस्सा होता था और वह भी आबादी के आधार पर। इस वर्तमान सरकार ने उसको बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया है। उसी आधार पर एनुअल प्लान, एनुअल बजट जो स्टेट्स का है, वह बढ़ा है। उसमें सबसे बड़ी देनदारी केन्द्र सरकार की है।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि सेण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स पहले दुनिया भर की थीं। अधिकांश सेण्ट्रल स्पांसर्ड स्कीम्स कम हो गयीं, बंद हो गयीं। उस आधार पर लगभग 08 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हमको केन्द्र से कम मिलने लगे। तो, यह तो बेलेंस हमको करना पड़ेगा। अनुमान था कि पैट्रो-कैमिकल में साढ़े ग्यारह-बारह हजार करोड़ की गत वर्ष, इस वर्ष, आय होगी। अंतरराष्ट्रीय पैट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत कम होने के कारण 08 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं हो पायेगी। इसीलिये डवलपमेंट का रास्ता, जो अब मुख्य मंत्रीजी ने अपनाया है, उससे बेहतर नहीं हो सकता था।

बजट में बार-बार सुराज की भी बात कही गयी है। अब सुराज की कल्पना अगर आप करेंगे तो सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट किये बिना सुराज सम्भव नहीं हो पायेगा। ज्यादा तो नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। लेकिन मूल बातें थोड़ी-थोड़ी कुछ विभागों की कह दें तो मेरे ख्याल से हाजमा भी ठीक रहेगा।

अभी केन्द्र में अंतरराज्यीय जल विवाद का स्थाई ट्रिब्युनल सैट-अप करने की बात आई। इन्दिरा गांधी कैनाल सिस्टम में सतलज, व्यास और रावी नदियों का जो हमारे को पानी मिल रहा था 52.52 प्रतिशत, इराडी ट्रिब्युनल तो अपना फाइनल अवार्ड दे चुका। उसमें 0.6 एम.ए.एफ. पानी हमारे को नहीं मिल रहा है। यहां पर प्रतिपक्ष के नेता बैठे हैं, मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर ने लोंगोवाला अकार्ड में पंजाब को उसको यूज करने की

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अनुमति दी। उस आधार पर अभी भी 0.6 एम.ए.एफ. पानी वे यूज कर रहे हैं। हालांकि हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप हो चुका, हमारे पानी की कमी होने की आवाज लगभग पिछले 20 वर्षों से जगह-जगह उठ रही है। 17 एम.ए.एफ. पानी उसका माना था, उस आधार पर 8.06 एम.ए.एफ. पानी हमारा हिस्सा बना। हिस्सा बनने के बाद, हमारा शेयर कम नहीं हुआ, लेकिन बी.बी.एम.बी. हमारे हाथ में नहीं है। पिछले दो वर्षों से वहां बी.बी.एम.बी. में हमारा मैम्बर भी नहीं है। उस आधार पर 49.49 प्रतिशत पानी ही हमको मिल रहा है और किसान यहां पर चिल्ला रहे हैं। किसानों को पानी की कमी हो रही है। जैसलमेर जिला, और जहां पर भी हम योजनाओं का पानी दे रहे हैं, उसमें बहुत बुरा इफेक्ट हुआ है। नहर मंत्रीजी आज नहीं हैं। लेकिन अगर उन्होंने या मुख्य मंत्रीजी ने पत्र लिखा हो तो निश्चित तौर पर सदन को अवगत कराना चाहिये। अस्थाई ट्रिब्युनल होने के बाद, 1978-79 में बी.बी.एम.बी. को केन्द्र सरकार के अपने हाथ में लेने का नोटिफिकेशन लगभग तैयार था। सिर्फ मंत्रीजी के हस्ताक्षर बाकी थे। अब तो कम से कम मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी जाकर प्रधान मंत्रीजी को इस बात का एहसास दिलायें कि यहां की लाखों-करोड़ों की जनता, जिसमें पीने के लिये पानी सीकर तक आ रहा है, कम से कम उनको लाभ मिले, पीने के पानी का एरिया हम एक्सपेंड कर सकें और जितना भी फेज-1 और फेज-2 में हमने जो सी.सी.ए. लिया, कल्चरेबल कमाण्ड एरिया, उसमें हम अच्छी तरह से सिंचित कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक वर्किंग है हमारी यू.डी.एच. डिपार्टमेंट की। मंत्रीजी शायद चैम्बर में बैठे हैं? यू.डी.एच. डिपार्टमेंट का और खास तौर पर जे.डी.ए. से संबंधित, क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र इसी में आता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्रीजी बैठे हैं, हंसी आएगी आपको, ऐसा उनके निर्णय पर। को-आपरेटिव अधिकारी की कारगुजारी जो जे.डी.ए. में पदस्थापित था, हमने पत्र लिखा। मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा। मुख्य मंत्रीजी को रिपोर्ट गयी और रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। उसमें बिलकुल सरासर झूठी बातें कही हैं और उस आधार पर एक कोई संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति थी। उसमें माना है कि ब्रहमकुमार और ओम प्रकाश पदाधिकारी नहीं थे जबकि रजिस्ट्रार ने जो इंक्वायरी अनियमितताओं की की

(श्री नरपत सिंह राजवी)

उसमें ओमदत्त शर्मा को उप मंत्री और ब्रह्मकुमार को कोषाध्यक्ष माना। यही नहीं, यह भी एक इंक्वायरी एक आर.ए.एस. अधिकारी द्वारा की गयी, आर.एस.चौहान और जिसके नाम से यह पट्टा देने की बात कही, वह तो 1995 में पट्टा ले रहा है सोसाइटी का, जबकि पहले दूसरा, जो प्रतिवादी है, जिसने दिया है, उसको 1982 में मिला है। बिजली का बिल आधार मानकर किया है कि साहब, यह उसका पजेशन है, आगे नाम-पट्टी लिखी हुई है, जबकि बिजली का बिल पड़ौसी के मकान का है। यह भी आपके डाकुमेंटेड प्रूफ हो सकता है। एक कोई सहायक अधिवक्ता है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, वह 2015 के बाद में सहायक अधिवक्ता का उसका एक्सटेंशन ही नहीं हुआ, उसकी एक एडवाइज देकर, इस प्रकार से अगर अधिकारी और जे.डी.ए. करेंगे तो यह सुराज आने का जो सपना है, वह सपना ही रह जाएगा।

एक और बात, 1999 में सूची दी थी और उस सूची में भी उनका नाम है, जिन्होंने किया है। आधार सिर्फ लिया है कि यह पावर आफ अटॉर्नी अनरजिस्टर्ड है। दोनों जिंदा हैं, दोनों सामने प्रस्तुत हुए लेकिन जिस प्रकार से यह अधिकारी तोड़-मरोड़ कर लेते हैं, उसकी कोई सानी नहीं है। और उदाहरण देना चाहूंगा। पृथ्वीराज नगर। पृथ्वी नगर, एक प्राइवेट कॉलोनी। जे.डी.ए. ने री-आर्गेनाइजेशन के नाम पर एप्रूव करने के बाद में जो सामूहिक सामाजिक सुविधा क्षेत्र था, उसके चार प्लाट अलॉट कर दिये किसी को। उसमें एक आर.ए.एस. अधिकारी भी है। उनको अलॉट करने का अधिकार नहीं है, ऑक्शन रूट है उनके पास लेकिन कर दिये और मुकदमा चल रहा है, चलता रहे, कॉलोनी वाले चिल्ला रहे हैं, चिल्लाता रहे।

एक है मदन बाड़ी का उदाहरण। मदन बाड़ी में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमि एक्वायर बाद में हुई, आर्गेनाइजेशन ने इससे पहले कन्वर्जन चार्जेज, पेरीफेरी चार्जेज, यह जमा करवा लिये और जे.डी.ए. में पैसा जमा होने के, कलक्ट्रेट में जमा होने के बाद वह जमीन सरकार के नाम से दर्ज होती है। सरकार के नाम से सिवायचक दर्ज हो गयी और 1982 में अवार्ड जारी, 1982 में एक्वायर कर लिया। यह प्रक्रिया का अंतर है। या तो इस सिस्टम में चेंज करें। इस सिस्टम में चेंज नहीं करेंगे तो यह अधिकारी इस प्रकार से यह कार्यवाही करते जाएंगे।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

एक और उदाहरण देना चाहता हूं रेवेन्यू मंत्री साहब, झोटवाड़ा का अभी अखबारों में पढ़ा होगा, झोटवाड़ा पुलिया के पास में कुछ तोड़ रहे थे, खसरा नम्बर 1063 की जमीन में। उसमें निर्माण हो गये, अनधिकृत निर्माण। कोई बात नहीं, अनधिकृत है तो तोड़ें लेकिन आखिरी दिन मेरे पास एक डाकुमेंट लेकर आए। एस.ओ. ने उसके ऊपर 1966 में मार्क लगाया कि अमुक-अमुक-अमुक की यह खातेदारी प्रोपर चैनल से, अधिकृत अधिकारी से घोषित करवायी जा सकती है क्योंकि सैटलमेंट वहां पर चल रहा था। उसके बाद में एस.ओ. का नोट खातेदारी अपने आप नहीं देता। उसने एक 1386 नाम की एक फाइल से एप्लाई किया। वाद दायर हुआ, खातेदारी उसको मिली और नामांतरण उसके नाम से हो गया। अब पटवारी उसका अमल-दरामद जमाबंदी में नहीं करे, तो मंत्री तो करेगा नहीं, सरकार खुद करेगी नहीं और उस आधार पर तोड़ने के लिए पहुंच गये। यह जयपुर और बड़े शहरों के आस-पास लगभग सभी जगह ऐसे म्युटेशन या ऐसे इंटरपॉलेशन अगर हों, तो उनकी जांच करके, बैठकर सुधारें।

जे.डी.सी. को मैंने एक लैटर लिखा, उसमें मैंने यह कहा है कि अगर किसी गलत अधिकारी ने आदेश दिया है और गलत इन्द्राज करवाया है तो उस आदेश को हटाने की भी एक प्रक्रिया है, रूल ऑफ लॉ है और उस आधार पर नामांतरण आप हटवाइये, उसके अगेंस्ट में अपील करिए। आपके रिकार्ड में सिर्फ सिवायचक दर्ज है और हाई कोर्ट का प्रेशर है, उसके आधार पर किसी का जो अधिकार बना हुआ है कहीं एक्सटिंग्विश नहीं होगा इसमें हाउस प्रोटेक्ट उसको करे। यह टेनेंसी एक्ट के टाइम में जब बना था, उस समय की बहस अगर आप उठाकर देखेंगे तो यह बातें सब सुस्पष्ट हो जाएंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्णय लेना, उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्रीजी को हैल्थ का चार्ज भी था। 15 जनवरी, 15 को, 29 जनवरी को 7 पी.एच.सीज., 23 पी.एच.सीज. जयपुर में हुईं, राशि भी आ गयी लेकिन उन 23 में से अधिकांश पी.एच.सीज. में आज तक जे.डी.ए. अलॉटमेंट का कागज आगे नहीं बढ़ा है। उसमें से एक दो का तो यहां तक उत्तर आया है, यह विधान सभा का प्रश्न, मैंने अतारांकित प्रश्न पूछा था, उसमें यह अमुक

(श्री नरपत सिंह राजवी)

समाज को आबंटन कर दी गयी है, आबंटन नहीं की है, आबंटन का पट्टा आज भी अगर हो तो वह सदन के पटल पर रख सकते हैं। पी.एच.सीज. के लिए कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह रिजर्व की है और रिजर्वेशन में रिजव्र्ड फॉर हैल्थ, चिकित्सा के लिए सुरक्षित रखी है। तो इसमें विलंब नहीं होना चाहिए।

पी.एच.ई.डी. की टंकियां, अगर आपको पीने का पानी उपलब्ध करवाना है तो टंकियों का निर्माण होगा। अभी तक तो धीरे-धीरे, एक-एक, दो-दो, का निकल रहा है लेकिन अभी तक नहीं निकल पाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा के बाद में गृह विभाग के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। आनन्दपाल का नाम लेते ही तो हमारे गृह मंत्रीजी को थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है। यह भूत हो गया। मैं तो एक दूसरी चीज पूछना चाहता हूं। जिसने ऑफेंस किया है, उसको पकड़ें, जो भी नियमों में, कानून में सज़ा होगी, वह सज़ा दें। लेकिन मैंने एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आया 24.07.2014 को, बंदी जयप्रकाश से हनुमान जाखड़ और ओम प्रकाश ने मुलाकात की। उस मुलाकात को रिकार्ड में नहीं लिया और मुलाकात के दौरान पपीते में काट कर पिस्तौल रखी और पपीता थोड़ा कच्चा होता है तो उससे जो दूध निकलता है उससे एढेसिवनेस वापस आ जाती है। बिना प्रोपर चैक किये वहां पर पहुंच गयी और पहुंचने के बाद में एक घटना घटी, फायर हुआ। एक कैदी मर गया बानूड़ा, बलवीर और केस 131/14 बीछवाल थाने में दर्ज हो गया।

सबसे पहले तो मैं यह कहता हूं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई स्थान है तो जेल है, जहां पर हथियार आरक्षी के अलावा और दूसरे के पास नहीं होगा, अंदर होगा उसके पास भी नहीं होगा और उसके पास हथियार पहुंचा यह ऑफेंस है लेकिन हथियार पहुंचाने वाला, जो मारा गया है, जिसके विरुद्ध मारा गया है, उसको भी मुलजिम बनाया। एफ.आई.आर. एक दर्ज की घटना दो हैं। फायर जिसको हुआ है, एक तो मर गया, बाकी दो इंजर्ड हुए हैं और जिस पर फायर हुआ है या मरा है, उनको भी एक्यूज्ड में रखा है। वह एक्यूज्ड कैसे हुए, क्योंकि दो जो फायर करने वाले थे, उसने उनको पकड़ा, उनका सिर आपस में भिड़ाया, उससे उनकी मौत हुई। उससे मौत हुई, तो

(श्री नरपत सिंह राजवी)

यह एफ.आई.आर. दूसरी बननी चाहिये थी। यह दूसरी एफ.आई.आर. होती तो निश्चित सैल्फ डिफेंस में अगर उसने काम किया है, जिसको अधिकार भारत के संविधान ने दिया है, आई.पी.सी. ने दिया है, एविडेंस ने दिया है, लेकिन यह नहीं किया।

यहां और निवेदन करना चाहूंगा कि एक जांच आई.ए.एस. अधिकारी से करवाई गयी थी, वह सदन के पटल पर आज तक भी नहीं रखी गयी। क्यों नहीं रखी गयी, क्योंकि जेल के वरिष्ठ अधिकारियों का सीधा जेलर लेवल से सम्पर्क था, वह कॉल डिटेल निकाली तो ली गयी, लेकिन अभियुक्तों का जेल अधिकारियों से सम्पर्क है, उसके ऊपर अध्ययन हो रहा है, जेल अधिकारियों के आधार पर नहीं। जेल अधिकारी को जिसने फोन किया, उस पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा? मुलाकात सीधी करा दी जाए और जेल सुपरिटेंडेंट को भी उसकी इत्तला नहीं थी। इसमें दोषी हम जांच करने वाले को भी बराबर का मानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक अनूपगढ़ का मसला मैं सामने रखता हूं। एक 25 साल का जवान वीरेन्द्र सिंह, उसके माता-पिता मूलत: अनूपगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन गंगानगर में रहते थे, उसका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। शव प्राप्त होने के बाद नामजद व्यक्तियों को जिन पर शक था, घरवालों ने कहा, उसके पिता ने कहा परन्तु एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गयी और यहां तक तो फिर भी सहन हो जाता, लेकिन मेडिको-लीगल केस में अगर कोई बॉडी मिलती है या मेडिको-लीगल केस कमिट होता है, तो पोस्टमार्टम के बिना शव नहीं दिया जाता। इस मामले में पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया और इसलिये नहीं किया गया कि जो वरिष्ठ अधिकारी, आनन्दपाल वाले मामले में शक के दायरे में है, उसी अधिकारी का रिश्तेदार इस मर्डर के अंदर था। इस प्रकार अधिकारी अगर इंटरफियर करेगा तो पुलिस प्रशासन सही नहीं चल पायेगा।

जयपुर में क्या स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे तो कोई छिपी हुई नहीं है, लेकिन कमिश्नरेट के जस्ट किनारे पर आप हैं। मेरे विद्याधर नगर थाने में 2009 में एक केस दर्ज हुआ। फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उन दो बिजनैसमैन का दो महीने तक जेल में रहना पड़ा। कोर्ट ने स्ट्रीकचर पारित

(श्री नरपत सिंह राजवी)

किये हैं कि पुलिस ने जान-बूझकर हरेसमेंट करने के लिये इनको अरेस्ट किया और एक ऐसा सीन बनाया जैसे कि एक फर्जी मुठभेड़ हो। अब फर्जी मुठभेड़ की स्थिति से तो हमारे गृह मंत्रीजी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इन पर भी एक इल्जाम लगा था, वह कोर्ट ही बता सकती है ऐसा एक बार इल्जाम लगने के बाद।

एक और मामला हुआ। वह नायला थाने का है। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): फिर आप गृह विभाग की डिमांड पर क्या बोलोगे?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उस समय पंचायती राज पर बोल लूंगा। ...(व्यवधान)...

कानोता थाने में एक सी.आई. जो यहां पर थे, वहां पर पहुंच गये और एक सीमा ज्ञान हो रहा था, सीमा ज्ञान थाने के आवेदन पर तहसीलदार ने आदेश दिये। सीमा ज्ञान हो रहा, उस खसरे का सह-खातेदार एक बार पहुंच गया गांव से निकलते ही, कि इतने लोग काहे को खड़े हैं। उसने पूछा तो पूछने पर न केवल उसको पीटा, बल्कि उसको अंदर भी ठोक दिया, उसको 151 में बंद कर दिया। मुझे जानकारी मिली तो मैंने कमिश्नर को कहा। उसकी जांच हुई और उस जांच में यह लिखा है, "थानाधिकारी का उक्त कृत्य थानाधिकारी की निहित सीमाओं से कुछ परे होकर मानवीय संवेदनाओं एवं सामान्यजन की प्रतिष्ठा के विपरीत है। उक्त कृत्य से पुलिस हाजा में पुलिस की छवि पर विपरीत प्रभाव पडा है।" लेकिन एक्शन क्या हुआ? उसको ए.पी.ओ. कर दिया। इस आधार पर अगर चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई सुराग आ पाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यहां पर है सुराग। इसी जगह पर है सुराग।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। एक लाख कनेक्शन और मिलने वाले हैं। वह काम तो खेती में ही आयेंगे। टैक्नोलाजी में जो अपग्रेडेशन हो रहा है, आपको जानकारी है क्या? होल टाइम मेगनेट टैक्नोलाजी से पम्प आधी बिजली खर्च

(श्री नरपत सिंह राजवी)

करके लगभग उतना ही पानी देते हैं। आपको जानकारी नहीं, कृषि मंत्रीजी को नहीं और पावर मिनिस्टर को नहीं, तो कौन लेकर आएगा। मैं कहता हूं कि आप जाएं, आपको अध्ययन करवाते हैं। स्टडी करना चाहिये, क्योंकि अब पावर ज्यादा कंज्यूम करने वाला सिस्टम नहीं चलेगा।

यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि टी एण्ड डी लोसेज पर खूब एग्जामिनेशन हुए। पी.यू.सी. में मैंने भी कई बार एग्जामिन किया है, लेकिन पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर साहब, पावर फैक्टर क्या होता है, आपको जानकारी है क्या? पावर फैक्टर का अध्ययन अगर आप कर लेंगे, सब-स्टेशन में पावर फैक्टर क्या है, सब-स्टेशन के अधिकारियों को स्वयं को पता नहीं है और 0.9 की फ्रिक्वेंसी से अगर पावर फैक्टर कम है तो सब-स्टेशन भी दोषी है, तो उपभोक्ता भी दोषी है। यह पावर फैक्टर अगर कंडक्टिव पावर का यूज करना शुरू कर देंगे तो टी एण्ड डी लोसेज लगभग आधे पर आ जाएंगे और आधी वास्तव में चोरी होगी। लेकिन जिस प्रकार से यह चला रहे हैं, लादूरामजी तो स्वयं हमारे यहां पर विधायक हैं, वह जानते हैं लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। सिस्टम में आप परिवर्तन करेंगे तो जनता भी खुश होगी, सिस्टम इम्प्रूवमेंट भी होगा, सुराज भी यहां पर आयेगा।

आप लोगों ने मुझे सुना इसके लिये तो आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री महेन्द्रजीत सिंहजी।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, आपने मुझे बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

वाद-विवाद के ऊपर पक्ष-विपक्ष के हमारे सदस्य अपनी-अपनी सरकार, अपनी-अपनी पार्टी और अपनी-अपनी नीतियों पर अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदयजी, राज्य सरकार द्वारा 2016-17 की तुलना में 1 हजार 925 करोड़ की बढ़ोतरी करते हुए एक लाख 81 हजार 518 का बजट पेश किया है। परन्तु विभिन्न विभाग ऐसे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। बजट में पिछले वर्ष आबंटित बजट में से भी आगामी 2017-18 में कटौती

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

कर दी गयी है। कुछ विभागों की स्थिति इस प्रकार है - यहां पर हमारे पंचायत राज मंत्रीजी विराजमान है, 2016-17 का मूल बजट 5 हजार 991 करोड़ का था और 2016-17 में इसको घटाकर 4 हजार 453 करोड़ कर दिया। इसमें 1538 करोड़ का अन्तर आ गया। अभी माननीय सदस्य राजवी साहब भी अपनी बात कह रहे थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह आंकड़ा आप कहां से ले आये? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट एट ए ग्लांस आपने दिया है, उसमें पेज नम्बर एक पर जो आंकड़ा बोल रहा है उसमें ग्रामीण विकास पर है 10 हजार 685 करोड़ रुपये तो आप आधे कम क्यों कर रहे हो?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): आप आराम से देख लेना, मेरे पास भी आंकड़े हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, रिकार्ड पर सही बात जाए, इतना कम मत करो।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): इसी तरह से 2016-17 के मूल बजट में से 1227 करोड़ कम हुए हैं और 2016-17 में यह करीबन 21 प्रतिशत कम है।

इसी तरह हमारे कृषि मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, 2016-17 में बजट था 3 हजार 634 करोड़ और यह घटाकर अब रह गया 3 हजार 71 करोड़। इसमें 563 करोड़ का यहां पर भी कम हुआ है। वर्ष 2017-18 के लिये 3 हजार 156 करोड़ रुपया, जोकि 2016-17 के मूल बजट से 478 करोड़ रुपया कम है। इस प्रकार कृषि और ग्रामीण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर भी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): रिकार्ड पर गलत बात जा रही हैं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भी रिकार्ड है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): देख लो न।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह बजट एट ग्लांस ही देख लो, इसमें कृषि एवं सम्बन्धित सेवा, उपाध्यक्ष महोदय, यह है 4483 करोड़ रुपये।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मेरे पास भी बजट है। मुझे बोलने दीजिए, होगा तो ठीक हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वो कोई पढ़ेगा तो इतने विद्वान आदमी हैं ...(व्यवधान)...

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): विद्वान तो नहीं हूं लेकिन कुछ पढ़ा-लिखा जरूर हूं। जब मैं बोलता हूं तो सदन को तकलीफ जरूर होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): चलो, ठीक है। .... व्यवधान.....

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): इसी तरह से पी.डब्ल्यू.डी. के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। 2016-17 में मूल बजट था 5690 करोड़ रुपये उसको घटा कर कर दिया आर.ई. के अन्दर 4201 करोड़ और इसी तरह से इसका अन्तर आता है 1489 करोड़। 2017-18 के लिए प्रस्तावित है 6657 करोड़ और यह अब 2016-17 के संशोधित अनुमान में आगामी का पी.डब्ल्यू.डी. का बजट 58 प्रतिशत अधिक बताया गया है। बजट आंकड़ों से स्पष्ट है कि मूल बजट से 26 प्रतिशत बजट कम कर के उसमें बढ़ोतरी की गयी है।

क्योंकि मैं टी.एस.पी. क्षेत्र से आता हूं और, माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, मैं खुद भी इस विभाग का मंत्री रहा हूं लेकिन आज मैं इस सदन का सदस्य हूं ...(व्यवधान)...

भैया, इसकी जांच करा लो। यह सदन में कह रहा हूं, दस बार कह चुका हूं और यहीं, अभी तुरन्त इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के आरोप लगाने की? माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, यह बात ठीक नहीं है।

मैं टी.ए.डी. के बारे में कहना चाहता हूं। जहां पर माननीय मुख्यमंत्रीजी ने अपने पहले बजट में यह बात कही कि सबसे ज्यादा टी.ए.डी. या टी.एस.पी. क्षेत्र के विधायक कांग्रेस से नहीं जीत कर भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आ गये, लेकिन मैं बजट की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं,

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

2016-17 में हमारा बजट था 602 करोड़ रुपये, उसको आर.ई. में कर दिया 562 और इसमें 40 करोड़ रुपये का अन्तर आ गया। 2017-18 का प्रस्तावित बजट है 596 करोड़ रुपया जो कि 2016-17 के मूल बजट से भी कम है।

यहां पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे टाइम पर, क्योंकि वहां पर गरीब बच्चे रहते हैं, गांवों में रहते हैं, अभावों में रहते हैं इसलिए वहां छात्रावास की आवश्यकता होती है, हमने एक-मुश्त 85 छात्रावास की स्वीकृति जारी की, जबकि वर्तमान सरकार में अब तक मात्र तीस छात्रावास स्वीकृत किये जा चुके हैं और चौथा बजट पेश है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, राजस्थान सरकार और भारत सरकार का नियम है, स्टेट का कुल बजट और भारत सरकार का जो बजट है उन दोनों बजटों का 13 परसेंट पैसा टी.एस.पी. क्षेत्र में सरकार को अनिवार्य रूप से खर्च करना है। मैं इस वक्त यह भी कहना चाहूंगा केन्द्र सरकार से पैसा प्राप्त होता है टी.ए.डी. को, 29 हजार 9 सौ 11 करोड़ राज्य सरकार का 1 लाख 41 हजार 428, उसका योग बनता है 1 करोड़ 71 हजार 340 करोड़ और अगर हम इसका 13 प्रतिशत पैसा मानते हैं तो 22 हजार 274 करोड़ रुपया हमारा टी.ए.डी. का बनता है। इसी तरह से 2017-18 में हम देखते हैं तो केन्द्र सरकार से हमको प्राप्त हो रहा है 26 हजार 770 करोड़, राज्य सरकार का पैसा हमको प्राप्त होता है 1 लाख 55 हजार 45 करोड़ और यह कुल पैसा बनता है 1 लाख 81 हजार 815 करोड़, अगर इसका 13 प्रतिशत पैसा टी.एस.पी. क्षेत्र में खर्च करती है, सरकार की नीयत साफ है तो यह पैसा बनता है 23 सौ करोड़ के आसपास।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी को, हमारे तमाम मंत्रीगण को मैं निवेदन करना चाहूंगा टी.एस.पी. क्षेत्र का निर्माण ही इसलिए हुआ कि वहां पर लोग अभावों में रह रहे हैं, ठीक से इनके सड़क नहीं है, बिजली नहीं है और इसीलिए बजट के अन्दर इसका प्रावधान किया है। जब टी.एस.पी. क्षेत्र का 13 परसेंट पैसा बनता है, वर्तमान समय में एक रुपया भी इसमें नहीं मिला है और उसका आप कहोगे कि आप कैसे कह रहे हो कि नहीं मिला?

मैं बताना चाहूंगा जिस दिन माननीय मुख्यमंत्रीजी ने बजट के ऊपर

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

अपनी बात रखी और पूरा सदन यहां पर पूरी तरह से यह आशा लेकर बैठा हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्रीजी हमको अच्छा बजट देने वाले हैं चौथा बजट है, पांचवें बजट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो नाम मात्र का बजट है, कोई टेण्डर नहीं कर पायेंगे, कुछ भी नहीं कर पायेंगे और अगला चुनाव हो जाएगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय जी, मुझे कहते हुए मन में बहुत दुख है जब टी.एस.पी. क्षेत्र में 13 परसेंट फंड फ्लो का इतना पैसा पड़ा हुआ है, हमारी जन कल्याण नीति यहां पर लागू है, इसके अलावा भी मुख्यमंत्री हमको पैसा दे सकते थे, दो सड़कें दी हैं उदयपुर से सलूम्बर और डूंगरपुर से चौरासी। इसके अलावा उस टी.एस.पी. क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)...

मैडम, पूरे टी.एस.पी. की बात कर रहा हूं मैं, यह बात छोड़ो यहां पर। पूरे टी.एस.पी. में 25 एम.एल.ए. के साथ जीत कर आ रहे हो, उसकी बात कर रहा हूं।

अब यह महसूस करता हूं कि जब तक इस टी.एस.पी. क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण नहीं होगा तब तक इस फंड फ्लो के ऊपर सम्बन्धित डिपार्टमेंट के ऊपर कोई नकेल नहीं रखेगा। इसीलिए चाहे सरकार हमारी हो चाहे सरकार दूसरी पार्टी की हो, जब तक ट्राइबल कमिश्नर की पोस्ट सेपरेट नहीं होगी, इन तमाम बजट के ऊपर इसकी मानीटरिंग नहीं होगी, तब तक उस क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता और न ही होने वाला है। इसलिए मैं पुरजोर मांग करता हूं। ट्राइबल कमिश्नर और डिवीजनल कमिश्नर, दोनों के ऊपर एक अधिकारी बैठा हुआ है, जब एक अधिकारी बैठा हुआ है तो वह अपने डिवीजनल कमिश्नर का काम करेगा या वो कभी शाहबाद-किशनगढ़ जाएगा, कभी अलवर जाएगा, कभी भरतपुर जाएगा। वो कभी जाते नहीं, कभी देखते नहीं हैं इसलिए हमारे साथ में एक तरह का बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।

पहली बार, आदिवासी बच्चे अच्छे नम्बर ला कर पढ़ाई कर रहे थे, उनको इनाम बंट रहा था और मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया कि जब आदिवासी क्षेत्र में इतने बड़े पढ़-लिख कर आगे आ रहे हैं तो ट्राइबल की अलग से यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और बजट में यह विश्वविद्यालय हुआ। हमने उदयपुर में बनाने की कोशिश की। अब वर्तमान सरकार में उसको

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

बांसवाड़ा ले गये और यह करते-करते पांच साल हो गये, पांच साल में वो विश्वविद्यालय कहां बनेगा? अब कह रहे हैं कि जो वर्तमान में कालेज है उसमें बनेगा, तो वर्तमान कालेज कहां जाएगी? इसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मात्र कितना पैसा दिया है, दस करोड़। दस करोड़ में मैं ऐसा मानता हूं कि विश्वविद्यालय आज भी नहीं बने, कभी नहीं बने और मैं कह सकता हूं कि आपकी सरकार में तो यह बनेगा ही नहीं। मैं कह सकता हूं कि आदिवासी क्षेत्र ने आपके ऊपर विश्वास किया था जनादेश दिया था, इसका हम को यह तोहफा मिला है? या मैं क्या कह सकता हूं?

इसी तरह से हमारी सरकार के समय में टी.एस.पी. का एक अलग से कैडर बनाने की बात थी, हमने कैडर बना दिया था और कैडर बना कर वो सरकार चली गयी। वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी थी, हम गरीबों के प्रति एक मन में भावना थी, तो जितने पद हॉस्टल के लिए, स्कूल के लिए जो अध्यापक की आवश्यकता थी, यह तमाम पदों को आपको तुरन्त प्रभाव से भरना था लेकिन भरा नहीं। आपने कह दिया, उधर से उधर, उधर से लेकर इन पदों को आपने भर दिया।

इसी तरह से पहली बार ऐसा लगा था कि आदिवासी अपनी रेल को देखेगा और रेल के साथ ही बांसवाड़ा में तीन पावर प्लांट हो रहे थे, उसका कोयला भी लाना था, मशीन भी लानी थी। बजट के अन्दर घोषणा हुई, घोषणा होने के बाद में राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को पैसा दिया और रेल बांसवाड़ा में आ रही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तीन पावर प्लांट वहां पर होने थे, वो तीन पावर प्लांट की जमीन एक्वायर कर ली, किसानों को आधा-अधूरा मुआवजा दे दिया, आधा-अधूरा मुआवजा दिया नहीं है, जब तक पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक किसान दूसरी जगह जाकर स्थापित होने वाला नहीं है। तो, आखिर में यह सरकार क्या चाहती है? पावर प्लांट भी नहीं लगा रहे हैं, रेल भी नहीं ला रहे हैं, किसानों को मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, विस्थापित के लिए जमीन का भी प्रबंध नहीं कर रहे हैं।

कहने के लिए तो बहुत अच्छी बातें हैं, विजन भी 20.20 है, संकल्प यात्रा भी आयी है और सब शानदार बातें करी लेकिन हमको तो कोई बात

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)
समझ में आती नहीं है, भाई। ...(व्यवधान)...

नहीं। वो तो, भैया, मेरी भी उम्र तो आयी है। आपकी भी आयी होगी, मेरी भी आयी है। आपकी भी आ गयी है।

मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदयजी, कहने के लिए तो खूब कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने भी जोरदार काम किया और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, इसको हम स्वीकार करते हैं लेकिन जो माही का काम हुआ है, माही हमारे वागड़ क्षेत्र की जीवन रेखा है। सोम कमला हमारी जीवन रेखा है। जाखम हमारी जीवन रेखा है। जयसमंद हमारी जीवन रेखा है। लेकिन इस बजट में एक रुपया तो हमें कहीं से मिलता। एक रुपया नहीं, सिंगल पाई नहीं मिला। आज हमारी स्थिति बहुत खराब हो गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ हमारे साथी कह रहे थे, वितरण व्यवस्था में पोस मशीन और कई सारी बातें हुईं। मैं गांव का आदिवासी हूं। मैं जितना समझता हूं शायद ही कोई उतना समझता होगा। वह गरीब राशन कार्ड लेकर के पीडीएस का गेहूं लेने के लिए गांव में जाता है, तो पोस मशीन में अंगूठा लगा रहा है। डीलर कह रहा है कि आपकी तो रेखाएं ही नहीं आ रही हैं। आपको गेहूं मिल नहीं सकता। वह जैसे ही अंगूठा लगाता है तो उसको क्या पता कि मशीन बोली कि नहीं बोली। उदयपुर में एक ऐसी स्थिति हुई, जो कि टीवी में भी आई कि पोस मशीन लेकर के आदमी जंगल में एक पेड़ पर चढ़ रहा है और पेड़ पर चढ़ाकर के उसका अंगूठा लगवा रहे हैं। वहां कहीं नैट पकड़ रहा है। अब उस पेड़ पर आदमी कितने दिन तक चढ़ेगा? जो जीवित आदमी खड़ा है, कार्ड लेकर के खड़ा है, भारत सरकार ने उसको अधिकार दिया है। अगर अंगूठा आएगा तो उसको गेहूं मिलेगा। अंगूठा नहीं आएगा तो गेहूं नहीं मिलेगा, तो क्या वह गरीब भूखे मर जाएं? मैं समझता हूं कि सरकार, मैडम इसका कोई निराकरण करेंगी। इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप यह बताएं कि कौनसे पेड़ पर चढ़ा आदमी?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): बता देंगे। सरकार का रिकार्ड है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कौनसी ग्राम पंचायत में, कौनसी पंचायत समिति में और कौनसा पेड़?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): रिकार्ड है, भाई, रिकार्ड है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बबूल का पेड़ था? आम का पेड़ था? इमली का पेड़ था? कौनसी ग्राम पंचायत थी?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): हमारे वहां इमली तो है नहीं? वहां तो सागवान है। पीपल और बड़ का पेड़ है वहां पर। हमारे वहां इमली नहीं है।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि साड़ी, कंबल दे दिया, पेंशन दे दिया, रेवड़ियां बांट दीं। अपने घर पर जाकर के अपने माता-पिता को पूछना। आज मैं भी लाट साहब बन गया तो यहां पर अच्छी तरह से कपड़े पहनकर के खड़ा हूं। लेकिन गांव में मेरे माता-पिता आज भी उस पेंशन के लिए चक्कर काट रहे हैं। आप बात मत करो, प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता को लाइन में खड़ा कर दिया तो वह गलत है क्या?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): वैसे तो मैं आपको टोकना नहीं चाहता था। लेकिन आपने पेंशन बांटी, बजट का प्रोविजन तो कर देते। आज 3,600 करोड़ का प्रोविजन करके सबको पहुंच रही है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय मंत्री जी, वह बाद की बात है। मैं किसी की बुराई की बात नहीं करता। मैं तो पेड़ पर आदमी चढ़ने को मजबूर हो गया, वह बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आप पेंशन की बात कर रहे हो? मैं इस सदन में मैडम को हाथ जोड़ता हूं, निवेदन करता हूं कि कोई और लैम्प्स खोल देते, पैक्स खोल देते, नहीं है तो अंगूठा लगाकर के डाकिया को ही दिलवा देते। लेकिन हमारा बुजुर्ग 25 किलोमीटर तक, जिसकी उम्र 70-75 साल है, वह गाड़ी में धक्के खाता हुआ जा रहा है। बैंक मैनेजर उसको धक्के देकर के निकाल देता है। मेरी खुद की पंचायत में एक औरत फांसी खाकर मर गयी,

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। क्या यह गलत है? हमको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आप वहां हो, कल हम वहां पर होंगे और आप यहां पर होंगे। आप इसको छोड़िए, तो क्या हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे? सच्चाई को स्वीकार करो। प्रजातंत्र में सब परिवर्तन हुए हैं। प्रजातंत्र की सच्चाई को स्वीकार करो। ऐसी कोई बातें करने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज दवाइयों की स्थिति के बारे में मैं कह रहा हूं। एक समय वह था कि आदमी हजार रुपये लेकर के हॉस्पिटल जाता था और वहां एक रुपया नहीं निकालता था। उसकी जांचें भी मुफ्त हो जाती थीं। उसका घर तक वापिस जाने का प्रबंध हो जाता था। हमने एकमुश्त 200 गाड़ियों की व्यवस्था की थी। आप कम से कम उसके टायर तो लगा दो। उसके टायर तक नहीं लगा पाए। क्या बात कर रहे हैं?

मैं एस.टी. के छात्रों की बात कर रहा हूं। हमारे मंत्रीजी हैं, अच्छी बात है। लेकिन कई लड़के आज भी छात्रवृत्ति के बिना घूम रहे हैं। भारत सरकार से छात्रवृति नहीं आ रही है हमारी। इसकी वजह से कई बच्चे अपनी पढ़ाई को भी छोड़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी नरेगा के बारे में खड्ड़े खोदने की बात कर रहे थे। आज इस धरती पर गुलाब सिंह जी शक्तावत नहीं हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इस सदन में रिकार्ड पर तो हम कम से कम सही चीज बोलें। आपके समय स्कालरशिप की क्या स्थिति थी? जब आप सरकार छोड़कर गये तब 4 साल की पैंडेंसी थी।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): तो अच्छा किया ना। मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उसके बाद में आज की तारीख में सबको पेंशन पहुंच रही है। उसको पूरा क्लिक करते जा रहे हैं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): कुछ तो मंत्री जी, पैंडिंग

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

होगी। आप कमिटमेंट कर दो कि पैंडिंग नहीं है। जिस दिन आप करेंगे उस दिन कह दूंगा।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप राजनीति करो, लेकिन जो चीज एप्रिशिएट करनी चाहिए, वह तो बोलो।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नरेगा के बारे में अपनी कुछ बात कहना चाहूंगा। गुलाब सिंह जी शक्तावत जब-जब भी गृह मंत्री रहे, तब अकाल के काम उनके पास ही रहते थे। जैसे अभी कटारिया साहब के पास हैं। क्या स्थिति होती थी? आदमी लेबर के रूप में काम करता था। वह दिन भर बैठता था और उसको काम नहीं मिलता था। जिस दिन से नरेगा आया है, इस राजस्थान में 45 लाख लोगों ने लेबर के रूप में काम किया है। मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, राजस्थान की प्रगति अभी ठीक है। लेकिन 45 लाख अपने आपमें मायने रखता है। इससे व्यक्ति की रोटी का इंतजाम हो रहा है। आप उन 45 लाख गरीबों के साथ में मजाक मत करो। यह हमारे लिए जीवन है। उससे हमारे जीवन स्तर में सुधार आया है। इससे पानी के टांके बने हैं। नरेगा में कुओं का निर्माण हुआ है। खालों का निर्माण हुआ है। तलाइयों का निर्माण हुआ है। इससे पानी रुका है और जल स्तर में वृद्धि हुई है। हमको अच्छी जिंदगी जीने का एक अवसर मिला है, लेकिन इसके अंदर भुगतान नहीं हो रहे हैं। अभी थोड़ा-बहुत ठीक हुआ है। माननीय मंत्री जी, अगर 8-8 महीने नरेगा का भुगतान नहीं होगा, फिर तो धन्यवाद आपको। मैं इस संबंध में ज्यादा कोई बात कहना उचित नहीं समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे टाइम में नरेगा कर्मियों के भर्ती के लिए हमने प्रयास किया, 7 हजार भर्ती किए। बाकी रहे वो कोर्ट में चले गये। अब शायद कोर्ट का हो गया है। मैं उम्मीद करूंगा माननीय मंत्रीजी, आप इन गरीबों के ऊपर ध्यान देकर इनका कुछ भला कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में और बात बढ़ा रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मानगढ़ भी आई हैं। माननीय मुख्यमंत्रीजी बेणेश्वर भी आई हैं। हमारे टाइम में 5-5 करोड़ रुपया विकास के लिए दे दिया और आपने उन पैसों को निरस्त कर दिया। एक ओर तो हम कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

धार्मिक प्रवृत्ति के कोई लोग नहीं हैं। मानगढ़ में तो देश की आजादी के लिए लोग शहीद हो गये थे। क्या उनका पैसा निरस्त करते हुए भी आपके मन में कोई हिचक नहीं हुई? हजारों साल पहले घोटिया में पांडव आए थे और इसके प्रमाण हैं कि वहां रहे हैं। उसका भी आपने पैसा निरस्त कर दिया। साढ़े तीन सौ साल पहले मावजी महाराज जैसे संत बेणेश्वर में आए थे, उन्होंने उस जमाने में आने वाला जमाना कैसा होगा, उसकी कल्पना की है। उन्होंने लिखा है इस धरती पर एक दिन ऐसा आएगा कि पानी नाप से पीना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि बिना रोड के गाड़ी चलेगी, तो हवाई जहाज चल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि तार से दिया जलेगा तो आज तार से दिए जल रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि धरती लोहे की तरह से तप जाएगी। इस तरह की बातें बड़े-बड़े ग्रंथों में लिखी हैं। उस पर मैडम ने दस्तखत किए हैं। राष्ट्रपतिजी ने दस्तखत किए हैं। उसका भी पैसा आपने निरस्त कर दिया। ऋषभदेव का पैसा भी आपने निरस्त कर दिया। आप आखिर में हमारे से क्या चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी जंगल में रहता है। वह जंगल का स्वामी है। इसी कारण से भारत सरकार 'फोरेस्ट राइट एक्ट' लाई थी। उस एक्ट में उस आदमी को जो कि जंगल में बैठा था, वहां रहने का, स्वामित्व का पट्टा मिला। लेकिन 4 साल हो गये, इस फोरेस्ट राइट एक्ट में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। लोग जंगल में बैठे हुए हैं। वह आज भी घूम रहे हैं। कल सरकार इस पर बैन लगा देगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वह तो भगवान जाने।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पेसा एक्ट (pesa act) आया। पेसा एक्ट के साथ में संविधान की अनुसूची 241 (1) के अंदर जो प्रावधान ट्राइबल के लिए किए हुए हैं, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अभी हमारे राजवी जी कुछ एनकाउंटर्स के मामले में कह रहे थे। इस पेसा एक्ट में कानून बना हुआ है कि गांव में कोई लड़ाई, झगड़ा हो गया, कोई छोटी-मोटी बात हो गयी तो पेसा एक्ट के आर्टिकल 244 (1) के अंदर एक प्रावधान किया हुआ है कि उस गांव में पुलिस जा ही नहीं सकती है। उसको मुखिया के पास में जाना पड़ेगा। ग्राम सभा के पास में जाना पड़ेगा। ग्राम

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

सभा उस आदमी को पकड़कर के अनुमति देगी कि उसको अरेस्ट करके ले जाओ। अगर कोई बड़ा जुर्म किया है तो उसको सीधा पुलिस पकड़ सकती है। लेकिन आए दिन पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जंगलों के अंदर खदेड़े जा रहे हैं। आज यह स्थिति वहां पर हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राठौड़ साहब से एक निवेदन कर रहा हूं कि पंचायतों का आपने पुनर्गठन कर दिया। पंचायत समिति को तो आपने आधा-अधूरा पैसा दे दिया। लेकिन पंचायतों का नरेगा से बनवा रहे हैं। जब नरेगा से पंचायतों को बनवा रहे हो तो फिर आपने पुनर्गठन क्यों किया? आपका चौथा बजट आ गया और उसके अंदर प्रावधान क्यों नहीं किया? क्या पंचायतों को हम नरेगा से बनवाएंगे? नरेगा से बनेंगे तो कब तक बनेंगे ? लेकिन इस संबंध में भी आप कोई बात कह नहीं रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी मित्रों की जो स्थिति है, हमको कह रहे थे कि यह तो कांग्रेस के लोग हैं। हमने कोशिश भी की थी। लेकिन कोई प्रक्रिया ऐसी आ गयी जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए। अब आप क्या कर रहे हो? कितने विद्यार्थी मित्र आत्महत्या करके मर गये?

(15.00 बजे)

या तो यह तय हो जाना चाहिए कि हम विद्यार्थी मित्र नहीं लगाएंगे, तो व्यक्ति कहीं और जाकर काम करे, या लगाना चाहते हैं तो राठौड़ साहब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए कोई कानून बन जाना चाहिए। कब तक वह आदमी सड़क पर बैठा रहेगा? आज धरने प्रदर्शन करके बैठा हुआ है, लेकिन इस ओर भी कोई विशेष बात हो नहीं रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरकार हमारे प्रति, एससी, एसटी के प्रति संवेदनशील है तो हमको अलग से कोई भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि 14 पर्सेंट फंड का पैसा है, उन पैसों से सड़कों का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जिस दिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना बजट रखा, दूसरे दिन तमाम सदस्यों की शक्ल देख रहा था, माफ करना आधे से ऊपर हमारा आदिवासी भाग चुका था और बजट के दूसरे दिन

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

17 मंत्री गायब थे, क्योंकि उनको मिला कुछ भी नहीं है। यह सच्चाई में आपसे ईमानदारी से कहना चाहता हूं, फिर आप कह रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट शानदार रख दिया, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कर दिया, अच्छा जो कर दिया उसके लिए धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जल स्वावलम्बन, मतलब इतना जोरदार काम हो रहा है, लेकिन मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि गत बार तो बजट का प्रावधान था, इस बार जल स्वावलम्बन में एक रुपये का प्रावधान नहीं है, यह कहां से होगा? निर्बंध योजना का पैसा हर पंचायत की जनसंख्या के आधार पर उस पंचायत में जाना था, वह पैसा उन्होंने नहीं दिया और उस पैसे को क्लब करके, पूल करके जिन पंचायतों में काम हुआ, सीधा पैसा वहां डाल दिया जबकि ऊपर हैड पैसा आ रहा है। आज पंचायतों स्थिति बहुत खराब हो गई है, जहां दो, सवा दो करोड़ रुपये एक एमएलए को स्वविवेक के नाम से दिया जाता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार पैसा दे, अब आपके यहां से एक ऑर्डर और जारी हो गया कि उसमें से 56 या 60 लाख रुपये आपको सीधा जल स्वावलम्बन में देना है तो फिर एमएलए को क्यों दिया? आज ऐसी कई परेशानियां हैं, अब इनके बारे में ज्यादा मैं क्या कहूं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माही हमारी जीवन रेखा है, माही के अपर कैनाल के लिए हमने सर्वे कराया था, 140 किलोमीटर कैनाल है और वह आगे जाकर गुजरात में मिलती है, फिजीबल है, कैनाल हो सकती है, बन सकती है और 40 टीएमसी पानी हम गुजरात में दे रहे हैं, गेट खोलकर पानी दे रहे हैं। गुजरात में लिखा हुआ है कि गुजरात में पानी हम देना बंद कर देंगे जिस दिन नर्मदा का पानी पहुंच जाएगा, नर्मदा का पानी बरसों से पहुंच गया तो क्यों नहीं अपर कैनाल में उस पैसे को लगाएं, अपर कैनाल निकालें और अपर कैनाल 140 किलोमीटर के बाद गुजरात को लिंक करती है, 40 टीएमसी पानी गुजरात ले जाना चाहते हैं तो हम अपर कैनाल के माध्यम से वह पानी गुजरात भी ले जा सकते हैं। लेकिन नहीं, वह काम हम नहीं करेंगे। फिर मैं आप सबसे निवेदन

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

करना चाहूंगा कि यह हो क्या रहा है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हमने टीएडी फंड से की। 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया लेकिन आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में न तो कोई स्टाफ है, न बिल्डिंग का ठिकाना है और वह पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति में आ गयी है इसलिए मैं इस अवसर पर माननीय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं और विशेषकर माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आपने पहले बजट भाषण में कहा था कि टीएसपी क्षेत्र के विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपये दूंगी, माननीय मुख्य मंत्रीजी, खुद वित्त मंत्री हैं, हमारे सदन की नेता हैं और ट्राइबल क्षेत्र में आती हैं तो खूब हम सबके दिलों पर राज करती हैं, लोगों ने खूब उनको वोट दिया है, बजट में कहकर मुकर गये हैं, हमारे लिए यह बहुत बड़े दु:ख की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह डांग, मेवात, बगरा, इन सबकी यही स्थिति है तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि सरकार का बजट शानदार है, जनता की भलाई के लिए है और जब हमारे लिए, टीएसपी क्षेत्र के लिए आपके मन में दया नहीं है तो फिर किसके लिए दया हो सकती है। यदि मैं गलत बात कह रहा हूं तो आप आंकड़े देख लो, दो सड़क के अलावा कुछ मिला नहीं। पानी की कोई योजना नहीं, हॉस्टल का कोई निर्माण नहीं, किसानों को खाद-बीज हम फ्री में देते थे, वह है नहीं। भारत के संविधान की अनुसूची में 5 को लागू करना चाहते नहीं, पेसा एक्ट (PESA Act) को चाहते नहीं, वहां कोई भर्ती चाहते नहीं। आज टीएसपी क्षेत्र में 77, 73, आरक्षण की मांग उठ रही है और बहुत जबर्दस्त उठ रही है। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं सदन की इच्छा है कि माननीय राजीव गांधीजी ने 73 अमेंडमेंट करके पूरे हिन्दुस्तान में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कर दिया पंचायतीराज में, टीएसपी क्षेत्र में अगर आपका मन है तो क्यों कि 73 की मांग कर रहे हैं, उन्हें 73 दीजिए और बाकी जो रहे हैं उनको क्योंकि आपने टीएसपी को यूनिट मान लिया है तो हम क्यों नहीं कर सकते? यदि नहीं कर सकते तो आप भारत सरकार को क्यों प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं?

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

लेकिन आपको वोट ही लेने हैं, यह तो आप भी मान चुके हैं कि अगली बार हमको आना नहीं है, आदिवासी को एक बार लूट लिया, यह तो आप मान चुके हैं और हम भी यह बात दावे के साथ कह सकते हैं कि अबकी बार हम आ रहे हैं। आप दूसरी जगह की बात मत कीजिए, यूपी में क्या हो गया, वहां क्या हो गया, वहां क्या हो गया?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट 2017-18 पर लंबी चर्चा हुई है और आज चर्चा का तीसरा दिन है। मैं पहले बजट से ही शुरू करूंगा। बजट 2017-18 जो आया है, उसमें संशोधित अनुमान 2016-17 के आए हैं। बजट अनुमान 2016-17 में 198 करोड़ का आधिक्य दिखाया गया था, माननीय पार्लियामेंटरी मिनिस्टर महोदय, वह अनुमान 8838 करोड़ के घाटे में बदल गया है। यह उदय योजना रहित है और उदय योजना सहित में जो 8801 करोड़ रुपये का घाटा था वह 17838 करोड़ के घाटे में बदल गया है। 198 करोड़ का घाटा 9036 करोड़ के घाटे में बदल जाए तो बजट अनुमान क्या है? बजट अनुमान में पांच परसेंट का फर्क, बीस परसेंट का फर्क तो समझ में आता है, पर यह पचास गुना फर्क, पैंतालीस गुना फर्क मेरे समझ में नहीं आता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं यह तो हुई बात 2016-17 की, हम 9036 करोड़ के राजस्व घाटे में आ गये और वर्तमान बजट जो 2017-18 का है, उस बजट में 13528 करोड़ रुपए का घाटा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माना है और पेश किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समझना यह पड़ेगा कि वाकई में राजस्व घाटा तो हो रहा है, राजस्व घाटा किसी की मर्जी से और बिना मर्जी से नहीं, आंकड़े से आ रहा है कि इतना घाटा हुआ तो राजस्व प्राप्तियों से हमारा राजस्व व्यय पचास परसेंट काफी नहीं होता। हमारी राजस्व प्राप्तियां पिछले साल में छियालीस परसेंट थीं और इस साल मुश्किल से पचास परसेंट है। पहले यह कहा जाता था कि राजस्व घाटा होना ही नहीं चाहिए। राजाखेड़ा से

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आने वाले माननीय सदस्य वित्त मंत्री रहे हैं और यह काफी अर्से चला कि राजस्व घाटा नहीं होना चाहिए। पर, मैं यह देख रहा हूं कि वर्ष 2015-16 में पांच हजार करोड़ से ऊपर हुआ, फिर 2016-17 में नौ हजार हो गया और अब 2017-18 में तेरह हजार करोड़ हो गया तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी मान्यताएं बदलनी पड़ेंगी। मान्यता स्पष्ट है कि राजस्व प्राप्तियों से विकास का खर्चा नहीं किया जा सकता। राजस्व प्राप्तियां काफी नहीं है और राजस्व खर्चे को चलाने के लिए भी पूंजीगत खाते से रुपया लेना पड़ रहा है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी क्या करें? फिर चौबीस हजार करोड़ रुपये का जो राजकोषीय घाटा बताया गया है उसी के आधार पर यह 2017-18 का बजट खड़ा है और बजट वास्तविकता है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसकी चर्चा करूं कि यह कैसे हो गया तो यह चर्चा करना बेकार है।

इसका कोई उपयोग नहीं है। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि राजस्व प्राप्तियां हमारे राजस्व व्यय के 50 परसेंट, 45 परसेंट है। यह तो राजस्व घाटे की बात हो गयी। माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने इन सब स्थितियों में भी 1 लाख 12 हजार करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा इस बजट में की है। विभिन्न विभागों में जो घोषणाएं की गयी हैं उनमें नोट करने वाली घोषणाएं यह हैं कि 15278 किलोमीटर सड़कों के लिए 6057 करोड़ रुपये दिये गये। जल संसाधन के लिए 3313 करोड़ दिये गये, शिक्षा में 25215 करोड़ दिये गये। पीएचईडी में 8647 करोड़ रुपये पेयजल मंत्रीजी को दिये गये। सामाजिक न्याय में 5596, महिला एवं बाल विकास में 1904, ग्रामीण विकास में 14698 करोड़ रुपये दिये गये। यह जो राशियां दी गयी हैं जिनका कुल जोड़ 1 लाख 12 हजार करोड़ हैं, विभिन्न विभागों में एक आवश्यक खर्च है इस वर्ष का। वर्तमान आर्थिक स्थिति है उसमें मैं इसका स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा सरकार को इस बात का ध्यान देना है कि 2015-16 में जो हमारा घाटा 147608 करोड़ था वह 2016-17 में 253311 करोड़ हो गया। यानी 1 लाख 6 हजार करोड़ ज्यादा हो गया। 2017-18 में यह घाटा 2 लाख 78 हजार करोड़ होगा। यानी 2015-16 से 1 लाख 30 हजार करोड़ ज्यादा। यह स्थिति इस बजट के आंकड़ों की है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने लम्बे-चौड़े बजट में मैं जब खोजता हूं कि राजस्थान में 577 लाख पशु हैं, 17 लाख हैक्टेयर चारागाह और गोचर की जमीन है। मुझे कहीं गोचर और चारागाह के विकास में एक पैसे का प्रावधान न इस बजट में मिला, न पूर्व के अन्य सरकारों के बजट में मिला। पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी 2003 से 2008 में, उसमें भी नहीं मिला। मैंने गोपालन निदेशालय का बजट भी देखा कि शायद उसमें कोई रुपया, कोई प्रावधान इन चारागाहों के लिए, इन गोचरों के विकास के लिए हो। कोई प्रावधान नहीं है। यहां पशुपालन मंत्रीजी नहीं है। 10 से 11 परसेंट का हमारी सकल घरेलू आय में कंट्रीब्यूशन है। क्या हम इन गोचरों का विकास करके, चरागाहों का विकास करके हमारी पशुधन की आमदनी को दुगुना नहीं कर सकते? यह सदन के सोचने की बात है। इसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? पंचायतों के पास धन है। कोई पंचायत ऐसी नहीं जिसके पास 40, 50, 60 लाख रुपया वित्त आयोगों से नहीं आया हो। ग्रामीण विकास मंत्रीजी चले गये हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं यहां बैठा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अच्छा। मैं अर्ज करना चाहता हूं पंचायतों को जो उनका 50-60 लाख रुपया मिलता है, आप उनको कहो कि 8 लाख, 10 लाख रुपया गोचर के विकास में लगाना पड़ेगा। आपकी कोई इफेक्टिव मानिटरिंग पंचायत के खर्च पर नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, सिस्टम को कह रहा हूं। जितना रुपया वे दें 7 लाख, 8 लाख, उतना रुपया राज्य सरकार दे और जहां 500 बीघा या 1000 बीघा पड़ी है, आप उसको विकसित करें ताकि हमारे दुगुने पशु हों। 577 लाख से भी अधिक पशु हों। 11 परसेंट कंट्रीब्यूशन पशुपालन का है। 5 साल में रोडमैप बनाइये कि प्रत्येक चारागाह और गोचर भूमि का हम विकास करेंगे। माननीय गोपालन मंत्रीजी यहां बैठे हैं। मैंने इनका बजट देखा है कोई 100-150-250 करोड़ का बजट है जो गोशालाओं को अनुदान के रूप में दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आप पशु गोचरों के विकास का अलग बोर्ड बनाएं। चाहे गोपालन मंत्रीजी, गोपालन निदेशालय को

(श्री मानिक चन्द सुराना)
इस काम को दें और इसको पंचायती राज के फण्ड से टाई-अप करें ताकि गोचरों का विकास हो। पशुधन को जब चारागाह मिलेगा तो आज जो दो गाय रखता है वह चार गाय रखेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, गोचर के विकास की बात मैंने कही। जो धन भारत सरकार का पड़ा है, जो प्रावधान हमारे आज हैं, मनरेगा में आज क्या स्थिति है? आज कहते हैं 4400 करोड़ खर्च हुआ, 45 लाख लोगों को रोजगार दिया। यह 2008 का आंकड़ा देता हूं जब माननीय मुख्यमंत्रीजी की सरकार थी। 6579 करोड़ नरेगा का खर्च था और 63 लाख लोगों को काम दिया था। आज हम 45 लाख पर हैं। 18 लाख की मजदूरी कहां चली गयी नरेगा में? हम 15 लाख को रोजगार देने को लालायित हैं और 18 लाख कहां गये? जो हमारे खुद के रिकॉर्ड से हम दे सकते थे और हमारे प्रयत्नों से आज भी दे सकते हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा, जब मैं चार्ट देखता हूं, जब हमारा बीजेपी का राज खतम हुआ (व्यवधान) चूंकि मैं बीजेपी में रहा हूं इसलिए मैंने कहा कि हमारा राज खत्म हुआ। वैचारिक एकता है जिसको आप काट नहीं सकते।

2009-10 में इन्होंने उस बजट को एक हजार करोड़ कम कर दिया, 5700 करोड़ पर आ गये। 2010-11 में 3500 करोड़ पर आ गये। 2011-12 में 2000 करोड़ पर आ गये। मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूं। 2012-13 में 2935 करोड़ पर आ गये। कुछ आगे बढ़े। 2013-14 में ये मात्र 1900 करोड़ पर आ गये। वापस बीजेपी का राज आने के बाद इसमें कुछ सुधार हुआ। 2014-15 में 3100 करोड़ पर आये, 2015-16 में 3300 करोड़ पर आये और अब 44 हजार करोड़ पर। मैं आपको अर्ज करूंगा 48 हजार करोड़ के बजट को देखिए माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी, जो भारत सरकार का है। यह मांग आधारित नरेगा है। सबसे बड़ी खूबी इसकी यह है कि इसमें सैल्फ सलेक्शन है। कोई दूसरा आदमी नहीं कहता कि हम इसका चयन करते हैं। व्यक्ति को खुद को कहना पड़ता है कि मैं रोजगार करना चाहता हूं। सरकार के एक्ट के अनुसार 100 दिन का रोजगार कोई खैरात नहीं है माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी, यह उसका अधिकार है। सारे हिन्दुस्तान में 100 दिन का रोजगार उसका अधिकार बनाया गया है। मैं सदन से कहना चाहूंगा कि आने वाले 2017-18 में आपको 4400 करोड़ से बढ़ाकर इसका आंकड़ा 8800

(श्री मानिक चन्द सुराना)

करोड़ पर लाना चाहिए। आज आप 50 दिन का रोजगार दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आपके कलेक्टर, आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकम्मा है। वह समझता है कि कोई भी पंचायत ने प्रस्ताव दिया तो खारिज कर दो, कुछ नहीं। मैं कहता हूं जिसने 80 दिन का रोजगार नहीं दिया हो उस मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ विपरीत एंट्री उसके रिकॉर्ड में आनी चाहिए। जिस कलेक्टर के क्षेत्र में मनरेगा में 80 परसेंट दिनों की उपलब्धि नहीं है, जो आंकड़ा 63 लाख का था वह हमें 80 लाख करना है, 100 लाख करना है ताकि इस मनरेगा से आज हम 4400 करोड़ पर खड़े हैं, हम 10 हजार करोड़ पर पहुंचें। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो 2008-09 में उपलब्धि की थी 6500 करोड़ की वो ही यदि निरन्तर रहती तो आज यह आंकड़ा 10 हजार पर होता। हर साल हजार-हजार करोड़ की भी मनरेगा की विकास यात्रा चलती तो 10 हजार करोड़ पर हम पहुंचते। सरकार को सोचना है कि जिसमें राज्य के बजट का कोई भार नहीं है और भारत सरकार से पैसा आना है उस कार्यक्रम को हम आगे चलाकर मनरेगा में 10 हजार करोड़ तक व्यय करें और 63 लाख ही नहीं, 80 लाख लोगों को, 50 दिन का नहीं, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करायेंगे।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी के यह ध्यान में है कि जो काम जल स्वावलम्बन में 1700-1800 करोड़ का चल रहा है इसमें भी तो व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं हैं। एससी, एसटी, बीपीएल, सीमांत किसान, लघु किसान, इन सबके खेतों में नरेगा से जल-कुण्ड बनाये जा सकते हैं। आज तक क्यों नहीं बनाये? 2005 में नरेगा आ गया तो इन 11 साल में क्यों नहीं बने? कौन इसका जवाब देगा? यह कौनसा सिस्टम है? मनरेगा अलाऊ करता है कि मुफ्त में उसके खेत में जल-कुण्ड बने और हम उसके खेत की तरफ ध्यान नहीं देते। माननीय मंत्री जी, जो आंकड़ा 2014-15 की आर्थिक समीक्षा में छपा है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सीमांत किसान की संख्या 12 लाख और छोटे किसान की संख्या 22 लाख है, तो ये 34 लाख आदमी तो उपलब्ध हैं सीमांत किसान और छोटे किसान। अनुसूचित जाति अलग है, अनुसूचित जनजाति अलग है, बीपीएल की श्रेणी अलग है। आप चाहते तो, आप चाहें तो इन 34 लाख के खेतों में नहीं, 40 लाख लोगों के खेतों में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कुण्ड बन सकते हैं। 68 लाख 88 हजार कृषि जोतें हैं, उन कृषि जोतों में सीमांत किसान की जोत 12 लाख है और छोटे किसान की जोत 22 लाख है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप कलेक्टर की इस बात को न मानिये। चाहे सरपंच नहीं बनाना चाहता था पर आप ऊपर से निर्देश दीजिये कि नरेगा का 66 परसेंट बजट, 2/3 बजट जल-कुण्ड बनाने में ही काम में आयेगा तो कौन रोक सकता है आपको ?

(15.22 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

इस शुभ काम का जनता स्वागत करेगी और जनता तैयार बैठी है कि उनके खेत में जल-कुण्ड बने। माननीय मंत्री जी, इस जल-कुण्ड को सरपंच के हाथ से निकालिये, सरपंच और ग्राम पंचायत की कमेटी के हाथ से निकालिये। जिस तरह इन्दिरा आवास व्यक्ति को दिया जाता है, वही बनाता है उसी तरह से खेत में जल-कुण्ड नरेगा में वो किसान बनाये, सरपंच का कोई लेना देना नहीं है। आपके पास स्टैण्डर्ड है कि कितनी ईंट, कितना सीमेंट, कितना चूना होगा तो आप उस व्यक्ति को दीजिये ताकि जिसके खेत में बनना है वह इतना मजबूत बनायेगा कि आने वाले 25 साल तक उसमें कोई मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सभापति जी, मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अब आपका नेतृत्व हो गया है, पहले माननीय सुरेन्द्र जी गोयल का था और जो आंकड़े मैंने रखे हैं ये मेरे प्रश्न के जवाब में सरकार के द्वारा ही दिये गये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि नरेगा का बजट 10 हजार करोड़ का आने वाले इस साल 2017-18 में हो इसकी उपलब्धि करिये।

माननीय सभापति महोदय, बजट के कुछ और पॉलिसी फेल्योर्स हैं। मोटे अनाज के भाव, मोटे अनाज की खरीद राजस्थान में निल है, गेहूं की खरीद निल है। मोटे अनाज में बाजरा है, जौ है, ज्वार है, मक्का है और इनके भाव तय हैं। आपकी सरकार पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करती कि मोटा अनाज खरीदा जाएगा। सभापति महोदय, ग्रामीण की गरीबी का मुख्य कारण है तो यह है कि उसको उसकी उपज का मूल्य नहीं मिलता है। आपका ध्यान इस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ओर नहीं गया, सरकारों का ध्यान इस ओर नहीं गया। उपज का मूल्य नहीं मिलता और जो भाव भारत सरकार ने तय किये हैं, मुझे आप बता सकते हैं, पंजाब का गेहूं 98 प्रतिशत खरीद किया जाता है माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी। कृषि मंत्री जी तो अभी गायब हैं। क्योंकि मोटे अनाज की ही बात हो रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि मोटे अनाज के भाव, मोठ के भाव आप क्यों नहीं तय करा रहे हैं ? ग्वार का भाव क्यों नहीं तय करा रहे हैं ? और जो भाव तय हैं उस पर खरीद नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के किसान की गरीबी का प्रमुख कारण यह है कि राजस्थान की सरकारों ने मोटे अनाज की खरीद, गेहूं की खरीद को हमेशा नजर अंदाज किया है। आपने मूंगफली वालों को मार दिया।

सभापति महोदय, मूंगफली की खरीद के लिए भारत सरकार तैयार हो गयी, 21 नवम्बर, 2016 का पत्र आ गया। 21 नवम्बर, 2016 को उन्होंने कहा कि हम खरीद को तैयार हैं। वहीं पत्र गुजरात गया, मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ गया। वहां की सरकारों ने एक दिन में बॉण्ड भर दिये। सभापति महोदय, भारत सरकार की शर्त यह थी कि राजस्थान में जो मूंगफली की सरकारी खरीद होगी उस पर टैक्स वसूल नहीं होगा। मण्डी टैक्स, वैट, ये वसूल नहीं होगा। किसान को 600 रुपये क्विंटल का चूना लग गया। 4220 रुपये भाव है मूंगफली का और 4220 भाव होते हुए भी उसकी खरीद 3400 और 3600 रुपये में हुई और मूंगफली रूल गयी। लेकिन आपकी सरकार ने, माफ करिये, आपकी सरकार ने नहीं, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने मूंगफली खरीद के पक्ष में फैसला नहीं किया। मैं सहकारिता मंत्री जी को दोष नहीं देता, मैं कृषि मंत्री जी को भी दोष नहीं देता क्योंकि ये कैसे निर्णय करते, फाइनेंस का सवाल है। 165 रुपये क्विंटल का आपको नुकसान था और 600 रुपये क्विंटल का फायदा किसान को था। अन्य सरकारों ने, गुजरात में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने क्यों खरीद लिया ? उन्होंने क्यों बॉण्ड भर दिया और आपने क्यों नहीं भरा ? जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि मूंगफली की खरीद में बीकानेर जिला 38 परसेंट पर है। 10 लाख टन मूंगफली राजस्थान में होती है, 3 लाख 80 हजार टन मूंगफली बीकानेर में होती है। हमको 240 करोड़

(श्री मानिक चन्द सुराना)

का घाटा और सारे 10 लाख टन मूंगफली पैदा करने वालों को 600 करोड़ का घाटा इस मूंगफली के प्रकरण में हो गया। मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार जो भाव निर्धारित हैं उन निर्धारित भावों पर, समर्थन मूल्य जो निर्धारित हैं उन पर वो जिन्स खरीदी जाए। जिनके भाव तय नहीं हैं, मोठ का भाव आप क्यों नहीं तय करा रहे हो 5 हजार रुपये जबकि मोठ से भुजिया बनता है और 150 रुपये किलो बिकता है। 5 हजार रुपये मोठ का भाव क्यों नहीं करते हैं, ग्वार का भाव 4 हजार रुपये तय क्यों नहीं करते हैं आप? भारत सरकार तय करेगी पर आप उनको प्रेरित करिये, आप उन पर दबाव दीजिये ताकि वो यह काम करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि खाली मूंगफली का ही मुद्दा नहीं है, खाली मोटे अनाज का ही मुद्दा नहीं है। कृषि मंत्री जी अभी नहीं हैं, डिग्गियों की सब्सिडी हमने कम की है, तीन लाख से दो लाख हुई है, सोलर की सब्सिडी जो 86 प्रतिशत थी, हमने 60 प्रतिशत की है। सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आंकड़ा डिग्गी बनाने का राजस्थान में है उसमें 10 हजार डिग्गियां बननी थीं उनकी जगह 2400 डिग्गी बनीं। जो 9750 किलोमीटर पाइप लाइन डालनी थी किसानों के खेत में उसमें से 1400 किलोमीटर पाइप लाइन ही डली। सरकार के प्रतिनिधि सुनें कि डिग्गी इसलिए कम बन रही है क्योंकि हमने सब्सिडी तीन लाख से दो लाख रुपये कर दी। मैं कहता हूं कि वापस सब्सिडी तीन लाख रुपये करिये। आप घाटे को क्यों देख रहे हैं, घाटा तो हो ही रहा है पर उस किसान के खेत में 110x110 की डिग्गी बन जाए, 20 लाख लीटर पानी उसमें रहे तो उसमें बारी का पानी भी लगा दे और आने वाली बारी में यदि नहर में अनिश्चितता है तो उसका पानी भी लगा देंगे। आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे? कौनसे घाटे की आप परवाह कर रहे हैं? 198 करोड़ रुपये के फायदे को तो 9,036 करोड़ रुपये के घाटे में बदल दिया। अब डर क्या है, लगने दीजिये 10-20-50 करोड़ रुपये और। सब्सिडी सोलर की बढ़ाइये। पहले जो 86 परसेंट थी, उसी पैटर्न पर लाइये। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमने डिग्गियों की सब्सिडी नहीं बढ़ाई, हमने सोलर की सब्सिडी नहीं बढ़ाई और सिर्फ यह कहा कि भारत सरकार ने घटा दी, मैं कहता हूं कि भारत सरकार को घटाने दीजिये।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राजस्थान की परिस्थितियां आप ज्यादा जानते हैं। आप जल स्वावलम्बन के प्रहरी हैं। आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम जल स्वावलम्बन है। मैं कहता हूं, सिंचित क्षेत्र में डिग्गी दीजिये, सब्सिडी बढ़ाइये। बारानी खेत में, हर खेत में डिग्गी 50,000 लीटर की बनेगी तो उसके साथ उसको सोलर भी दीजिये, सोलर पैनल दीजिये ताकि वह बिना बिजली... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) वहां उसके खेत में पहुंचे और वह उत्पादन का काम जोर-शोर से कर सके।

भाजपा ने नारा दिया "हर खेत को पानी, हर हाथ को काम" हर खेत को पानी कैसे देंगे? एक मात्र जल स्वावलम्बन का कार्यक्रम है जो हर खेत को पानी पहुंचा सकता है और हर खेत में पानी पहुंचाने से हर हाथ को काम मिल सकता है। एक हाथ को ही नहीं, जिसके यहां डिग्गी बन गयी, सोलर पैनल लग गया, दो आदमी को रोजगार देने के लायक हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि डिग्गी की सब्सिडी बढ़ाइये, सोलर की सब्सिडी बढ़ाइये ताकि राजस्थान के खेतों का, बारानी खेतों का कल्याण हो। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापतिजी, मैं जल स्वावलम्बन पर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पिछली बार 3,500 गांव लिये, वह 3,520 या 3,525 हैं, इस साल 4,200 कुछ हैं। आप जरा यह तो गौर करिये... इनसे बात करनी हो तो पहले बात कर लीजिये, माफ करें।

श्री सभापति: माननीय सुराना साहब, अपना वक्तव्य पूरा करें। काफी समय भी हो चुका है। जल्दी करें थोड़ा। खतम करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जल्दी करूंगा। मैं इर्रिलेवेंट बोलूं तो आप तत्काल रोक दें।

श्री सभापति: सभी रिलेवेंट ही बोलेंगे, यह विश्वास किया जाता है लेकिन समय की मर्यादा भी जरूरी है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं जो बात कह रहा हूं, सरकार को समझ में आए तो बोलने दीजिये, नहीं तो कोई बात नहीं। 3,500 गांवों में रेगिस्तानी के 11 जिलों का हिस्सा, पंचायत समितियां 108, हमारे हिस्से के 808 गांव हमको मिले और 2,700 गांव मिले गैर रेगिस्तानी जिलों में। यह जल

(श्री मानिक चन्द सुराना)

स्वावलम्बन किसके लिए है ? यह सिंचित क्षेत्रों के लिए है क्या ? जो क्षेत्र सिंचित है, मंत्रीजी, मैं कड़वी बात कह रहा हूं, उस क्षेत्र को जल स्वावलम्बन की कोई जरूरत नहीं है। 11 रेगिस्तानी जिले और वह नहरी जिले, जहां बारानी क्षेत्र है, उसी में जल स्वावलम्बन के कार्यक्रम को सीमित करिये। यदि आप ऐसा करेंगे, आपके पास टार्गेट बहुत बड़ा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा, 95,000 स्ट्रक्चर बनाये गये, मतलब 95,000 खेतों में जलकुण्ड बनाये गये। अब की बार है डेढ़ लाख। क्या हुआ, 2,40,000, मैंने आंकड़ा दिया ना कि 12 लाख तो सीमांत किसान बैठे हैं और 22 लाख छोटे किसान बैठे हैं... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) और अनुसूचित जाति वगैरह दूसरे हैं। मैं यह नीतिगत बात संक्षेप में इसलिए कह रहा हूं ताकि जब आपके विभाग का मुद्दा आएगा तो मैं इस पर विस्तार से कहूंगा। सभापतिजी, कुछ नीतिगत बात है। शिक्षाकर्मियों को आपने 30.6.2005 को एक आदेश जारी कर दिया कि इनको छठे वेतन आयोग का परिलाभ नहीं दिया जाएगा। चलिये, आपने कर दिया पर मैं पूछता हूं, सात लाख लोगों को छठे वेतन आयोग का परिलाभ मिल रहा है। सिविल लाइन्स, जयपुर से आने वाले माननीय विधायक और चूरू से आने वाले माननीय विधायक दोनों उस कमेटी के चेयरमैन और सदस्य हैं जो कमेटी राजकीय कर्मचारियों की पीड़ा को देखती है। मैं कहता हूं, क्या अधिकार है आपको ? 30.6.2005 में क्यों नोटिस जारी कर दिया कि इनको छठे वेतन आयोग का परिलाभ नहीं मिलेगा ? छठे वेतन आयोग का परिलाभ सात हजार लोगों को नहीं दिया तो क्या सात लाख को देने से रोक लोगे ? मैं निवेदन करता हूं कि उस 30.6.2005 की विज्ञप्ति को जो अपने ही राज में जारी हुई है, उसको कृपया विदड्रा करिये और जो भी आपके प्रबोधक के नियम हैं, उन प्रबोधकों के नियमों को शिक्षाकर्मियों पर लागू करिये, उनको नियमित करिये...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य रामहेत सिंहजी यादव (अनुपस्थित) माननीय सदस्य गोपाल कृष्णजी।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): थैंक यू। माननीय सभापति महोदय,

(श्री गोपाल कृष्ण)

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को बधाई कि उन्होंने एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है और अपने वादे पर खरी उतरी हैं। इसे विपक्षी हो सकता है कि इलेक्शन का बजट भी कहें, क्योंकि इसके अंदर बहुत-सी रियायतें दी गयी हैं। बहुत सा पैसा सड़कों में खर्च किया गया है, बहुत सा पैसा मेडिकल कालेजेज में, कई कालेज खोले हैं, उनमें लगाया गया है। विधवा पेंशन वगैरह में दिया गया है। किसानों को छूट दी गयी है। अब सवाल यह है कि बजट चुनावी है या नहीं है, लेकिन यहां तो चुनाव हो नहीं रहा। चुनाव तो कहीं और हो रहे हैं। अब अगर यह बजट चुनावी बजट है तो समझ लीजिये कि बजट तो यहां पेश किया और इसका असर यूपी, उत्तराखण्ड और वहां पर हुआ तो इसलिए फिर अपनी यशस्वी वसुन्धराजी को बधाई का पात्र मानना पड़ेगा कि जो बजट यहां दिया है, जिसको चुनावी बजट कहते हैं तो उस चुनावी बजट का असर वहां पर पड़ा है, यह बहुत ही खूबी की बात है, लेकिन विपक्ष की अपनी नियति है। उसे कोई बात अच्छी लगे तब भी बात अच्छी कहते नहीं है। हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं, हस्तिनापुर से जो बंधे हुए लोग हैं तो चाहे बुराई की तरफ भी हों, उनके साथ चिपटे रहेंगे। चाहे हार के ही लोग हैं, उनके साथ चिपटे रहेंगे, जब हार की बात है तो कांग्रेस के बारे में अब क्या बतायें। एक दफा ये कहा करते थे कि कांग्रेस का इतिहास भारत का इतिहास है। यही सब कुछ है लेकिन अभी क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में 403 सीट के अंदर 105 सीट तो उन्होंने बार्गेनिंग में ली और 105 के अंदर सिर्फ सात में जीते, जबकि एक छोटा सा दल 'अपना दल' है, उसने नौ सीटें जीत ली।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): पंजाब में आप एक ही जीते। (व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): अब सिमटते हुए यहां के लिए तो आप देखिये, बीकानेर को धन्यवाद, शुक्रिया कीजिये कि यहां बीकानेर से दो आदमी जीतकर आ गये... (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): धीरजजी, आपको ऐसी गलत सूचना किसने दी कि एक भी नहीं जीते? (व्यवधान) आपको यह मालूम नहीं कि एक ही जीते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठें। प्लीज प्लीज, विराजें। आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मेरा टाइम खराब हो रहा है। मेरा टाइम मत खराब कीजिये। क्यों आप मेरा टाइम खराब करते हैं। आपको जो बोलना है, आप बोल देना।

बीकानेर का शुक्रिया अदा करो कि दो आदमी यहां से भंवरसिंहजी और डूडी साहब आ गये, वर्ना आपका तो अपोजिशन भी नहीं बनता। यहां पर भी यही हालत थी। देखिये, कैसी हालत आपकी हो रही है जगह-जगह पर और इतनी बड़ी जबर्दस्त हार के बाद में भी आपके बड़े नेता ने कभी यह नहीं कहा कि मेरा इस्तीफा ले लीजिये, यह तो मेरी हार है। देखिये ना, यह भी कैसी शर्म की बात है। फिर भी बड़ी खुशी है, आप लोग अगर इसको मानते हो तो ठीक है। आपमें से कई लोग गुपचुप हमारी नेता को बधाई तो देते हैं, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते हैं लेकिन यह कभी खुलकर नहीं कहते, फिर भी हम यह समझते हैं कि इस मुखर विपक्ष के कितने विरोध करने वालों ने गुपचुप अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद तक ज्ञापित कर दिया। आपको धन्यवाद और बधाई कि आपने अपना धर्म निभाया है लेकिन मेरी राय है कि कभी-कभी मन की बात भी सुन लेनी चाहिए। खुले मन से आप अगर बजट का समर्थन करते तो यह अच्छी बात थी। वैसे खैर, मेरी नजर में यह बजट में नये राजस्थान की संभावनाएं हैं। पर्यटन क्षेत्र, चाहे युवाओं को सम्बल देने की बात हो, दोनों ही विषय में यह छिपी हुई बात नहीं है प्रोत्साहन तो मिल ही रहा है। राजस्थान की गति को कोई रोक नहीं सकता। युवाओं के साथ किसानों के लिए भी दरवाजे खोल दिये हैं बजट ने। कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी और निवेश को भी प्रोत्साहित करने के लिए संभाग स्तरीय जो कार्य योजना बनाई गयी है उसमें खेती किसानी में अपूर्व फायदा दिख रहा है। स्टाम्प ड्यूटी में भारी कमी की है यह सबको मालूम है। जहां 5 परसेंट थी उसको 3 परसेंट, 3 परसेंट को 1 परसेंट और 1 परसेंट को .25 परसेंट तक मतलब छूट दी गयी है। यह छूट कोई थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी छूट है। अब अगर मैं बीकानेर की बात करना चाहूं तो बीकानेर में मीनासर में जहां शोभासर से पानी आता है वहां से लेकर मीनासर तक पाइप लाइन डाली गयी है। यह बहुत बड़ा काम उन्होंने

(श्री गोपाल कृष्ण)

इस ढंग से किया है बीकानेर में।

एक सबसे बड़ी बात यह है कि बीकानेर में खेल के मैदान में लोगों ने बड़े कमाल किये हैं। एक ही परिवार के दो महाराजा करणीसिंह व राज्यश्री कुमारी को अर्जुन अवार्ड मिला है। एक फुटबालर हैं उनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है और राज्यवर्द्धन सिंह जी वहां के सिल्वर ओलम्पिक विजेता हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए कि बड़े खिलाड़ी हुए हैं और साइकिलिंग एकेडमी वहां खोलने की जो घोषणा की है इन सबके लिए मैं एक दफा फिर यशस्वी वसुन्धरा जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सत्तर साल में काम नहीं हुआ वो इन तीन सालों में हुआ है। हमारे चिकित्सा मंत्री का कहना है कि सत्तर साल में नहीं हुआ वो तीन साल में हुए हैं। उससे भी ज्यादा दो साल में और करके दिखाएंगे। यह बहुत बड़ी हमारी जीत है। विजयसिंह मेमोरियल अस्पताल में कम से कम तीन सौ करोड़ का काम राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और जनसहयोग से हुए हैं। मोर्चरी का उन्नयन, गर्ल्स होस्टल, ट्रोमा सेन्टर और इस ढंग से कई तरह की एमडीआरयू सुपर स्पेशिलिटी, पीसीसी वगैरह, तीन सौ करोड़ का काम हुआ है, लेकिन कभी भी हमारे विपक्ष के लोग इसको मानेंगे नहीं और हमेशा ये कहते हैं कि आप यशस्वी वसुन्धरा जी, यशस्वी वसुन्धरा जी कहते रहते हो, आपके समय में जब सरकार आपकी थी तब आप चीफ मिनिस्टर के कैसे क़सीदे पढ़ते थे। क़सीदे पढ़ते थे कि हमारा चीफ मिनिस्टर नम्बर-1 है, यह है, वो है, सारा कुछ करते थे। अब लेकिन हालत क्या है। वैसे दूसरों को तो आप कुछ भी कहिये सुरताल के साथ में तारीफों के ढोल बजाते थे और अब हमने तो थोड़ी सी बंसी बजाई है। अभी बंसी बजाई है उसमें भी आपके कान फटने लग गये हैं। देखिये दूसरों को नसीहत देते थे, दूसरों को नसीहत देते हैं, 'दूसरों को नसीहत और आप मियां फजीहत' आप तो फजीहत हैं। देखिये किस ढंग की फजीहत आपकी चारों तरफ से हो रही हैं। सिमट रही है आपकी पार्टी सारी की सारी, लेकिन अभी भी जब बोलते हैं तो जोरों से बोल-बोल करके क्या असर डालना चाहते हैं, मुझे यह पता नहीं है। 'उन्हें यह फिक्र हरदम कि नयी तर्जेवफा क्या है हमें यह शौक देखें सितम की इंतहा क्या है' बोलते

(श्री गोपाल कृष्ण)

जाओ, बोलते जाओ, गालियां निकालते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिये हमेशा से तो इनको अपना तो चेहरा पता नहीं चलता कि मेरा चेहरा क्या है इसीलिए गालिब का एक ये शेर आपको अर्ज करता हूं कि 'उम्र भर गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा।' इस ढंग से ये सारे के सारे करते रहे। मैं यही कहता हूं कि यशस्वी वसुन्धरा जी ने जो हमको बजट दिया है यह बजट वास्तव में सिद्धांतों पर आबाद है।

राजस्थान में नवाचार के पुरस्कारों की भरमार हो गयी। कौशल विकास के लगातार सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य के रूप में गोल्ड ट्राफी। ई-गवर्नेंस के लिए ई-गवर्नेंस का स्वर्ण पदक। भामाशाह परियोजना को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट। राजधारा जीआईएस और ईएसआरआई अवार्ड एलईडी लाइट लगाने के उत्कृष्ट कार्य पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक ऋण देने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति विकास सहकारी निगम को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। भारत सरकार से कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना में झुंझुनूं जिले को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मानित किया गया। जहां एक ओर आर्थिक आधारभूत संरचना जैसे बिजली, पानी, सड़क को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है, वहीं सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार के नये अवसर सृजित करना, ये जरूरी चीजें इसके अन्दर रखी गयी हैं और राजस्थान को आकर्षक पर्यटन केन्द्र के रूप में भी विकसित करना, ग्रामीण व्यवस्था का आधार, अर्थव्यवस्था का आधार, कृषि व पशुपालन को मजबूती प्रदान करना, ये सब कुछ हैं। सभी ने तारीफ की है। अभी आपने देखा कि हमारे बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री मानिक चन्द जी सुराना ने बजट की तारीफ की और अच्छे सुझाव भी दिये। बहुत अच्छी बात है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इन्होंने रिकोग्नाइज तो किया है, इसी ढंग से आपको भी रिकोग्नाइज करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि बीकानेर में एक कन्या महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और टैक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए घोषणा हो चुकी है उस घोषणा की अब विधेयक के रूप में लाकर के पूर्ति की जानी चाहिए।

खनन पट्टों में ई-ऑक्शन के माध्यम से आगे के खनन पट्टे दिये

(श्री गोपाल कृष्ण)

जाएंगे। कितनी बड़ी चीज है। इसमें धांधली जो होती थी वो भी रुकने वाली है इससे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में 53 लाख कृषकों की तथा रबी में 30 लाख कृषकों की फसलों का बीमा किया गया था और अभी भी हो रहा है। आरक्षित वर्ग द्वारा भेड़ों का बीमा करवाने की प्रीमियम राशि का अस्सी प्रतिशत व अन्य वर्ग के पशुपालकों के लिए प्रीमियम राशि का सत्तर प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। देखिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता में विधवा पेन्शन योजना के तहत 1 जुलाई से साठ वर्ष से अधिक को पेन्शन बढ़ा कर अब एक हजार रुपये प्रति माह, 75 वर्ष से अधिक की आयु की विधवा पेन्शनर्स को पन्द्रह सौ रुपये। सहयोग एवं उपहार योजनान्तर्गत कन्या के विवाह पर देय अनुदान राशि तथा प्रोत्साहन राशि दोनों ही दुगुनी करने का यहां पर प्रस्ताव है और समस्त पात्र विशेष योग्यजन को अब समान रूप से 775 और खास तौर से सुखद दाम्पत्य जीवन योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता राशि प्रति दम्पति अब पचास हजार रुपये की घोषणा की है। इस ढंग की घोषणाएं होती आ रही हैं। आपको मालूम होगा कि बीकानेर के खिलाड़ी इतने मैडल जीत करके लाते हैं, साइकिल के अन्दर कि अगर एक आदमी उठाना चाहे तो वो उठ नहीं सकता। अगर आप सारे मैडल इकट्ठे करो तो कम से कम एक क्विंटल से ज्यादा मैडल लोग जीत करके आये हैं। इसीलिए साइकिल की एकेडमी के लिए जो घोषणा की है, बहुत स्वागत योग्य और धन्यवाद के योग्य है। कुल मिला करके बजट बहुत ही अच्छा है और इतना अच्छा बजट बहुत कम लोगों ने दिया होगा। मैं समझता हूं और यह चुनाव की बंसी बजाई है और इससे अगर किसी को दुख होता है तो होता रहे लेकिन हमारी यशस्वी वसुन्धरा जी ने यह एक बहुत अच्छा खूबसूरत और प्रोग्रेसिव बजट दिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र जी कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से बजट पर बोलना चाह रहा हूं और आपने अनुमति दी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी बजट पर ही हमारे से पूर्व बांसवाड़ा जिले से आने

(श्री देवेन्द्र कटारा)

वाले सदस्य ने काफी कुछ अनुसूचित क्षेत्र के बारे में जिक्र किया और इस बजट को उन्होंने क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं बताया।

माननीय सभापति महोदय, उस क्षेत्र में यदि बदहाली या धीमी प्रगति का कोई कारण रहा है, आजादी के बाद से अब तक का इतिहास उठा कर हम देखते हैं तो 48 साल तक कांग्रेस सरकार ने शासन किया है। 48 साल में अनुसूचित क्षेत्र को क्या दिया, क्या नहीं दिया इस बारे में थोड़ी सी बात करके फिर मैं हमारे बजट पर चर्चा करुंगा। सबसे पहले तो उस क्षेत्र के लिये भारत के संविधान के जो स्पेशल प्रावधान बने हुए हैं, 48 साल तक कभी कोई व्याख्या नहीं की और सबसे ज्यादा जितने भी उस क्षेत्र की व्यवस्था के कानून थे, सारे के सारे कानून कांग्रेस शासन में वहां पर लागू हुए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 (3) (क) की अगर हम लोग व्याख्या करते हैं तो जितने भी कानून उस क्षेत्र में लागू हुए हैं वह कानून वास्तव में संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत एक भी वहां पर लागू होने लायक नहीं था। जबरन उस क्षेत्र के लिये कानून थोपे। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां का ट्राइबल अनावश्यक अपराधी बना है। वहां पर प्रावधान है कि उस क्षेत्र में, उस गांव में कोई व्यक्ति अपने कब्जे में शराब कितनी रखेगा, अपने सगाई समारोह में शराब का कितना इस्तेमाल करेगा, अपने तमाम प्रकार के रीति रिवाजों को सम्पन्न कराने के लिये उनके पास क्या क्राइटेरिया होगा, यह सारा का सारा प्रावधान अलग से है। इसके बावजूद भी आपने आबकारी अधिनियम लागू कर दिया, जबकि आबकारी अधिनियम की विधि और परम्परा, दोनों ही विपरीत है।

यही नहीं जब आपने आरक्षण की बात कही, जब 1950 में संविधान लागू हुआ उस समय पांचवीं अनुसूची में स्पष्ट प्रावधान है कि वहां पर शासन, प्रशासन और वहां की नौकरियों के नियोजन की जो व्यवस्था होगी, वह साफ स्पष्ट है, इसके बाद भी 48 साल तक न तो टीएसी में कोई प्रावधान किया और न ही उस क्षेत्र के लिये कभी कोई मीटिंग कॉल की, न ही यहां पर किसी प्रकार का उन्होंने प्रावधान किया, जिस वजह से 1970 में जब पहली अधिसूचना जारी हुई तब से लेकर अब तक उस क्षेत्र में नियोजन में इतनी असमानता हुई, चाहे वह पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन

(श्री देवेन्द्र कटारा)
डिपार्टमेंट हो, चाहे अन्य प्रकार के कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां पर ट्राइबल की नियुक्तियां नगण्य के बराबर हैं। माननीय सभापति महोदय, जब कांग्रेस के साथी यह कहते हैं कि उस एरिये में दो तीन जीवन रेखा के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। जबकि भारत के संविधान के आर्टिकल 46 में यह साफ प्रावधान है कि उस क्षेत्र के लोगों के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक हितों के संसाधनों में वृद्धि करना भारत सरकार और राजस्थान सरकार का कर्तव्य है और उसके लिये प्राथमिकता के आधार पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में उस क्षेत्र में बजट खर्च करने का प्रावधान भी है। लेकिन 48 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया और अब राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने इस व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम शुरू किया है, इसकी जिन्होंने आलोचना की है, मैं समझता हूं कि गलती उनकी है, उनके द्वारा क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय किया गया है और साथ साथ में उनकी कमजोरी को दबाने के लिये इस बजट को आधार मानते हुए बात की है, जो अनुचित है।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट न केवल सभी वर्गों को साथ में लेने वाला है बल्कि राजस्थान की दशा और दिशा तय करने वाला है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पिछले तीन वर्षों में 20822 करोड़ की लागत से 4281 गांव और ढाणियों को जोड़ा है जबकि गत सरकार ने तीन वर्ष में 9157 करोड़ रुपये की लागत से मात्र 66 गांवों को जोड़ा था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सभी नव गठित पंचायतें हैं उनमें चार, पांच पंचायतों को छोड़कर करीब-करीब सारे पंचायत मुख्यालय और गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। जो पंचायत मुख्यालय सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं उनमें एक धमलाकला है, एक आशियावाव है, एक बटकाफला है। कुल मिलाकर 69 ग्राम पंचायतों में से 3 पंचायतें ऐसी हैं जहां वास्तव में सड़क की आवश्यकता है, क्योंकि अभी परिसीमन हुआ था और यह नेक्स्ट प्लान में आएंगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। माननीय सभापति महोदय, थाना से हिम्मतपुर सड़क 2012 में स्वीकृत हुई थी, यह पूरी 30 किलोमीटर की सड़क थी, उसमें से 25 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। उसमें 5 किलोमीटर वन क्षेत्र भी पड़ता है। सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में फाइल चलने की वजह से मात्र 5 किलोमीटर सड़क अभी

(श्री देवेन्द्र कटारा)
तक पूरी नहीं हो पाई है। मैं समझता हूं कि यह सड़क, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी के प्रयास से बहुत ही शीघ्र इस समस्या का समाधान होगा।

माननीय सभापति महोदय, एक सड़क डूंगरपुर से बिछवाड़ा, जो लंबे समय से जर्जर हालत में थी, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने करीबन 26 करोड़ के आस पास की लागत की सड़क है, इस बजट में घोषणा की है। इसके लिये न केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से बल्कि इस रोड से गुजरात, मध्यप्रदेश और राजस्थान के तीन चार जिले जो इस क्षेत्र से लाभान्वित होते हैं, उन सबकी तरफ से मैं माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

गौरव पथ हमारा वास्तव में एक अभिनव प्रयोग है। पानी जहां भरता है वहां डामर की सड़कें टूट जाया करती थीं, बहुत अच्छी क्वालिटी की सीमेंट की सड़कें पंचायत मुख्यालय पर बन रही हैं, वह उदाहरण का रूप ले चुकी हैं। आज हर व्यक्ति, हर पंचायत यही मांग करती है कि हमारे तो डामरीकृत सड़क की बजाय गौरव पथ निर्मित किया जाए। आने वाले समय में एक भी पंचायत मुख्यालय गौरव पथ से वंचित नहीं रहेगा, ऐसी अपेक्षा करता हूं।

नाबार्ड योजना में पांच हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की 1518 के कार्य शुरू कर दिये हैं। आरआईडीएफ 23 के तहत भी 800 करोड़ की लागत से 5 हजार किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान इस बजट में लिया है, वास्तव में यह तारीफ के काबिल है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इससे पहले जब हम 2013 में चुनकर आये डूंगरपुर जिले की एक भी सड़क वाहनों के आवागमन के लायक नहीं थी, अब मात्र तीन सड़कें ऐसी रही हैं जो जर्जर हालत में हैं। डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में डूंगरपुर से पालपादर वाया साबली, बोखला सड़क जो करीबन 32 किलोमीटर है। इसी तरह एक सड़क डूंगरपुर से देव सोमनाथ जो घडा मरिया होकर जाती है, वह क्षतिग्रस्त है। साथ ही एक बामडी देवल सड़क है वह थोड़ी सी तकलीफ वाली है। मैं अपेक्षा करता हूं कि इनका चौड़ाईकरण, नवीनीकरण हो जाए तो निःसंदेह इस क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

माननीय सभापति महोदय, खनिज में सड़कें, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में करीबन 30 प्रतिशत एरिया पूरा खनिज एरिया है। पहले वहां से कम लोड वाले वाहन गुजरा करते थे, अभी 22 चक्का, 18 चक्का इस तरह के बडे वाहन जो लोड लेकर जाते हैं, कोई भी सड़क वहां निर्मित होती है तो ओवरलोड वाहनों की वजह से 6 महीने से ज्यादा टिकती नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में देवल से लेकर कोटाणा मेहताली, खेमारू घडा मोरिया और रोहनबाड़ा, ये 30 किलोमीटर की सड़कें बनती हैं। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, पहली बार समय मिला है और दस मिनट भी नहीं हुए, मेरे दो-तीन पाइंट ही हैं, ज्यादा नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदया और हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री से हमने निवेदन किया है। ये सड़कें खनिज महत्व की हैं और अगर इनका सुदृढ़ीकरण कर लिया जाता है तो डूंगरपुर जिले में एक भी सड़क ऐसी खराब हालत की नहीं होगी और क्षेत्र का विकास भी बहुत जल्दी होगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में टोटल 198 गांव हैं। 198 गांवों में झालन, बोलोदरा, काला-पन्ना, खैरवाड़ा, माकरेडा, सलिया, नान का नाला, धमलाफलां, ये गांव ऐसे हैं, जो आबादी के क्राइटेरिया में आ रहे हैं और सड़कों से नहीं जुड़े हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि ये सड़कें भी हमारे इन गाँवों को जोड़ देंगी।

परिवहन के मामले में बजट में सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड का उद्धार करने का प्रावधान तो है, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में आबादी के हिसाब से जो बसें संचालित थीं, ऐसे दस रूट हैं, जो वास्तव में प्राफिट के रूट थे और वे बसें बंद हुई हैं। जिसमें एक तो डूंगरपुर से जयपुर बस जो शाम के टाइम चलती थी, वह बंद हुई है। दूसरी, डूंगरपुर से पालीसोड़ा बस चल रही थी, वह भी बंद हुई है। डूंगरपुर से मालमाथा, डूंगरपुर से बेनड़ा, डूंगरपुर से संचिया, डूंगरपुर से गामड़ी देवल, डूंगरपुर से हिम्मतपुर, डूंगरपुर से गलंदर और बिछिवाड़ा से हिम्मतपुर बसें जो संचालित हो रही थीं, वे बंद हुई हैं, जिससे क्षेत्र में काफी परेशानी आ रही है। मैं अपेक्षा करता हूं कि ये बसें पुन: शुरू हों। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

इसके अलावा नए रूट, जो कि लंबे समय से सरकारी बस की अपेक्षा करते हैं, डूंगरपुर से पालपादर वाया साबली, डूंगरपुर से पीतापुर है जो कि

(श्री देवेन्द्र कटारा)
इंटीरियर क्षेत्र है। डूंगरपुर से बरोटी संचिया है और डूंगरपुर से बिजोड़ा गांव है, नई बसें, वहां नए रूट स्वीकृत करके शुरू कराने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में काफी कुछ सुधार हुआ है और डूंगरपुर में तेज गति से सभी बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन देने का कार्य शुरू कर दिया है। टेण्डर भी हो चुके हैं और करीब-करीब दिसम्बर, 2017 तक कार्य पूरा करने का उनका लक्ष्य है। डूंगरपुर का आधा क्षेत्र कवर हो चुका है। वास्तव में, ये बधाई के पात्र हैं। माननीय सभापति महोदय..। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मात्र चार पत्ते हैं और एक पत्ता ही मैं बोला हूं।

श्री सभापति: आपके पास कितने पत्ते हैं, वह ध्यान नहीं, पर बाकी सब पत्ते एक मिनट में खोल दो।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): एक पत्ता पढ़ लिया है, दूसरा थोड़ा-सा बाकी है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): पढ़कर ही बोल दो।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): पढ़कर ही बोल दूं, पर वही लिखा है जो बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, बजट में खनन के पट्टों के बारे में काफी कुछ दर्शाया है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में पूरी तरह से खनन के पट्टे जो केंद्रीय पेसा एक्ट, 1996, पेसा एक्ट, 1999 और पेसा रूल्स, 2011 के तहत केवल वहां के निवासियों या वहां के निवासियों की सोसाइटी बनाकर खुद खनिज का खनन करने का प्रावधान है। लेकिन उस क्षेत्र में आज जितने भी पट्टे जारी किए गये हैं, वे उन क्षेत्र के लोगों के हाथों में नहीं है। वहां की सारी की सारी कमाई बाहर जा रही है और वहां पट्टाधारी को उस क्षेत्र के विकास के लिए चिकित्सा, शिक्षा और वहां की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कम-से-कम 20 परसेंट राशि वहां सुरक्षित रखनी है, इसके बावजूद एक भी पट्टाधारी ने न उस क्षेत्र में काम किया है, उलटा पूरी तरह से दोहन किया है, शोषण किया है और क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं दिया है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): मैं समझता हूं पेसा एक्ट, पेसा रूल्स और भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत वहां के लोगों को जो भारत के संविधान में पालिसी बनी हुई, **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)** उस पालिसी के तहत अगर खनन किया जाता है तो निःसंदेह उस क्षेत्र का विकास होगा, उद्धार होगा। वहां के लोग पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के मामले में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा क्षेत्र पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। फोर वाटर कनसेप्ट और इर्रिगेशन दोनों विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फोर वाटर कनसेप्ट में बजट का प्रावधान तो रखा है, लेकिन पिछले बजट में भी डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र और पूरा डूंगरपुर जिला छोड़ दिया गया था। इस बार भी वहां तालाब, एनिकट बनाने की पूरी गुंजाइश है। पूरा पानी बहकर गुजरात जा रहा है। वहां न तो कोई बड़ी औद्योगिक इकाई है, न किसानों की खेती के लिए सिंचाई के पानी की व्यवस्था है।

श्री सभापति: आ गया। सरकार के नॉलेज में आपकी बात आ गयी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, एक जो तालाब बना हुआ है, प्लान में ले लिया, नहर में ले लिया, लेकिन मौक़े पर नहर भी नहीं बनी। किसानों को पानी नहीं मिला और पिछले तीन साल से उस तालाब का एक बूंद पानी भी खेतों की सिंचाई के उपयोग में नहीं आया है।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य नारायण सिंह जी देवल।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरी डिमांड ही आपको बता देता हूं।

श्री सभापति: आपकी डिमांड आप बता देना।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): मैं डिमांड ही बता देता हूं कि मेवाड़ा सिंचाई परियोजना, भजियाणा बांध, फारकी माता बाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर, सुरवैया

(श्री देवेन्द्र कटारा)
वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और पिपलावाला डेरा बांध, इन तीन-चार तालाबों को फोर वाटर कनसेप्ट और इर्रिगेशन की अन्य स्कीम में लेकर अगर इनको बांध दिया जाता है तो न केवल वहां के लोगों की सिंचाई की व्यवस्था होगी, पीने के पानी की व्यवस्था होगी और वह पानी क्षेत्र की जनता के लिए लाइफ लाइन बन जाएगा। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री नारायण सिंह जी देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा पेश चौथे बजट पर आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद पेश करता हूं। 2017-18 का जो बजट पेश किया, यह बजट सर्वांगीण विकास का बजट है और इस बजट की पूरे राजस्थान भर में हर वर्ग ने प्रशंसा की है। मैं भी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई और आभार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने विजन ट्वेंटी-ट्वेंटी को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया और इसी के साथ राजस्थान विकास के पथ पर अग्रसर होगा।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में राजस्थान बीमारू प्रदेश की श्रेणी आ चुका था। हमेशा ये लोग खजाना खाली है, ऐसा रोना रोते थे। पिछली सरकार में बिजली की क्या हालत थी, पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता जानती है। कानून व्यवस्था तार-तार हो गयी थी। सड़कों की हालत पूरे राजस्थान में बहुत खराब थी और पिछले पांच साल में सरकारी भर्तियां भी बहुत कम हुईं। खूब सारे फर्जी राशन कार्ड भी बने और नरेगा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। माननीय मुंख्यमंत्री जी ने जो ई-गवर्नेंस लागू किया है, उससे हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन हुआ है और डिजीटल क्रांति के माध्यम से आज राजस्थान आगे बढ़ रहा है। आज राजस्थान में जन-कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई हैं, जैसे - भामाशाह योजना, इसमें राजस्थान को गोल्ड

(श्री नारायण सिंह देवल)

मैडल मिला। स्किल डवलपमेंट में राजस्थान आज दूसरे नंबर पर है। सौर ऊर्जा में आज राजस्थान एक नंबर पर है और स्वच्छ भारत अभियान में राजस्थान एक नंबर पर है। इस सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार खोले और इसमें उचित मूल्य पर खाने-पीने की ब्रांडेड सामग्री, आज राजस्थान की जनता वाह-वाही कर रही है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' में भी देश के प्रधानमंत्रीजी से हमारी मंत्री जी को नारी-शक्ति पुरस्कार मिला, यह हमारे राजस्थान के लिए गर्व की बात है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा के बारे में बताना चाहूंगा। मुझे याद है पहले के समय घरों के अंदर बिजली तब आती थी जब कृषि के लिए बिजली आती थी। 2003 से 2008 में प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुन्धरा राजेजी ने कृषि और घरों के सिंगल फेस के कनेक्शन को अलग किया।

आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान में घरों के अंदर 22 से 23 घंटे बिजली मिल रही है। आज किसानों को साढ़े छह घंटे दिन में और सात घंटे रात्रि में अच्छी क्वालिटी की बिजली मिल रही है। इन लोगों ने जब 31 मार्च, 2013 को सत्ता छोड़ी थी तब राजस्थान की जनता के ऊपर 72 हजार, 724 करोड़ रुपये का कर्ज लादा। इस सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उदय योजना के तहत 62 हजार 421 करोड़ रुपये, इस ऋण को टेक ओवर करके, बिजली कम्पनी को एक बहुत बड़ी राहत दी है।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार में पांच साल के अंदर 2957 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ और हमारी सरकार ने तीन साल में, अभी तक 4752 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर दिया है। इन तीन साल में पूरे राजस्थान में किसानों को एक लाख 27 हजार कनेक्शन दे चुके हैं। आगामी दो साल में एक लाख कनेक्शन की मुख्यमंत्रीजी ने इस बजट में घोषणा की है। तीन साल में राजस्थान में 17 लाख 87 हजार घरेलू कनेक्शन भी दिए गये हैं।

मैं पेयजल के बारे में भी कहना चाहूंगा। हमारे मंत्री महोदय भी यहां विराजमान हैं। पूरे राजस्थान में एक लाख 21 हजार 648 गांव ढाणियों में से 55 हजार 25 ढाणियां पेयजल से 2016 तक जुड़ चुकी हैं। गत सरकार में

(श्री नारायण सिंह देवल)

तीन वर्षों में 6 हजार 97 करोड़ रुपये पेयजल पर खर्च किए थे, हमारी सरकार ने तीन वर्ष में 13 हजार 473 करोड़ रुपये खर्च किए, जो लगभग दुगना है। आगामी योजना में 2 हजार 500 गांव और ढाणियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान के कई गांवों में फ्लोराइड़ है। अभी तक 895 आर ओ प्लांट लग गये है और एक हजार 66 आर ओ प्लांट के लिए 245 करोड़ की स्वीकृति जारी हो गयी है। अगले 1446 आर ओ प्लांट राजस्थान में लगेंगे।

मैं सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने तीन साल के अंदर 20 हजार 822 करोड़ रुपये खर्च करके 4 हजार 281 गांव ढाणियों को सड़कों से जोड़ा है, जबकि गत सरकार ने तीन वर्ष में 9 हजार 157 करोड़ रुपये खर्च करके मात्र 661 गांव और ढाणियों को सड़कों से जोड़ा था। पिछले तीन साल में 15 हजार 278 किलोमीटर लंबाई की नवीन सड़कों का निर्माण कर 4 हजार 637 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं जबकि गत सरकार ने पांच वर्षों में मात्र 12 हजार 554 किलोमीटर सड़क बनाई जिसमें 2 हजार 993 करोड़ रुपये खर्च किए गये।

इसी तरह से इस वर्ष नाबार्ड में 800 करोड़ की लागत से 5 हजार किलोमीटर से अधिक की सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्रीजी पंचायत मुख्यालय पर हमारी जो मुख्य सड़क है उसके लिए ग्रामीण गौरव पथ योजना लाईं। फर्स्ट फेज के अंदर एक हजार 972 ग्राम पंचायतों में 1720 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। सैकिण्ड फेज में 2 हजार 86 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 2 हजार 98 किलोमीटर के गौरव पथ बनेंगे। अगले साल 1200 करोड़ की लागत से गौरव पथ और मिसिंग लिंक के काम सड़कों के अंदर होंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा कि पिछले बजट के अंदर हमारे जालौर जिले को नेशनल हाइवे, जालौर से लगाकर भीनमाल करड़ा होते हुए सांचौर को दिया। उसके लिए पूरी जनता मुख्यमंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती है।

चिकित्सा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर 1715 बीमारियों को शामिल करके भामाशाह स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्रीजी लाई हैं,

(श्री नारायण सिंह देवल)

इसमें करीब 67 परसेंट लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें 30 हजार से लेकर 3 लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज करवाया जा सकता है। इसके अंदर 300 करोड़ की अभी तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी है। सभापति महोदय, गरीब आदमी, साधारण और छोटे से छोटे हास्पिटल में इलाज करवाता था परंतु भामाशाह योजना के माध्यम से बड़े से बड़े, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हों, उसमें इलाज करवा सकता है।

सभापति महोदय, डाक्टर्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले पांच साल में 1453 डाक्टर्स की भर्ती की गयी और इस सरकार ने 4 हजार 164 डाक्टर्स की भर्ती की।

किसान के खेतों की उर्वरक क्षमता कैसे बढ़े इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 29 लाख सॉइल हैल्थ कार्ड बनाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गयी। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत में राजस्थान नम्बर वन पर है। पूरे राजस्थान में 3407 करोड़ की लागत से 46 लाख परिवारों के लिए शौचालय बनाए गये। पूरे राजस्थान में 3553 ग्राम पंचायत ओडीएफ हुईं।

हमारा जल स्तर दिनों दिन घट रहा है इसके लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान लाया गया। फर्स्ट फेज में 3529 गांवों में काम हुआ। सैकिण्ड फेज में करीब 4200 गांवों का काम होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में, 5 हजार ग्राम पंचायत मुख्यालय क्रमोन्नत हुए। यह ऐतिहासिक कदम है। 86 हजार पदोन्नति दी गई, 37 हजार अध्यापकों की भर्ती हुई। एक लाख से अधिक अध्यापकों के काउंसिल के माध्यम से जिन-जिन जगह पर अध्यापकों की कमी थी, सारे पद भर दिए गये।

राजश्री योजना लाई गयी। 5 हजार अन्नपूर्णा भण्डार खोले गये। बहुत सारे काम राजस्थान में हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक राजकीय महाविद्यालय खोला जाए। रानीवाड़ा विधान सभा में सुंधामाता का मंदिर है,

(श्री नारायण सिंह देवल)
हर साल वहां 40 लाख लोग आते हैं, वह सड़क खराब है, उस सड़क को ठीक करवाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री राजकुमार जी शर्मा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पूरे सदन को होली की बहुत-बहुत बधाई देता हूं। यूपी और उत्तराखण्ड में आप लोग जीते, उसके लिए आपको बधाई और पंजाब, मणिपुर, गोवा में यह जीते इनको बधाई। ...(व्यवधान)... मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा बहुमत किसको है, उसकी बात कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उससे न केवल आम जनता, वैसे आप लोगों में, हममें ज्यादा फर्क नहीं है। आप लोग पहले तारीफ करते हो और बाद में अपनी पीड़ा जाहिर करते हो लेकिन जब पीड़ा जाहिर करने का समय आता है तब सभापति जी बैल को दबाने लग जाते हैं। हम हमारी पीड़ा से शुरूआत करते हैं, अच्छी चीज हैं उसको बाद में एप्रिशिएट भी करेंगे, इसमें क्या बात है। आम जनता ही नहीं बल्कि हमारे साथी विधायक, क्योंकि सबसे बातचीत होती थी, सब लोग खुश थे इस बार चुनावी बजट आएगा। जब बजट आया तो उसके बाद सब लोगों के अंदर एक निराशा का भाव छा गया। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चौथा बजट आता है तब लोगों को उम्मीद रहती है कि अगले साल चुनाव है तो इस बजट के अंदर हर क्षेत्र को कुछ न कुछ मिलेगा। ऐसी घोषणाएँ होंगी तो जनता को सीधा फायदा पहुंचेगा और फायदे का हिस्सा विधायक के कोटे में भी आ जाएगा। लेकिन इस बजट में सभी को निराशा हुई। अब मैं कुछ चीज बोलूंगा, आप लोग यह मत कह देना कि साढ़े तीन साल पहले जो सरकार थी, उसने क्या किया। उसको तो भूल जाओ। क्योंकि अब साढ़े तीन साल बीत गये। अब चौथा बजट है तो साढ़े तीन साल के अन्दर आपने क्या किया, उस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

बजट में हम सब लोगों ने यह अपेक्षा की थी कि राज्य में रिफाइनरी की घोषणा होगी, नये जिले बनेंगे, नई तहसीलें-उप तहसीलें बनेंगी, नये सैटेलाइट अस्पताल खुलेंगे, नई सी.एच.सी., पी.एच.सी. खुलेंगी, आपके घोषणा

(डा. राजकुमार शर्मा)
पत्र के अनुसार हर उपखण्ड मुख्यालय के ऊपर बालिका महाविद्यालय खुलेगा, बालकों के लिये महाविद्यालय खुलेगा, बड़ी परियोजनाएं आएंगी, बेरोजगारों के लिये सरकारी नौकरियों की घोषणा होगी, सरकारी कर्मचारियों के सातवें वेतनमान की सिफारिश भी लागू होगी। ऐसी घोषणाएं हमने सोची थीं कि इस बजट में निश्चित रूप से होंगी। लेकिन वे नहीं हुईं।

सबसे बड़ी ताज्जुब बात है कि हमारा झुंझुनूं जिला, मुझे तो लगता ही नहीं कि राजस्थान में है क्या। लगता है कि इसको या तो पंजाब में भेज दिया या हरियाणा हमारा पड़ौसी है, हरियाणा में शामिल कर दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो कुछ भी झुंझुनूं के नाम से इस किताब के अन्दर लिखा गया है, वह नये पैकेट के अन्दर पुरानी चीजें डाल दीं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि आपने पैरा नम्बर 179 में लिखा है कि झुंझुनूं में वॉलीबाल अकादमी की स्थापना की जाएगी। बल्कि वहां पर चार साल से वॉलीबाल अकादमी चल रही है। आप सदन के अन्दर या तो उन अधिकारियों को दण्डित कीजिये कि मुख्य मंत्री महोदय को इन लोगों ने गुमराह क्यों किया। आपने इस बार इसमें दो करोड़ रुपये का बजट दिया है, वह काबिल-ऐ-तारीफ है। लेकिन आपने यह कैसे लिख दिया कि हम लोग इस बार स्थापना करेंगे, जबकि चार साल से हमारे वहां पर वह स्थापना हो चुकी है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): कागजों में स्थापित है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): नहीं, नहीं, भैया, चल रहा है वहां पर, आप जाकर देखिये, झुंझुनूं के अन्दर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात कर ली। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आज से पांच साल पहले खुल गयी। तीन साल तक वाइस चांसलर उसमें रह कर भी चले गये और आज वह परिस्थिति है वहां पर कि खेल के नाम पर जो एक विकास की बात की थी, चाहे पिछली सरकार ने, इस सरकार ने, दोनों सरकारों ने उस काम को नहीं किया।

माननीय पी.डबल्यू.डी. मंत्रीजी ने कहा कि मुकुन्दगढ़ को डीडवाना से जोड़ दिया है, जो भी इन सड़कों की घोषणा हुई है, वह ज्यादातर सड़कें टोल रोड्स हैं। अब उन टोल रोड का किन पर फर्क पड़ने वाला है। सीधा-सीधा जनता पर असर पड़ने वाला है। जनता को आपने सड़कों की सौगात नहीं दी है, आपने जनता को, विशेष तौर से झुंझुनूं की जनता को तो सदमा दिया

(डा. राजकुमार शर्मा)

है। वह सदमा इस रूप में दिया है कि पहले सीकर से लेकर लुहारू तक जिस टोल रोड से पीछा छुड़ाने के लिये लोगों ने जन-आन्दोलन किये, आज उनको आप वापस उसी चीज को देना चाहते हो। आज पूरा झुंझुनूं जिला ही नहीं, पूरा शेखावाटी क्षेत्र इस बात से त्रस्त है कि हमने क्या गुनाह कर दिया। नवलगढ़ का तो मैं मानता हूं कि हमने राज्य सभा के अन्दर आपके सामने चुनाव में खड़े किये, वे हमारे नवलगढ़ के थे, इसलिये आपका जो गुस्सा है वह जायज भी है। लेकिन झुंझुनूं जिले का क्या दोष है। नवलगढ़ की बात मैं करना चाहता हूं और विशेष तौर से ग्रामीण गौरव पथ के बारे में आप सब लोगों ने कहा। अभी जोशीजी, जो बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, वे भी कह रहे थे कि आप लोग तारीफ करो। तारीफ क्या करें, हंसी तो आपके चेहरे पर भी है, हमारे पर भी है। इसलिये जो उन्होंने शेरो-शायरी की, चार लाइन के माध्यम से उनको मैं एक जवाब देना चाहता हूं, सभी सदस्यों की तरफ से, 'दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आधियां जमाने की, मेरे गम को कोई समझ न पाया, क्योंकि मेरी आदत थी हमेशा मुस्कराने की'। ...(व्यवधान)... मुस्कराने की, आप भी मुस्करा रहे हो, महाराज। अन्दर ही अन्दर आप चोट खाये हुए हो, लेकिन ऊपर ही ऊपर आप सब मुस्करा रहे हो, हम भी मुस्करा रहे हैं। सदन के अन्दर मेरे सैकड़ों साथी हैं, यहां पर बैठे हैं, पक्ष-विपक्ष के, मेरी सबसे दोस्ती है। लेकिन वे कहते हैं कि हमें तो सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई इलाज नहीं है।

जो भी सड़कों की घोषणा हुई, यूनुस खान साहब ने पहले घोषणा की थी, इस बार बजट में शामिल कर लिया, कोई बात नहीं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदया, आप अपने पी.डबल्यू.डी. मिनिस्टर को डांटिये। उन्होंने 199 विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर ग्रामीण गौरव पथ स्वीकृत कर दिये, काम भी चालू करा दिया। लेकिन नवलगढ़ के अन्दर वे राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। आप लोग कहते हो, आपने एक पूरा नारा दिया कि 'सबका विकास-सबका साथ', तो नवलगढ़ ने क्या गुनाह कर दिया। गुनाह डा. राजकुमार ने किया, तो वह जनता तो आपकी है। मैं मैडम से निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्री महोदया से कि आप कम से कम गौरव पथ

(डा. राजकुमार शर्मा)

वापस दो, मिसिंग लिंक जो सब जगह दे दी, सिर्फ नवलगढ़ को आपने उससे क्यों वंचित रखा। आपने सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से आम जनता से बड़े-बड़े वादे किये थे। गुरु गोलवलकर स्कीम, वह योजना इस बजट में भूल गये। 2003 में आपने इस योजना को चालू किया। 2008 में कांग्रेस की सरकार आई, उसने बंद कर दिया। 2013 में आप वापस आये, आपने वापस घोषणा की कि गुरु गोलवलकर योजना को हम लोग अब गांव-गांव तक लेकर जाएंगे। आपसे त्रुटि हो गयी। माननीय मुख्य मंत्री महोदया, जब रिप्लाई दें तो इस योजना के अन्दर बजट का प्रावधान रखवा दो, वर्ना गुरु गोलवलकर साहब आपसे नाराज हो जायेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 125 करोड़ का प्रावधान है, आप बजट पढ़ लो, 125 करोड़।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं आपको अब भी कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पिछली बार 100 करोड़ का प्रावधान था, इस बार 125 करोड़ का प्रावधान है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): जवाब मान लिया मैंने। इनका जवाब है, वह भी मान लिया मैंने, और इनकी वास्तविकता भी बताऊंगा, भाई साहब की, आगे भी।

गाय माता ढूंढ़ रही है आप सबको। साधु-संत आपको ढूंढ़ रहे हैं। बाबाजी ढूंढ़ रहे हैं आपको। गऊ माता का अनुदान खा गये। बड़ी मुश्किल से बाबाजी ने जाकर मुख्य मंत्रीजी को कहा कि मुख्य मंत्री महोदया, आपने मेरे को गो-पालन का अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन पैसा तो दो। साधु-संत आकर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि बाबाजी आप तो गो-भक्त हो, आप तो कम से कम गो-माता की सेवा करो। आज जिस तरह से, मैं आपको सच कह रहा हूं कि, राजस्थान की 36 कौम की जनता आपको ढूंढ रही है, गो-माता भी ढूंढ़ रही है, उसके सींगों का ख्याल रखना आप।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गोपालन): अनुदान दे दिया।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अनुदान दे दिया। बाबाजी, वह आपकी जान जानती है, आपकी आत्मा जानती है कि वह अनुदान आप कैसे लेकर आये हो। लेकिन बढ़िया है।

(डा. राजकुमार शर्मा)

सभापति महोदय, मैं युवाओं के लिये कहना चाहता हूं कि 15 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन आज तक कितनी नौकरियां दीं। आज बेरोजगारों की क्या स्थिति है, 09 लाख की बात करते हैं।

श्रीमती अनीता (नगर): 11 लाख।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 11 लाख तो, माननीय सदस्या, जब आप क्षेत्र में जाएंगी तब पता चल जाएगा। मैं कुछ नहीं चाहता। मैं तो आपके मन की बात कह रहा हूं। जो बात आप विपक्ष में रह कर कह सकते हो, वह मैं कह रहा हूं तो आप चुप रहिये ना एक बार। आप सुनो, आपके दिल की भावना मैं सरकार को बताना चाहता हूं।

आज बेरोजगार युवा नौकरी के लिये मारे-मारे फिर रहे हैं। सरकार उन पर डण्डे बरसा रही है। चाहे वह होमगार्ड हों, विद्‌यार्थी मित्र हों, संविदा कर्मी हों, रोजगार मांगने पर जिस प्रकार से सरकार उनको रिलीफ देने के बजाय डण्डे मार रही है। आपने सरकारी नौकरियों के पद तो विज्ञापित कर दिये, लेकिन आज अधिकांश भर्तियां किसी न किसी कारण से माननीय न्यायालयों के अन्दर लम्बित हैं।

पंचायती राज में, पंचायती राज मंत्रीजी, अब बने हैं आप तो, ग्राम सहायक का एक पद क्रियेट किया गया और ग्राम सहायक को सरपंच को अधिकार दे दिये कि आप दो ग्राम सहायक के रूप में भर्ती कर लो। वह भर्ती अटक गयी। क्योंकि वह विधि के अनुसार थी ही नहीं। आप सरपंच को कैसे इस परीक्षा के घेरे में डाल सकते हो कि वह पूरे गांव का विरोध लेकर किन्हीं दो व्यक्तियों को, अपने चेहतों को वहां नौकरी दे देगा। किस आधार पर, और वही चीज आपने उसके बाद में स्कूलों के अन्दर विद्‌यालय सहायक के रूप में ले ली। आज विद्‌यालय सहायक, आपके प्रिंसिपल और एस.डी.सी. के सदस्य मुंह छिपाते घूम रहे हैं कि हम किसको डालें। हजारों बच्चे जाकर कोर्ट के अन्दर खड़े हो गये कि ये लोग सिर्फ अपने-अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रख रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आपके कार्यकर्ताओं का भी ध्यान नहीं रखोगे, क्योंकि उस स्कूल के आसपास आपके सैकड़ों कार्यकर्ता रहते हैं, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता रहते हैं, अगर दो कार्यकर्ताओं को ओब्लाइज भी कर दिया तो 98 कार्यकर्ता तो नाराज होंगे। तो आप इस तरह का जनता के बीच

(डा. राजकुमार शर्मा)
में क्या मैसेज देना चाहते हो, मुझे नहीं पता।

चिकित्सा राज्य मंत्रीजी बैठे हैं। इस विभाग में काम करने का मुझे भी सौभाग्य मिला है। आज मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि भामाशाह, आज आप ही का स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, 'निजी अस्पताल तो मरीजों को लूटते हैं: बाजिया'। 'निजी अस्पताल तो मरीजों को लूटते हैं', बहुत सम्मानित अख़बार है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया ने बुधवार को एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने यहां भा.ज.पा. कार्यालय में कार्यकर्ताओं से कहा, यदि जयपुर में किसी बीमार को डाक्टर को दिखाने में परेशानी आ रही हो तो सीधे मेरे पास आ जाएं। इनके जो बड़े साहब हैं, वे भी कह रहे हैं मेरे पास आ जाएं, ये भी कह रहे हैं मेरे पास आ जाएं, तो आपके पास आते-आते क्या एम्बुलेंस के अन्दर दम तोड़ दें। ...(व्यवधान)...

श्री बंशीधर (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): आप मेरी बात सुनिये। आप अख़बार के आधार पर बोल रहे हैं। मैंने ऐसा बयान नहीं दिया। मैंने बोला था, निजी अस्पतालों में लुटो मत, आप सरकारी अस्पतालों में आइये। निजी अस्पताल अच्छा इलाज नहीं करते, मैंने यह कहा है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मेरी बात सुनिये। मैं आपको कब कह रहा हूं।

श्री बंशीधर (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): जब सरकार आपको फ्री में इलाज दे रही है तो वहां लुटने का क्या काम है। मैंने यह कहा है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं तो जो पब्लिक में चीज गयी है, उसको बताना चाहता हूं और आपने सच बोल भी दिया तो आप डरते क्यों हैं। आप इतने मर्द मंत्री हैं, क्यों डर रहे हैं आप।

श्री बंशीधर (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): मैं कहूंगा सच ...(व्यवधान)... आप सरकारी हास्पिटल में आइये और इलाज हम कराएंगे।...(व्यवधान)...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आपको डरने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): जोर से बोलकर आप असत्य को सच करवा लोगे क्या।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): इतना दबंग मंत्री मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): जोर से बोलकर असत्य को सच करवा लोगे क्या।

श्री बंशीधर (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): इसीलिये मैं कह रहा हूं। मैंने बोला वहां लुटो मत। आप सरकारी अस्पताल में आइये, इलाज हम कराएंगे, आप सबका कराएंगे अपन।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मंत्री महोदय, आज घंटों इंतजार, फिर भी नहीं आया नम्बर। सात घंटे की कतार, गश खाकर गिरे बुजुर्ग। एस.एम.एस. अस्पताल जिसके अंदर करोड़ों लोगों का ....(व्यवधान)....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अख़बार के आधार पर नहीं बोलना चाहिए यहां सदन में, केवल अख़बार के आधार पर नहीं ....(व्यवधान)....

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): देखिए, उसी के आधार पर अपन सब लोग चल रहे हैं। अभी सब बोल रहे हैं इसीलिए कि सुबह छप जाए। सारी, सब चीजें इसीलिए बोलते हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): कोई आधार हो तो बोलो।
(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। गंभीर विषय है चिकित्सा विभाग वाला। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब चिकित्सा मंत्री थे तो आपने पहले बजट के अंदर कहा कि 8 मेडिकल कालेज खोलेंगे। हम भी कह रहे थे कि 8 मेडिकल कालेज खोलेंगे। मैंने उस समय कहा था और आज भी कह रहा हूं कि एम.सी.आई. ने आपके आठों मेडिकल कालेजों को हरी झंडी नहीं दी है। उन्होंने खामियां निकाल दी हैं और उस समय मैं भी कहता था कि कोटा, बीकानेर, झालावाड़, उदयपुर और जोधपुर यह पांचों आपके मेडिकल कालेज वेंटिलेटर के ऊपर है। आज भी मैं कह रहा हूं क्योंकि जब एम.सी.आई. का इंस्पेक्शन आता है तो हम लोग जयपुर एस.एम.एस.

(डा. राजकुमार शर्मा)
मेडिकल कालेज से लोगों को वहां पर एक महीने के लिए ट्रांसफर करते हैं। यह पूरा राजस्थान जानता है। हमारे पास में जो पहले से सरकारी महाविद्‌यालय चल रहे हैं, हमारे मेडिकल कालेज, जब उनको चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है तो 8 कालेज जो आप खोलने जा रहे हो और वह भी कह रहे हो कि सरकार की तरफ से खोलेंगे, जो काम आपको पी.पी.पी. मॉडल पर करना चाहिए इन कालेजों को देने का, वह तो आपने किया नहीं। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय सभापति महोदय, कोई नहीं बोलेगा इधर से, बस मैं ही हूं बोलने वाला। आज हमने आपसे निवेदन भी कर लिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यही लास्ट हैं, कोई नहीं बोलेगा।

श्री सभापति: आपकी तरफ से तो हो गया पूरा कभी।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आप ट्रांसपोर्ट के अंदर पी.पी.पी. मॉडल लेकर आ गये, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क में लेकर आ गये, पेयजल में लेकर आ गये, उच्च शिक्षा में लेकर आ गये लेकिन मैं आपको भगवान का वास्ता देता हूं, भगवान श्रीराम का कि चिकित्सा क्षेत्र के अंदर तो यह पाप मत करो।

मेरे नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर गांव सोठवारा, उसकी पी.एच.सी. को पी.पी.पी. मॉडल पर दे दिया गया। सरपंच सहित वहां के गांवों के लोग दस दिन तक सड़कों के ऊपर संघर्ष करते रहे लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आज वहां पर निजी अस्पताल का चिकित्सक बैठा है। जब आपके राज्य मंत्री यह कहते हैं कि निजी अस्पताल लूटते हैं, आपने सरकारी उपक्रम को निजी हाथों में दे दिया तो आपकी इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि वह वहां पर गरीब जनता के साथ में न्याय करेंगे?

आज हमने तीन सालों में जितनी भी नई पी.एच.सी., सी.एच.सी. खोलीं, आप सबकी आत्मा जानती है। हमने उस समय न पक्ष देखा, न विपक्ष देखा, जो हमारे पास में आया हमने वहां सी.एच.सी., पी.एच.सी. दीं। सुबह

(डा. राजकुमार शर्मा)
हबीबुर्रहमान साहब बोले कि गुणावगुण के आधार के ऊपर, कालीचरणजी सराफ बोले कि मैं दे दूंगा। माननीय मंत्रीजी, लेकिन मैं कहता हूं कि हमने तो वहां की स्थिति देखी कि वास्तव में इतनी संख्या के अंदर लोग हैं तो यहां पर पी.एच.सी., सी.एच.सी. खोलनी चाहिए, वहां पर खोली।

आज चिकित्सा विभाग के अंदर पदों की स्थिति का आपको सबको पता है। भर्तियों की स्थिति क्या है, मैं उन आकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय सभापति महोदय मुझे जितना समय बोलने का दे रहे हैं, आज डाक्टर आप भर्ती कर रहे हो, आज अभी कहेंगे कि डाक्टर्स का वेतनमान आपने क्यों नहीं बढ़ाया? मैं कहता हूं कि साढ़े बारह हजार से, साढ़े सोलह हजार रुपये से बत्तीस हजार रुपये, पैंतीस हजार रुपये हमने किये थे, आप एक लाख रुपये कीजिए न। आप एक लाख रुपये कीजिए।

आपके सुराज संकल्प यात्रा में माननीया वसुन्धराजी ने जो घोषणा की थी कि मैं हर उपखंड मुख्यालय के ऊपर महिला चिकित्सक की नियुक्ति करूंगी ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो। आप महिला चिकित्सक की नियुक्ति तो भूल जाओ, ऐसी सैकड़ों पी.एच.सीज. हैं जिनमें आपके पास चिकित्सक ही नहीं है और वह चिकित्सक हमारे समय में भी नहीं थे, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होंगे। जब तक यह आठों मेडिकल कालेज बनकर तैयार नहीं हो जाते और उसमें से छात्र-छात्राएं निकाल कर डाक्टर हमारे बाहर नहीं आ जाते। यह हम पहले भी कहते थे और आज भी कहते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस डेढ़ साल के अंदर एम.सी.आई. ने आपकी आठ मेडिकल कालेजों को रोक दिया, उसके अंदर आपको कोई सफलता मिलेगी और वह दिक्कत, वह नुकसान आपको ही नहीं, हमको भी है।

मैं आप सब विधायकों की तरफ से माननीया मुख्या मंत्रीजी से कहना चाहता हूं और हमारी वकालत करेंगे, विधायक कोष दो करोड़ रुपये हैं। क्या होता है आजकल दो करोड़ रुपये में? ....(व्यवधान).... दो करोड़ रुपये हैं, सवा दो मान लो, तीन मान लो।

आज पी.एच.ई.डी. को एक कुआं अपन देंगे तो साढ़े आठ लाख रुपये पी.एच.ई.डी. वाले अपन से चार्ज करते हैं। 100 मीटर सड़क के चार-चार

(डा. राजकुमार शर्मा)

लाख रुपये पी.डब्ल्यू.डी. वाले चार्ज करते हैं। वह ही कुआं, अगर ट्यूबवैल अपन खुदवाएंगे तो दो लाख रुपये, तीन लाख रुपये में हो जाएगा लेकिन वही सरकारी उपक्रम पी.एच.ई.डी. साढ़े आठ लाख रुपये विधायक कोष से मांग करती है। तो मैं कह रहा हूं, मैं आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तो कह ही नहीं रहा, मत बढ़ाओ न। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)** लेकिन, दो करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये विधायक का कोष निश्चित रूप से होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां पर सैटेलाइट अस्पताल साढ़े तीन साल पहले खोला गया था। 90 परसेंट बनकर तैयार हो गया था। सौभाग्य से मेरे यहां पर जो तत्कालीन प्रभारी मंत्री थे वह चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ साहब थे, उस समय। मैं अनशन पर बैठा तो खुद आए और इन्होंने मुझे कहा मेरे छोटे भाई आप उठ जाओ और मैं सात दिन के अंदर इसका काम चालू करवा दूंगा। मुझे कहते हुए दु:ख है कि हमारा सैटेलाइट अस्पताल आज भी ज्यों का त्यों पड़ा है। साढ़े तीन साल के अंदर दस परसेंट काम नहीं करवा पाए आप लोग। हमारे सैटेलाइट अस्पताल के अंदर पहले 17 डाक्टर्स हुआ करते थे, जो पुरानी बिल्डिंग है और आज मात्र 4 डाक्टर है। मात्र 4 चिकित्सक हैं। इतनी बड़ी आबादी के अंदर हम लोग कैसे कर सकते हैं?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी अभी कह रहे थे, अरुणजी भाई साहब। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास आज से साढ़े तीन साल पहले 90 प्रतिशत बन गया था। दस प्रतिशत बनाने के लिए आपकी सरकार को अभी तक भी टाइम नहीं मिला है। आप सोचिए कि तीन साल पहले वह छात्रावास बनकर तैयार हो जाता तो शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चे वहां पर पढ़ते, गरीब बच्चे वह पढ़ते जिनके पास पैसे नहीं है। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): बस लास्ट दो-तीन बिंदु और हैं मेरे तो।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा समाज कल्याण मंत्री महोदय से कि वह समाज कल्याण का छात्रावास आपकी नजर में मैंने डाल दिया है। उसको आप चालू करवाइये ताकि बच्चे उसका फायदा उठा सकें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

इंदिरा गांधी केनाल आधारित चौधरी कुंभाराम लिफ्ट केनाल, शुरू के अंदर यह योजना बनी थी, तब इसके अंदर नवलगढ़ का नाम था। लेकिन तत्कालीन पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी ने जब वापस इसकी डी.पी.आर. बनाई और प्रशासनिक स्वीकृति 25.08.2016 को जारी की उसमें नवलगढ़ का नाम ही हटा दिया। मैंने क्या बुरा कर दिया? मैडम, मैंने क्या बुरा कर दिया? अगर मेरे से ही नाराजगी है तो कम से कम आप नवलगढ़ के लोगों को तो पानी पिलाने से वंचित क्यों कर रहे हो? अगर उदयपुरवाटी, मंडावा और पूरा जिला पानी पी रहा है तो नवलगढ़ को क्यों रोक रहे हो आप लोग? और आप चाहते हो कि वहां पर जन आंदोलन शुरू करें तो जन आंदोलन भी आप लोग देख लेना। जो सरकार सबको साथ लेकर सबका विकास करने का दम भरती हैं तो हमने भी सोच लिया कि चलो नवलगढ़ को भी एक बार हम लोग, अभी उच्च शिक्षा मंत्रीजी बैठी हैं, मैडम, सरकारी कालेज खोला था आज से तीन साल पहले, साढ़े चार सौ छात्र-छात्राएं मेरे यहां पर पढ़ते हैं। कला संकाय खोला था, आज भी कला संकाय ही है। आपने उसमें कहीं पर भी वाणिज्य संकाय या विज्ञान संकाय नहीं खोला।

आपने, कालेज शिक्षा विभाग द्वारा आठ हजार वर्ग मीटर भूमि की मांग की थी और हमने 1651.50 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध करवा दी। हम आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे थे। हमारे भामाशाह मोरारका जी पांच करोड़ रुपये देकर वहां पर भवन बनाना चाहते थे लेकिन आपने उस आठ हजार वर्ग मीटर को बढ़ा कर सोलह हजार वर्ग मीटर कर दी। माननीय सदस्य, मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि कौनसा ऐसा शहर है, जिसमें सोलह हजार वर्ग मीटर जमीन मिल जाएगी? अगर आठ हजार वर्ग मीटर हमने आपको सरेंडर कर दी, शिक्षा विभाग को समर्पित कर दी तो आप हमारे कालेज की बिल्डिंग के अंदर क्यों रोड़ा अटका रहे हैं? आपसे हम बजट भी नहीं चाहते। हम तो चाहते भी नहीं कि आप हमें बजट दो। हमारे पास बजट की व्यवस्था है लेकिन सिर्फ वह काम नहीं हो, इसका प्रयास आप लोग करते हैं।

सीवरेज योजना, यू.डी.एच. मंत्रीजी यहां पर नहीं है। सीवरेज की योजना के लिए पूरा शहर आंदोलनरत है। आपने कहा था कि 17 महीने में उस काम को पूरा कर देंगे, आज 13 महीने हो गये, 10 परसेंट भी काम नहीं

(डा. राजकुमार शर्मा)
हुआ सीवरेज योजना का। हम भी तारीफ करना चाहते हैं आपकी इस सरकार की। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

श्री सभापति: कृपया अपना वक्तव्य पूरा करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): लास्ट दो मिनट, माननीय सभापति महोदय, लास्ट दो मिनट, वादा है मेरा।

मैं तो तारीफ करना चाहता हूं आपके इस बजट की लेकिन तारीफ कैसे करें? दिल से तो रोने की आवाज निकलती है। यह सुन्दर काका, हमारे काका जितना भी पुलिंदा यहां पर देकर गये, वहां पर, काका, आपका चिड़ावा का हास्पिटल आपके राजकुमार ने पहले कर दिया था 30 से 50, इस सरकार ने आकर उसको खारिज कर दिया। अब सिर्फ आपको राज़ी करने के लिए एक झुनझुना पकड़ा दिया, जिस तरह से आपको लाल-बत्ती पकड़वायी है। थोड़ा सा गुस्से में आ जाओ, काका। आप बताओ इस सरकार को कि सुन्दर काका में भी दम है। हम आपके बच्चे हैं, हम आपका अनुसरण करते हैं।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): आपने तो कुछ करा ही नहीं, अब हमारी सरकार ने ही तो किया है। पहले तो किया ही नहीं। कागजों में कर दिया होगा, हुआ तो अब है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): नवलगढ़ में आठ महीने में 15 ई.ओ. बदल गये। आठ महीने में 15 ई.ओ. बदलना इस सरकार की नाकामी को दर्शाता है कि वास्तव में यह शहरी परियोजनाओं को, शहरी योजनाओं को किस तरह से काम में लेना चाहते हैं। आठ महीने में, माननीय सभापति महोदय, 15-15 ई.ओ. बदलना, क्या कोई व्यक्ति चेयरमैन का काम कर पाएगा? दु:ख इस बात का है कि माननीय प्रभारी मंत्रीजी उस समय नवलगढ़ के इंचार्ज थे और इनको तीन ही सीटें मिल पाईं, इसमें मैं क्या करूं? उसमें मैं क्या करता? **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)** तीन सीटें दी हैं, नवलगढ़ के लोगों ने।

श्री सभापति: धन्यवाद।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): तीन बजट में नवलगढ़ का कोई जिक्र तक नहीं किया, इस बजट में नवलगढ़ का नाम भी नहीं आया, ऐसे बजट

(डा. राजकुमार शर्मा)

का मैं पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं और नवलगढ़ के साथ की जा रही राजनीति, राजनीतिक भेद-भाव, उपेक्षा का घोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अजीत सिंहजी।

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय सभापति महोदय, आपने मुख्य मंत्रीजी के 8 मार्च, 2017 को प्रस्तुत 2017-18 के बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी विचारधाराएं होती हैं, उनके अनुरूप सत्ता में आने पर शासन करते हैं। पूंजीवाद में मानव को एक आर्थिक इकाई माना है, साम्यवाद में व्यक्ति को मात्र एक राजनीतिक कार्मिक इकाई माना है और समाजवाद में व्यक्ति को एकांगी माना है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को मानने वालों में हैं। हम एकात्म मानववाद में व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और फिर मानवता की चराचर सृष्टि का विचार किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पिछले तीन साल में गरीब, पिछड़ों और दलितों के कल्याण और भलाई के लिये जितने काम किये हैं, वह कांग्रेस के 50-55 सालों के पिछले शासन कालों में नहीं हुए। हमारी सरकार बनने के बाद प्रदेश में गरीबों के उत्थान के लिये काफी कुछ किया गया है। सरकार की हर योजना गरीब, शोषित और समाज के निचले तबके को समर्पित है। हमारी सरकार की मंशा गरीब और गरीब वर्ग के उत्थान करने की है। राज्य सरकार की ओर से जो भी योजना लायी गयी है वह गरीब, पिछड़े और शोषित वर्ग के हितों के लिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश में जनता को यह चौथा बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाला बजट है। यह बजट विजन 2020 को आधार मानकर प्रस्तुत किया गया है। यह बजट केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्रदेश के

(श्री अजीत सिंह)
विगत तीन वर्षों की विकास यात्रा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर हम नया राजस्थान बनाएंगे। हमारी सरकार इस दिशा में तीव्र गति से काम कर रही है ताकि हम खुशहाल राजस्थान की अवधारणा को पूरा कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, उद्योगों के क्षेत्र में निवेश के लिये अनेक कार्यक्रम होते रहे हैं। लेकिन कृषि क्षेत्र में निवेश के लिये पहली बार इतना बड़ा प्रयास निश्चित रूप से काबिले-तारीफ है। राजस्थान में ग्लोबल एग्रोमीट 2016 में 38 निवेशकों ने सरकार के साथ प्रत्यक्ष रूप से 4 हजार 400 करोड़ 89 लाख का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था। इस निवेश प्रस्ताव के क्रियान्वयन होने के उपरान्त राज्य में लगभग 47 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। उक्त परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि भी एक से पांच वर्ष की है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के अंदर इन सवा तीन सालों के अंदर विशेष रूप से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने भामाशाह योजना, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, राजश्री योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, प्रधान मंत्री जन-धन योजना, अटल पेंशन योजना, ऐसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से सीधे आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को कैसे लाभान्वित किया जाए, उसको देने का हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने प्रयास किया है।

सभापति महोदय, जिस तरह सड़कों की बात की गयी है, आज हम ग्रामीण गौरव पथ की बात करते हैं। शहरों की तर्ज पर गांवों को भी कैसे साफ-सुथरा बनाया जाए, इसकी चिन्ता हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने की। मैं मानता हूं 36 पंचायतों में से मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर 27 पंचायतों के अंदर सी.सी. रोड मय नाली के बनकर तैयार है। आज जिस तरह से गांवों का चेहरा बदला है, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार और अभिनन्दन करना चाहता हूं और उनसे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने शहरी गौरव पथ की बात की। जहां आज छोटी नगरपालिकाएं या नगर परिषद हैं, जिनकी स्थिति गांवों से भी ज्यादा बदतर थी, वह भी शहर की

(श्री अजीत सिंह)

तरह नजर आये, उसके लिये आपने शहर गौरव पथ देने की बात कही है, यह भी तारीफे-काबिल है। जिस तरह से आपने मिसिंग लिंक दी है, नोन-पेचेबल सड़कें दी हैं, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना दी है, हम कांग्रेस के तीन वर्ष के बजट को उठाकर देखते हैं तो उन्होंने 9,157 करोड़ रुपये तीन साल के अंदर खर्च किये तो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री के तीन वर्ष के शासन काल के अंदर 20 हजार 822 करोड़ रुपये सड़कों के ऊपर हमने खर्च किये हैं।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन की बात करूं, जिस प्रदेश के अंदर एक प्रतिशत जल रहा करता हो, उस प्रदेश के अंदर जल स्वावलम्बन जैसी योजना मुख्य मंत्रीजी ने शुरू की है, जहां इनकी कल्पना भी नहीं थी, उसको विचार करके राजस्थान के अंदर जमीन पर उतारने का प्रयास हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे टोंक में बीसलपुर बांध में टोंक, देवली, उनियारा पेयजल परियोजना का काम 2017 में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा और 2017 के अंदर हमारे पूरे उनियारा, देवली, टोंक को बीसलपुर का पानी मिलेगा, इसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, इसलिये मैं उन्हें साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसी प्रकार से टोंक के अंदर जिला मुख्यालय पर स्थित पूरे विश्व में विख्यात अरबी-फारसी शोध संस्थान, जिसमें प्राचीन दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थों का अमूल्य संग्रहण है, इन हस्तलिखित ग्रन्थों को बचाने के लिये इनका डिजिटलाइजेशन कार्य करने के लिये साढ़े 23 करोड़ रुपये की घोषणा की है, इसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे टोंक के अंदर सआदत हास्पिटल की ओ.पी.डी. को आप उठाकर देखें तो 2017 के अंदर एक महीने में 45 हजार से ज्यादा मरीज आये। उसके बावजूद भी मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, ट्रोमा वन, एफ.बी.एम.सी., आई.सी. वार्ड होने के कारण मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मरीजों को समय

(श्री अजीत सिंह)
पर सुलभ स्वास्थ्य सुविधा मिले, अत: मेरा निवेदन है कि उक्त अस्पताल 200 बैड की जगह 300 बैड में क्रमोन्नत किया जाए, इससे टोंक के अंदर लोगों को सुविधाएं मिलेंगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारा बीसलपुर का बांध इस बार तीन बार भरकर खाली हो गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि बीसलपुर का ओवर-फ्लो का पानी अगर टोरड़ी के अंदर डाला जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पूरे जिले के किसानों का जीवन अच्छा हो जाएगा, यह हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मांग है। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस पर विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंदर लहन, पालड़ा, टोंक जिसकी कुल लम्बाई 11 किलोमीटर है और जिसमें से 7 किलोमीटर सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं, उस क्षेत्र में नदी के अंदर खनन होता है और सरकार को राजस्व भी आता है। मैं माननीय मंत्रीजी से मिला था और मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब वहां पर माइनिंग होता है, जिस तरह से वहां पर सड़कों की हालत है, कोई गाड़ी ढंग से नहीं जा सकती और उस जगह पर आप देखिये, वहां पर राजकीय महिला पोलीटैक्निक कालेज है, डाइट संस्थान है, सेंट जोसफ है, आई.टी.आई. प्रशिक्षण संस्थान है, पन्नाधाय बालिका आवासीय विद्यालय है और शारदा आवासीय बालिका छात्रावास है। मतलब पूरा एजुकेशन हब उस क्षेत्र में बना हुआ है और वहां सड़कों की इतनी ज्यादा स्थिति खराब है, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उस क्षेत्र को आपके माध्यम से हमारी सरकार उक्त सड़क देने का प्रयास करेगी।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि टोडा की 31 पंचायतों में हमारी 11 पंचायतें आती हैं और टोडा में एकमात्र थाना 11 पंचायतों के अंदर है। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद जब कभी अपराध हो जाता है, हम सूचना देते हैं और पुलिस एक-डेढ़ घंटे तक भी नहीं पहुंचती तो मेरी उप तहसील 11 पंचायतों में बखास है, वहां पर एक नवीन थाना खोलने की कृपा करेंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री अजीत सिंह)

हमारे चिरोन्ज-मण्डावर की सड़क 17 किलोमीटर की है, वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बजरी के खनन की वजह से सारे ही ओवरलोड वाहन उधर से गुजरते हैं। 8-10 साल पहले डामरीकरण हुआ था और वह सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है, इसलिये मैं आपका ध्यान उस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। आज इस अवसर पर मुझे मालूम है कि आप घंटी बजाएं, उससे पहले ही मैंने अपना विषय आपके बीच में रखा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया। माननीय सदस्य, श्री विद्याशंकर जी नन्दवाना।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की विधान सभा में जो बजट रखा, उस बजट भाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्रजातंत्र की जब से नींव रखी गयी, तभी से यह परम्परा बनी हुई है कि हर वर्ष सदन की नेता, वित्त मंत्री द्वारा इस सदन में आय-व्यय का ब्यौरा रखा जाता है। जब प्रजातंत्र की स्थापना हुई तो उस समय दो विचारधाराएं बहुत प्रबल हुआ करती थीं - एक साम्यवादी विचारधारा और दूसरी पूंजीवादी विचारधारा। लेकिन इसके बाद एक नई विचारधारा को

(श्री विद्‌याशंकर नन्दवाना)

माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय द्‌वारा जन्म दिया, जिसे हम एकात्म मानववाद कहते हैं। आज हमें इस बात का गर्व है कि इस सदन में या हम लोक सभा की बात करें तो उसमें उस विचारधारा के लोगों को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिला।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पंडित दीनदयालजी की जन्मशती के अवसर पर जो बजट प्रस्तुत किया, उस बजट में उन्होंने उस विचारधारा को आगे मजबूत करने के लिये बड़ा योगदान दिया। सम्पूर्ण बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस विचारधारा पर ही समर्पित किया। किसी भी राष्ट्र या राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये सबसे जरूरी होता है उस राज्य की यातायात की सुगमता और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सबसे ज्यादा उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है।

आजादी के बाद यदि हम किसी को इतिहास में याद करते हैं तो शेरशाह सूरी का नाम इस देश में सब से ज्यादा यातायात और मार्गों को बनाने में लिया जाता है लेकिन उसके बाद, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद गैर-कांग्रेसी सरकार के रूप में अटल बिहारी जी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व देश की इसी व्यवस्था पर दिया और इस देश को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, नेशनल कॉरिडोर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ऐसी कई योजनाएं देकर आज इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम अंकित किया।

आज हम हमारे प्रदेश की बात करें तो आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा पैसा ग्रामीण विकास के नाम पर या इस प्रदेश के विकास के नाम पर, या हम कहें कि रोड़ की कनेक्टिविटी के नाम पर यदि सबसे बड़ा बजट किसी ने दिया तो माननीय वसुन्धराजी ने दिया।

प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयीजी ने जिस प्रकार पूरे देश में सड़कों को बनाने में अपना योगदान दिया उसी प्रकार तीन वर्षों में इस देश के आर्थिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में माननीय मुख्यमंत्रीजी ने 20 हजार 822 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 4281 गांव, ढाणियां, मजरों को सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया। विगत तीन वर्षों में 15 हजार 278

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

किलोमीटर लम्बाई की नई सड़कों का निर्माण हुआ, नया आयाम स्थापित हुआ। जहां 2016 में बजट में 4200 करोड़ का प्रावधान रखा गया वहीं इस वर्ष 2017 में 6557 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान कर एक ऐतिहासिक पहल की।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में पहली बार ग्रामीण विकास पर यदि किसी ने चिन्तन किया तो माननीय मुख्यमंत्रीजी ने गौरव पथ देकर गांवों में एक इतिहास कायम किया। इससे पहले कभी भी किसी भी अन्य योजनाओं में या किसी भी सरकार के बजट में एक मुश्त 60 लाख रुपये किसी पंचायत मुख्यालय की सड़क के निमित्त आबंटित नहीं हुए। लगातार पहले फेज में, दूसरे फेज में इस योजना को प्रबलता देते हुए आज मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में जो पंचायत राज का स्वरूप निकल कर आया है, जो गांव में विकास की हम कल्पना लेकर चलते थे वो कल्पना साकार होती नजर आ रही है।

शुद्ध पेयजल के लिए विगत तीन वर्षों में 13 हजार 473 करोड़ की राशि खर्च कर एक बड़ा कार्य राजस्थान में किया। इसके अतिरिक्त हम कृषि की बात करें, सिंचाई की बात करें, विद्युत व्यवस्था की बात करें, प्रदेश लगातार अग्रसर होता नजर आ रहा है, हमने कई कीर्तिमान बनाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जब पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी और उसके मुखिया के रूप में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने अंत्योदय योजना को हाथ में लिया और उसी अंत्योदय योजना को हाथ में लेते हुए आज हमारी मुख्यमंत्रीजी ने भी गांवों में गरीब व्यक्ति, जो अपने आपको असहाय रूप में खड़ा महसूस करता है, उसके कल्याण के लिए कई प्रभावी योजनाएं प्रारम्भ की। उसके उत्थान के लिए जहां माननीय मुख्यमंत्रीजी ने भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए उस ग्रामीण व्यक्ति के लिए, उसको संबल देने के लिए, उसको अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए कई योजनाएं और भी प्रारम्भ कीं।

पंडित दीनदयाल जन कल्याण शिविर के रूप में जहां पूरे जिले का प्रशासन, पंचायत-पंचायत स्तर पर गया और वहां जाकर उन्होंने गांवों की जो

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

आवश्यकता थी, आम नागरिक की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करने का प्रयास किया।

इसके अतिरिक्त राजस्व कैम्पों के माध्यम से पूरे राजस्थान भर में ऐतिहासिक काम हुआ। किसानों की जो भी कृषि से जुड़ी हुई परेशानियां थीं उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया गया।

राजस्थान कभी सूखे के कारण या पानी की कमी के कारण जाना जाता था, आज राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्रीजी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। पिछले एक वर्ष में, 27 जनवरी, 2016 को इस योजना को प्रारम्भ करते हुए 96 हजार जल संरक्षण के कार्य कराये गये और दूसरे चरण में जो 9 दिसम्बर, 2016 से प्रारम्भ हुआ उसमें 42 हजार कार्य इस योजना के निमित्त सरकार ने हाथ में लिये हैं।

कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत इस वर्ष खरीफ में 53 लाख कृषकों की 73 लाख हैक्टेयर भूमि और रबी में 30 लाख कृषकों की 29 लाख हैक्टेयर भूमि का बीमा किया, जो अपने आपमें एक कीर्तिमान है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को स्वावलम्बी बनने के लिए एक अनूठी योजना मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना प्रारम्भ कर किसानों को अपने स्तर पर अपने बीज को उन्नतशील बीज बनाने के लिए प्रेरणा देने का एक अनूठा प्रयास किया है।

पंचायती राज में एक बड़ा परिवर्तन हर पंचायत मुख्यालय पर उप पशु केन्द्र खोल कर पशुओं की, जो चिंता कांग्रेस के माननीय सदस्य कर रहे हैं, हमने उसमें अपनी समर्थता व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्रीजी ने राजस्थान के समग्र विकास के लिए इस बजट में दीनदयाल जी की जन्मशती के अवसर पर अपनी विचारधारा को समाहित करते हुए सम्पूर्ण राजस्थान के विकास के लिए एक अनूठा प्रयास किया है जो आगे आने वाले समय में हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

अंत में माननीय मुख्यमंत्रीजी ने 2004 में अपने भाषण में जो बात कही

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

थी उसे दोहराते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, 'जो कश्ती के मकामात बदल सकते हैं, देखते देखते हालात बदल सकते हैं, लोग तो वही रहते हैं लेकिन उनके ख्यालात बदल सकते हैं।' धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नन्दकिशोरजी महरिया। (अनुपस्थित) माननीय सदस्य श्री कैलाश जी भंसाली।

एक माननीय सदस्य: आ गये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार।

मैं सबसे पहले प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग किसान वर्ग की बात करना चाहता हूं। प्रदेश में कृषि व किसानों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। कभी ओलावृष्टि, कभी अकाल तो कभी आवारा पशु, कभी प्राकृतिक आपदा झेलने वाले किसान की सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही है। चाहे मुआवजे की बात हो, या समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की बात हो, किसान के हाथ आज के दिन कुछ नहीं लग रहा है।

सरकार के बजट में यह बताया गया है कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सभापति महोदय, इस सरकार ने यह कहीं नहीं बताया कि किस तरह से करेंगे और आज के दिन आमदनी क्या है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि किसानों की आत्महत्या के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। 2015 के डाटा देखे थे, 42 प्रतिशत आत्महत्याएं बढ़ गयी हैं। तो कहना पड़ रहा है राज्य सरकार ऐसे कदम उठाये कि किसान को आत्महत्या न करनी पड़े। मुआवजे की बजाय ऐसे कदम उठाये जिससे समस्याओं का अंत हो, यानी कि वैलफेयर के लिए कोई काम हो।

नोटबंदी के कारण भी किसानों को लाखों का नुकसान हुआ, फसलों के दाम गिरे, रबी की बुवाई में देरी हुई। सरकार का धर्म था कि किसान के हुए नुकसान की भरपाई करे लेकिन एक रुपया भी नहीं दिया गया। नोटबंदी की वजह से हजारों किसान फसल बीमा करवाने से वंचित रह गये, मैं निवेदन

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

करना चाहता हूं कि सरकार उनको अब बीमा कराने का मौका दे।

कर्ज माफी, किसान आयोग, आय आयोग बनाने, जन धन खातों में पैसा जमा करवाने जैसी बातें सिर्फ बातें ही रह गयीं, इस सम्बन्ध में कोई काम नहीं हुआ।

(17.00 बजे)

कृषि मंत्री जी विराजे हैं। कृषि के हालात यह हैं कि हमारे फतेहपुर में कृषि अनुसंधान केन्द्र है, वहां 48 वैज्ञानिकों की पोस्ट है और सिर्फ एक काम कर रहा है, 47 पद खाली हैं। किस तरह से कृषि का विकास होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

सोलर पंप में भी यह शर्त रख दी है कि 2011 से पहले जिसका कुआ होगा, उसी को सोलर पंप लगाने दिया जाएगा। खुद के खेत में भी अगर किसान का कुआ खराब हो जाता है तो वह दूसरा कुआ वहां नहीं खोद सकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि खुद के खेत में अगर पंप खराब हो जाए, मोटर उलझ जाए या किसी भी वजह से एक बोर खराब हो जाए तो उस खसरे में तो कम से कम उसको दूसरा बोर खोदने की परमिशन मिले।

सभापति महोदय, जीएसएस से लोन लेने वाले जो किसान हैं, जिनको ब्याज में सब्सिडी मिलती है, वह किसी अन्य बैंक से केसीसी नहीं ले सकते। यानी सिर्फ डेढ़ लाख रुपये तक उनको सीमित कर दिया जाता है। केसीसी लेने से उनको वंचित कर दिया जाता है। जीएसएस से लोन लेने वालों को केसीसी से लोन लेने की अनुमति दी जाएगी तो किसानों के लिए अच्छा रहेगा।

सरकार के पास ना तो उच्च गुणवत्ता के बीज बांटने की व्यवस्था है, ना ही पूरी मिट्टी जांचने की व्यवस्था है और ना ही समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी जा रही है। आज हमारे प्रदेश में 30 लाख हैक्टेयर से भी ऊपर सरसो का रकबा है और 40 लाख टन से ऊपर सरसों के पैदावार की उम्मीद है। सिर्फ अपना प्रदेश, देश के कुल सरसो उत्पादन का आधा उत्पादन कर रहा

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

है। देश में उत्पादन और उत्पादन के रकबे में प्रथम स्थान पर होने के बावजूद भी अब तक इसे सरसों प्रदेश घोषित नहीं किया गया। मंत्रीजी की भी इच्छा है। मैंने एक-दो जगह अखबारों में भी पढ़ा है। मैं मांग करता हूं कि प्रदेश को सरसों प्रदेश घोषित किया जाए। उसके साथ ही व्यवस्था की जाए कि हर हाल में सरसों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए।

आज 60 हजार करोड़ रुपये का तेल आयात होता है। अगर हमारे यहां अच्छा समर्थन मूल्य मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा तो राजस्थान का किसान इतनी सरसों पैदा कर देगा कि हमें विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए सरसों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कम पानी की फसल है। अपने यहां टोंक वगैरह जो क्षेत्र हैं, इस एरिये में दुनिया की सबसे बढ़िया सरसों होती है। इसका लाभ हमें लेना चाहिए। अभी फसल आना शुरू हो गयी है।

श्री सभापति: रुकें, माननीय सदस्य। आपके वक्तव्य पर मंत्री जी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): हां, दे देना। बोलने के बाद दे देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्री जी प्रतिक्रियावादी हैं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): नहीं, क्रियावादी हूं।

श्री सभापति: आशीर्वाद आपने दिया, अभी आते ही।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं प्रतिक्रियावादी नहीं हूं। सकारात्मक क्रियावादी हूं।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने 2-3 विषयों पर अभी कहा कि एक तो सोलर पंप 2011 वालों को देते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। सोलर पंप हों, डिग्गी हो या हौज बना हो, सभी में पात्रता रखने वाले ऐसे लोग जो ड्रिप इर्रिगेशन या ग्रीन हाउस लगाते हैं, इसमें पात्रता के आधार पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कलेक्टर को देकर के ले सकते हैं।

दूसरा, आपने यह कहा कि हमारे एक ही वैज्ञानिक है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो पांचों यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें भर्ती प्रक्रिया शुरू हो

(श्री प्रभू लाल सैनी)

गयी है। अभी आवेदन मांग रहे हैं। शीघ्र भर्ती करके उनको भरेंगे।

तीसरा, जहां तक सरसों का सवाल है, यह नेगेटिव सूची में कई वर्षों से डला हुआ था, इरुसिक एसिड जो इसमें आती है, उसकी वजह से जो थोड़ी जलन होती है, इससे विदेशों में इसका एक्सपोर्ट कम होता था। इसका अब राजस्थान में 48 परसेंट तेल होने लगा है। विश्व में तीसरा हमारा स्थान है। पहला जापान है, उसके बाद कनाड़ा है। देश का 48 परसेंट प्रोडक्शन राजस्थान में हो रहा है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इरुसिक एसिड है, उसके ऐसे सीड तैयार करके उसको कम करेंगे ताकि वह नेगेटिव लिस्ट में न रहे। बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है। मैं सोचता हूं कि इसका अच्छा भविष्य है। इसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। लेकिन जिला लेवल पर जो स्थिति है, उसमें अगर सोलर पंप के लिए आज कोई एप्लाई करता है तो उससे 2011 का सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आप इस तरह का स्पष्ट कोई सर्कुलर निकाल देंगे तो किसानों पर बड़ी कृपा होगी।

सभापति महोदय, दिसम्बर, 2013 में जो विजन 20-20 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हमारी सदन की नेता बहुत अच्छी मानिटरिंग भी कर रही हैं। बहुत अच्छी गवर्नेंस भी चल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी जो नौकरशाही है और जो मिनिस्ट्री है, वह सुराज संकल्प में जो वादे किए गए थे, उनको पूरा करने की मंशा रखती है।

मैं कृषि मंत्री जी के विभाग की ही बात बताता हूं। सुराज संकल्प के पत्र में स्पष्ट लिखा है कि राजस्थान में कृषक सुरक्षा अधिनियम बनाया जाएगा। मैंने इस संबंध में छठे सत्र में 7981 नम्बर से प्रश्न पूछा था, तो स्पष्ट जवाब यह आया कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

किसान खंड में, न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि में सुराज संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि मोठ, मूंग, मेहँदी, चोला, ग्वार, जीरा, बाजरा, धनिया, लहसुन सबको लाया जाएगा। जब प्रश्न पूछा गया तो जवाब आया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि में शामिल नहीं किया जा सकता।

कृषि खंड में लिखा है कि बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट कार्ड की सीमा निर्धारित की जाएगी। आपके विभाग से जवाब आया है कि ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। गोवंश संवर्धन जो संकल्प पत्र का खंड है, उसमें लिखा है कि गायों के दूध को हर जिले में 6 रुपये प्रति फैट की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। मेरे सत्र 7 के प्रश्न संख्या 165 के जवाब में आया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पशुपालन, डेयरी के खंड में लिखा गया है कि कृषि ऋण की दर पर पशुपालन हेतु आसान शर्तों पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा व पशुपालक क्रेडिट कार्ड की योजना शुभारंभ की जाएगी। प्रश्न संख्या 165 में जवाब है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैं कहना यह चाहता हूं कि बड़ा अच्छा सुराज संकल्प पत्र है। लेकिन उस पर नौकरशाही ध्यान दे और मंत्री ध्यान दें तो निश्चित रूप से जनता के लिए कुछ अच्छे काम हो पाएंगे।

हमारे शिक्षा मंत्री जी से सुराज संकल्प पत्र की एक बात, कि स्नातक तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अलग से करने की व्यवस्था की जाएगी। जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। कोई प्रस्ताव ही विचाराधीन नहीं है। सभी विद्यालयों को अलग से खेल सामग्री का बजट रखा जाएगा, ऐसी घोषणा सुराज संकल्प पत्र में की गयी थी। जब सत्र 6 में प्रश्न पूछा तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत तो जीरो बजट है। ऐसा हमारा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सभापति महोदय, प्रत्येक पंचायत समिति में 2 करोड़ रुपये की लागत से स्टेडियम बनाने की बात की गयी। आज कहा जा रहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह सातवें सत्र में प्रश्न का जवाब आया है।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

महिला एवं बाल विकास के खंड में लिखा गया है कि प्रत्येक मुख्यालय पर सभी छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या छात्रावास की स्थापना की जाएगी। स्थापना तो भले ही नहीं हो। लेकिन जवाब शिक्षा मंत्री का आया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह अच्छी मानीटरिंग और गुड गवर्नेंस के नतीजे हैं।

शिक्षा में, राज्य में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के संचालन हेतु एक नियामक बोर्ड बनाया जाएगा। प्रश्न पूछा गया तो कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह किस तरह की गवर्नेंस और मानीटरिंग चल रही है? शिक्षा के खंड में यह लिखा गया कि प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से डिजीटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। जब प्रश्न पूछा तो कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह प्रश्न संख्या 164 है सत्र 7 का।

दसवीं कक्षा के परिणाम के साथ जाति प्रमाण-पत्र दिए जाने थे। संकल्प पत्र में स्पष्ट लिखा है कि माता-पिता और छात्रों को इसे लेने में परेशानी ना हो। जवाब आया कि ऐसा हमारा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा नौकरशाही पर ध्यान दें। थोड़ा ध्यान मानीटरिंग पर दें। काम हों या नहीं हों, कम से कम कोशिश तो की जाए।

सभापति महोदय, प्रदेश के विद्यालयों को समय सीमा में एनएएसी से प्रमाणित करवाया जाना था। जवाब आया है कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। शिक्षा में ही प्रत्येक उपखंड पर छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग कालेज और एक सम्मिलित कालेज खोलने की बात थी। वह तो पूरे सदन को ही पता है कि एक ही जवाब है कि वित्तीय संसाधनों के आधार पर देखा जाएगा।

सभापति महोदय, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में बीपीएल परिवार में चयन हेतु एक प्रभावी, स्थायी तंत्र विकसित किए जाने की घोषणा की गयी थी और सुराज संकल्प पत्र में वादा किया था। अब जब प्रश्न संख्या 245 पूछा पिछले सत्र में तो जवाब आया कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में ही हमारे निर्वाचित सदस्यों का मानदेय बढ़ाने की बातें हुई थी। स्पष्ट वादा किया गया था। जब

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

प्रश्न पूछा गया तो वही जवाब कि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किस तरह से सदन में लोग जवाब दे रहे हैं। इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, परिवहन एवं सड़क विभाग में जनता से वादा किया गया था कि अगर सरकार में आए तो परिवहन प्रणाली में इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लागू करेंगे। जवाब आया है कि लागू नहीं की गयी है और न ही लागू किए जाने का कोई प्रस्ताव पैंडिंग है।

ऐसे ही सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन विभाग को, अभियांत्रिकी विभाग का दर्जा दिए जाने की बात थी, जवाब सीधा-सीधा आया कि अभियांत्रिकी विभाग का दर्जा दिया जाने का कोई औचित्य समीचीन प्रतीत नहीं होता। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के स्वरोजगार हेतु बैंक लोन की व्यवस्था कराएंगे, ऐसा वादा किया गया था, अभी जवाब आया है, प्रश्न संख्या 7979 का कि ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। व्यापार-उद्योग में रूरल इंडस्ट्रियल हब कायम करने की बात थी, प्रश्न संख्या 161, सत्र सातवें का जवाब है कि कोई विचार नहीं है। शहरों को स्लम फ्री करने की बात थी, स्वायत्त शासन के प्रश्न संख्या 578 का जवाब है कि अभी तो हमने इस तरह का कोई सर्वे ही नहीं किया है। तारबंदी पर अनुदान देने की बात थी, कृषि मंत्रीजी शायद चले गये हैं, उसका स्पष्ट जवाब आया है कि हमारा ऐसा कोई प्रावधान या प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह तो सिर्फ नमूना है, ऐसे सैंकड़ों प्रश्न हैं, ...(व्यवधान)... यह तो एक नमूना मात्र है, मैं यह कहना चाहता हूं कि गुड गवर्नेंस और अच्छी मानिटरिंग की बात करने वाली सरकार के मिनिस्टरों की जब यह हालत है और जब सदन में इस तरह से जवाब दिए जा रहे हैं तो जनता का क्या हाल होगा, यह आप सोच सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके आगे प्रारम्भिक शिक्षा में मैंने आपको बताया कि जीरो बजट दिया गया है, आज हमारे पड़ौसी राज्य हरियाणा में....

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, 160 मिनट का बजट था, 16 मिनट तो बोलने दो।

श्री सभापति: ज्यादा हो गये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): नहीं हुए हैं, 7-8 मिनट ही हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, हरियाणा में पदक विजेता को डीएसपी बनाया जा रहा है और हमारे यहां बाबू भी नहीं बनाया जा रहा, ऐसे में कैसे खेलों के विकास की बात होगी? यह सिर्फ खिलाड़ियों के साथ खेल खेला जा रहा है, सरकार द्वारा निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, 1 लाख को भी सरकारी नौकरी अभी तक नहीं मिली है। हमारे विद्यार्थी मित्र, पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी, कम्प्यूटर टीचर, सबको नियमित होने का इन्तजार था लेकिन अब तक कोई एलान इस बजट में भी नहीं हुआ। बेरोजगार लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जो नई पोस्टें निकल रही हैं, वे भी बिना गाइड लाइन के हैं, जिससे कल कोर्ट में जाते ही इन पर स्टे मिल जाए। इस तरह की कार्यवाही रोकनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सड़क परिवहन के बारे में बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जयपुर में जो लोग आरटीओ लगे हुए हैं उनके दलालों के साथ बैठ-बैठ कर इन्टरव्यू हो रहे हैं, एसीडी में यह हालात हैं, इन हालात में, हां हड़ताल में जरूर रोडवेजकर्मी सबसे आगे हैं। कालेज के बारे में उच्च शिक्षा मंत्रीजी बैठी हैं, मेरे यहां भी मांग है लेकिन जवाब एक ही है इसलिए कहने में कोई फायदा नहीं, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री कैलाशजी भंसाली।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, 11 मार्च को जो ऐतिहासिक भाजपा की जीत हुई, जिसका श्रेय हमारे माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी और अध्यक्ष अमित शाहजी को है। मैं इस सदन के माध्यम से उनको हार्दिक बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने दो दूनी चार सरकारें बनाकर भारत का नेतृत्व किया है उसमें वे सफल बनें, देश आगे बढ़े, सभी चारों प्रांत खूब आगे बढ़े, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान का बजट यशस्वी मुख्य

(श्री कैलाश भंसाली)
मंत्री, वसुन्धराजी ने रखा। राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विजन के साथ जिस हालत में और जिस वित्त स्थिति में उनको सरकार मिली उससे बाहर निकाल कर हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का बीमारू राज्य से एक उन्नत राज्य बनाने का जो संकल्प किया है, उसका हम सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बजट में घोषणा की गयी, हर वर्ग को, हर का विकास, सबका विकास के नारे के साथ हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी जिस तरह से कार्य कर रही हैं, राजस्थान प्रगति की ओर बढ़े और राजस्थान देश का श्रेष्ठ प्रदेश बने, ऐसी हमारी तमन्ना है, ऐसा वह करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उन्होंने जिस प्रकार से कोई टैक्स नहीं लगाया, एंट्री टैक्स में छूट दी, मरीजों को सस्ती दवाइयों के लिए एटीएम की तरह करना, सम्पत्ति बेचान व आम जनता की स्टाम्प ड्यूटी में ढाई प्रतिशत की कमी, स्टाम्प ड्यूटी पर 60 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की रियायत की घोषणा, फैमिली सैटलमेंट के दस्तावेजों की रजिस्ट्रेशन फीस को कम करना और अधिकतम 10 हजार रुपए तक करना, स्टार्ट अप स्थापित करने के लिए छूट की घोषणा, यूनिट स्थानांतरण में स्टाम्प ड्यूटी फ्री की गयी है। इसी के साथ हजारों बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने भर्तियां खोली है। 15 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की जो हमारी घोषणा थी उस पर हम खरे उतर रहे हैं, सरकार में 1 लाख और समथिंग रोजगार दिए गये हैं और बाकी स्किल्ड लेबर में 12 लाख लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए ब्याज की दरें कम की गयी हैं और आगे उनको बढ़ाया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, गांवों के साथ-साथ शहरों में भी गौरव पथ की जो घोषणा की गई उसका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जोधपुर जिले में बाप में सोलर पार्क को विकसित करना, रामदेवरा पैदल पथ को विकसित कर परिवर्तन के साथ जोधपुर में कई योजनाएं प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1483 आरओ प्लांट लगाने की, आगामी दो वर्षों में 12 लाख 27 हजार 700 नए कृषि कनेक्शन देने की, जोधपुर के मंडोर संग्रहालय को पुन: स्थापित करने, 5 हजार वरिष्ठ लोगों को धार्मिक स्थलों की हवाई यात्रा कराने की जो बात की गयी है वह बहुत ही स्वागत योग्य है और बड़े बुजुर्गों

(श्री कैलाश भंसाली)

को इसका बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा। युवाओं के लिए ऋण में छह प्रतिशत की सब्सिडी देने का मैं स्वागत करता हूं। जेएनयू, जोधपुर में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं, सिंडिकेट के मैम्बर के नाते उनका स्वागत करता हूं। रीको द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं ऑनलाइन करना, सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाएंगे तथा बापनी एवं सांखला में पशु चिकित्सालय खोले जाने एवं जोधपुर के पशु चिकित्सालय को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करना और पशु चिकित्सालयों में कलर डॉप्लर सुविधा उपलब्ध कराना, जोधपुर को आगरा से हवाई मार्ग से जोड़ने इत्यादि की घोषणाएं स्वागत योग्य है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ समस्याओं के बारे में जोधपुर की जनता की ओर से निवेदन करना चाहूंगा। वसुन्धरा राजेजी द्वारा प्रदेश में बीस वर्षों के लिए विजन बनाने का सतत प्रयत्न किया गया है। जोधपुर की जनता की ओर से निवेदन है कि एलीवेटेड फ्लाई ओवर सवा दस किलोमीटर का आखलिया चौराहे से लेकर पावटा तक बनाने का, बूंदपुरिया पुलिया का पुन: विकास करने का, राजीव गांधी नहर का थर्ड फेज प्रारम्भ करने का बाईजी तालाब, गुलाब सागर, फतेह सागर, नया तालाब का सौन्दर्यीकरण और कायलाना झील का सौन्दर्यीकरण, नौकायन शुरू हो इसका मैं निवेदन करता हूं। जालोरी गेट से सोजती गेट नई सड़क तक तीन कारें चल सकें ऐसी रोड बनाने का आग्रह है। जोधपुर पानी पर तैर रहा है, जगह-जगह पानी पर हजारों मोटरें लगाकर लोग उसको नाले में डाल रहे हैं, पानी बह रहा है, उसको उपयोग में लिया जाए और नदी में भेजकर उस पानी को खेती में उपयोग में लिया जाए ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है।

हमारे यहां पार्किंग के लिए व्यवस्था बहुत जरूरी है, गांधी मैदान के विकास का जो काम चल रहा है उसे शीघ्र पूरा किया जाए। उसके लिए नगर निगम और जेडीए के पास पैसों की कमी है वह सरकार उपलब्ध कराए। 300 करोड़ रुपया नगर निगम और 500 करोड़ रुपया जोधपुर विकास प्राधिकरण को दिया जाए तभी यह कार्य संभव होगा अन्यथा जोधपुर का विकास ठप्प हो जाएगा और आम आदमी में यह बात हो रही है कि जोधपुर के लिए कुछ

(श्री कैलाश भंसाली)

नहीं हो रहा है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को लोग कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं हो रहा है इसलिए उसका काम शीघ्र पूरा किया जाए।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से पानी का रुकाव हो जाता है। ज्यों ही थोड़ी बारिश होती है, एक इंच बारिश में भी जोधपुर पानी से लबालब हो जाता है। दुर्भाग्य था, 8 अगस्त की भयंकर बारिश में जोधपुर तबाह हो गया, जोधपुर एक झील बन गया, जहां भी जाओ पानी-पानी हो गया। मैं उस दिन जयपुर में था, नेक्स्ट डे पहुंचा था, कालोनियों में 10-10, 12-12 फीट ऊपर छतों पर बैठकर चाय पी रहे थे, दूसरे लोग उनको खाना खिला रहे थे, चाय पिला रहे थे। वैसी त्रासदी वापस नहीं हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि जोधपुर का पानी का बहाव है उसके लिए जयनारायण विश्वविद्यालय में जल्दी से नाला बनाया जाए, उस पर एयरकंडीशनर मार्केट बनाने की व्यवस्था की जाए ताकि जयनारायण विश्वविद्यालय, जो अभी खराब हालत में है उसमें सुधार हो। वहां एक हजार करोड़ रुपया पेंशन के लिए चाहिए। वहां पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन बहुत मुश्किल से दे पा रहे हैं उसके लिए आवश्यक है।

जोधपुर में झालामण्ड एरिया में एक खेल स्टेडियम की आवश्यकता है। मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, जोधपुर की बात पर ध्यान दें और झालामण्ड में नया स्टेडियम तथा इनडोर गेम्स की घोषणा करें। झालामण्ड में बालिका विद्यालय में आर्ट्स व कॉमर्स है। वहां विज्ञान विषय भी शुरू किया जाए ताकि बच्चियां आगे पढ़ सकें।

इसी तरह से डॉ. पदमचंद बिलमकंवर गांधी विद्यालय में सभी विषय हैं, लेकिन विज्ञान व गृह विज्ञान के लिए क्रमोन्नत किया जाए। जयनारायण टाउन हॉल में अभी 750 लोगों के बैठने की जगह है। उसको नया हॉल बनाया जाए तथा 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाए।

सेंट्रल जेल को अन्य स्थान पर ले जाकर झालामण्ड एरिया में दिया जाए और राइका बाग़ की तरफ उसका विस्तार किया जाए। बरकततुल्लाह स्टेडियम में एक इनडोर स्टेडियम की घोषणा की जाए। हैरिटेज लुक के लिए घंटाघर, फतेहपोल, ब्रह्मपुरी एरिया में इतने लोग आते हैं, हैरिटेज लुक दिया जाए, सड़कें वैसी ही बनायी जाए, मांडणे मांडे जाए। कुछ काम नगर निगम

(श्री कैलाश भंसाली)

ने शुरू किया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उम्मेद भवन में फ्लड लाइट लगाकर रोशनी की जाए ताकि बहुत दूर से लोगों को उम्मेद भवन दिखायी दे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनट सर।

मण्डोर उद्यान का जो पुरातत्व महत्व है, उसमें मैडम ने रुपये दिये हैं, परन्तु 33 करोड़ देवी-देवताओं के देवालयों की अनदेखी की गयी है, उसके लिए अच्छा प्रावधान किया जाए।

जल स्वावलम्बन के अंतर्गत चाँद बावड़ी, हाथी बावड़ी, झामण बावड़ी, मोहनपुरा बावड़ी, जना बावड़ी एवं मण्डलनाथ आदि स्थानों पर हैरिटेज लुक देकर उन बावड़ियों को ठीक किया जाए। उसके लिए जेडीए, नगर निगम को पैसा सरकार उपलब्ध कराए तभी यह काम हो सकेगा।

सबसे महत्वपूर्ण मांग जोधपुर के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। पश्चिमी राजस्थान के औद्योगीकीकरण के लिए रिफाइनरी की आवश्यकता है। अशोक गहलोत साहब ने इसको प्रारंभ करने की घोषणा की थी। बाड़मेर के पचपदरा में लगाना तय किया था। पचपदरा में इतने लोग बस गये, उनके लिए आज रिफाइनरी बहुत आवश्यक है। रिफाइनरी खोली जाए। हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह एक पुरजोर मांग है। सदन में मैं निवेदन करता हूं कि सरकार यह कार्य करे और जोधपुर के विकास में जो रोड़े हैं उनको समाप्त किया जाए, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री मानसिंह जी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय,

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सभापति महोदय, महरिया जी से पहले मेरा नम्बर था। आज एक ही लेडी बोल रही है और सबसे लास्ट में नम्बर दे रहे हो।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, बजट 2017-18 पर बहस चल रही है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मेरा राजकुमार शर्मा जी के बाद ही नम्बर था।

श्री सभापति: नम्बर चलता ही रहता है। सभी माननीय सदस्य एक ही

(श्री सभापति)
समान हैं, पहले, आगे-पीछे कुछ नहीं होता है। आपकी स्लिप आयी हुई है। आपका समय जो माननीय अध्यक्ष ने निर्धारित किया है वह समाप्त हो चुका है, फिर भी आपको समय दिया जाएगा।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने राजस्थान का जो बजट प्रस्तुत किया है उसको चंद शब्दों में पूंजीगत बुनियादी ढांचागत विकास पर अधिक निवेश के साथ अनुशासित वित्तीय प्रबंधन का यह बजट है। यही कारण है कि देश और प्रदेश की कई फ्लैगशिप योजनाओं में राजस्थान प्रथम नम्बर पर है। उन सभी योजनाओं का लगभग सभी साथियों ने जिक्र किया है, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। बहुत सी योजनाओं में राजस्थान अव्वल है वह राजस्थान सरकार की गुड गवर्नेस का परिणाम है और राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्रीजी की टीम राजस्थान की भावना है, उस टीम राजस्थान का नतीजा है कि राजस्थान अनेक योजनाओं में देश में पहले नम्बर पर है। सड़कों के मामले में भी राजस्थान देश में अव्वल है, यह राजस्थान के लिए अपने आपमें खुशखबरी का काम है। माननीय मुख्यमंत्रीजी की गुड गवर्नेस का परिणाम है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर सड़कों के साथ-साथ ग्रामीण गौरव पथ का, जैसा सब साथियों ने वर्णन किया था, मैं उसको ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ग्रामीण गौरव पथ ने गांवों के अंदर आम आदमी को यह महसूस कराया है कि सरकार दिल्ली व जयपुर जैसी सुविधाएं गांवों में भी देना चाहती है। उससे गांव के आदमी का, गांव का मान-सम्मान बढ़ा है। जिस प्रकार चिह्नित तरीके से, चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण गौरव पथ काम काम चल रहा है, निश्चित रूप से 2018 तक पूरे राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण गौरव पथ बनेगा तो राजस्थान देश का वह प्रदेश होगा जो गांव व शहर के प्रत्येक व्यक्ति को एहसास कराएगा कि मेरी सरकार है। मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा।

माननीय मुख्यमंत्रीजी ने इस बजट में हमारे सवाईमाधोपुर को हवाई यात्रा से जोड़ने का काम किया उसके लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस बजट में पर्यटन को माननीय मुख्यमंत्रीजी ने

(श्री मान सिंह)

फोकस किया है। उसी के साथ-साथ 34 कॉलेजों में इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल इंटरएक्टिव सेल बनाकर जिस प्रकार उद्योग तथा कॉलेजों के बीच मैनपावर की जरूरत को परिभाषित किया है, यह एक ऐसा कदम है कि 34 कॉलेजों को उद्योगों से पूरी तरह से जोड़ने का काम किया है उससे हमारा यूथ, जो स्किल डवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार से कॉलेज के समय से पूरा इंडस्ट्री तथा जो टैक्निकल कॉलेजेज हैं उनके अंदर मैनपावर को खपाने का, मैनपावर को जोड़ने का एक नया रास्ता बनेगा और इससे राजस्थान के यूथ को एक रास्ता मिलेगा, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहली बार 34 कॉलेजों को इससे जोड़ने का काम किया है वह सराहनीय है व इसके लिए वे बधाई की पात्र हैं।

इसके साथ-साथ ग्रामीण पेयजल के लिए जिस प्रकार से इस बजट में प्रावधान किया गया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्रीजी की जो भावना है कि सबको स्वच्छ पानी मिले, पीने के पानी के लिए भरतपुर-धौलपुर-सवाईमाधोपुर की 9 तहसीलों का चयन किया है, जिस प्रकार शहरों के लिए चयन किया है कि शहर के व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल मिले उसके लिए पहली बार जनसहभागिता के आधार पर आर.ओ. प्लांट की प्लानिंग की है, हमारी तहसीलों के अंदर 34-34 आर.ओ. प्लांट लगेंगे इससे निश्चित रूप से स्वच्छ पेयजल देने का माननीय मुख्यमंत्रीजी ने प्रयास किया है उससे आम आदमी को यह विश्वास हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्रीजी ठेठ नीचे बैठे व्यक्ति के लिए सोचती है और यह बजट उनके लिए समर्पित है।

माननीय सभापति महोदय, बजट के अंदर बहुत सी बातें आयी हैं। जल स्वावलम्बन की जो बात आयी है वह सब साथियों ने कही है। विद्युत के मामले में राजस्थान ने जो प्रयास किये और विद्युत के मामले में जो आमूलचूल सुधार हुआ है उससे राजस्थान प्रगति के पथ पर है और राजस्थान के आम आदमी ने इसे महसूस किया है।

अभी कृषि के ऊपर चर्चा चल रही थी और हमारे नन्दकिशोर जी महरिया जिस प्रकार से कृषि के मामले में जिक्र कर रहे थे, निश्चित रूप से राजस्थान में सरसों की पैदावार, विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान जो हमारा

(श्री मान सिंह)

भरतपुर सम्भाग है और अजमेर का आधा सम्भाग है वहां पर एक तरीके से बम्पर पैदावार सरसों की इस बार है। राजस्थान अगर सरसों का प्रदेश घोषित होता है तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सरसों के अन्दर हमारे व्यापारियों और किसानों को RIPS 2014 में छूट दी है उससे RIPS 2014 में व्यापारी को छूट मिलेगी तो उससे किसानों को भी भाव मिलेगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से किसान के सरसों की बम्पर पैदावार हुई है उसमें कांटे की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सरसों की खरीद होनी चाहिए क्योंकि सरसों की इस बार बम्पर पैदावार हुई है।

माननीय सभापति महोदय, स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए अभी ग्रामीण गौरव पथ के साथ-साथ शहरों में ढाई-ढाई करोड़ रुपये की शहरी पथ की घोषणा की है उससे भी हमारी स्थानीय निकायों को बल मिलेगा और ऐसे रास्ते जो बहुत ज्यादा खराब हैं उनको ठीक करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्थानीय निकायों को एक सम्बल दिया है जिसके लिए भी हमारी सरकार स्वागत और धन्यवाद की पात्र है। मैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

प्रत्येक अटल सेवा केन्द्र पर जो ए.टी.एम. की घोषणा है, कैशलैस व्यवस्था में राजस्थान के आम व्यक्ति को जिस प्रकार से माननीय प्रधान मंत्री जी जोड़ना चाहते हैं उसको बल मिलेगा और राजस्थान निश्चित रूप से इसमें अव्वल होगा, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

इसी के साथ-साथ हमारे बहुत से साथियों ने बजट के बारे में जिक्र किया तो बजट के बारे में मैं कुछ आंकड़े आपके बीच में रखूंगा। सभापति महोदय, हमारी और इनकी जब तुलना करते हैं तो राजस्व विकास का व्यय 2013-14 में था वो 51 हजार 921 था वो 2017-18 में 99 हजार 733, यानी लगभग डबल है। राजस्व खर्च जब हमने बढ़ाया है तो सरकार ने इस प्रकार से ढांचागत विकास को बढ़ावा देते हुए राजस्व विकास के अन्दर कोई कमी नहीं की। इसी के साथ-साथ जो हमारा गैर विकास व्यय है वो 2013-14 में 23 हजार 587 था और आज हमारा 43 हजार 951 है। तो इन सारी चीजों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में कोशिश की है जिसके

(श्री मान सिंह)

दूरगामी परिणाम आएंगे। अभी हमारे विपक्ष के कई साथी कह रहे थे कि किसको क्या मिला, तो इस बजट में जिस प्रकार से एक-एक चीज पर ध्यान दिया गया है। आज हमारे प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर गिरदावर ऑफिस का डिजिटाइजेशन का काम हुआ है उसमें जिस नकल के लिए हमारा व्यक्ति जिला हैडक्वार्टर पर 20-20 चक्कर लगाता था कि मेरे परदादाओं की नकल मिल जाए वो नकल उसको अब हमारे वहां अटल सेवा केन्द्र पर मिलेगी। इसलिए इस बजट के जो परिणाम होंगे, इस बजट की जिस प्रकार से खूबियां हैं, इस बजट में जिस प्रकार से आम आदमी का ध्यान रखा गया है, माननीय मुख्य मंत्री जी उसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं। इसी के साथ-साथ हमारा कुल राजस्व व्यय, विकास व्यय की हिस्सेदारी को 68.76 से बढ़ाकर 69.41 प्रतिशत पर हम लाये हैं।

इसी के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अन्दर 2013-14 में 4414.39 करोड़ रुपये था उसको हमने 8419.95 करोड़ रुपये कर दिया है। मेरे विपक्ष के किसी भी साथी को अगर शक है तो पूरी तरीके से इस बुक के पेज नम्बर 22 पर देख सकते हैं। मैं इसको डाटा के साथ में इसलिए कह रहा हूं कि कई बार हमारे साथी कई चीजों को ऐसे ही कहते रहते हैं, अपने-अपने हिसाब से लगा देते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसकी महती आवश्यकता है, प्रत्येक कल्याणकारी सरकार की अपने लोगों के स्वास्थ्य की जो चिंता है, जिस भामाशाह की यहां चर्चा की गयी उन सबका मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर जो खर्च है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सरकार का मंतव्य है और जो उन्होंने 5 साल में किया उससे तीन साल में डबल से ज्यादा किया है। यह इस सरकार की गुड गवर्नेंस है, यह इस सरकार की जवाबदेही है और यह माननीय मुख्य मंत्री जी की राजस्थान के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ, जलापूर्ति शहरी विकास में 2013-14 में 4422 करोड़ रुपये था उसको हमको 7812.16 करोड़ रुपये किया है। मात्र तीन साल में इसको भी लगभग डबल खर्च किया है तो सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि सरकार ने जिस प्रकार से पैसे का यूटिलाइजेशन किया है, निश्चित रूप से कर्ज की जो व्यवस्था राजस्थान को मिली है उसमें सरकार

(श्री मान सिंह)

ने कुछ छिपाया नहीं है लेकिन पैसे का, कर्ज का उपयोग पूंजीगत ढांचे पर किया गया है न कि खैरात बांटने पर किया गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने खैरात बांटी थी तो इस पैसे में एक भी पैसा पूंजीगत विकास पर खर्च किया है न कि इस प्रकार की अन्य मदों पर खर्च किया गया है और यह इस बजट की विशेषता है।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण जलापूर्ति पर 582.32 करोड़ रुपये को हमने 1204.62 करोड़ रुपये, यानी इसको भी हमने डबल किया है। जो व्यवस्था 5 साल में की थी वो 3 साल में डबल से कम कहीं नहीं है। हर क्षेत्र में, शिक्षा में 15307.66 करोड़ को 26807.18 करोड़ रुपये किया है जो पूरी तरीके से दिखाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली पर जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने फोकस करके इस मद को तीन साल में बढ़ाकर व्यवस्था का काम किया है वो वित्तीय प्रबन्धन का इससे बड़ा देश में दूसरा कोई उदाहरण मिल नहीं सकता। यही कारण है कि राजस्थान जिस प्रकार से प्रगति के पथ पर बढ़ेगा, यह बजट उसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है और इसको समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ कृषि पर इनका जो 3522.44 करोड़ रुपये था उसको भी हम 5693.47 करोड़ रुपये पर लाये हैं। ग्रामीण विकास में आप देखिये कि ग्रामीण विकास पर 2013-14 में इनका 4991.36 करोड़ रुपये था उसको हमने 13311.83 करोड़ किया है, यानी पूरी तरीके से तिगुना किया है। हमारे माननीय राजकुमारजी यहां पर नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास पर इस सरकार का जिस प्रकार का फोकस रहा है, ग्रामीण विकास पर जिस प्रकार से सरकार समर्पित हुई है, यह डाटा इस बात का सबूत है कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में वित्तीय प्रबन्धन को बढ़ावा देकर राजस्थान को अग्रिम पंक्ति पर लाने का जो काम किया है उसके आगे सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे।

इसी के साथ-साथ सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, पैट्रोलियम पर उदय रहित 8892.13 करोड़ रुपये के बजाय 12042.36 करोड़ रुपये, यानी हर तरीके से सरकार ने काम किया है, यह सरकार पूरी तरीके से हमारे हर वर्ग को समर्पित करते हुए राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मान सिंह)

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ दो मिनट। सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि हमारा जो पूंजीगत खर्च है उदय रहित, वो 2013-14 में 13664.66 करोड़ रुपये था उसको हमने मात्र तीन साल में 25603.8 करोड़ रुपये किया है। एक रुपया हमने कहीं अनुदान पर, कहीं तनख्वाह पर, कहीं ऐसी जगह पर खर्च नहीं किया जिससे राजस्थान के पैसे का दुरुपयोग हो। चाहे बिल्डिंग का विकास होगा, चाहे कहीं सड़क का विकास होगा, पूरी तरीके से ढांचागत पूंजीगत विकास का काम किया है और पैसे का पूरा सदुपयोग किया है इसको आप आराम से समझ सकते हैं।

इसी तरीके से सामाजिक सेवाओं पर 4551.31 करोड़ रुपये के बजाय हमने 9881.79 करोड़ रुपये, लगभग डबल किये हैं। सामाजिक सरोकार का सबसे पहले सरकार की दो ही चीजें होती हैं कि ढांचागत विकास और हमारे व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं जिसको हम सामाजिक सेवा कहते हैं, उस सामाजिक सेवा के अन्दर इनके पांच साल की तुलना में लगभग डबल से ज्यादा पैसा खर्च करना सरकार की गरीब के प्रति जवाबदेही को प्रदर्शित करता है।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ हमारा जो टोटल विकास व्यय है जिसको पूंजी राजस्व व्यय कहते हैं वो इनका 66063.18 करोड़ था उसमें हमने 1 लाख 25 हजार 219.04 करोड़ रुपये, यानी तीन गुना इस पर खर्च किया है और यह केवल माननीय मुख्य मंत्रीजी का जिस प्रकार का वित्तीय प्रबन्धन है, उससे राजस्थान के लिए बहुत बड़े सुखद परिणाम मिलेंगे।

सामाजिक सेवाओं पर हमने टोटल व्यय किया है, उसका 36,340.81 करोड़ रुपये के मुकाबले 62,873.24 करोड़ रुपये, यह भी लगभग डबल है और स्वास्थ्य पर हमने पूंजीगत व्यय किया है। इनका था 4,255.18 करोड़ रुपये और हमने किया है इस पर 9,750.57 करोड़ रुपये, यानी हर क्षेत्र में डबल से कम कहीं नहीं है। इसी प्रकार से सरकार ने जिस प्रकार से वित्तीय प्रबन्धन किया... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसमें कोई लोटा, डोलची, चम्मच, कम्बल नहीं बांटे। इन पैसों का उपयोग किया पूंजीगत विकास के लिए, पैसों का उपयोग किया ढांचागत सामाजिक सेवाओं के लिए और तीन साल के अंदर पिछली सरकार से जितना भी चाहे वह स्वास्थ्य पर हो, शिक्षा

(श्री मान सिंह)

पर हो, चाहे सामाजिक सेवा पर हो, पूरी तरीके से डबल से कम कहीं नहीं है और ग्रामीण विकास को समर्पित इस बजट में जिस प्रकार से तीन गुना पैसा खर्च किया है...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान का वह बजट है, पूरे राजस्थान के समग्र विकास के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार पैसों का सदुपयोग किया है, राजस्थान के एक-एक पैसे को सदुपयोग करके पूंजीगत विकास पर खर्च किया है। यह पहला बजट है जिसमें इतना पूंजीगत पैसा खर्च हुआ है। तुलनात्मक रूप से हमारे जितने भी अर्थशास्त्री यहां हैं, वे उसका अध्ययन करें कि पूंजीगत विकास इस बजट में ज्यादा क्यों हुआ? वह इसलिए हुआ कि राजस्थान की सरकार ने जिम्मेदारीपूर्वक इस बजट को खर्च किया है।

राजकोषीय घाटे का नियंत्रण भी देखिये माननीय सभापति महोदय, जीडीपी का 2.99 प्रतिशत है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मान सिंह (गंगापुर): जीडीपी का 2.99 प्रतिशत अब इसको लाये हैं। सभापति महोदय, पंचायती राज को हस्तान्तरण देखिये आप। इनके समय में 17,638.85 करोड़ रुपये था, उसको हमने 27,531.5 करोड़ रुपये किया है। यह हमारा पंचायतों को हस्तान्तरण है। इतना बड़ा पंचायती राज को हस्तान्तरण हमने किया है माननीय सभापति महोदय, और बिना कर बढ़ाये, आप देखिये कि 1,30,162 करोड़ रुपये की राजस्व आय का जो लक्ष्य हमने रखा है, उसको आने वाले वर्षों में लगातार बढ़ाने का काम है। इसी के साथ में राजस्व व्यय, हमने इस पर नियंत्रण रखने का काम किया है सभापति महोदय। इसी के साथ-साथ मैं एक और बात आपसे सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा। ऋण को हमने जिस प्रकार से...

श्री सभापति: हो गया, बहुत हो गया।

श्री मान सिंह (गंगापुर): एक बस, लास्ट है। सभापति महोदय, हमारा जो पूंजीगत खर्च है, 2013-14 में इनका 13,664 करोड़ रुपये था, वह हमारा

(श्री मान सिंह)

2017-18 में 20,603 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार से परिवहन के ऊपर इन्होंने 2,377 करोड़ रुपये किया था, वह हमारा 4,882 करोड़ रुपये है मात्र तीन साल में। ऋण का जो हमारा जीडीपी का अनुपात है, उसको लगातार घटाया है। 2015-16 में हमने 36.5 प्रतिशत रखा, 2017-18 में हमने 35.5 प्रतिशत है और 2019-20 में इसको 34 प्रतिशत पर रखने का हमारा इस बजट में संकल्प है। यह ऐसा बजट है जिसको लगातार हर तरीके से नियंत्रित हमने किया है। इसलिए सभापति महोदय, मैं इस बजट के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए कहूंगा कि यह समग्र विकास का बजट है जिससे राजस्थान अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा। आपने बोलने का समय दिया, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया को एवं हमारे जलदाय मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे प्रतापगढ़ जिले के 554 गांव जो दूर-दराज के इलाकों में थे, जिन ग्रामीणों को, जनजाति भाइयों को पीने के पानी के लिए कई-कई किलोमीटर पैदल चलकर पीने के पानी की समस्या से मजबूर होकर कई साधनों का उपयोग करना पड़ता था, उन सबकी समस्या को सुनकर आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में उन 554 गांवों के लिए 900 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है। मैं आदरणीया मुख्य मंत्रीजी, आदरणीय जलदाय मंत्रीजी, हमारे जनजाति विकास मंत्रीजी नन्दलालजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस पूरे जिले को महती सौगात दी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने पिछले कार्यकाल में एक पिंड बांध परियोजना का शिलान्यास किया था। उसके लिए लगभग 54 करोड़ रुपये की उन्होंने स्वीकृति भी जारी की थी। मैं सामने विराजे अपने प्रतिपक्ष के भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप किसानों के हितों की बात तो करते हैं, लेकिन पिछले पांच साल के आपके कार्यकाल में आपने उस पिंड बांध परियोजना को ठंडे बस्ते

(श्री गोतम कुमार)

में डाला और 54 करोड़ रुपये की स्वीकृति होने के बावजूद उस पर कोई काम नहीं किया, किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया। उसके बावजूद भी आपके कान में जूं तक नहीं रेंगी। फिर हमारी सरकार बनी। हमारी संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी ने फिर उस परियोजना की सुध ली और किसानों को बढ़ी हुई दरों से मुआवजा देकर आज मैं आपको, इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि आने वाले बारिश के दिनों में वहां पानी भी रुकेगा और इस बारिश में ही उस क्षेत्र के किसानों को, हमारी पूरी विधान सभा क्षेत्र को पिंड बांध परियोजना का लाभ मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी योजना तो हमारे लिए स्वीकृत की है। एक बागन बांध परियोजना भी हमारे यहां चालू है। उसमें नहरों की स्थिति काफी जीर्ण-शीर्ण है। उनका भी सुदृढ़ीकरण हो जाए। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान भी बात हुई थी, किसानों ने उस समय आदरणीया मुख्य मंत्रीजी से आग्रह किया था, तब आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने उस समय आश्वासन दिया था कि यहां एक खेरिया बांध है प्रतापगढ़ जिले में, अगर वह भी बन जाएगा तो निश्चित रूप से प्रतापगढ़ जिले के किसानों को उसका पूरा-पूरा लाभ मिलेगा।

हमारे विधान सभा क्षेत्र में वर्षों से लम्बित चली आ रही सड़क की, मांग चाहे वह मंगलवाड़ से बड़ी सादड़ी सड़क हो, चाहे होड़ा चौराहा से बानसी सड़क हो, इन दोनों टू-लेन सड़कों के लिए आदरणीय मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्री महोदयाजी ने उसके लिए लगभग 140 करोड़ रुपये की स्वीकृति की घोषणा की और स्वीकृति की घोषणा के साथ में वह दोनों काम मूर्त रूप में नजर आ रहे हैं और उनका लगभग 90 परसेंट काम अभी तक पूरा हो चुका है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से आदरणीया मुख्य मंत्रीजी का और आदरणीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए जो दोनों टू-लेन महत्वपूर्ण सड़कें थीं, उनके लिए बजट स्वीकृत किया और निर्माण कार्य इन-टाइम उन्होंने पूरा किया। मेरा छोटा सा आग्रह भी है आपके माध्यम से आदरणीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से कि हमारे क्षेत्र में कुछ मिसिंग लिंक सड़कों की जरूरत है। चूंकि आवागमन में कहीं-कहीं गांवों में, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए

(श्री गोतम कुमार)

अगर कोई मिसिंग लिंक सड़क बन जाए दो-तीन किलोमीटर की तो कहीं-कहीं 15-15 किलोमीटर और 20-20 किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर हमारे यहां मिसिंग लिंक सड़कों के लिए आप अगर थोड़ा सा बजट जारी कर देंगे। वैसे तो आपने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन अगर ये मिसिंग लिंक सड़कों की मांग भी अगर आप पूरी करेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों को काफी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरे राजस्थान में और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाएं 10वीं के बाद पढ़ने से वंचित रह रही थीं, उन बालिकाओं के लिए सोचकर कैसे उन्होंने हर पंचायत मुख्यालय पर पूरे राजस्थान में, विशेष रूप से हमारे प्रतापगढ़ क्षेत्र और बड़ी सादड़ी क्षेत्र में जहां 12वीं के स्कूल 15-15 और 20-20 किलोमीटर तक उपलब्ध नहीं थे। कई बालक-बालिकाएं पढ़ने से वंचित रह जाते थे। आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने हर पंचायत मुख्यालय पर 12वीं के स्कूल खोलने की घोषणा की और उनके परिणाम आज अपने को देखने को मिल रहे हैं... कि किस तरह से 34 से 35 परसेंट नामांकन बढ़ा है। मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से भी अनुरोध है कि उनमें नामांकन जिस तरह से बढ़ा है थोड़ी सी कक्षा कक्षों की भी कमी हुई है, थोड़ी सी वहां शिक्षकों की भी जरूरत है, व्याख्याताओं की भी जरूरत है। आपने भर्ती निकाली है, लेकिन वो कोर्ट की वजह से अटकी हुई है, मेरा आपसे आग्रह है कि जल्दी से जल्दी उन व्याख्याताओं की और शिक्षकों की कमी को आप पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से छात्रों को अच्छी शिक्षा और सुविधा मिल सकेगी। हमारी सरकार ने पर्यटकों के लिए विशेष रूप से इस बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया है। इस बजट में बीस से तीस परसेंट बजट पर्यटन विभाग के लिए बढ़ाया है मेरा आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी से और वन मंत्री जी से आग्रह है कि हमारे यहां सीतामाता में एक वन्य जीव अभयारण्य है जहां लगातार बारह महीने पानी बहता रहता है, वहां एक विश्व प्रसिद्ध उड़न गिलहरी भी है और इसके अलावा भी चोसींगा और कई प्रकार के जंगली जानवर वहां निवास करते हैं और इतनी अच्छी ग्रीनरी है शायद राजस्थान में कोई दूसरा अभयारण्य ऐसा

(श्री गोतम कुमार)

हो तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि उस सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य पर भी आप थोड़ी सी नजर रखें और उस पर कृपादृष्टि करके इस बजट में जो इतना अच्छा प्रावधान आपने रखा है उसमें कहीं न कहीं सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य के लिए भी थोड़ा सा अगर उस पर बजट मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वो अभयारण्य भी पूरे राजस्थान के मानचित्र पर नजर आएगा।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए हमारी यशस्वी मुख्यमंत्रीजी ने जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में हरेक पंचायत मुख्यालय पर मूकबधिर पशुओं के लिए जो बोल नहीं सकते उनके लिए भी पशु उप केन्द्र खोलने की घोषणा की है और काफी उप केन्द्र पिछले दो सालों में भी खुले थे, लेकिन अभी इस बजट में हर पंचायत मुख्यालय पर पशु उप केन्द्र खोलने की घोषणा की है निश्चित रूप से गांवों में जो पशुपालक हैं, किसान हैं वो लगभग पन्द्रह-बीस किलोमीटर दूर चिकित्सा सुविधा नहीं होने से न तो वो पशुओं को ले जा सकते हैं, न ही कोई चिकित्सा सुविधा उनको मिल रही थी। ऐसे में पंचायत मुख्यालय पर जो पशु उप केन्द्र खुले हैं उससे निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के जो भी पशुपालक हैं, जो भी गौशालाएँ हैं उनको निश्चित रूप से उसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्रीजी का, आदरणीय कृषि मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इन्सानों के साथ-साथ में मूकबधिर जानवरों का भी, न बोलने वाले और न सुनने वाले जानवरों का भी ध्यान रख करके जिस तरह से हर पंचायत मुख्यालय पर जो आपने उप केन्द्र खोले हैं निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता, पूरे राजस्थान की जनता आने वाले समय में आपको याद रखेगी।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक बार मुख्यमंत्रीजी का और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से हमारे आदरणीय और हमारे प्रेरणास्रोत दीनदयाल जी उपाध्याय जिन्होंने जीवन भर गरीब के कल्याण के लिए सोचा, किस तरह से योजनाएं बनी कर अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति तक एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से उन्होंने गरीब के लिए सोचा और उन्हीं के नाम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दीनदयाल जनकल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया उसमें पूरे राजस्थान में जो जनता को लाभ मिला, मैं

(श्री गोतम कुमार)

निश्चित रूप से अपनी ओर से और पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से चूंकि हर शिविर में मेरा जाने का काम पड़ा। वहां पेन्शन और सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी उन आम आदमियों तक पहुंची और उनका लाभ नीचे तक पहुंच सका। आदरणीय दीनदयालजी के सपने को साकार करने का जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया, उसके लिए उनको धन्यवाद देते हुए मैं आपका भी धन्यवाद दूंगा कि इस बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती अंजू धानका जी।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं और साथ में यह भी आज समझ में आ गया कि जिसका बहुमत उसकी सत्ता और जिसकी सत्ता उसकी दादागीरी। चार मैंबर पहले मेरा नम्बर था, लेकिन चार के बोलने के बाद आया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह क्या बोला आपने।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपकी सिफारिश की है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): आपकी मेहरबानी। आपने सिफरिश की I know. आपने की है thank you. आपने की मैंने बताया, तो मैं बजट पर बोलना चाहूंगी।

सभापति महोदय, एक समय था जब आम बजट सीधा और सच्चा हुआ करता था पर अब बजट असत्य वाहवाही लूटने का माध्यम बन गया है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। हर वर्ष बजट में ढेर सारे लोक लुभावने वादे किये जाते हैं जिनके लिए न तो वित्तीय प्रावधान होते हैं, न ही प्रशासनिक ढांचा और न कोई प्लान उसमें ठीक तरीके से होता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि 31 मार्च के बाद पता चलता है कि अनेक घोषणाएं सिर्फ बजट भाषण की किताब का हिस्सा बन करके रह गयीं। उस समय वाहवाही लूटने का सबसे शानदार तरीका है।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

सभापति महोदय, पिछले पन्द्रह साल की बजट घोषणाएं और उनमें से कितनी पूर्ण हुई या आरंभ हुई इसकी विधान सभा कमेटी अगर जांच करे तो मुझे विश्वास है कि इनकी संख्या सैंकड़ों में होगी। अत: मेरा सभापति महोदय, आपसे अनुरोध है आप विधान सभा की प्राक्कलन समिति को ये निर्देश दें कि पन्द्रह सालों में बजटों में क्या-क्या घोषणाएं की गयी और उनका क्या परिणाम निकला। मैं यह भी मांग करती हूं कि हर बजट के साथ पिछले बजट में की गयी घोषणाओं का हिसाब-किताब भी सदन पटल पर रखना अनिवार्य किया जाए, ताकि जनता के साथ लगातार हो रहे छल को रोका जा सके। सभी बजट अच्छी घोषणाओं का पुलिंदा होता है। बजट अच्छा या खराब नहीं होता है। खराब वह तब हो जाता है जब उसमें आकांक्षाएं अधूरी रह जाती हैं या जो वास्तविकता में होता ही नहीं है, सिर्फ चुनावों के मद्देनजर कुछ घोषणाएं कर दी जाती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो जमीन पर कहीं नहीं होती हैं और अबका बजट तो जमीन पर है ही नहीं। मुझे खुशी होगी यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदया, पिछली बजट घोषणाओं में से जो पूर्ण नहीं हो सकीं, के बारे में सदन को सूचित कर एक स्वस्थ परम्परा आरंभ करें यहां।

माननीय सभापति महोदय, साल दर साल प्रतिभावान छात्रों को स्कूटी देने की घोषणाएं की जाती हैं, जो इस बजट में भी की गयी हैं परंतु वह कागजी रह जाती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के वर्ष 2015-16 की घोषणाओं के दो साल बाद भी स्कूटी नहीं मिली है और यह कल के ही अख़बार में आया है मेरे पास अख़बार की कटिंग है। 66 छात्राओं को स्कूटी देनी थी जो पिछले दो साल से उन तक पहुंची नहीं हैं। इस बजट में फिर से एक बार घोषणा की गयी है और यह मैं नहीं कह रही हूं राजस्थान पत्रिका जैसा सजग समाचार पत्र लगातार इस प्रकार की खबरें छाप रहा है पर सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। वर्तमान सरकार शिक्षकों तथा चिकित्सकों की लगातार नियुक्ति कर रही है परंतु अभी भी बड़ी मात्रा में पद खाली पड़े हैं उन्हें शीघ्र भरने के लिए प्रयास करने होंगे, ताकि ग्रामीण शिक्षा व चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त हो सके। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि शहरी डाक्टर और शिक्षकों का स्थानान्तरण गांवों में कर देना

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

चाहिए क्योंकि शहरों में तो बहुत सारे निजी हास्पिटल्स भी हैं और बहुत सारे स्कूल्स प्राइवेट भी हैं। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम बच्चे जा पाते हैं, लेकिन गांवों में ज्यादातर डिपेंड रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल के लिए बच्चे तो वहां ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है। अत: मैं अपने क्षेत्र की दो बड़ी समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। बस्सी में एक आरओबी की घोषणा आठ साल में दो बार हो चुकी है और दो बार टैण्डर भी हो चुके हैं और एक टैण्डर निरस्त होकर जब दूसरा हुआ है उसके बाद भी आज तक काम चालू हुआ नहीं है। इस बात को भी आज दो-तीन साल हो गये हैं और अभी भी जेडीए का और बजट में बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गयी हैं बहुत ऐसा लग रहा है कि क्या अरबों-खरबों रुपया लुटाया जा रहा है इस बजट में दिया जाएगा और राजस्थान का विकास चरम सीमा पर होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं आठ साल में इस आरओबी का सिर्फ इसलिए काम नहीं हो रहा है क्योंकि वहां जो प्रभावित हैं उस आरओबी से उन लोगों को अब तक मुआवजा सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि जेडीए के पास पैसा नहीं है। जेडीए कहता है कि हम कंगाल हो चुके हैं हमारे पास पैसा नहीं है। नाबार्ड में जाओ उनके पास पैसा नहीं है। माडा में जाओ उनके पास पैसा नहीं है। पीडब्ल्यूडी में जाओ तो उसका जवाब मैं आपको बताती हूं कि मुझे क्या दिया था। राजस्थानी में था थोड़ा हो सकता है कि मैं गलत बोल जाऊं कि म्हे तो केंचुली उतार बेस पेहरा छां, ऐसा कुछ उन्होंने बोला मुझे मंत्री जी के यहां जो मैं ठीक से नहीं बोल पाऊंगी, तो उनकी हालत भी ऐसी है। जब डिपार्टमेंट में पैसा ही नहीं है तो इतनी बड़ी-बड़ी जो घोषणाएं हो रही हैं, इससे पता चलता है कि पिछली घोषणाएं ही पूरी नहीं हुई। दूसरा मिसिंग लिंक पीडब्ल्यूडी में,

(18.00 बजे)

200 विधान सभा क्षेत्र है लेकिन शायद निर्दलीय होने की वजह से मेरे साथ इतना भेदभाव किया जाता है कि पूरे राजस्थान को 2015-16 के बजट में मिसिंग लिंक दी गयी, टेंडर भी हुए और पूरे राजस्थान में बन भी चुके हैं, एक सिर्फ बस्सी विधान सभा क्षेत्र ऐसा है जिसको 2015-16 में एक भी मिसिंग लिंक सड़क नहीं दी गयी है। पूरे राजस्थान को पीएचईडी विभाग से

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

सोलर सिस्टम से सिंगल फेस 5-5 सभी को दिये गये हैं, लेकिन इकलौती विधान सभा क्षेत्र बस्सी को नहीं दिये गये हैं। ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय, पिछले 8 साल से लगातार मैं मेरे क्षेत्र की बच्चियों के लिये महिला महाविद्यालय की मांग कर रही हूं परंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की, बात तो सभी महिलाओं की तरक्की की करते हैं, परंतु जब उनकी शिक्षा की बात आती है तो उनकी उपेक्षा कर दी जाती है क्योंकि यह सभी जानते हैं कि यदि महिलाएं पढ लिख जाएंगी तो समाज के ठेकेदार बने पुरुषों की गद्दी हिल जाएंगी। यह हुआ है, 2013 के चुनाव में हमने साक्षात देखा है। इसी कारण पुरुष नेता इस मांग को कभी नहीं रखते हैं। महिलाएं भी यहां बैठी हुई हैं, आपने कभी भी किसी क़द्दावर पुरुष नेताओं को पिछडे क्षेत्रों में महिला शिक्षा के लिये कालेज खोलने की मांग करते हुए, आंदोलन करते हुए या विधान सभा में कभी इसकी मांग करते हुए नहीं देखा होगा। अगर करेंगे तो आप ही करेंगे, महिलाएं ही कर रही होंगी। परंतु इस बजट से मुझे काफी उम्मीदें थीं क्योंकि पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री 2016 में हमारे यहां बस्सी विधान सभा क्षेत्र में आये थे और बहुत बड़ा वादा करके गये थे, महाविद्यालय खोलने का, बच्चियों को आश्वासन देकर गये थे लेकिन वह असत्य ही निकला, उन्होंने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया।

यही नहीं, राठौड साहब, जून 2016 तारीख आप खुद याद कर लेना, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री और देवस्थान चेयरमैन ने मुझे 100 प्रतिशत आश्वस्त किया था कि मुख्य मंत्री ने सहमति दे दी है, बाकी चीजें आप खुद समझ लेना और 2017 के बजट में बस्सी की बच्चियों के लिये महाविद्यालय खोल दिया जाएगा। राठौड साहब, आप गवाह है उस दिन के, परंतु महिला दिवस के दिन महिला मुख्य मंत्री ने अपने जन्म दिन के दिन भी बच्चियों के अरमानों की हत्या कर दी। माननीय मुख्य मंत्री अपने किये वादों को पूरा करने के लिये संपूर्ण राजस्थान में जानी जाती हैं, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती हूं कि मैं एज ए मुख्य मंत्री उन्हें जानती हूं और मैं यह जानती हूं कि जो भी लोग उनकी बात करते हैं वह कहते हैं कि वह जो कह देती हैं, वह करती है, परंतु पता नहीं क्या हुआ उनकी ओर से वरिष्ठ

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

नेताओं द्वारा किये गये वादों को पूरा नहीं किया। मैं यह पूछना चाहती हूं क्या बीजेपी अध्यक्ष और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आपकी अनुमति के बिना ही वादा किया था? लगता नहीं है किसी में इतनी हिम्मत है कि मुख्य मंत्री के बिहाफ पर कोई असत्य वादा कर सकता है।

सम्माननीय सभापति महोदय, मैं पिछले दिनों अपने क्षेत्र में महिलाओं तथा बच्चियों के साथ इस संबंध में चर्चा कर रही थी तो एक महिला बोली, अपने राजस्थान में तो यह कहावत मशहूर है कि महिला की महिला से बड़ी कोई दुश्मन नहीं होती है। किरण जी, आप जरूर सुनना ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्या, यह कौनसी महिला है, क्या नाम था उस महिला का जिसने कहा कि महिलाओं की महिला दुश्मन। ऐसा कोई नहीं कह सकता। आप महिला होते हुए भी महिला का अपमान कर रही हैं।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): रामप्यारी। आप पूरी बात तो सुनो, आपको मुझसे बात करना ज्यादा अच्छा लगता है, जब भी मैं बोलती हूं आप खड़े हो जाते हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आसन को संबोधित करें।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सभापति महोदय, महिलाओं की बात है तो महिलाओं की तरफ तो देखूं ना। उसका नाम रामप्यारी था, ...(व्यवधान)... रामप्यारी काकी ने यह कहा कि महिला की महिला से बड़ी कोई दुश्मन नहीं होती। बस्सी की महिला विधायक, मंत्री महिला और मुख्य मंत्री भी महिला, फिर भी बस्सी में गरीब बच्चियों के लिये महाविद्यालय नहीं खुला, इसका कारण यह है कि महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला ही होती है। मैंने इसका विरोध किया और कहा, ऐसा नहीं है। वह कहने लगी, देख लो हर घर में बहू की दुश्मन सास ही होती है। जो लड़की इस सैशन के बाद कालेज में जाने वाली हैं वह इन सब बातों को सुन रही थी, उसने बड़ा मासूम सवाल किया कि मैडम जो बहू होती है उस पर सास अत्याचार कर सकती है .. **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

सभापति महोदय, चार लोगों के बाद आपने बुलवाया है तो मैं एक्सट्रा बोलूंगी।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

उसने यह कहा कि सास बहू पर अत्याचार कर सकती है लेकिन बेटी पर तो नहीं कर सकती। हम तो मुख्य मंत्री जी की बेटियां हैं, हमारे लिये थोडे ही ऐसा सोचेंगी। आप भी मुख्य मंत्री की बेटी हो तो आप विधान सभा में फिर यह बात रखना कि ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्या, आप क्या कह रही हो, सास बहू पर अत्याचार करती है, राजस्थान की जितनी भी सास हैं वह सारी आपके खिलाफ हो जाएंगी। आप जब वोट मांगने जाओगे तो हर घर में कोई न कोई सास होगी।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): वह मैं मना लूंगी, वह टैक्निक मुझे बहुत अच्छे से आती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): राजस्थान में जितनी भी सास हैं उन सब पर आरोप लगा रही हो, रिकार्ड में बात जा रही है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैंने कहा, आपको मेरे से बात करना अच्छा लगता है। नहीं तो आप चुपचाप सुन लो ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सास भी कभी बहू थी ...(व्यवधान)...

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैंने कहावत की बात की है कि ऐसी कहावत है कि सास बहू पर अत्याचार करती है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): उस बच्ची ने यह कहा कि सास चाहे बहू पर अत्याचार करे लेकिन बेटियों से बहुत प्यार करती है और मैडम आप भी तो मुख्य मंत्री की बेटी जैसी है फिर ऐसा क्यों। फिर वह कहने लगी मैडम, आप विधान सभा में मुख्य मंत्री जी से बात कहना कि हम गरीब बच्चियों के लिये बस्सी में महाविद्‌यालय खोले और इस कहावत को असत्य सिद्‌ध करेंगे।

श्री सभापति: इस पेपर का रैफरेंस जरूर दें।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी कल करने वाले हैं और 'हां' भी कह रहे हैं, कल घोषणा आप करवा रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैं उम्मीद करती हूं कि अपने वादे को हर सूरत में पूरा करने वाली माननीय मुख्य मंत्री महोदया की ओर से दिये गये वादे को पूरा करेंगी और गरीब बच्चियों को पढ़ने का मौका देंगी, क्योंकि सभी निजी कालेज में नहीं पढ़ सकते।

मैं लास्ट में महिलाओं के लिये एक बात और कहना चाहूंगी, सभी महिलाएं सुन लें, महिलाओं के लिये संसद में और विधान सभाओं में आरक्षण का विधेयक तो पुरुष प्रधान समाज कभी पास होने नहीं देगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहती हूं एक काम मुख्य मंत्री जी कर सकती हैं कि महिला विधायकों के क्षेत्रों में अधिक से अधिक विकास के काम होने चाहिये ताकि संपूर्ण राजस्थान में मैसेज जाए कि यदि आपको क्षेत्र का विकास कराना है तो महिलाओं को विधायक चुने। ऐसा हो सका, तो बिना आरक्षण के ही महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। अब यह बात आपके गले नहीं उतर रही होगी।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): एक लास्ट, लास्ट, मैं एक बात और कहना चाहती हूं, जो मैंने वादे की बात कही, महिला महाविद्यालय का वादा जून 2016 को किया था, तो जिस व्यक्ति ने किया था, प्रदेशाध्यक्ष। बीजेपी ने ऐसे प्रदेशाध्यक्ष बनाये जिनकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है। मैं लास्ट में यह भी कहना चाहूंगी।

श्री सभापति: माननीय हीरालाल जी नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया।

पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से तीन बजट प्रस्तुत किये और यह चौथा बजट है, निश्चित रूप से हमारी इस विधान सभा में भी और आम जनता में भी यह

(श्री हीरालाल नागर)

एक संदेश है कि इन तीन सालों में जो विकास के काम हुए हैं, जिस तरह के आयाम इन तीन सालों में स्थापित किये गये हैं और मदवार, आंकडोंवार, जिस तरह से हमारे सदस्यों ने यहां बताया है कि कांग्रेस के लगभग पांच साल और हमारे तीन साल, उससे भी ज्यादा विकास के काम हमारे इन तीन सालों में हुए हैं।

(18.09 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमारे अब दो साल बाकी हैं। आने वाले समय में भी लगभग इतने ही विकास के कार्य और होंगे, निश्चित है। हम जब भी गांव में जाते हैं, आज जनता यही कहती है कि इन तीन सालों में जो विकास के काम हुए हैं। जो विकास की गंगा गांव-गांव में बही है, वह निश्चित रूप से एक इतिहास है कि इतना विकास का काम जो इस राज में तीन साल में हुआ, उतना पिछले कई वर्षों के राज में नहीं हुआ। इस बात का जनता में यह संदेश है, और हमारी मुख्यमंत्री ने एक कुशल नेतृत्व के कारण करके दिखाया, उनकी कड़ी मेहनत से..।

जिस तरह से हमारी मुख्यमंत्री ने इस बजट में वित्त का जो समायोजन किया, निश्चित रूप से ऐसे कई खर्चे जो गैर-उपयोगी होते थे, उनको रोककर उपयोगी खर्चों का किया। उसी कारण आज, आप चाहे किसी भी विभाग में ले लीजिए। हर विभाग में पिछले राज से दुगने से ज्यादा काम हमारे केवल इन ढाई-तीन साल के राज में हुए हैं और इसका यह नतीजा है कि आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता चाहे बैठे हों, कोई जवाब नहीं दे पाते कि आपने तीन साल में कितने काम किए थे? उसके दुगने से ज्यादा काम हमारी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने करके दिखाए हैं और जनता में भी यह बात आज जा रही है।

हमारी मुख्यमंत्री ने गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में जाकर जिस तरह से उन्होंने यात्रा की और उस परिवर्तन यात्रा में उन्होंने देखा कि हमारे गांवों की कैसी स्थिति है, हमारे प्रदेश की कैसी स्थिति है। किस तरह से पिछले कांग्रेस के शासन में टूटी हुई सड़कें, गांव में कीचड़, चाहे स्वास्थ्य की स्थिति हो,

(श्री हीरालाल नागर)

चाहे शिक्षा की स्थिति हो, इस प्रदेश को बदतर बनाया था। उसको संवारने का काम तीन साल में धीरे-धीरे पटरी पर लाने का काम हमारी मुख्यमंत्री ने किया है और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी उनको जोड़ने का काम हमारी मुख्यमंत्री ने किया है।

आज प्रदेश में चाहे भामाशाह की योजनाएं हों, चाहे हमारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, राशन कार्ड हो। राशन कार्डों पर भी आज पंचायती राज मंत्री जी बोल रहे थे कि पोस मशीन का विरोध कर रहे थे। आज भ्रष्टाचार रोकने का कोई बड़ा काम किया है तो राशन में पोस मशीन के माध्यम से किया है। जहां पहले 40 परसेंट से भी ज्यादा राशन, राशन डीलर्स खा जाया करते थे। आज उस पर रोक लगी है तो इसका काम हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया है।

हमारे प्रदेश में गांव की जो खस्ताहाल सड़कें थीं, हमारी मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में आज चाहें वे मिसिंग लिंक हो, चाहे गौरव पथ के माध्यम से हो, चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से हो, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने..। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तीन वर्ष में 20 हजार 822 करोड़ रुपये की लागत से 4 हजार 281 गांवों, मजरों व ढाणियों को जोड़ने का काम किया है। जबकि तीन वर्ष के राज में कांग्रेस ने मात्र 9 हजार 157 करोड़ की लागत से 661 गांवों, मजरों व ढाणियों को जोड़ने का काम किया था। हमने तीन वर्षों में 15 हजार 278 किलोमीटर लम्बाई की नवीन सड़कों का निर्माण करके 4 हजार 637 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस ने पांच वर्षों में मात्र 12 हजार 554 किलोमीटर लंबाई की सड़क में 2993 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो कि हमारे तीन वर्ष के कार्यकाल से भी कम है।

इसी तरह से गौरव पथ गांव के लोगों में एक मिसाल बन गये हैं कि गौरव पथ के माध्यम से कैसे शहर की तर्ज पर गांवों का विकास किया जा सकता है? गांव के लोगों को कभी विश्वास नहीं था कि हमारे गांव में कोई अच्छा सी.सी. बन सकता है। कांग्रेस के भाई आरोप लगाते हैं कि सड़कों पर रोड़ बना रहे हैं। डामर पर रोड़ बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उस

(श्री हीरालाल नागर)

डामर पर, उस सड़क पर खड्डे ही खड्डे थे जहां रोड़ बन रही थी, वहां सड़क थी ही नहीं। गांव के बीच में से कोई रोड़ गुजर रही है तो उसको ठीक करने का काम आज कर रहे हैं। बढ़िया नाली बना रहे हैं। बढ़िया एम-30 की सी.सी. बन रही है, जो आने वाले बीस साल तक उस रोड़ को सुरक्षित रखेगी। यह काम हमारी मुख्यमंत्री ने किया है। जो हमारी मुख्यमंत्री की सोच है, एक बहुत बड़ा संदेश गौरव पथ के माध्यम से गांवों में गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिसिंग लिंक के माध्यम से भी प्रथम चरण में 2246 किलोमीटर की मिसिंग लिंक की सड़कों का निर्माण चालू वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा और द्वितीय चरण में 1820 किलोमीटर लंबाई की सड़कें भी आगामी वर्ष में पूरी कर ली जाएंगी। आगामी वर्ष में दो हजार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1200 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण गौरव-पथ, मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

इसी तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ढ़ाई सौ से साढ़े तीन सौ आबादी के 1 हजार 480 गांवों को 1 हजार 618 करोड़ 64 लाख रुपये की लागत से 4 हजार 303 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को जोड़ने का कार्य अभी प्रगति पर भी है। इस योजना के प्रथम चरण में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूर्ण कर लिया गया है और द्वितीय चरण के लिए भी पात्र हो गये हैं।

आगामी वर्ष में 3 हजार 665 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन व रखरखाव का कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा।

सड़कों के मामले में आज हमारा प्रदेश पूरे देश में नंबर-वन पर है और यह विकास हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री के कुशल वित्तीय प्रबंधन और उनके एक-एक योजना पर ध्यान देने के कारण संभव हो पाया है। जबकि पुराने कांग्रेस के शासन में कोई बजट नहीं होता था, केवल स्वीकृतियां जारी होती थीं। इन्होंने बिना कोई बजट के यहां से जो भी इनके सड़क मंत्री थे, 800 करोड़ का बजट सड़कों पर और 4200 करोड़ की स्वीकृतियां जारी कर दीं, जिसको हम दो साल तक भी बजट देते रहे और इनको पुराने कामों को पूरा कराने का काम भी हमने किया है।

(श्री हीरालाल नागर)

मानीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में राजमार्गों का विस्तार करने के लिए हमारी मुख्यमंत्री ने भी एक दृढ़ संकल्प किया है और मुख्यमंत्रीजी एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में देवली से कनवास तक की 15 किलोमीटर सड़क पर 38 करोड़ रुपये को बजट में शामिल करके सांगोद की जनता को जो सौगात दी है। कोटा से कैथून, देवली, सांगोद, बपावर, कवाई का जो स्टेट हाई-वे था, उसको नेशनल हाई-वे घोषित करके उसकी डीपीआर बनाने के लिए टैण्डर निकाल दिए गये। फिजिबिलिटी के लिए टैण्डर निकल गये और मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने उसको नेशनल हाई-वे में शामिल करके इस विधान सभा क्षेत्र के लिए कार्य किया है। साथ ही, माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि कैथून से, बालाजी की थाक से अड़ूसा तक की एक एम.डी.आर. सड़क है, जो 185 नंबर है। कुंदनपुर से घानाहेड़ा, लक्ष्मीपुरा, अमृतकुंआ, पनवाड़ जो झालावाड़ जिले से जोड़ती है। अगर इसे भी बजट में शामिल कर लिया जाता है तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज गांवों में पेयजल की बहुत कमी है तथा जहां पेयजल है तो वहां पर फ्लोराइड अधिक मात्रा में है। पेयजल की गुणवत्ता और प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गांवों में सतही जल की कमी और गुणवत्ता आधारित जल हेतु पेयजल योजनाओं पर सरकार द्वारा अब कुल 1 लाख 21 हजार 648 गांवों एवं ढाणियों में से अब तक 55 हजार 25 गांव और ढाणियों को मार्च, 2016 तक पेयजल से लाभान्वित किया चुका है। शेष समस्याग्रस्त गांवों और ढाणियों में से भी 265 गांवों और ढाणियों को भी नवम्बर, 2016 तक लाभान्वित किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 2039 गांव एवं ढाणियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसी क्रम में आगामी वित्तीय वर्ष में 2500 गांव एवं ढाणियों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर गत सरकार द्वारा प्रथम तीन वर्ष में 6 हजार 97 करोड़ रुपये का व्यय किया, जबकि हमारी सरकार के द्वारा प्रथम तीन वर्ष में दुगने से भी ज्यादा 13 हजार

(श्री हीरालाल नागर)

473 करोड़ रुपये पेयजल पर खर्चा किया गया है। निश्चित रूप से यह हमारा संकल्प दोहराता है कि हम विकास में कितने..। पुरानी सरकारी पांच साल में तीन साल का मुकाबला भी नहीं कर पा रही। हमारा इससे ज्यादा है।

हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश में फ्लोराइडयुक्त गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। फ्लोराइडयुक्त गांवों को गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार द्वारा आर ओ प्लांट का एक नया कंसेप्ट लाया गया है कि गांवों में रहने वाले गरीबों को भी आर ओ का पानी मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में आर ओ प्लांट लगाने के लिए कार्य किया जा रहा है जिसके लिए प्रथम चरण में 885 आर ओ प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। द्वितीय चरण में एक हजार 66 आर ओ प्लांट 245 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत किए गये हैं। 445 आर ओ प्लांट इंस्टालेशन कर दिए गए हैं। शेष के इंस्टालेशन कार्य भी 2017- 18 में पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसके अलावा भी हमारी सरकार 2017-18 में एक हजार 483 आर ओ प्लांट लगाने की और भी योजना रखती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र की जनता जल योजनाओं में जीर्णोद्धार के माध्यम से, जो जीर्ण शीर्ण योजनाएं थी उनको भी ठीक करके हमारी मुख्यमंत्री ने सुदृढीकरण किया है, जिसके लिए 135 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से 1586 योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। इसी तरह से 2016-17 में भी एक हजार अतिरिक्त योजनाओं को दुरूस्त करके 127.47 करोड़ से 767 योजनाओं की स्वीकृति भी प्रारम्भ कर दी गयी है। वर्तमान में 500 अतिरिक्त जनता जल योजनओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया जाएगा।

मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक दर्जन से ज्यादा जनता जल योजनाओं का जीर्णोद्धार किया है, सुदृढ़ीकरण किया है, आर ओ प्लांट लगाए हैं। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके आने से थोड़ी कठोरता हो रही है, पहले वालों ने बहुत समय दिया था। तो मुझे भी थोड़ा सा समय दे दें।

पूरे प्रदेश में 2015-16 में एक हजार नलकूपों की स्थापना के विरुद्ध 1390 सौलर वाटर पम्प लगाए गये हैं।

(श्री हीरालाल नागर)

मुख्यमंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि कोटा में बोराबांस पेयजल परियोजना, जिसे बजट में शामिल किया है उसमें मेरी विधान सभा क्षेत्र के मोरूकलां पंचायत तक भी उसका लाभ मिलेगा। इस पूरी योजना से 207 गांव और 52 मजरों को लाभान्वित करके चम्बल का पानी मुहैया कराया जाएगा।

मैं मुख्यमंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की एक पेयजल परियोजना है जिसकी डीपीआर बन चुकी है, हरिपुरा माझी पेयजल परियोजना है। जलदाय मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं, इस परियोजना की डीपीआर बनकर तकनीकी परीक्षण के लिए सरकार के पास पहुंच चुकी है। इसकी अनुमानित लागत डीपीआर में 291.79 करोड़ की है। माननीय महोदय, इस पेयजल परियोजना से सांगोद विधान सभा के 102 गांव, 20 मजरे, पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के 44 गांव, 6 मजरे, लाड़पुरा विधान सभा क्षेत्र के 61 गांव और 26 मजरे, कुल 207 गांव और 52 मजरे लाभान्वित होंगे। 46 गांव ऐसे हैं जो फ्लोराइडयुक्त भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विधान सभा क्षेत्र की हरिपुरा-माझी पेयजल योजनाओं को भी बजट में शामिल करके मुख्यमंत्रीजी घोषणा करें तो मैं उनका बहुत- बहुत आभार करता हूं।

इसी तरह से सिंचाई में भी एक नया आयाम स्थापित किया गया है। किसानों को, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन के माध्यम से हमारी मुख्यमंत्री ने 1.6 प्रतिशत जो जल प्रदेश में है उसमें एक इतिहास रचा है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में वाटर लेवल में इजाफा हुआ है एक बड़ा क्रांतिकारी कदम हमारी मुख्यमंत्री ने उठाया है। निश्चित रूप से उससे आने वाले समय में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन के माध्यम से हम पानी कम होते हुए भी इसका संचय करके, अच्छी तरह से उपयोग करके, हमारी उपज को बढ़ाने का, सिंचाई, पेयजल के लिए काम करेंगे।

मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2003 से 2008 के कार्यकाल का उनका सपना था कि परवन परियोजना बने। परवन परियोजना बनकर, तैयार होकर, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने केन्द्र सरकार को भेजी, कांग्रेस शासन होने के कारण उस समय स्वीकार नहीं हो सकी,

(श्री हीरालाल नागर)

पांच साल तक कांग्रेस शासन रहने के बाद भी उस परियोजना पर कुछ काम नहीं हुआ। अनेक आपत्तियों के बावजूद भी इनके, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हो, उन्होंने आकर उस परियोजना का केवल असत्य शिलान्यास करने का काम किया। उसकी आपत्तियों को दूर करके आज हमारी मुख्यमंत्री ने परवन परियोजना के लिए घोषणा की। 700 करोड़ का बजट पिछले बजट में दिया। एक हजार करोड़ का बजट इस बार दिया है। मैं बारां, झालावाड़ और कोटा जिले की सारी जनता की तरफ से मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह से 313 गांवों में परियोजना का लक्ष्य था अब उसको एक लाख 31 हजार हैक्टेयर से बढ़ाकर 2 लाख हैक्टेयर किया जा रहा है। यह प्रदेश की एक महती योजना होगी जिससे पूरे हाडौती क्षेत्र में उत्पादन के क्षेत्र में लागत कम करने के लिए, हमारी केन्द्र सरकार का भी, प्रधानमंत्री का भी सपना है कि किसान की उत्पादन लागत कम करें और उसके अच्छे भाव मिले, उसको दुगनी आमदनी हो। इसके लिए यह परियोजना होगी। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो पाइंट और हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। आपके एक-दो पाइंट से एक-दो सदस्य बोलने से वंचित रह जाएंगे।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, धन्यवाद। जैसा आदेश।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट की जितनी व्याख्या अपन करें, उसकी बड़ाई करें। बजट बनाया जाता है, सारे विभागों को छूकर, उन विभागों का प्रदेश के सामाजिक जीवन के ऊपर कहां-कहां, किस-किस पर प्रभाव पड़ेगा, उन सभी को साथ लेकर, उनकी विचारधाराओं को साथ लेकर। पेयजल का विषय है तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वहां के सामाजिक संगठनों को साथ लेकर। खेती वाला है तो किसान संगठनों को साथ लेकर। अगर मजदूरों का विषय है तो मजदूर यूनियनों को साथ लेकर। इन सभी से विचार करने के

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

बाद मुझे लगता है यह राजस्थान का बजट है। जिस प्रकार से तीन वर्षों का समय काल बीता है, बजट के मामले में इतनी व्यापकता रखी है। वास्तव में जिस प्रकार से एक परिवार को चलाना चाहिए वैसा हमारी मुख्यमंत्री महोदया ने इस राजस्थान को चलाया।

पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार से अनैतिक विषय लाकर हमें प्रश्नचिन्ह के रूप में खड़ा कर दिया था कि क्या करना और क्या नहीं करना। पूर्ववर्ती सरकार ने जाते- जातेजिन घोषणाओं का पिटारा खोला, उनके जो भी सारे अधिकारी थे, उनके जो भी नजदीक के लोग होंगे, उन्होंने कह दिया था सरकार नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो पीछे आने वाली सरकार भी दुःखी होकर कैसे काम करें, सुखी न हो और जनता का सही काम ना करें, इसलिए आनन फानन में जो कुछ भी किया वह जनता ने देख लिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2013 से हमने संभाला तब जिस-जिस फील्ड में हमारे विभाग, देश लेवल पर कहीं न कहीं अपने आप में पुरस्कृत हुए हैं, उनमें काम की चेष्टा और काम के विजन को उन्होंने आगे बढ़ाया।

बजट के साथ-साथ, राजस्थान के आम अवाम को सुख चैन कैसे दें, वह विचार तो हमारा है ही है। उसके साथ-साथ आने वाली युवा पीढी का समग्र विकास कैसे हो, उसकी चिंता भी है। हमारी युवा पीड़ी का पर्सनलिटी डवलपमेंट कैसे हो उसमें स्किल डवलपमेंट के नाते यह पहली बार विजन हुआ कि सरकार ने दो यूनिवर्सिटी, एक सरकारी और एक प्राइवेट फील्ड में लाकर युवाओं के साथ बहुत बड़ा न्याय किया। पूर्ववर्ती सरकारों के पहले कभी ध्यान में नहीं आया। लेकिन मैं मुख्य मंत्री महोदया को और हमारे मंत्री महोदय को भी इसमें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे निवेश के मामले में भी बढ़ावा, काफी आंकड़े आये हैं, काफी कुछ हुआ है। निवेश, रोजगार और फिर हमारा एक तीसरा स्तम्भ है, सामाजिक न्याय और कल्याण। मतलब समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति का भी, अंत्योदय, कल्याण कैसे करें, इसकी सारी चिंता भी हमने बजट के समय की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा एक टैक्निकल पाइण्ट, हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने बजट में प्लान और नॉन प्लान के जो भी एक्सपेंसेज

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

हैं उनके वर्गीकरण को समाप्त किया। ईवन, सेण्ट्रल गवर्नमेंट में भी जाना है तो गये। लेकिन कहीं न कहीं एक अच्छा विजन प्रदेश को मिले, इसकी चिंता हमने की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की मूलभूत आवश्यकताएं और प्रदेश के समग्र विकास में सबसे महत्वूपर्ण सड़क वाला विषय जब आता है, आंकड़े आये हैं, मैं बहुत ही शोर्ट में कुछ विषय रख दूंगा। हमारी सरकार ने गत तीन वर्षों में सड़क के क्षेत्र में लगभग 20822 करोड़ रुपये व्यय कर 4281 गांव-ढाणियों को सड़क से जोड़ा। जबकि, गोविन्दसिंहजी, आपने क्या किया। गत सरकार ने तीन वर्षों में मात्र 9157, मतलब आधे से भी कम व्यय कर 661 गांव-ढाणियों को इन्होंने जोड़ा। गत सरकार के पांच वर्षों में 12544 किलोमीटर सड़कें बनीं, जो हमारे तीन वर्षों के लक्ष्य से भी बहुत कम हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण सड़क के तंत्र में हमने गौरव पथ का, अब गोविन्दसिंहजी, आप अगर मचलते होंगे, आपके मन में, ध्यान में यह विषय क्यों नहीं आया कि मेरे गांव की, वह ग्रामीण पंचायत भी एक सीमेण्टेड सड़क के साथ, शहर जैसा वातावरण, वैसी सड़क, और गोविन्दसिंहजी, कई सड़कें तो गौरव पथ के नाम से ऐसी बनी हैं कि सड़क पर खड़े रह जाओ तो अपने आप आपका चलने का मूड हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के लगभग 9894 गांवों में, पंचायतों में ऐसे अपने मिसिंग लिंक और गौरव पथ ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, चलने का ही होगा, चाटने का तो नहीं होगा ना कम से कम। यह भी बता दो, क्या-क्या मन होगा सड़क के ऊपर।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): ऐसा है, प्रतिपक्ष के बंधु, आपने तो जो-जो किया है ना, आपकी एक-एक बात पर, एक-एक योजना पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ है और उनका आज दिन तक आप जनता में जवाब नहीं दे पाये हो।

श्री उपाध्यक्ष: जैसे?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): जैसे कि इनका मुफ्त दवा वाला

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)
विषय चला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक बात पर आ सकते हैं इस पर, कोई दो राय नहीं है। आज मुफ्त दवा वाली योजना में इन्होंने, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): जैसे महिपाल मदेरणा।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक मिनट।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): जैसे महिपाल मदेरणा। उनका जवाब इनके पास नहीं है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): चलो, वह ठीक है।

लेकिन इन योजनाओं में, मतलब मुफ्त योजना हो, अब ये एल.ई.डी. खरीदने वाली बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहते हुए बड़ा दर्द महसूस होता है, इनके नेता के सम्बन्धियों की फैक्ट्रियों से ऐसी लाइट्स लाए कि क्या किया, भगवान जाने, करोड़ों रुपयों का चूना इस राजस्थान की जनता को लगा दिया। वह प्रश्न चिह्न नहीं तो क्या है। ऐसी कई और बातें हैं। उन बातों में जाएंगे तो फिर आप अपनी घण्टी बजा देंगे।

माननीय, वास्तव में अगर कांग्रेस राज के 50-60 वर्षों पर प्रश्न चिह्न ढूंढने जाएं तो आज दिन तक हम यह कहते हैं, मैंने कई बार पहले भी कहा है, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या पर प्रश्न चिह्न है, संजय गांधी की हत्या पर प्रश्न चिह्न है, ललित नारायण मिश्र की हत्या पर प्रश्न चिह्न है, इन्दिरा गांधी की हत्या पर प्रश्न चिह्न है। ये सारे प्रश्न चिह्न आप लोगों पर आते हैं। इनका जवाब आप जनता को अभी तक नहीं दे पाओगे। ...(व्यवधान)... मैंने प्रश्न चिह्न कहा है। मैंने कोई गलत नहीं कहा है। ...(व्यवधान)... लाल बहादुर शास्त्री, पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी, सब पर प्रश्न चिह्न है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन को जोड़ने वाले मामले में स्टेट हवाई सेवा योजना, इनके ध्यान में कभी क्यों नहीं आया। हमारे ध्यान में आया इण्टर स्टेट हवाई सेवा योजना से जोड़ने का काम, इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, आपका बिजनस भी बढ़ेगा। मतलब, ट्यूरिस्ट और बिजनस, दोनों पर, नहीं तो कभी कल्पना भी नहीं करते थे जैसलमेर, आज जैसलमेर क्या, पूरे उत्तर

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

भारत का पर्यटन खाली जैसलमेर और बीकानेर की तरफ आ सकता था। लेकिन हमने यह सेवा नहीं दी। हम इसको चालू करने जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पेयजल के मामले में, ...(व्यवधान)... मनोजजी, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो है ही, और आप दे रहे हो धन्यवाद। अच्छा है, हर सम्भाग पर, पेयजल योजना में लगभग हमने 01 लाख 21 हजार 648 गांव-ढाणियों में अब तक, 55 हजार गांव-ढाणियों को 2016 तक, मतलब 50 प्रतिशत तक हम चले हैं, और अब आने वाले समय में इसको भी हम पूरा कर देंगे। यह हमारा मानना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पेयजल वाली बात आती है, पेयजल मंत्री महोदय विराजे हैं, मेरा एक निवेदन है। नर्मदा वाला विषय, नर्मदा से जालौर जिले को पानी पिलाना था। 2007 में काम चालू हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने उसको ठण्डे बस्ते में डाल दिया। कोस्ट बढ़ गयी। अब आज की स्थिति में वह योजना अभी भी कहीं न कहीं कम्पनियों के झगड़े में, कई कम्पनियां ब्लेक लिस्टेड हो गयी हैं तो उसमें मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह बहुत जालौर जिले की एक मार्मिक योजना है, 739 गांवों को पानी पिलाने वाला विषय है, मेरे आहौर इलाके में, नर्मदा में एफ.आर., डी.आर. और ई.आर., तीन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आपको पानी देना है। उसमें ई.आर., रामसिंह तक पानी आएगा। उसके बाद में वागड़ से जुड़ा हुआ जो जालौर का और आहौर का हिस्सा है, उसमें लगभग 28 गांव ऐसे हैं, वह अभी तक रह रहे हैं। क्लस्टर योजना आपकी बनी नहीं है। तब तक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को भी मेरा एक निवेदन है कि इसके लिये छोटा सा कोई पैकेज आप अपनी तरफ से जरूर कराएं, जिससे ये छूटे हुए 28 गांव हैं, वे भी जुड़ जाएंगे। इस पूरी योजना को कहीं न कहीं हम एग्जस्टिंग प्लान से कैसे जोड़ सकते हैं, इसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ सिंचाई योजना, जालौर जिले की जो जवाई नदी है, उसमें जवाई बांध बन गया है, उस जवाई बांध को पुनर्भरण करने की योजना और दूसरा एक माही, कड़ाना डैम से जालौर को पानी देकर जालौर और बाड़मेर को बहुत हरा-भरा कर सकते हैं। इन बातों पर भी थोड़ा सा विचार होना चाहिये।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के मामले में बहुत कुछ सभी सदस्यों ने कह दिया है। लेकिन वास्तव में जैसा पूर्ववर्ती सरकार ने ऊर्जा का सिस्टम दिया, एकदम कोलेप्स होने जैसा सिस्टम, मैं मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सारे सिस्टम को उदय योजना के तहत लेकर इसको वापस धरातल पर लाने की कोशिश की है। अभी तक 5086 मेगावाट की वृद्धि हम कर पाये हैं, आगे और करेंगे। इसमें हम इनसे कही आगे हैं।

सबसे बड़ी बात है किसानों के हित में मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि कहीं कुएं में पानी सूख गया है, अगर कनेक्शन ट्रांसफर करना चाहता है, पहले पंचायत समिति लेवल पर था, वह एक जिले में अपन कर सकते हैं। यह भी मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

उसके साथ-साथ, एक विजन को सामने रखते हुए, क्योंकि अगर किसान समृद्ध होगा, किसान मजबूत होगा तो राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसलिये आने वाले समय में एक लाख कृषि कनेक्शन देने की जो घोषणा मुख्य मंत्री महोदय ने की है, उसके लिये भी मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत अच्छा मार्मिक विषय जब आता है, बीच में दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, मतलब, किसी के ध्यान में यह क्यों नहीं आया? हमने आज दिन तक लगभग दस हजार वरिष्ठ नागरिकों को 13 धार्मिक स्थानों पर यात्रा करवायी। यहां जयपुर के स्टेशन पर भोपालगढ़ के कोई तीर्थ यात्री आए हुए थे, आगे ट्रेन में जाना था। मैंने कहा कि भाई, कहां से? तो भोपालगढ़ से। मैंने कहा, क्या? तो कहते हैं कि साहब, यात्रा करवा रहे हैं, भला हो वसुन्धराजी का। भला हो आप लोगों का कि हमें यात्रा करवाई। मतलब, हमको यह बद्री-विशाल की यात्रा कैसे मिलती? हरिद्वार की यात्रा कैसे मिलती? ईवन उसमें पांच हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा भी हमने उपलब्ध करवाई है। यह बहुत बड़ा पुण्य का काम सरकार ने किया है।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यावरण वाला विषय है। इसमें बाड़मेर के उद्योगों में जो भी कास्टिक सोडा वगैरह लगने वाला है, उसके लिए हमने प्लांट में छह करोड़ रुपये लगाने की व्यवस्था की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज मेरे ध्यान में है, मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ पोर्टेबल ट्रीटमेंट प्लांट अभी आ रहे हैं तो कुछ ऐसी जगह जहां पर पाल्यूशन पानी का, जमीन खराब होती हो, वहां पर भी इसको उपयोग में लाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल आपका इशारा समझ कर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन सामाजिक उत्थान वाली जहां बात है, उसमें भी हमने विधवा पेंशन, निश्चित रूप से वसुन्धराजी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जिस प्रकार से विधवाओं के ऊपर मतलब, जिसका कोई नहीं है, उसका राज है, यह दर्शाया है उन्होंने। दूसरा, विशेष-योग्यजन के सम्मान में जो पेंशन योजना, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद की पात्र है। मुख्य मंत्री राजश्री योजना, के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद की पात्र है।

एक विषय है, जनजाति विकास की तरफ भी माननीया मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत ध्यान दिया है, सारी व्यवस्था की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनजाति मंत्री महोदय विराजे हैं। बस एक निवेदन है कि आहौर मतलब, जालौर जिला मीणा और भील जाति बहुल है। आहौर में लगभग 17 से 18 परसेंट मीणा और भील जाति हैं तो इसमें 50 प्रतिशत से जनसंख्या से अधिक जनसंख्या के जो विलेजेज हैं, जिसमें मीणा और भील है, मेरा एक निवेदन है कि उनको कहीं टाडा, माडा योजना में आप कराएं। आपने लिखा था लेकिन आपके विभाग ने गलत हमको इंफोर्मेशन दी है कि इसमें यह हमने 2011 की कलक्ट्रेट से बिलकुल ठप्पा बनवाकर, वह मैं पत्रावली आपको दे दूंगा, वह भी आप टाडा, माडा में कराएं और एक सबसे बड़ा काम, आज पाली, जालौर और सिरोही का मीणा बहुत दबा हुआ है। इस दबे हुए तबके को ऊंचा उठाने के लिए कहीं न कहीं शिक्षा जगत की जरूरत है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरे एरिये में 50 बीघा जमीन चिह्नित कर दी है एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए और जनजाति का जो केन्द्र सरकार का आवासीय विद्यालय जब भी अलॉट हो, आप हमें देने की कृपा करें।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

जमीन आपके आदेश से बिलकुल चिह्नित कर दी है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारे लिए होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एरिया की दो-तीन बातें हैं, फिर मैं मेरा विषय खतम करूंगा। माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि शिक्षा जगत में बड़ा जोरदार काम किया है इन्होंने जो एकीकरण वाला विषय लिया। मतलब, नहीं तो आज हम अध्यापकों की पूर्ति नहीं कर पाते थे। एक अच्छा निर्णय किया है उससे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन सुधरा है और बहुत अच्छी मोनिटरिंग हुई है, इससे हमें शिक्षा के स्तर पर बहुत बड़ा फायदा मिला है। दूसरा, 86 हजार शिक्षकों की जो पदोन्नति की है, इसके लिए भी शिक्षा विभाग बहुत-बहुत धन्यवाद का पात्र है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुरु गोबिन्द सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा में विकास कार्य के लिए इन्होंने सोचा है। हकीकत में गुरु गोबिन्द सिंहजी ने इस देश के लिए बहुत बड़ा त्याग, मतलब, जब वह पंक्तियां याद आती हैं कि गुरु गोबिन्द सिंह जी के दो बच्चे जिनको दीवारों में चुन दिया गया था। जोरावर जोर से बोला, फतहसिंह शोर से बोला, चुनो दीवार, रखो गारा, हत्यारे लेकिन भारत माता की जय हो, हिंद माता की जय हो, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की जय हो और जिंदा उनके बच्चे दीवारों में चुन लिये गये, लेकिन उन्होंने राज धर्म और देश धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे गुरु गोबिन्द सिंहजी के उपलक्ष्य में अगर कुछ किया जाता है और जितना करे उतना कम है।

अंत में मेरा निवेदन है कि आहौर में मुंसिफ कोर्ट, छोटा सा काम है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर एस.डी.एम. कोर्ट के पास में जगह है, बिल्डिंग, सब कुछ है और लगभग 1300 केस मेरे तीन थानों के ए.सी.जे.एम. फर्स्ट में जालौर में चलते हैं, वह ऐसा का ऐसा शिफ्ट अपने को करना है आहौर में। आहौर में यह ए.सी.जे.एम. कोर्ट अगर दे दिया जाता है तो मेरी आहौर की जनता आपकी बहुत-बहुत आभारी रहेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए तो मैं आभारी हूं। साथ में यह बजट अपने राजस्थान का एक मील का पत्थर और

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

विकास का एक बिलकुल पर्यायवाची रूप है और इसमें एक परिवार का रूप देकर, परिवार का जो विकास करना चाहिए उस तरह से उन्होंने बजट के मामले में सोचा है। मैं मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय, कोई विपक्ष में भी है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड पर बोल लेंगे। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्री भागीरथ जी चौधरी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो बजट पेश किया गया, उस वाद-विवाद में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम तो उत्तर-प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सभी भाइयों और

(श्री भागीरथ चौधरी)

बहनों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा। किसी शायर ने यह ठीक ही कहा है कि -

सलाम जीत के इस जज्बे को,

सलाम वर्षों बाद खतम हुए वनवास को,

सलाम देश के जुनून को,

सलाम इस एकजुट आवाज और प्रयास को,

सलाम विश्वास की इस जीत को।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार ने इस प्रदेश की कमान संभाली तब जीर्ण-शीर्ण अर्थव्यवस्था वाला यह बीमारू प्रदेश हमें मिला। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अभी इस बजट पर वाद-विवाद है, वह अपनी बात कहेंगे परंतु सच्चाई यह है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश बना दिया। हर दृष्टि से हमारे प्रदेश की अनदेखी की और उसी का परिणाम है कि जो जर्जर व्यवस्था इस प्रदेश की बनी, "उसको ठीक करने के लिए जहां कदम-कदम पर बिछे हुए थे तीखे-तीखे कंकर, कंटक, उष्ण पवन थी तृप्त धरा, कोई भी उपचार नहीं था पर साथी हम न दलेंगे तो कौन दलेगा?"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने इन तमाम बाधाओं के बावजूद आज इस प्रदेश को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। निश्चित ही राजस्थान राज्य का यह बजट वर्ष 2017-18 राज्य के विकास के नये आयाम बनाएगा।

'तुम्हारे पत्थरों में चोट की ताकत न होगी,

हमारे हौंसले जब तक रहेंगे आसमानी।।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि और पशुपालन की बात करूं। राज्य में पहली बार ग्लोबल राजस्थान एग्रीटैक मीट का आयोजन कर 58 हजार किसानों को पशुपालन और खेती की नवीन तकनीक की जानकारी दी गयी। ऐसा प्रयास पूर्व में कभी नहीं किया गया।

यह जो प्रतिपक्ष है, इन्होंने वर्षों तक इस देश और प्रदेश पर राज किया, परन्तु कभी भी इन्होंने किसान की भलाई की नहीं सोची। यदि हम आज

(श्री भागीरथ चौधरी)

याद करें, उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को, जिन्होंने 1999 में पहली दफा किसान क्रेडिट कार्ड की शुरूआत की और उसी का परिणाम है कि आज किसानों को मुआवजा इस प्रदेश में मिला है और इस देश में मिल रहा है। परन्तु इन्होंने कभी किसान की सुध नहीं ली।

केन्द्र और राज्य में इन्होंने वर्षों तक सत्ता संभाली, परन्तु इनकी यह सोच रही किसान, शोषित और गरीब रहे, अशिक्षित रहे, ताकि इनके चंगुल में वह फंसे रहे। परन्तु मुझे खुशी है कि चाहे केन्द्र में हो, चाहे राज्य में हो, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तब तब ही इस देश और प्रदेश का विकास हुआ है। चाहे किसान का हो, चाहे मजदूर का हो, हर वर्ग का विकास तभी हुआ है और इस देश का विकास भी तभी हुआ है।

आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने तीन सपने संजोये थे। पहला उनका सपना था कि हर गांव और ढाणी सड़क से जुड़नी चाहिये और उनका वह सपना पूरा हुआ। उनका दूसरा सपना था सर्वशिक्षा का, सबको शिक्षा मिले। वह सपना भी तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जी जोशी थे, उस समय शिक्षा का अलख जगा और उसी का परिणाम रहा कि हर गावं और ढाणी में शिक्षा की अलख जगी।

उनका तीसरा सपना था नदियों को जोड़ने का। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि इस प्रदेश में सबसे बड़ी विकास की जरूरत है तो वह नदियां जुड़ने की है। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी दुबारा प्रधान मंत्री नहीं बन सके और उनका वह सपना अधूरा रह गया। यदि हमारे देश की नदियां जुड़ जातीं तो सबसे बड़ा फायदा राजस्थान को होता। सबसे ज्यादा जमीन इस देश में हमारे राजस्थान में है और सबसे कम पानी राजस्थान में है। यदि नदियां जुड़ जातीं तो हर खेत को पानी मिल जाता, हर हाथ को काम मिल जाता, नौजवानों को रोजगार मिल जाता, बेरोजगारी खत्म हो जाती और गांवों में खुशहाली आ जाती। इसके साथ ही किसानों के घर में समृद्धि आ जाती, परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने किसानों के प्रति सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाये।

हमें खुशी है कि हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के लिये इस बजट में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं।

(श्री भागीरथ चौधरी)

मैं मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। आज किसानों की आर्थिक स्थिति दो चीजों पर निर्भर करती है एक तो खेती और दूसरा पशुधन। आज किसान पानी की कमी की वजह से बर्बाद हो रहा है। दूसरा पशु है, यदि हर पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय बनेगा तो इससे किसान को एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

सबसे बड़ी 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं 4 हजार पशुधन सहायकों के रिक्त पद भरने की घोषणा जो इस बजट में की है, यह अत्यन्त ही सराहनीय है।

किसानों को इस वर्ष एक लाख विद्युत कृषि कनेक्शन देने का इस बजट में जो प्रावधान किया है, यह बहुत ही अच्छा है, इससे बड़ी कोई सौगात मिल नहीं सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, 40 हजार कृषि कनेक्शन 2016-17 में दिये। एक लाख कनेक्शन का इस बजट में प्रावधान किया है। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि 2008 से लेकर 2013 तक आपकी सरकार रही। क्या किसी भी किसान ने आवेदन किया 2008 से लेकर 2013 तक? उस समय के आपके कार्यकाल में एक भी किसान को आपने यदि कृषि कनेक्शन दिया है तो आप बताइये। आपने किसान को बर्बाद किया है। आज यह सोच रहे हैं कि हम क्यों हार गये, कैसे हारे हैं? आपने काम तो कुछ किया ही नहीं, इस देश और प्रदेश को आपने तो बर्बाद ही किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज 83 लाख कृषकों की 102 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल जमीन का बीमा करवाया गया है। यह किसान के लिये बहुत बड़ी खुशी की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि फसली बीमा योजना के बारे में कभी कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं सोचा। जैसा मैंने बताया कि आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने किसानों के प्रति एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया, उसी का परिणाम है कि आज किसान के घर में थोड़ी बहुत राहत की, एक आशा की किरण बनी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामाजिक विकास की बात करूंगा। राज्य की भाजपा सरकार गरीब, मजदूर और आमजन की सरकार है। राज्य के बजट में कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान किया गया, जिसमें आने वाले समय में

(श्री भागीरथ चौधरी)

कोई अपने आपको असहाय न समझे, क्योंकि राज्य सरकार उनके उत्थान के लिये उनके साथ खड़ी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधवा पेंशन की बात करें। विधवा पेंशन को एक हजार व 1500 रुपये बढ़ाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदया को मैं साधुवाद देना चाहूंगा। सहयोग एवं उपहार योजना के तहत बी.पी.एल. कन्याओं के विवाह हेतु देय अनुदान राशि को दोगुना किया जाना निश्चित ही सामाजिक कल्याण की महत्वपूर्ण योजना है।

विशेष योग्यजनों की आयु को आधार न मानकर पेंशन 750 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा विशेष योग्यजनों के लिये अत्यन्त राहत का कदम है। वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार ने सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत विशेष योग्यजनों के विवाह हेतु देय आर्थिक सहायता को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार प्रति दम्पत्ति करने का एक सराहनीय कार्य किया है।

लावारिस एवं निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु पर दाह-संस्कार पुण्य का काम है। ऐसे व्यक्तियों का दाह-संस्कार कराने वाली संस्थाओं को 5 हजार रुपये की राशि की घोषणा की है। मानवता के कार्य करने वाली संस्थाओं के लिये प्रोत्साहन देना, यह भी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में एक सराहनीय कदम उठाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क की बात करूं। बड़े-बड़े महानगरों में, शहरों में हम ऐसी सड़क देखते थे। गौरव का हम एहसास करते थे कि ऐसी सड़कें महानगरों और बड़े-बड़े शहरों में हुआ करती थीं। परन्तु मैं इस सरकार को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को और परिवहन व सड़क मंत्रीजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी प्रदेश का आधारभूत ढांचा तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक आवागमन हेतु अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सड़कें नहीं होंगी। मुझे आज गर्व है कि हमारी सरकार ने मात्र तीन वर्ष की अवधि में ही पूर्ववर्ती सरकार से ढाई गुना ज्यादा राशि खर्च कर सड़कों का जाल प्रदेश में बिछाया है, जिसमें सात गुना अधिक गांव और ढाणियों को सड़कों से जोड़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव की सड़कें कभी भी गौरवपूर्ण हो सकती हैं। कहने-सुनने में कल तक अविश्वसनीय लगने वाली बात आज जमीनी

(श्री भागीरथ चौधरी)

हकीकत बन चुकी है। हमारी सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रदेश में 5,907 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण किया है जिससे गांवों में आज साफ-सुथरी गड्ढे रहित और नालियों सहित सड़क गांवों की शोभा बढ़ा रही है। सचमुच यह गांवों के लिये गौरव पथ बन चुके हैं।

राज्य के इस बजट में राजमार्गों को विकसित करने की श्रेणी में मेरे विधान सभा क्षेत्र से होती हुई रूपनगढ़ से नरैना वाया जूणदा होते हुए 33 किलोमीटर की सड़क मार्ग की घोषणा के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब ऊर्जा की बात करें। 2008 में जब बीजेपी की सरकार गयी थी, जब 15 हजार करोड़ का कर्जा था ऊर्जा विभाग पर, परन्तु जब 2013 में हमारी सरकार आयी तो इन्होंने 80 हजार करोड़ का कर्जा कर दिया। एक ही विभाग में इन्होंने इस प्रदेश का भट्टा बिठा दिया और 2011 में एम.ओ.यू. पर इन्होंने साइन किये कि हम हर वर्ष बिजली के दाम बढ़ाएंगे। आज यह गांव में कहते फिर रहे हैं कि बिल के दाम बढ़ गये। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसानों के बिजली के बढ़े हुए दामों को उन्होंने वापस लिया। वह मानती हैं कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई दु:खी वर्ग है तो वह किसान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान की कोई जाति नहीं होती है। गांव में रहने वाला हर व्यक्ति किसान है और जब तक किसान को हम हर तरह की सहूलियत नहीं देंगे तब तक इस देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। हमारी मुख्य मंत्रीजी को और मैं ऊर्जा मंत्रीजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा......

(19.00 बजे)

कि उन्होंने इस प्रदेश की जो खराब हालत थी, जर्जर स्थिति थी उससे राजस्थान को बचाया। राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था को तहस नहस करने में इस क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी किन्तु हमारी सरकार ने न-केवल इस घाटे से उबरने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किया अपितु राज्य को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में गत तीन वर्षों में 5 हजार

(श्री भागीरथ चौधरी)

86 मेगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि की। आज प्रदेश के नागरिकों को 22 से 24 घंटे घरेलू विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 1292 मेगावाट उत्पादन कर राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी और इस सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे हम ज्यादा नहीं बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, गैर-आबादी क्षेत्र में छितराई हुई ढाणियां हैं, आज वहां अंधेरा रहता है इस देश के 70 साल से आजाद होने के बाद भी, परन्तु मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी को और ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि छितराई हुई ढाणियों को कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना, निश्चित ही जो छोटी-छोटी आबादी की ढाणियां हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा की बात करूं। पूर्ववर्ती सरकार ने, इन्होंने आठवीं में भी बोर्ड को समाप्त कर दिया, जब किसी मकान की नींव ही कमजोर होगी तो हम क्या उम्मीद करें कि उसके ऊपर हम कुछ निर्माण कर सकते हैं। इन्होंने इस प्रदेश और इस देश के हमारे जो नौनिहाल हैं, जो हमारे इस देश के भविष्य हैं उनका भविष्य खराब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी परन्तु मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पांचवीं और आठवीं बोर्ड बनाने का फैसला लिया है। यह हमारी मुख्यमंत्रीजी की एक बहुत बड़ी सोच है। आज पंचायत एजुकेशन आफिसर बनाये गये हैं। यह हालत है।

पांच हजार नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता है देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक जब-जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, यह एक विद्यालय खोलते थे तो उसके लिए इनके नेता पूरे गांव वालों को बुलाते थे और उसमें भी यह कहते थे कि आधा पैसा जन सहयोग से दीजिए, तब जाकर यह स्कूल क्रमोन्नत करते थे परन्तु हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही झटके में पांच हजार स्कूल, सीनियर

(श्री भागीरथ चौधरी)

सेकण्डरी स्कूलों को इस प्रदेश में इन्होंने क्रमोन्नत किया है। यह इस प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह हालत है कि सरकारी विद्यालय में नामांकन बढ़ा है, परिणाम अच्छे आये हैं, सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता बढ़ी है। देश आजाद होने के बाद यह पहली दफा हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालयों के गठन के बाद इनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर की मांग हुई है जिसके लिए सरकार ने बजट में पर्याप्त प्रावधान किये हैं जिसके तहत 'रमसा' के अन्तर्गत 1334 कक्षा कक्षों का निर्माण कराया गया है एवं 58 नवीन विद्यालय भवन बनाये जायेंगे। इसके लिए 114 करोड़ 48 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए प्रदेश के निवासी इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंच निष्ठा, अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, आदरणीय पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए एवं ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए वरदान साबित हो रहे हैं।

आज ग्रामीण जनता कहीं जाती है, एस.डी.एम. मिल जाता है तहसीलदार नहीं मिलता है, गिरदावर नहीं मिलता, पटवारी नहीं मिलता है, कोई न कोई अधिकारी नहीं मिलता है, वो चक्कर काट कर फिर वापस चला जाता है परन्तु हमारी सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जन कल्याणकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर लगा कर आज लाखों प्रकरण वहीं निपट रहे हैं। हमें उन शिविरों में जाने का अवसर मिलता है, उपाध्यक्ष महोदय, इतना सराहनीय कार्य हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे शिविरों के आयोजन में सम्मिलित होते हुए मैंने अनुभव किया है कि राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। ग्रामीण कागजी

(श्री भागीरथ चौधरी)

कार्यवाही, ऑफिसों के चक्कर लगाने एवं जानकारी के अभाव में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे, इन शिविरों में प्रदेश के ग्रामीणों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। पेन्शन, श्रमिक कार्ड एवं राजस्व विभाग से सम्बन्धित कार्यों का हाथों हाथ निस्तारण करवाया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को ऐसे शिविर सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसे शिविरों के आयोजन से राज्य सरकार निश्चित ही सुराज की अवधारणा को साकार कर रही है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, आरोग्य राजस्थान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की योजनाएं इतनी कारगर सिद्ध हो रही है, सच्चे अर्थों में आज भा.ज.पा. की यह सरकार जन कल्याणकारी सरकार साबित हुई है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, चिकित्सा जैसी सेवाओं को राज्य सरकार ने गरीब और अमीर की बीच की दूरी को पाटते हुए सर्व सुलभ कराने का प्रयास भामाशाह स्वास्थ्य योजना से किया है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कला और संस्कृति के बारे में मैं बात करूं। यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया ने राजस्थान के गौरवशाली और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया।

श्री उपाध्यक्ष: आप सारे ही विभागों के बारे में बोलेंगे क्या?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, पांच मिनट, पांच मिनट।

इसी संदर्भ में मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्थित निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य श्रीजी महाराज की स्मृति में पेनोरमा के निर्माण की स्वीकृति इस बजट में की गयी है, जिसे निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री महोदया की हाल ही में जगदगुरु श्री निम्बार्काचार्य, श्री राधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ चाहिए?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हां।

श्री उपाध्यक्ष: तो आप वहां आ जाओ न सीधा।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर राजस्थान का यह बजट 2017-18 सुराज का बजट है जिसमें राजस्थान के प्रत्येक नागरिक और वर्ग के उत्थान, कल्याण की बात कही गयी है चाहे वो किसान हो, श्रमिक हो, उद्यमी हो, महिला हो या फिर युवा हो। यह बजट राज्य के मूलभूत ढांचे को विकसित करने वाला प्रगतिशील और भविष्य का बजट है जो आने वाली पीढ़ी को एक समृद्धशील राजस्थान के निर्माण की दिशा में सहायक सिद्ध होगा।

माननीय मुख्यमंत्रीजी की महत्वपूर्ण योजनाएं भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, अन्नपूर्णा भण्डार योजना, राजश्री योजना, न्याय आपके द्वार, ग्रामीण गौरव पथ, आदर्श विद्यालय, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ में हमारे इस प्रदेश को, अभी हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री को राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है।

अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में बजट में तहसील मुख्यालय, अराई में उप-कोष कार्यालय की स्थापना की घोषणा की। उपाध्यक्ष महोदय, 23 नवम्बर, 2013 को अराई में उपखण्ड कार्यालय खोलने, राजकीय महाविद्यालय खोलने, विद्युत विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय खोलने एवं अराई में औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना की घोषणा की गयी थी, मूर्त रूप प्रदान करा कर मुझे अनुगृहीत करायें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के बोराड़ा एवं हरमाड़ा में उप-तहसील कार्यालय की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक स्वीकृति प्रदान करावें ताकि आम जन को राजस्व कार्यों की समुचित व्यवस्था स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे गांवों में जो पेयजल की व्यवस्था है, 2006 में

(श्री भागीरथ चौधरी)

210 गांव, ढाणियों को फ्लोराइडयुक्त पानी से मुक्ति दिलाने हेतु 150 करोड़ रुपये की लागत से माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने इन गांवों में सुलभ और सुचारु आपूर्ति बीसलपुर योजना तहत स्वीकृत करायी थी किन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस पाइप लाइन का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं कराया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन आपको बड़े आदर से निवेदन कर रहा है कि अब आप कृपया कर के विराज जाएं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आधा मिनट।

विनम्र अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बरोल, डिगारिया, सोयला, गूजरवाड़ा, सरवर, बंथली, खरवड, बहेड़ा, बोराड़ा, रिंगनोर, कालानाड़ा, भोगाति, सान्दोलिया, ढ़सक, सिरोंज, आकोडिया, टिकावड़ा बरना, काढ़ा, डीडवाड़ा और नलू में पेयजल योजना प्रस्तावों को स्वीकृत कराएं। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: गला बैठ गया।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अधिक समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंह जी। आप भी बता दो कितने समय तक के लिए बोलेंगे? आसन आपको बीच में टोकना नहीं चाहता।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैं तो बिलकुल अनुशासन में रहता हूं, आप जैसे आदेश देओगे मैं तुरन्त बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: चलिये आप दस से पन्द्रह मिनट में अपनी बात फरमाओ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2017-18 के बजट पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया वसुन्धरा जी के द्वारा 8 मार्च को राजस्थान के कल्याण के लिए बजट पेश किया गया है, मैं उसकी तह दिल से प्रशंसा करता हूं। जो बजट पेश किया

(श्री शंकर सिंह)
गया है वह किसी एक जाति के लिए नहीं, 36 जातियों के उत्थान करने के लिए किया गया है। सबका भला कैसे हो, उसके अनुरूप यह बजट बनाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्षी माननीय सदस्यों के कई बार यह गले नहीं उतर पाता है। मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह बजट गरीबी मिटाने के लिए पेश किया गया है। आपके कार्यकाल में जो बजट पेश होता था वह गरीबों को मिटाने के लिए होता था। राजस्थान के कल्याण के लिए एक-एक योजना लाई गयी है। आप कोई एक योजना बताओ जो कि आपके गले नहीं उतर रही हो। आपके टाइम में यह बजट कहां जा रहा था? आपने राजस्थान का बजट इस जयपुर शहर में एक जगह लगाया, मैट्रो के अंदर। इस मैट्रो की 10 वर्ष तक भी अभी आवश्यकता नहीं थी। इस जगह पर बजट को लगाकर के खाली नाम करने की कोशिश की गयी। लेकिन राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है। राजस्थान में विकास की देवी आदरणीय वसुन्धरा जी ने, आप भी मान लो, हम तो पूजा करते हैं, आप भी सीख लो, कि अगर राजस्थान का कल्याण कोई करेगी तो वसुन्धरा जी की सरकार ही करेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से वर्ष 2013-14 में विद्युत वितरण निगम का जो घाटा 15,645 करोड़ तक पहुंच गया था, उसको सुधार करके हमारी सरकार ने 62,421 करोड़ 96 लाख रुपये का कर्ज राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करना, बहुत बड़ा यह उदाहरण पेश किया है। मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया को देता हूं। उन्होंने एक ही झटके में आने वाले 2 वर्षों के लिए 1 लाख कृषि कनेक्शनों की घोषणा की है, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। उनसे इस योजना में मेरा निवेदन है कि काश्तकारों को बूंद-बूंद योजना, फव्वारा एवं डिग्गी योजना में सिंगल फेस कनेक्शन देना आप सुनिश्चित करें।

उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल के अंदर, प्रदेश में 1,21,648 गांव और ढाणियों में से 55,025 गांव और ढाणियों को मार्च, 2016 तक पानी पिलाने की व्यवस्था कर दी गयी थी। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की परियोजनाओं पर पूर्व की सरकार के द्वारा प्रथम 3 वर्ष में 6,097 करोड़ रुपये खर्च किए

(श्री शंकर सिंह)
गयी। हमारी सरकार के आने के बाद 13,473 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकार में और हमारी सरकार में यह अंतर है।

माननीय जलदाय मंत्री महोदय, आपने जवाजा के लिए 199 करोड़ की योजना स्वीकृत कर रखी है, उस संबंध में निवेदन है कि अभी एक ही फर्म को वह टेंडर नहीं दिया जाए। पूर्ववर्ती सरकार ने भी एक ही फर्म को, दिल्ली की फर्म को टेंडर दिया था। उसकी वजह से यह कार्य अभी तक 3 सालों में भी पूरा नहीं हो पाया, जबकि 31 मार्च, 2016 को यह कार्य पूरा हो जाना था। अभी आप उसको 4 भागों में बांटकर के, 4 अलग-अलग ठेकेदारों को योजना में टेंडर निकालकर के देने चाहिंए ताकि दिसम्बर, 2017 तक यह कार्य पूरा हो सके। जिससे कि कार्य समय पर पूरा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा में जो सुधार किया गया है, उसके लिए हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया की जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है। पहली से आठवीं तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से पास करने की योजना पर विराम लगाते हुए, हमारी मुख्यमंत्री जी ने अच्छी योजना लागू की है। शिक्षा के अंदर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इतनी स्कूलें एक साथ, प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीनियर माध्यमिक विद्यालय खोले हैं। उसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में कहीं पर भी इन्होंने भेदभाव नहीं किया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हर ग्राम पंचायत पर सीनियर माध्यमिक विद्यालय खोला है। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय ब्यावर खास, ग्राम पंचायत ब्यावर खास और दूसरा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय धधालिया, ग्राम पंचायत मालातों की बेर, यह 2 विद्यालय ऐसे बचे हुए हैं, जिनके ऊपर सीनियर विद्यालय नहीं हैं। इनमें भी सीनियर विद्यालय खोले जाएं। ब्यावर शहर में एक महिला कालेज की आवश्यकता है, इसलिए महिला कालेज भी खोला जाए।

माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में नरेगा योजना प्रथम बार शुरू हुई थी। हमारी सरकार का काम उनको पचा नहीं। 2008 के अंदर जो नरेगा योजना शुरू हुई थी, उसमें तत्कालीन ग्राम पंचायतों में जो हमारी 5-6 ग्राम

(श्री शंकर सिंह)

पंचायतें हैं, पंचायत समिति जवाजा की ग्राम पंचायत बनजारी, आसन, बियानखेड़ा, बामनहेड़ा, बराथन, तारागढ़, लोटियाना और सूरजपुरा, इन ग्राम पंचायतों के नरेगा के 2009-10 के काम की पूर्ववर्ती सरकार ने 4-4 बार जांचें करवा दी। उसके बाद श्रमिकों का भुगतान हो गया। लेकिन उसमें मेट, बजरी, पत्थर, सीमेंट और कारीगरों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस समय जो टेंडर निकाले गए थे, उसमें टिन नंबर नहीं होने की वजह से उन पर आब्जेक्शन लगा था, उनकी अब जांचें भी हो चुकी हैं। उस समय पहली बार नरेगा योजना चालू हुई थी। उन सरपंचों को उस समय इतनी जानकारी नहीं थी कि टिन नंबर होना अति आवश्यक है। पहली बार ऐसा हुआ था। उस पर विचार करके उनका भुगतान किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, नरेगा के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं, उनमें भी मैं एक सुधार की आवश्यकता बता रहा हूं कि राजस्थान सरकार का जो हमारा बजट है, वह 2/3 बजट काश्तकारों के खेत पर खर्च होना चाहिए। नरेगा में काश्तकारों द्वारा अपने खेत पर तारबंदी लगाना, चारदीवारी बनाना, जल का टांका बनाना, यह सरपंचों के स्थान पर प्रत्येक काश्तकार को कार्य दिए जाने चाहिए। ग्राम पंचायतों के मार्फत होने से इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इससे बजट खर्च होने में भी कमी आ रही है। इसमें कुछ छूट देकर के प्रत्येक ग्राम पंचायत में काश्तकारों को देने का कार्य शुरू करोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बजट भी ज्यादा खर्च होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकारों को अगर परेशानी है तो अंग्रेजी बबूल से है। काश्तकारों को खेती करते समय इससे बहुत परेशानी है। अंग्रेजी बबूल की जड़ों से फसल नहीं हो पाती है। अगर यह खेत के पास है तो फसल पैदा नहीं हो सकती। उस खेत में अगर कुआ है तो उनकी जड़ें इतनी गहरी होती है कि वह अपने आप पानी खींच लेती हैं। इससे कुओं का जल स्तर भी नीचे गिरता है। उसकी छाया में भी कोई फसल पैदा नहीं हो सकती है। ग्राम पंचायतों को नरेगा योजना में ऐसे अधिकार दे दिए जाएं कि ग्राम पंचायतें अंग्रेजी बबूल रहित हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे हमारी सरकार ने इस बजट में

(श्री शंकर सिंह)

कल्याणकारी योजनाओं का जो कार्य किया है उसमें मैं आपके माध्यम से एक और सुधार का निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर आपने सबका उत्थान किया है लेकिन गौमाता थोड़ी परेशान ज्यादा है, गौमाता के उत्थान के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक गौशाला खोलने के लिए नरेगा योजना के तहत ऐसी कोई योजना बनाकर अगर सुधार हो जाता है तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया को पूरे राजस्थान की जनता और गौमाता की तरफ से बड़ा आशीर्वाद मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा राजस्थान में 6 हजार 657 करोड़ 32 लाख का बजट इस आने वाले वर्ष में खर्च किया जाएगा, 2017-18 के लिए वह गत बजट से 58.47 प्रतिशत अधिक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर शहर के लिए एक सिक्स लेन सड़क का एस्टीमेट माननीय मंत्री महोदय के पास में पहुंच चुका है। इस सम्बन्ध में भी निवेदन है कि वहां पर यह सड़क बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। यह पूरे क्षेत्र की और शहर की मांग भी है। ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार जस्सा खेड़ा से दुधारेश्वर तक जो सड़क तीस किलोमीटर की है, माननीय मंत्रीजी ने उसमें सात मीटर से चौदह मीटर की चौड़ाईकरण के लिए स्वीकृति दी है, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस कार्य को लिया है लेकिन स्वीकृति अभी डिपार्टमेंट से जारी नहीं हुई है। आप उसमें जरूर आगे बढ़ाने के लिए और जल्दी उसको पूरा करने के लिए योजना बनाएंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट और।

मैं तो स्पीड में बोल रहा हूं, जिस प्रकार कई धीरे-धीरे बोलते हैं उस तरह नहीं बोल रहा।

श्री उपाध्यक्ष: आप दो-तीन मिनट और ले लो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग जितने भी छेड़ने का काम करते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान

(श्री शंकर सिंह)

की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने जो सुराज संकल्प यात्रा में जो अभी योजना बनाई है वह लिस्ट पूरी लाइन पर लगी हुई है और वह पूरी की पूरी करेंगे, सब काम पूरे होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से और याद दिलाना चाहता हूं कि सुराज संकल्प यात्रा में ब्यावर को जिला बनाने के लिए भी एक घोषणा हो रखी है, उस सम्बन्ध में भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान)... निवेदन करना चाहता हूं कि उसको भी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया कल बजट की रिप्लाई देगी तो सुराज संकल्प यात्रा का जो अधूरा सपना है वह कल पूरा करेंगी।

जिस प्रकार अभी विपक्ष के भाई बता रहे थे, आप तसल्ली रखें, आपके समय में देश के प्रधान मंत्री थे वह वहां से घोषणा करते थे और यहां राजस्थान में आकर पूछा था आम जनता से कि हम एक रुपया भेजते हैं और यहां कितना पैसा पहुंचता है, 15 पैसा तो यह 85 पैसा कहां जा रहा है? यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, आप राजस्थान की मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धराजी को धन्यवाद दो कि उन्होंने 85 पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, आज एक रुपया भेज रहे हैं और एक का एक रुपया पूरा वहां पहुंच रहा है।

राजस्थान के हमारे सभी मंत्री महोदय, उनके मंत्रिमंडल में ऐसा कोई भ्रष्ट मंत्री नहीं है जैसे आपकी सरकार में थे, ऐसा आज तक कहीं है नहीं, ऐसा उदाहरण उन्होंने पेश किया है, मैं इस बात के लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

अभी आप नतीजे तो सब देख ही रहे हो, जो बेटा अपने बाप का नहीं हो सकता है, जो बेटा अपनी मां का नहीं हो सकता है, उसको जनता पूरी समझ चुकी है, अब वह किसी के नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप धैर्य और तसल्ली रखिए, अभी तो आप एक मिनी बस में बैठकर आ रहे हैं, ध्यान रखना अगर जनता से दूरी बना ली और इस विकास पर अगर चुनाव हो गया तो आपको कोई ऑटो ही पकड़ना पड़ेगा। इसलिए इस देश की पूरी जनता आपकी बातों को समझ चुकी है। दोस्तों, फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर कोई भी गाड़ी चलाता है उसको पुलिस वाला तुरंत पकड़ कर उसका चालान

(श्री शंकर सिंह)
बना देता है, यह तो पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम होता है लेकिन आप लोगों ने, विपक्ष के भाइयों ने इस पूरे देश की जनता की आंखों में आपने धूल झोंकी है। आपने फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर पूरे देश की आंखों में धूल झोंक दी है। +++

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, नाम नहीं लेंगे। नाम नहीं लेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि जब अगर +++

श्री उपाध्यक्ष: फिर आपने नाम लिया।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): +++ ये कौन थे? इसलिए आपको हिन्दुस्तान की जनता ने.. ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, फिर आप वही बात कहते जा रहे हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): हिन्दुस्तान की जनता आपको जान चुकी है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य छींटाकशी कर रहे हैं, मजमा लगा रखा है क्या? ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप सब विराज जाओ, सम्माननीय सदस्य आप भी विराज जाओ।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): शंकरसिंहजी, यह अख़बार में नहीं छपेगा। ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। जय हिन्द, जय-जय राजस्थान।

श्री उपाध्यक्ष: गत वक्तव्य के अंदर जो सम्माननीय सदस्य बोल रहे थे, जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके नाम लिए गये, वह भी अपलिखित करें और उनके ऊपर जो भी अभिव्यक्ति की गयी, वह भी अपलिखित करें।

श्री जगसीरामजी।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-18 का बजट हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, गांव, ग्रामीण और गरीब आदमी को समर्पण किया गया है। प्रदेश के महिला वर्ग को आर्थिक रूप से और अधिक स्वावलम्बी बनाने का जो प्रयास किया गया है इस अवसर पर मैं प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बजट में शिक्षा को मुख्य एजेंडे के तौर पर शामिल किया गया है, यह आने वाले समय के अंदर एक सराहनीय कदम साबित होगा। प्रदेश को नवाचारों के साथ विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में लाने का प्रयास हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है, कला संकाय वाले स्कूलों में साइंस स्ट्रीम शुरू होने से विज्ञान के स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, कई कालेजों में नए सब्जेक्ट शामिल किए जाने से छात्राओं को स्थानीय स्तर पर पढ़ाई के बेहतर मौके मिलेंगे उसके लिए मैं इस अवसर पर हमारी प्रदेश की मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट में कई घोषणाएं की गयी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया गया है, यह इस बजट की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा छात्राओं तक एजुकेशन के फायदे पहुंचाएगी वहीं कैरियल काउंसलिंग और स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम से बेनीफिट दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की बेटियों को आर्थिक सहायता और शिक्षा के लिए पांच हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देना फायदेमंद होगा। कन्या के विवाह पर देय अनुदान राशि और प्रोत्साहन राशि को दो गुना करने की घोषणा सीधे तौर पर हमारी प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी का एक सीधा सराहनीय कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को ऋण, ब्याज पर अनुदान, गांवों, कस्बों में बहुत सी सैकंडरी स्कूलों को हायर सैकंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत करना, कई जगह नए कॉलेज और छात्रावास आदि अनेक प्रावधान सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाले कदम उठाए गये हैं।

मैं इस अवसर पर प्रदेश की मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा स्टाम्प ड्यूटी की रेट को कम करने वाला प्रावधान लाये हैं यह आम जनता

(श्री जगसी राम)

के लिए सही साबित हो रहा है। इसे मुख्यमंत्रीजी का तीन साल का सफल कार्यक्रम माना जा रहा है।

सड़कों के रखरखाव पर इस बार माननीय मुख्यमंत्रीजी ने ज्यादा जोर देकर विशेष प्रावधान किये हैं। ग्रामीण गौरव पथ, शहरी गौरव पथ, मिसिंग लिंक, किसान पथ ही नहीं, उसमें क्वालिटी मैंटेन करने के लिए जो प्रावधान किये हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी व पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

यही नहीं छात्रावास में स्टूडेंट्स को स्कूल जाने के लिए साइकिल देने का काम किया है, हर स्कूल में जो साइकिल वितरित की गयी है उसमें गरीब तबके के बालकों को सीधा-सीधा फायदा मिल रहा है। एक लाख नये कृषि कनेक्शन देने की घोषणा करने से किसानों को विशेष राहत मिलेगी। कृषि प्रधान प्रदेश के लिए यह एक सराहनीय कदम है। ग्रामीण इस घोषणा से झूम उठेंगे।

मेरा विधान सभा क्षेत्र रेवदर है उसमें आबूरोड का पूरा टीएसपी क्षेत्र है, उसमें 1 जनवरी, 2017 तक के सारे डिमाण्ड नोटिस एकमुश्त जारी कर दिये हैं ताकि उस टीएसपी एरिया में आदिवासी व आम लोगों को कृषि कनेक्शन से फायदा मिलेगा। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी और मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ गांवों में महिलाएं जो दुग्ध समितियों का संचालन करती हैं उनको प्रोत्साहन करने की योजना सराहनीय है। इस योजना के अंतर्गत एक हजार दुग्ध उत्पादन केन्द्र बनाये जाने की घोषणा की है इससे आने वाले समय में महिलाओं के अंदर एक जागृति पैदा होगी और पूरे प्रदेश में सराहनीय कदम माना जाएगा।

मुख्यमंत्री राजश्री, पशुपालन व मत्स्य के लिए 822 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है यह पूरे प्रदेश के लिए फायदेमंद रहेगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में जनवरी, 2016 से जनवरी, 2017 तक जन्मी 3.57 लाख बालिकाओं के अभिभावकों को 89.25 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, इस योजना का विस्तार किया जाना बेहद सराहनीय कदम है। इस अवसर पर प्रदेश की मुख्यमंत्रीजी का मैं तहेदिल से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं।

(श्री जगसी राम)

प्रदेश में 2039 गांव पेयजल योजना से लाभान्वित होंगे। ग्रामीण व शहरी योजना के लिए मुख्यमंत्रीजी व पेयजल मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने प्रदेश के 70 प्रतिशत जिलों की पेयजल समस्या को देखते हुए इस बजट में पेयजल योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है।

बजट में रोजगार का ध्यान रखते हुए उन्हें दी जाने वाली मदद में पहले मिलने वाले भत्ते 500 रुपये को बढ़ाकर 650 रुपया प्रतिमाह किया गया है। इस अवसर पर 60 वर्ष से ज्यादा आयु की माता-बहनों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर एक हजार रुपया किया है, यह बहुत सराहनीय कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से मेरे सिरोही जिले व रेवदर विधान सभा क्षेत्र के लिए कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, भामाशाह योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में हमारे रेवदर विधान सभा क्षेत्र में एमआई टैंकों के माध्यम से किसानों को पानी के स्टोरेज करने के लिए जो कदम उठाया है यह सराहनीय है। आने वाले समय में पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा और किसानों में खुशहाली होगी।

पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, आर.ओ. प्लांट है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर फ्लोराइड से वहां की जनता त्रस्त हो रही थी, तकलीफ पा रही थी, आर.ओ. के माध्यम से फायदा मिल रहा है, वहां की जनता को सीधा-सीधा फायदा मिल रहा है। सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम रखा था इसके लिए मुख्यमंत्रीजी और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत सराहनीय कदम उठाया था। आबूरोड क्षेत्र, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर चिकित्सा में 3 करोड़ की लागत से एक बड़ा होस्पिटल बनकर तैयार हो गया है उसके लिए मैं मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय राठौड़ साहब के हाथों से उसका शिलान्यास किया गया है, 70 परसेंट वह पूर्ण हो गया है, कम समय में इसका उद्घाटन किया जाएगा।

परिवहन क्षेत्र में हमारे सिरोही जिले के नई बसें आयी हैं, 27 बसें सिरोही जिले में सुचारू की है, जनता के लिए बहुत सराहनीय कदम है।

(श्री जगसी राम)

आबूरोड शहर व ग्रामीण क्षेत्र के लिए भैसासिंह परियोजना सिंचाई के लिए थी, लेकिन हमारी मुख्यमंत्रीजी की सिरोही जिले की विजिट थी उस समय क्षेत्र की जनता की मांग पर पूरे आबूरोड शहर व आबूरोड से लगते ग्रामीण क्षेत्र के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए मैं मुख्यमंत्रीजी व मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। इससे वहां की जनता को राहत मिलेगी।

शिक्षा के अंदर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, पूरे राजस्थान में, विशेष तौर पर सिरोही जिले में तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के देरोल में बहुत बड़ी अच्छी स्कूल है। उसके लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कभी विजिट करो। यह प्राइवेट स्कूल की तुलना में बहुत अच्छा स्कूल है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुख्यमंत्रीजी का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिरोही जिले के लिए इसी 2017-18 के बजट में आबूरोड से अम्बाजी की घोषणा की है, हमारे माननीय राठौड़ साहब सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री हैं, हम हमेशा इनको कहते रहते थे अम्बाजी की धार्मिक सड़क है, वहां कई पर्यटक व दर्शनार्थी आते थे, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने इस 14 किलोमीटर सड़क को इस बजट में लिया है। मैं जनता की ओर से, मेरी ओर से मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरी सड़क इसी तरह से है, सांचोर-रानीवाड़ा-रेवदर-आबूरोड 26 किलोमीटर सड़क को इसी बजट में लिया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में एक निवेदन करना चाहूंगा रेवदर रोड तो सैंक्शन हुई है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसमें रेवदर बाइपास को भी सम्मिलित किया जाए ताकि आये दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा।

हमारे यहां जल संसाधन में सिरोही लघु सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार की घोषणा इस बजट में की है उसके लिए सीएम साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

जनजाति विकास, आबूरोड-सिरोही ब्लॉक खेल छात्रावास की क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 छात्र की है उसके लिए मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में सिरोही के उच्च माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान संकाय की घोषणा इसी बजट के अंदर की है उसके लिए मैं सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री जगसी राम)

राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड (सिरोही) में स्नातकोत्तर में अर्थशास्त्र विषय खोलने की घोषणा की है उसके लिए मैं मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर में उपखण्ड स्तर का कार्यालय है, 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में एक भी महाविद्यालय नहीं है रेवदर उपखण्ड स्तर पर। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट के अंदर आप उसकी घोषणा करें ताकि हमारे रेवदर क्षेत्र की जनता को राहत मिले। मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रतनलाल जी जलधारी।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री सम्माननीय वसुंधरा राजे जी ने वर्ष 2017-18 का बजट इस पवित्र सदन में प्रस्तुत कर राज्य की जनता को जो सौगातें दी हैं, मैं उनका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बजट में किये गये प्रावधानों से प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा और खुशहाल राजस्थान बनेगा।

इस बजट में जीएसटी के लिए कॉल सेंटर्स और हैल्प डेस्क की जो बात कही गयी है उससे उद्योग और व्यापार जगत को उनकी समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलेगी। पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करने पर भू-रूपान्तरण में छूट देकर उद्योग एवं रोजगार बढ़ाने का कार्य किया गया है, जो सराहनीय है। इसी प्रकार औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स आधारित इंसेंटिव दिये गये हैं।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना में झुंझुनूं जिले को सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार राज्य सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ और ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य का सम्मान मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।

इतनी उपलब्धियों और जन-कल्याणकारी फैसलों के उपरांत भी हमारे प्रतिपक्ष के साथी बजट की सराहना न कर आलोचना-प्रत्यालोचना करने में

(श्री रतन लाल जलधारी)

कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं इस सदन के माध्यम से मेरे प्रतिपक्ष के भाइयों को इतना ही कहना चाहूंगा:-

सभी को रोका जाता है, सभी को टोका जाता है

सभी की राहें मंजिलों पर कांटों को फेंका जाता है,

रुकते कुछ, ठहरते कुछ, कुछ तो लौट आते हैं,

बनाकर राहें जो चले, वो ही मंजिल को पाते हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र और सीकर जिले की बात करूं तो सीकर से हर्ष पर्वत के लिए 15 किलोमीटर सड़क की घोषणा की गयी है। सीकर-झुंझुनूं-लुहारू की 92 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना, दौलतपुरा से लोसल तक की 23 किलोमीटर सड़क, तिड़ोकी बड़ी से पाटोदा की 16 किलोमीटर सड़क और अजीतगढ़-चला 33 किलोमीटर सड़क के साथ ही नागौर-लक्ष्मणगढ़-मुकन्दगढ़ राज्य राजमार्ग निर्माण करने की घोषणा से जिले में सड़क सुविधा आम जनता को उपलब्ध होगी। इसी तरह तारानगर-सीकर-खेतड़ी की पेयजल परियोजना के लिए बजट प्रावधान कर सरकार ने क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने का बेहतरीन काम किया है जिसके लिए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र एवं सीकर जिले की जनता की ओर से आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विभिन्न करों में जो छूट दी गई है उससे निश्चित ही प्रदेश और प्रदेशवासियों का भला होने वाला है।

इस बजट में प्रदेश के ढाई हजार गांव और ढाणियों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है और प्रदेश में पहली बार पांच हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाने की बात कही गयी है। तिरूपति बालाजी और बद्रीनाथ में सरकार की ओर से धर्मशालाओं की व्यवस्था करवाने से भी आम जनता को बहुत बड़ी कठिनाई से राहत मिलेगी।

खनन कार्यों में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए इस बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान कर गरीब तबके के लोगों को राहत देने का काम हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने किया है।

(श्री रतन लाल जलधारी)

इसी के साथ में इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार और माननीय मुख्य मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूं कि सीकर में लम्बित मिनी सचिवालय के भवन निर्माण की मांग को पूरा किया जाए। सीकर में रामपुरा व कंवरपुरा बाइपास की सड़क के लिए कई बार अधिकारियों को कहा गया, परन्तु वह पैंडिंग है। इसके अलावा जयपुर रोड से बीकानेर रोड तक रिंग रोड का कुछ हिस्सा फोरलेन होने से वंचित है जिसके लिए मैंने विशेष उल्लेख प्रस्ताव भी इस सदन में प्रस्तुत किया है। वह लगभग 12 किलोमीटर का टुकड़ा यदि जोड़ दिया जाता है तो बीकानेर-जयपुर के बीच चलने वाले वाहनों को सुविधा होगी। इसी तरह सीकर शहर में नवलगढ़ पुलिया की चौड़ाई बढ़ाकर उस क्षेत्र में रह रहे बाशिंदों को राहत दिया जाना जरूरी है, इसके लिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं। राज्य में प्रोबेशन पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का फिक्स वेतन तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा सहयोगिनी का मानदेय बढ़ाया जाकर हम उन्हें राहत दे सकते हैं।

शेखावाटी की सबसे बड़ी मांग सीकर, झुंझुनूं, चूरू को मिलाकर सीकर को संभाग बना दिया जाए तो शेखावाटी के लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए जयपुर नहीं जाना पड़े। यदि सीकर संभाग बनता है तो शेखावाटी के लोगों को काफी राहत मिल सकेगी।

एक प्रमुख समस्या सीकर के कल्याण अस्पताल में है। एम.आर.आई. मशीन के अभाव में पूरे जिले एवं आस-पास के जिलों के मरीजों को भारी दिक्कत रोज हो रही है। प्राइवेट लोग मनमर्जी के दाम वसूल करते हैं, अत: सीकर के कल्याण अस्पताल में एम.आर.आई. मशीन तुरन्त स्थापित की जानी जनता की मांग है, इसके लिए मैं इस विधान सभा से निवेदन करता हूं।

इसी प्रकार छात्रों की सुविधा के लिए पं. दीनदयाल महाविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए बजट एवं कला महाविद्यालय, कटराथल के अन्य कमरों को बढ़ाने का बजट देकर जो आपने सीकर के छात्रों को सौगात दी है इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा छात्रों और अभिभावकों को सुविधा हो इसके लिए मांग करता हूं कि सीकर में वर्तमान में संचालित कन्या महाविद्यालय को कल्याण कालेज के

(श्री रतन लाल जलधारी)

भवन में शिफ्ट किया जाए एवं कल्याण कालेज में संचालित विज्ञान संकाय को ग्राम सबलपुरा में निर्मित नये महाविद्यालय भवन में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। उच्च शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे इस आग्रह को स्वीकार कर सीकर शहर एवं जिले की जनता को राहत देने का काम किया जाए। मैं इस बजट की भूरि-भूमि प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुंधराजी ने वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया वो गरीब, मजदूर, युवा, किसान, बेरोजगार, महिला, सबको केन्द्रित करते हुए, सबके उत्थान के लिए, सबके विकास के लिए बजट बनाया है। आज विकास की बात सामने दिख रही है कि हिन्दुस्तान की बहुत सारी योजनाओं का राजस्थान को पुरस्कार मिल रहा है, प्रथम स्थान पर आ रहा है तो यह हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी और उनकी टीम राजस्थान की गुड गवर्नेंस की वजह से ही इतने इनाम मिल रहे हैं और राजस्थान आगे जा रहा है। सबको पता है कि

(श्री अशोक डोगरा)

विरासत में जो आर्थिक स्थिति मिली थी वो कैसी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी। अकेली बिजली कम्पनियों पर ही 77 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्जा था। हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी ने और उनकी पूरी टीम ने एक-एक विभाग की पूरी समीक्षा की, उसमें सुधार किया तब जाकर के इन तीन सालों में राजस्थान विकास की तरफ बहुत आगे बढ़ गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी जरूरत की चीजें थीं उन सबकी समीक्षा की। आंकड़े तो मेरे से पहले बहुत सारे सदस्यों ने दे दिये तो आंकड़े देने से फायदा नहीं है लेकिन सड़क, पेयजल, ऐसी दूसरी चीजों में जो पिछली सरकार ने 5 साल में भी जितना पैसा खर्च नहीं किया, जितना विकास नहीं किया, हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में तीन साल में उससे ज्यादा विकास हो गया। कई डिपार्टमेंट में तो उससे डबल खर्च हो गया।

विधवाओं की पेंशन की जहां तक बात थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इनकी पीड़ा को समझा और उसको 1 हजार और 1500 रुपये किया। किसानों की बिजली की बात थी तो 1 लाख 27 हजार कनेक्शन पहले दे चुके और दो साल में एक लाख और कृषि कनेक्शन देने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है।

स्वस्थ धरा एवं खेत हरा, इस विजन के साथ 29 लाख सोइल हैल्थ कार्ड बनवाये गये और जैसा मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि सोइल हैल्थ कार्ड में दर्शाई गयी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए एक लाख किसानों को किट वितरित किये जाएंगे।

दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा में दस हजार वरिष्ठ नागरिकों को 13 धार्मिक स्थलों की यात्रा करायी गयी और इस बार 20 हजार का टार्गेट है जिसमें 5 हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा करायी जाएगी। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं और योजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो फ्लैगशिप योजनाएं बनीं वो इतनी ज्यादा हैं कि उन सबका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है लेकिन जैसे भामाशाह योजना है वह पुरानी कांग्रेस के राज से पहले भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको चलाने का प्रयास किया था लेकिन राज बदलते ही कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको बन्द कर दिया।.....

(श्री अशोक डोगरा)

उससे इतने परिवार जुड़ गये और उनको लाभ भी हुआ। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, गरीब आदमी 30,000 रुपये से तीन लाख रुपये तक सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करा सके और राजस्थान के 67 परसेंट लोग इससे जुड़े हुए हैं। 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का लाभ अभी इससे ले चुके हैं।

ग्रामीण गौरव पथ, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गांवों में भी शहर से बढ़िया क्वालिटी की सीसी सड़क बन सकती है। वह मुख्य मंत्रीजी ने बनवाईं। कौशल रोजगार प्रशिक्षण देकर बेरोजगारों को रोजगार देने का पूरा-पूरा प्रयास किया। मुख्य मंत्री राजश्री योजना बालिकाओं के लिए, फिर इन योजनाओं के अलावा श्रमिक कार्ड योजना। जो भी श्रमिक 90 दिन की मजदूरी कर ले चाहे नरेगा में ही करे, उसका एक कार्ड बनाकर, उसको और उसके परिवार को इतने फायदे दिये गये ताकि गरीबों का, श्रमिकों का उद्धार इससे हुआ।

मुख्य मंत्री जन आवास योजना, हर परिवार को छत मिले। आदर्श ग्राम पंचायत योजना, न्याय आपके द्वार योजना, करीब 70 लाख लोगों के राजस्व प्रकरण इसमें खतम हुए। सौर ऊर्जा में देश में राजस्थान प्रथम। स्वच्छ भारत मिशन में देश में राजस्थान में सबसे ज्यादा शौचालय बने। अन्नपूर्णा भण्डार, और भी बहुत सारी योजनाएं मुख्य मंत्रीजी की हैं। मुख्य मंत्रीजी का विजन 2020 यह है कि पंक्ति के आखिरी में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसको भी इसका लाभ मिले।

अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो माननीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने बूंदी विधान सभा क्षेत्र को और बूंदी जिले को बहुत कुछ दिया। बूंदी से बिजौलिया 50 किलोमीटर की सड़क दी। उसके लिए बहुत-बहुत आभार। जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी तो इनके पहले बजट में, उस समय के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने भी इस सड़क की घोषणा की थी, 111 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था लेकिन पांच साल में एक इंच भी उन्होंने इस पर सड़क नहीं बनवाई। अब माननीया मुख्य मंत्रीजी इस सड़क को बना रही हैं।

(श्री अशोक डोगरा)

मेरे एरिया में बरड़ एरिया है जहां 59 गांव और ढाणियों में फ्लोराइड और टीडीएस की मात्रा बहुत ज्यादा थी। माननीया मुख्य मंत्रीजी का और हमारे पेयजल मंत्रीजी बैठे हैं, इनका भी, आप दोनों का आभार। इन्होंने 80 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से उन 59 गांव और ढाणियों को स्वच्छ पेयजल से जोड़ने के लिए घोषणा की है।

बूंदी में एक गरडदा बांध है। जब पुरानी सरकार थी, 15 अगस्त, 2010 को वह बांध, आपके कांग्रेस सरकार के टाइम भी बन रहा था लेकिन बनते ही, जब पहली बार 25 परसेंट ही भरा तो वह बांध टूट गया था। 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की उस पर लागत थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने गरडदा बांध के पुनर्निर्माण की घोषणा की है। मैं बूंदी की पूरी जनता की तरफ से माननीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

बूंदी में एक बाबा मीराशाह की दरगाह है जिसको पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। उनका भी बहुत-बहुत आभार।

मेरे यहां राजकीय महाविद्यालय है, वहां दो विषय, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र की कई सालों से मांग हो रही थी, उनको भी वह विषय दिये। उसके लिए भी आभार।

हमारे सरकारी अस्पताल में ब्लड सैपरेशन यूनिट नहीं थी, जिसके लिए बार-बार कोटा भागना पड़ता था। वह भी इन्होंने दिया। उसके लिए भी आभार।

अब एक चीज इसमें रह गयी है जो माननीया मुख्य मंत्रीजी की पहले घोषणा भी थी। मैं वह आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी को याद कराना चाहता हूं कि बूंदी से देई नैनवां खटकड़ लाखेरी इन्द्रगढ़ सवाईमाधोपुर जाने का जो रास्ता है, वह शहर के अंदर से निकलता है और लाखेरी में एसीसी फैक्ट्री भी है। उसके ट्रोले भी चलते हैं। सवाई माधोपुर का ट्रैफिक भी निकलता है। उससे रोज एक्सीडेंट होते हैं। यदि बूंदी में एक बाइपास दे दिया जाता है जो मात्र 10.5 किलोमीटर का है। मैं मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से यह भी याद कराना चाहता हूं, जब माननीय गडकरीजी और

(श्री अशोक डोगरा)
माननीया मुख्य मंत्रीजी कोटा कुछ उद्घाटनों के लिए आये थे, जिसमें मेरे बूंदी में टनल बनी थी, उसका भी उद्घाटन था। यह साल भर पुरानी बात है। उस समय जब मुख्य मंत्रीजी भाषण दे रही थीं तो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर माननीय युनुस खान साहब ने एक कागज पर लिखकर माननीया मुख्य मंत्रीजी को दिया था और वहां उन्होंने घोषणा कर दी थी बूंदी नैनवां बाइपास की। उस टाइम अखबारों में काफी हाइलाइट हुआ। यह मांग थी जो पूरी हो गयी, घोषणा हुई लेकिन इस बजट में नहीं आने से, इसका अखबारों ने भी गलत तरीके से लिखा है। बहुत कुछ दिया है बूंदी को, आज तक इतना नहीं मिला। इसकी तो सबने सराहना की लेकिन बाइपास के लिए हैडलाइन में बूंदी के सभी अखबारों में मुखपृष्ठ पर यह आया कि मुख्य मंत्रीजी की घोषणा थी, यह बजट में नहीं आई। यह अति आवश्यक है तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीया मुख्य मंत्रीजी को यह निवेदन करता हूं इस बाइपास की, क्योंकि ज्यादा महंगा काम नहीं है। 39.76 करोड़ रुपये का इसका एस्टीमेट है, 40 करोड़ रुपये से भी कम है। यह 10.5 किलोमीटर का बाइपास है। यदि यह बन जाता है तो बूंदी में जो रोज एक्सीडेंट होते हैं, उनसे निजातमिलेगी। बूंदी की 40 परसेंट जनता उसी रास्ते पर रहती है नैनवा रोड पर, जिधर से यह ट्रैफिक शहर के अंदर से निकलता है। एक और कारण है कि बूंदी में नई कृषि उपज मण्डी बन रही है जो अप्रैल में शिफ्ट हो जाएगी। इन सभी गांवों से करीब एक लाख बोरी रोज सीजन के टाइम पर आती है, वह भी उसी रास्ते से आएंगी क्योंकि मण्डी का रास्ता वही है। यदि यह बाइपास बन जाता है तो मंडी को टच करता हुआ निकलेगा। नहीं तो यह सारा ट्रैफिक, सारे गांव के ट्रैक्टर-ट्रोलियां जो यह माल लेकर आएंगी, ये भी उसी रास्ते से आएंगी तो एक्सीडेंट्स में और बढ़ोतरी हो जाएगी, इसलिए बूंदी नैनवा रोड पर बाइपास की घोषणा जरूर करायें।

दूसरा, डाबी कस्बे में 132 केवी के जीएसएस की करीब दो साल पहले घोषणा हुई थी लेकिन आज तक बना नहीं। वह बता रहे हैं कि जमीन नहीं मिल रही है फोरेस्ट में, जबकि जो अभी 33 केवी का जीएसएस लगा हुआ है, उसमें ही 12.5 बीघा जमीन है, उसी में वह बनाया जा सकता है तो मेरा यह निवेदन है कि उसको भी जल्दी से जल्दी बनायें।

(श्री अशोक डोगरा)

बूंदी में संस्कृत स्कूल तो बहुत सारे हैं, संस्कृत कालेज नहीं है। जिसकी वजह से स्कूली शिक्षा खतम होने के बाद बच्चों को कोटा तक जाना पड़ता है तो संस्कृत का एक कालेज बन जाए।

दो मेरी छोटी-छोटी पुलियां हैं, एक तो ग्राम गुढ़ा पंचायत राजपुरा में है। एरू नदी की पुलिया टूटी हुई है और स्कूल का रास्ता वही से है। हर साल एक-दो बच्चों के साथ हादसा हो जाता है। बच्चे पानी में से निकलते हैं। कभी पानी बढ़ जाता है। अभी तक चार बच्चों की डैथ हो चुकी तो ग्राम गुढ़ा पंचायत राजपुरा में एरू नदी में पुलिया का निर्माण हो जाए। बहुत छोटी पुलिया है। एक करोड़ रुपये से भी कम की लागत है। दूसरा, एक ग्राम अल्कोदिया का बांध, गुमानपुरा पंचायत में है। वहां गांव और खेतों के बीच में एक पुलिया थी, जो अभी पंचायती राज विभाग ने बनाई थी। वह टूट गयी तो वह पुलिया का भी निर्माण हो जाए।

दूसरा, बूंदी की 40 परसेंट आबादी नैनवा रोड पर है। वहां नौ प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। लेकिन लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है। लड़कियों को पांच किलोमीटर दूर महारानी स्कूल में जाना पड़ता है। जिस वजह से जो उनके गार्जियन हैं, वो उनको सुरक्षित महसूस नहीं करते। बहुत सारे लोग पढ़ाई छुड़ा देते हैं। वहां एक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय लड़कियों के लिए खुल जाए तो बच्चियों का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा, वे पढ़ने लग जाएंगी।

तीसरा, सबसे लास्ट में यह है कि बूंदी पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 18 से 20 हजार विदेशी पर्यटक और 40 से 45 हजार देशी पर्यटक हर साल वहां आते हैं। यदि पर्यटन की दृष्टि से एक पैकेज बूंदी को मिल जाए जिसमें बूंदी की साफ-सफाई हो और जो पुराना बूंदी है, वह डवलप हो जाए तो पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और बूंदी का भी विकास होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, 8 मार्च को

(श्री कैलाश चौधरी)

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट पेश किया गया, उसके ऊपर उनके पक्ष में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

हमारा बजट इस वर्ष आया और इस बजट का हम सबको इंतजार था। पहले भी जब कोई बजट आता था तो हर व्यक्ति यह सोचता था कि बजट आएगा तो निश्चित रूप से उसमें कोई न कोई टैक्स लगेगा और इस बार जो बजट आया, उस बजट को सुनने के बाद एकमात्र सिगरेट के ऊपर टैक्स लगा, उसके अलावा किसी भी वस्तु के ऊपर टैक्स नहीं लगा। इस बजट की पूरे प्रदेश में सराहना की गयी। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में बैठे भाइयों के अलावा, पूरे प्रदेश ने इसकी सराहना की। निश्चित रूप से आज हमारी मुख्य मंत्रीजी ने सर्वस्पर्शी बजट पेश किया, जिसके अंदर हर वर्ग को छुआ और हर वर्ग के लिए उन्होंने बजट के अंदर प्रावधान रखे गये। उन प्रावधानों के अंदर जो पिछला बजट था, उसको बढ़ाकर इस बार बजट पेश किया गया और इसी के साथ में हर क्षेत्र में अगर देखें तो जो पिछला कांग्रेस का कार्यकाल था, उसकी अगर हम तुलना भी करें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे परिवहन के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, हम इनसे बैटर हैं। अगर परिवहन की बात करें तो परिवहन में वर्तमान की जो सरकार है, उसने पिछले 38 माह के अंदर 1,327 नये मार्ग खोले जबकि पूर्व की जो सरकार थी, उन्होंने पांच वर्ष के अंदर 1,224 नये मार्ग खोले।...

(20.00 बजे)

इसी तरह से अगर उद्योग के क्षेत्र में बात करें तो उद्योग में वर्तमान सरकार ने 38 माह में 1 लाख 37 हजार 234 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित किये जिससे 21,700 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ तथा आठ लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए, जबकि पिछली सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में 74 हजार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की ही स्थापना की जिससे 11 हजार 100 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ एवं 1 लाख 92 हजार रोजगार सृजित हुए। इसी तरह हर क्षेत्र में अगर देखें तो कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी उससे हम बैटर थे, बैटर हैं पर फिर भी कांग्रेस के बंधु विपक्ष में जो हैं वो खड़े होकर कहते हैं कि बजट सराहनीय नहीं है। मैं इस समय यही कहना चाहूंगा कि चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो या

(श्री कैलाश चौधरी)

किसी भी क्षेत्र में हो यह कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसानों की अगर सबसे ज्यादा किसी ने सुध ली है तो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर विद्युत की बात करें तो किसान के लिए सबसे पहले विद्युत की आवश्यकता होती है। किसानों के लिए जिस तरह से इस बजट के अन्दर उन्होंने घोषणा की एक लाख कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया। विनियामक आयोग के द्वारा जो रेट्स बढ़ाई गयी थी उसको भी हमारी मुख्यमंत्रीजी ने वापस लेकर किसानों को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया और कांग्रेस के बंधु यह कहते हैं कि हमने किसानों के लिए, मैं तो इनसे यह पूछना चाहूंगा कि इन्होंने पिछले अपने पांच साल के कार्यकाल में एक भी कृषि कनेक्शन नहीं किया उसके बावजूद भी ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं।

राजस्व की बात करें तो हमारी मुख्यमंत्रीजी ने 'राजस्व आपके द्वार' लोक अदालतें लगाईं। पूरे प्रदेश में जिस तरह भाई-भाई आपस में खेत में लड़ते थे उनके कई वर्षों से मुक़दमे चल रहे थे तो हमारी मुख्यमंत्रीजी ने 70 लाख ऐसे मुकदमों का निस्तारण करने का काम राजस्व लोक अदालत आपके द्वार के द्वारा प्रदेश की जनता को राहत देने का काम किया।

उसी के साथ पंचायतों के पुनर्गठन की बात हुई। पूर्व की सरकार ने जिस तरह से सभी लोगों को कहा कि हम पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे, पंचायत समितियों का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन उनके कागज जहां थे वहीं रहे गये। हमारी मुख्यमंत्रीजी और हमारे उस समय के मंत्री माननीय गुलाब कटारिया जी साहब ने पूरे प्रदेश में जिस तरह से पंचायतों का पुनर्गठन किया राजस्थान में एक इतिहास रचा और 47 नयी पंचायत समितियां बनाईं। उसमें बाड़मेर जिले को सबसे ज्यादा खुशी हुई कि बाड़मेर जिले में भारत आजाद होने के बाद में मात्र आठ पंचायत समितियां थी लेकिन इस एक वर्ष में 17 पंचायत समितियां हमारे आज हो गयी हैं। नौ पंचायत समितियां नयी बनाई गयी। इस तरह से एक इतिहास रचा गया।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो तो स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे राशन कार्ड हो, जिस तरह से इनके समय में राशन कार्ड में हमेशा घोटाला होता था,

(श्री कैलाश चौधरी)

कई तरह के भ्रष्टाचार होते थे, लेकिन हमारी मुख्यमंत्रीजी ने पोस के द्वारा सीधा पैसा जो भी अनाज उनको चाहिए वो पोस मशीन के आधार पर उनको सीधा देने का काम किया, भ्रष्टाचार को खतम करने का काम किया।

गौरवपथ की बात करें तो गांवों में मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बताऊंगा कि हम वैर चुनाव में गये थे तो वहां पर चुनाव में जिस तरह से गांवों में कीचड़ हमने देखा। उस कीचड़ में एक हमारे माननीय सदस्य भी मेरे साथ थे, गाड़ी फंस गयी, गाड़ी के पीछे से धक्का दिया गाड़ी निकल गयी और वो वहीं कीचड़ में गिर गये। तो इस तरह से आपने सत्तर साल में गांवों में सिर्फ कीचड़ दिया लेकिन हमारी मुख्यमंत्रीजी ने गांवों को आदर्श गांव बनाने के लिए गौरवपथ बनाये जिससे उस सड़क पर चलते हुए गांव के हर आदमी को एक खुशी महसूस होती है। इस तरह से स्मार्ट गांव का इस बजट के अन्दर प्रावधान रखा। स्मार्ट गांव में आज कॉलेजों के अन्दर हो या हायर सेकेण्डरी स्कूल हों, के अन्दर नि:शुल्क वाईफाई की जिस तरह से व्यवस्था की हमारी मुख्यमंत्रीजी ने मैं उसके लिए उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करूंगा।

इसी के साथ मैं गांवों में जिस तरह पशुओं के इलाज के लिए लोगों को दूर-दूर जाना पड़ता था, हर जगह जाते शिकायत आती थी तो मुख्यमंत्रीजी ने कहा कि सबको साथ लेकर और हर पंचायत में पशु चिकित्सालय खोलने का जो निर्णय लिया इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा।

इसी के साथ में शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में एक इतिहास रचा गया। भारत आजाद होने के बाद में इस राजस्थान में मात्र 3500 हायर सैकण्डरी स्कूलें थी और उसके बाद में इस एक वित्तीय वर्ष में हमारी मुख्यमंत्रीजी ने 5200 नयी हायर सैकण्डरी स्कूल खोल कर एक इतिहास रचा जो कभी भूतो न भविष्यति, क्योंकि कई ऐसी बहनें थी जिनको सैकण्डरी करने के बाद दूरदराज जाना पड़ता था उनको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन हमारी मुख्यमंत्रीजी ने उन बहनों की, उन भाइयों की चिन्ता की। हमारे शिक्षा मंत्रीजी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस तरह से शिक्षा में परिवर्तन करके और अध्यापकों को व्यवस्थित करके,

(श्री कैलाश चौधरी)

सबका प्रमोशन करके एडजस्ट किया। विद्यालय के अन्दर स्टाफ की जिस तरह से कमियां चलती थीं उसकी पूर्ति करने का जो काम किया इसके लिए शिक्षा मंत्रीजी का भी मैं आभार प्रकट करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की हमेशा यही सोच रही कि गरीब गरीब रहना चाहिए और अशिक्षित अशिक्षित रहे, ताकि हम हमेशा सत्ता में आते रहें लेकिन इस बार यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारी मुख्यमंत्रीजी ने शिक्षा को बढ़ावा दिया। पूरे राजस्थान में जिस तरह से पिछली बार जब सत्ता में थे तो पंचायतों में सैकण्डरी स्कूलें खोली और इस बार हायर सैकण्डरी खोली उसके बाद में जिस तरह से छात्र-छात्राओं की संख्या हायर सैकण्डरी विद्यालयों में इस एक वित्तीय वर्ष में बढ़ी है उसके लिए निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्रीजी का आभार प्रकट करूंगा।

मैं आपसे इस समय यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा के अन्दर जिस तरह से इन्होंने व्यवस्था दी थी कि इनकी सोच यह रही कि एक अनपढ़ व्यक्ति, आज अगर बात करें तो एक विद्यालय के अन्दर अगर चपरासी लगाने की जरूरत होती है तो उस चपरासी के लिए एजुकेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन इनके कार्यकाल में ऐसे भी मंत्री बने जिनकी कोई शिक्षा नहीं थी वो यही चाहते थे। इनका अगर बस चलता पूरा तो ये सदन के अन्दर भी सारे अशिक्षित लोग आएं इनकी यहां तक सोच रही, लेकिन मैं आपसे यह कहूं कि इनके टाइम में दुर्भाग्य इस राजनीति का इनके समय में रहा कि इस देश के अन्दर ऐसे लोग आए जिनको कृषि के बारे में कभी जानकारी नहीं, कभी खेत में हल पर हाथ नहीं लगाया लेकिन वो कृषि मंत्री बन बैठे और कई ऐसे जिन्होंने कभी दुकान नहीं लगायी, जिन्होंने कभी चाय की दुकान भी नहीं लगायी, वो वाणिज्य मंत्री बने। उसके बाद में फाइनेंस के बारे में एबीसीडी की उनको जानकारी नहीं लेकिन वो वित्त मंत्री बने। सेना में कोई उनके परिवार का सदस्य कभी गया नहीं वो देश के अन्दर रक्षा मंत्री बने। इसी तरह जो खुद भूखे और वो खाद्य और आपूर्ति मंत्री बने, उन्होंने स्वयं का पेट भरा भ्रष्टाचार करके, लेकिन जनता का पेट भरने का उन्होंने कभी काम नहीं किया। इसी तरह अगर बात करें साइंस और टैक्नोलोजी की जिनको कभी उसका अन्तर मालूम नहीं वो इस देश में साइंस और

(श्री कैलाश चौधरी)
टैक्नोलोजी के मंत्री बने और इसके बाद में जिनको इनमें से किसी की जानकारी नहीं वो इस देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में जो +++ जो इनकी सेवा करने वाले। इस तरह से इस सदन के अन्दर भी इस बात के ऊपर आपके मंत्री जी को इन्होंने अपने इस वक्तव्य के ऊपर आपके मंत्री ने ...(व्यवधान)... इस सदन के अन्दर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि +++ जो नाम लिया गया उसको अपलिखित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, वैसे तो यह आपका अपने विवेक का भी कभी-कभी इस्तेमाल करना उचित ही रहता है। इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी आये, हम तो अपलिखित कर देंगे, लेकिन आपका उच्चारण जो इस सदन में हो गया उसके लिए आप क्षमायाचना ही कर लें तो कम से कम दूसरों के लिए एक...।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्षमा चाहूंगा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): मेरा निवेदन यह है कि इस राष्ट्र में जिस तरह से शिक्षा को गर्त में डालने का काम किया है, मैं धन्यवाद दूंगा भैरोंसिंह जी जो हमारे मुख्य मंत्री थे, उन्होंने मुख्य मंत्री रहते हुए हर पंचायत पर आठवीं तक की स्कूलें खोली और उसके बाद में हमारी मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा को बढ़ावा दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारा प्रदेश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, उन्नति की ओर बढ़ रहा है। हमारी मुख्य मंत्री जी ने जो इस वर्ष बजट पेश किया है, इस बजट की मैं बहुत सराहना करता हूं और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां विकास में निश्चित रूप से कोई कमी नहीं है लेकिन बालोतरा को जिला बनाने की हमारी मांग जो पिछले काफी वर्षों से चल रही है, बालोतरा को जिला बनाया जाता है तो बाड़मेर जिले के और बालोतरा के आस पास के लोगों के लिये बहुत बड़ी राहत होगी।

दूसरा, मेरे यहां एक गिड़ा पंचायत समिति है उस गिड़ा पंचायत समिति

(श्री कैलाश चौधरी)
में एक सीएचसी की आवश्यकता है क्योंकि वहां के लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जीसे निवेदन करूंगा कि एक सीएचसी वहां खुल जाए। आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका बहुत बहुत आभार।

श्री उपाध्यक्ष: समाराम जी गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया है वह आम जन के हित का बजट है जो कि काबिल ए तारीफ है। भारतीत जनता पार्टी की हमारी सरकार जब भी बनी है तो गरीब को गणेश मानते हुए कदम उठाया गया है जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। शिक्षा में गुणवत्ता भी दिखाई दी है। जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे उनको भी सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा आबू में दो बच्चियां तो ऐसी हैं जिनको सरकार ने अमेरीका में पढ़ने के लिये चयनित किया है। 10 लाख रुपये एक बच्ची का खर्चा आएगा वह सरकार देगी, इस प्रकार पढ़ाई में गुणवत्ता दी है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने शिक्षा में जो कदम उठाया है, चपरासी से लगाकर डीईओ तक पहली बार शिक्षा में व्यवस्था सही तरीके से की है।

सड़कों का पूरा जाल बिछाया गया है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा आबू के लिये कहना चाहूंगा कि 2003-04 में जब सरकार थी उस समय भी शहरों में गौरव पथ था, गौरव बढ़ाया गया था और कांग्रेस ने पिछले पांच सालों में गौरव पथ योजना ही बंद कर दी। अब पुन: हर पंचायत मुख्यालय पर और नगरों में गौरव पथ देकर बहुत ही गौरव बढ़ाया है। हमारे शासनकाल में 2003-04 में जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे उनको मैं बधाई देना चाहूंगा। उस समय जो हमारा रजवाड़ा ब्रिज आबू रोड का था वह बहुत ही सकड़ा था, दो तरफ पुलिस लगती थी, उस समय इन्होंने जो पांच करोड़ का पुल बनाया था, हमारा जो बत्तीसानाला बांध निर्माण हो रहा है, जहां एक नदी बत्तीस बार कटती है वहां लोगों के आवागमन की दुविधा थी, वहां इन्होंने पांच पुलों की घोषणा की थी और वहां पांच पुल भी बने। जब अपनी सरकार 2008-09 में नहीं आई तब एक अध्यापक नदी में बह

(श्री समाराम गरासिया)

गया था, एक पुल बनना रुक गया था, जो पूर्व सदस्या थी गंगाबेन गरासिया, उन्होंने पुल बनाने की घोषणा की थी लेकिन पुल तो क्या एक ईंट तक नहीं रखी। तब लोगों को पता लगा कि वास्तव में जब भाजपा की सरकार होती है तब पुलों का निर्माण होता है। मैं वर्तमान सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को बधाई दूंगा कि सागवाड़ा ब्रिज 2 करोड़ 70 लाख में तैयार हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आती है तो 'न्याय आपके द्वार' में 35-40 वर्षों का जो पुराना केस था वह भी निपटाया गया। जो छोटे छोटे गरीब आदिवासी भटकते थे 'न्याय आपके द्वार' में उनके केसों को निपटा कर बहुत ही अच्छा काम किया।

चिकित्सा विभाग में इतना अच्छा काम हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू में दो नई पीएचसी खोली है जो कि एक तो भूला में है और एक झाड़ोली में है।

मैं हमारे जनजाति विकास मंत्री जी को बधाई दूंगा, जब पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत थे उन्होंने एक लिल्लौरी वरली शहीद स्मारक की घोषणा की थी वहां वह एक पत्थर लगाकर आये, मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया और जनजाति विकास मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करुंगा कि उन्होंने उसी जगह पर 3 करोड़ 29 लाख का आवासीय बालिका जनजाति छात्रावास तैयार करवा कर उसका उद्घाटन भी किया है। हमारी सरकार घोषणा नहीं करती है, काम करके बताती है और कांग्रेस की सरकार हमेशा थोथे वादे और घोषणाएं करती हैं।

कांग्रेस की पूर्व सरकार ने घोषणाएं खूब की, कहते हैं कि नौजवानों को नौकरी नहीं दी, कौशल विकास के हिसाब से 18 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों के लिये हमारे यहां पिण्डवाड़ा आबू में कौशल विकास के शिविर भी हैं जिसमें तीन महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें किसी भी प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं।

(श्री समाराम गरासिया)

हमारे सिरोही जिले में सबसे बड़ा जो पत्थर गढ़ाई का काम चलता है जिससे सिलिकोसिस की बीमारी होती है, पहली बार सरकार ने एक ऐसी योजना निकाली जिसमें किसी के सिलिकोसिस बीमारी पाई जाती है उसे एक लाख का चैक मिलता है और मृत्यु होने पर उसे तीन लाख रुपये दिये जाते हैं। यह इस सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को गणेश मानकर काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे सभी मंत्रीगणों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा काम किया है। पूर्व सरकार में जो भी काम हुए हैं वह बिलकुल गलत हुए हैं। यह काम कम और बातें ज्यादा करते हैं और अखबारों में छाये रहते हैं। अपन अखबारों में नहीं, बिना मांगे जिस प्रकार का काम हुआ है, माउंट आबू में 700 करोड़ की सड़क भारत माला के तहत अम्बाजी से गुरुशिखर तक दी है और अनादरा से होते हुए आबू पर्वत पर 33 केवी की लाइन बिछाई है। सीवरेज के लिये भी आबू पर्वत में 100 करोड़ का बजट दिया है, जब 2003-04 में भी हमारी सरकार थी उस समय भी 35 करोड़ सीवरेज के लिये दिये थे। पूर्ववर्ती सरकार 35 करोड़ का भी काम पूर्ण नहीं कर सकी। यह केवल घोषणा में ही रहते हैं, बाकी कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी है उसने गरीब को गणेश मानते हुए काम किये हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): 'आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितना व्यवधान मिले। बढ़ना ही हमारा काम, आगे बढ़ना ही हमारा काम है।' उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों को होली की राम राम। चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, हमारी सरकार बनी है उसके लिये सभी सदस्यों को, खास तौर से विपक्षी सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यह लोग नोटबंदी के समय से रो रहे थे, पीट रहे थे कि नोटबंदी करके क्या किया, इन्होंने अच्छा जवाब दिया है, यूपी में जो जवाब मिला है इससे यह सारे शांत हो गये और खुश हो रहे हैं कि वास्तव में यह काम तो सही था लेकिन बोलना हमारी मजबूरी थी।

(श्रीमती द्रोपती)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2017-18 के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि प्रदेश की गत तीन वर्षों की विकास यात्रा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश को एक नई दिशा मिली है। यह बात कांग्रेस के माननीय सदस्यों के गले नहीं उतर रही, क्योंकि इन्होंने विकास करने में कम और देश-प्रदेश को लूटने में ज्यादा विश्वास किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में राजस्थान को अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, वे अपने आपमें काबिल-ए-तारीफ है और विपक्षियों को अपने आपमें जवाब दे रहे हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य के रूप में गोल्ड ट्रॉफी, ई-गवर्नेंस का स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार इत्यादि। इस तरह से हमारे राजस्थान को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। अभी-अभी 8 तारीख को महिला दिवस पर हमारी मंत्री महोदया को भी सम्मानित किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हम जो 'सबका साथ, सबका विकास' लेकर चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में इसकी तारीफ हो रही है और हम राजस्थान में बहुत ज्यादा विकास करवा रहे हैं।

मैं सबसे पहले अगर सड़क का ही नाम लूं तो वास्तव में सड़क का कार्य जो हमारी राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री ने इस बार किया है। गांव के अंदर गौरव पथ जो दिए हैं, वे वास्तव में काबिल-ए-तारीफ हैं। जिस तरह से मेरे से पहले माननीय सदस्य बोल रहे थे किकीचड़ के अंदर गाड़ी फंस जाती थी। वास्तव में, गांव के अंदर यही हालत थी। जब हम गांव के अंदर जाते थे तो बारिश के समय मुख्य गली से नहीं निकल पाते थे और अब जो गौरव पथ दिए हैं, गांव वाले भी तारीफ कर रहे हैं कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसी रोड़ क्या हमारे गांव में होगी? इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और श्री युनुस खान, मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी। गत तीन वर्षों में 15 हजार 278 किलोमीटर की नई सड़कें हमारे राजस्थान में

(श्रीमती द्रोपती)

बनाई गयी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले कार्यकाल 2003 से 2008 के अंदर जो सड़क बनी थी, किशनगढ़-रतनगढ़ और हमारे हनुमानगढ़ होते हुए संगरिया तक बनी थी, वह अब तक नहीं टूटी है और बहुत ही अच्छी और सुंदर सड़क पड़ी है। गत सरकार के कार्यकाल के अंदर जो हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ रोड़ बनी थी, यदि माननीय कांग्रेसी भाई उस रोड़ पर गये हैं तो वे भी बता देंगे कि वह सड़क कैसी है? इतनी जर्जर हालत में पड़ी है कि पूछो मत। कई बार तो कांग्रेसी सदस्य मुझे भी कहते हैं कि विधायक जी हमारी सरकार नहीं है, अब आपकी सरकार है। हमारी सरकार ने तो ऐसा घटिया काम कर दिया। जैसा भी है, लेकिन अब आप अच्छा काम करो और आप इस सड़क की मरम्मत कराओ। उस पर टोल भी वसूला जाता है तो माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगी कि टोल बंद करके उस सड़क की दुबारा रिपेयरिंग करवाई जाए, ताकि वह सड़क अच्छी लगे। हाई-वे रोड़ है। उस पर बहुत साधन आते हैं और वह पूरी सड़क टूटी हुई है। इसकी जांच कराओ और जनता को न्याय दिलवाओ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण की घोषणा में प्रदेश की शेष बची हुई सड़कों का विकास होगा, वह हमारे जिले के अंदर बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि हमारे जिले के अंदर तीन सड़कें तो ऐसी थीं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री ने पहली बार में ही इस बजट के अंदर ले लिया। हनुमानगढ़-अबोहर सड़क 43 किलोमीटर की है, यह सड़क बहुत ही इम्पोर्टेंट सड़क है। पीलीबंगा-लखुवाली सड़क 35 किलोमीटर है। नोहर-पल्लू की सड़क 67 किलोमीटर की है, जो नई बनाई जाएगी। यह बहुत लंबे समय से टूटी पड़ी है और जनता से मांग आ रही है कि आप यह सड़क बनाओ। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में ये जो सड़कें दी हैं, यह काबिल-ए-तारीफ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी।

मैं पेयजल की बात करूं, क्योंकि हमारा राजस्थान प्रदेश सूखा है और यहां पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत रहती है, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री ने इस बार बजट भाषण में 2016-17 के अंदर जो घोषणा की थी। किरण जी मंत्री थीं, तब उन्होंने आर.ओ. सिस्टम

(श्रीमती द्रोपती)

लगाए, जो वास्तव में काबिल-ए-तारीफ है। गांव के अंदर जब से डिग्गी बनी है, उसकी किसी सरकार ने कभी सुध नहीं ली। इस बार माननीय मुख्यमंत्रीजी ने रिपेयरिंग के लिए जो पैसे दिए हैं। कहीं पचास लाख दिए, कहीं एक करोड़ रुपए दिए और डिग्गियों की रिपेयरिंग होने से गांवों में शुद्ध पेयजल जाएगा तो गांव वाले अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आर.ओ. का पानी, जो कि सिर्फ शहरों में पिया जाता था, गांव के अंदर तो यह एक सपना था और अब वे गांव में शुद्ध पानी देंगे। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने एक अच्छी सोच की शुरूआत करके जो यह योजना लागू की है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगी।

मैं ऊर्जा विभाग की बात करूं। हमें जब सरकार मिली थी। सरकार जब कांग्रेस से हटकर बीजेपी में आई, तब बिजली विभाग में बहुत बड़ा घाटा लगा था और 72 हजार करोड़ से भी अधिक का घाटा था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, हमने जैसे-तैसे प्रयास करके इसको पूरा किया और इस वित्तीय वर्ष में 400 केवी के दो, 200 केवी के छह, 132 केवी के पन्द्रह तथा 33 केवी के दौ सौ नए सब-स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए सराहनीय कदम है। इससे राजस्थान की जनता को बहुत लाभ होगा। एक लाख कृषि कनेक्शन देने से किसान भाइयों को जो फायदा होगा, वह भी सराहनीय काम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2015 की तुलना में पर्यटकों की संख्या में 17.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें एक छोटा-सा सुझाव मैं भी दूंगी। मेरे पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में एक कालीबंगा गांव आता है, जिसमें हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं और वहां एक छोटा-सा संग्रहालय बना हुआ है। अगर उसको विकसित किया जाए तो पीलीबंगा के क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा और वहां भी पर्यटकों का आना-जाना होगा। एक अच्छा संदेश भी जाएगा और वह विकसित होगा।

कृषि एवं पशुपालन विभाग- 'स्वस्थ धरा एवं खेत हरा' के तहत माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी ने 19 फरवरी, 2015 को सूरतगढ़ में soil health card योजना का शुभारंभ किया था और यह किसान भाइयों के लिए ऐतिहासिक कदम है। इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा

(श्रीमती द्रोपती)

योजना के तहत प्रदेश के 83 लाख किसान भाइयों ने फसल बीमा करवाया और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा बारिश के समय में। पहले तहसील को इकाई माना जाता था और अब एक गांव को इकाई मानते हुए फसल बीमा के तहत उन्हें बीमा मिलेगा तो किसानों भाइयों को बहुत बड़ी खुशी होगी। मैं माननीय मंत्रीजी महोदय और माननीय मुख्यमंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरूआत होगी, जिससे किसान भाइयों को फायदा होगा।

सहकारिता विभाग के मंत्री माननीय अजय जी एवं मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वर्ष 2017-18 किसानों के लिए रियायती ब्याज पर फसली ऋण प्रदान करने के लिए 370 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो किसान हित में है। किसानों के लिए है।

मैं जल संसाधन विभाग की बात करुं। माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि इन्होंने किसानों को पूरा पानी मिले, इसके लिए 3 हजार 313 करोड़ 8 लाख रुपये का प्रावधान बजट में रखा है, जो गत वर्ष 2016-17 की तुलना में 11.14 प्रतिशत अधिक है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं शिक्षा विभाग की बात करूं। उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का टाइम चाहिए। लास्ट में मैं ही हूं और अभी आधा घंटे होने में दस-पंद्रह मिनट पड़े हैं। मैं थोड़ा-सा ही बोलूंगी। माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने शिक्षा के अन्दर प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर बारहवीं का स्कूल किया है। क्योंकि हमारे गांवों में यह होता है कि आठवीं का स्कूल है या पांचवीं का स्कूल है या फिर दसवीं का है तो गांव की बच्चियों को वहां तक ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अगर गांव के अंदर बारहवीं का स्कूल होगा तो वहां पर वे बच्चियां शिक्षा प्राप्त करेंगी और जब बच्ची शिक्षित होगी तो सात पीढ़ी तरेगी। अपना मानना है कि एक बच्ची पढ़ेगी, एक बच्ची शिक्षा लेगी तो वह सात पीढ़ियों

(श्रीमती द्रोपती)

तक काम आती है। माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और प्रदेश के अंदर 772 ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनमें कक्षा दस में 40 नामांकन होने पर उस विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा, यह भी एक सराहनीय कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(**तदनन्तर सदन की बैठक** 20.30 **बजे शुक्रवार, दिनांक** 17 **मार्च** 2017 **के** 11.00 **बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

चित्तौड़गढ़ जिले के वन क्षेत्र को जिले के वन अधिकारी के अधीन करने की योजना

302. श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): क्या वन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा में आने वाला वन क्षेत्र सीमा से लगते हुए अन्य जिलों के जिला वन अधिकारियों के अधीन है? यदि हां, तो जिले के किस-किस विधान सभा क्षेत्र का कितना वन क्षेत्र अन्य जिलों के जिला वन अधिकारियों के अधीन है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा परिधि में आने वाले वन क्षेत्र जो अन्य जिला वन अधिकारी के अधीन हैं, को चित्तौड़गढ़ जिला वन अधिकारी के अधीन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वन विभाग में जिला वन अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है, अपितु प्रत्येक जिले में उप वन संरक्षक के एक या एक से अधिक पद स्वीकृत हैं।

चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा में क्षेत्राधिकार रखने वाले ऐसे उप वन संरक्षक कार्यालय जिनका मुख्यालय अन्य जिलों में है एवं उनके अधीन चित्तौड़गढ़ जिले की वन भूमि का विधानसभा क्षेत्रवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "ए" अनुसार है।

(2) जी नहीं। जिला चित्तौड़गढ़ की वन भूमि के आंशिक क्षेत्र को वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन को दृष्टिगत रखते हुए बेहतर प्रबन्धन हेतु समीपस्थ जिलों के उप वन संरक्षकों के नियंत्रण में दिया हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर में हैंडपम्पों पर लगे प्रीपेड मीटरों का भुगतान

303. श्री कैलाख भंसाली (जोधपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर द्वारा विभाग के द्वारा खोदे गये और संचालित किए जा रहे हैंडपम्पों पर लगे विद्युत मीटरों को प्रीपेड में बदल दिया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में ऐसे कितने विद्युत मीटरों को कब-कब बदला गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई मौहल्लों में समितियां गठित नहीं होने से एवं मौहल्लेवासियों में आपसी समन्वय नहीं होने के कारण उक्त प्रीपेड मीटरों का भुगतान नहीं किया गया, जिससे उक्त मौहल्लेवासियों को खोदे गये हैंडपंप का कोई फायदा नहीं हुआ? यदि हां, तो वर्तमान में ऐसे कितने प्रीपेड मीटरों वाले हैंडपंप बंद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आम जनता को समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने के लिए विभाग पूर्ण-रूपेण उत्तरदायी है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रीपेड मीटर का भुगतान अपने स्तर से करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, जोधपुर शहर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैण्डपम्प आधारित 42 सिंगल फेज नलकूपों पर पूर्व में लगे विद्युत मीटरों को जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर द्वारा प्री-पेड मीटरों में बदला गया है। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, जोधपुर शहर में प्री-पेड आधारित उक्त 42 सिंगल फेज नलकूपों का संचालन एवं इनके विद्युत बिलों का भुगतान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्र में प्री-पेड मीटर वाले 30 सिंगल फेज नलकूप वर्तमान में बंद हैं तथा इन नलकूपों की रिचार्ज राशि जमा कराने की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। ये समस्त नलकूप माह अप्रैल, 2017 के प्रथम सप्ताह में चालू कर दिये जाएंगे। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, जोधपुर शहर में वर्तमान में 140 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से नहरी स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इस पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ उक्त सिंगल फेज नलकूपों से भी अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की गयी है। इन समस्त नलकूपों की विद्‌युत राशि का भुगतान विभाग द्‌वारा ही किया जा रहा है तथा क्षेत्र की आम जनता पर इस व्यय का भार नहीं डाला गया है। उक्तानुसार 30 नलकूपों की विद्‌युत राशि के भुगतान की कार्यवाही विभाग द्‌वारा प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकरी डाइवर्जन बांध का जीर्णोद्‌धार कराने की योजना

304. श्रीमती अनीता (नगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नगर के सीकरी डाइवर्जन बांध का जीर्णोद्‌धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जुलाई व अगस्त, 2016 में उक्त बांध में रूपारेल नदी का पानी आया था? यदि हां, तो कब व कितना पानी आया व उक्त पानी से किस-किस गांव की पोखर भरी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्‌वारा गुड़गांव कैनाल की पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी को लिफ्ट कर सीकरी डाइवर्जन बांध में डालने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो योजना के डी.पी.आर. का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त योजना को कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। सीकरी डाइवर्जन बांध के चैन 0 से 120 तक के कार्य ग्राम वजीरखेडा ग्राम पंचायत झंझार के अंतर्गत मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन

(जल संसाधन मंत्री)

योजना में राशि रुपये 62.34 लाख के स्वीकृत किये गये है। कार्य जून, 2017 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) रूपारेल नदी से सीकरी डाइवर्जन बांध माह जुलाई व अगस्त में आये पानी की मात्रा का विवरण परिशिष्ट "अ" पर तथा रूपारेल नदी के पानी से सीकरी बांध की नहरों से भरी गई ग्रामवार पोखरों की संख्या का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) गुडगांव कैनाल के पहाडी डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी को लिफ्ट कर सीकरी डाइवर्जन बांध में डालने की डीपीआर अभी तैयार की जा रही है।

(4) गुडगांव कैनाल की पहाडी डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी को लिफ्ट कर सीकरी डाइवर्जन बांध में डालने की योजना, जल उपलब्ध नही होने से स्वीकृति हेतु विचाराधीन नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 305

(स्थगित)

प्रदेश में राशन डीलरों के निलम्बन के नियम

306. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों का निलम्बन व बर्खास्त किये जाने का नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो निलम्बन एवं बर्खास्त किन कारणों से किसके द्वारा किया जा सकता है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसी दुकान का पद रिक्त होने पर उसका अतिरिक्त प्रभार अन्य उचित मूल्य दुकानदार को दिये जाने का नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो अतिरिक्त प्रभार किन नियमों के तहत, कब तक दिया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उचित मूल्य दुकानदार के विरुद्ध अनियमितता पाये जाने पर जिला कलक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

खण्ड 8 व 9 के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र निलम्बित/निरस्त किये जाने का प्रावधान है। यदि बिना सुनवाई का अवसर दिये निलम्बित किया जाता है, तो उसकी अवधि 90 दिवस से अधिक नहीं होगी। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) किसी उचित मूल्य की दुकान के रिक्त होने पर उसका अतिरिक्त प्रभार अस्थाई रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत स्थायी व्यवस्था होने तक नजदीक की अन्य उचित मूल्य दुकान से सम्बद्ध (अटैच) किया जाता है। इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 23.08.2016 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर के कुंजबिहारी मंदिर के जीर्णोद्धार पर व्यय राशि

307. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर स्थित प्राचीन कुंज बिहारी मंदिर की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो कब व कितनी?

(2) सरकार द्वारा उक्त मंदिर की मरम्मत का कार्य कब व किसको दिया तथा उक्त कार्य को पूर्ण करने की तिथि क्या निर्धारित थी? ठेकेदार द्वारा मरम्मत का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं करने पर सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर शहर स्थित प्राचीन कुंज बिहारी मंदिर की मरम्मत हेतु शासन के पत्रांक प.4(4)देव/ 2013 दिनांक 18.11.2014 के द्वारा राशि रुपये 52.00 लाख की स्वीकृति जारी की गयी।

(2) मंदिर श्री कुंज बिहारीजी जोधपुर के मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यादेश दिनांक 13.06.2016 के द्वारा मैसर्स आसीया कन्सट्रक्शन कम्पनी जोधपुर को दिया गया एवं अनुबन्ध के अनुसार कार्य

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की तिथि क्रमश: 23.06.2016 एवं 22.12.2016 निश्चित थी। उक्त मन्दिर का मरम्मत कार्य समय-दर-समय प्रशासनिक/वित्तीय कार्य एजेन्सी की प्रक्रिया निष्पादन के पश्चात वर्तमान में प्रगति पर है।

चन्दवाजी-जायवाली सड़क का पुनर्निर्माण

308. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि महार से चन्दवाजी वाया जायवाली की सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत कब-कब की गयी?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। महार से चन्दवाजी वाया जाटावाली सड़क की कुल लम्बाई 15 किमी. है, जिसमें से 7 किमी. महार से जाटावाली आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, इस सड़क पर वर्तमान में पेच मरम्मत कार्य प्रगति पर है। जाटावाली से एन.एच.-8 तक 1 किमी. सड़क पीपीपी प्रोजेक्ट (चौमूं से एन.एच.-8 एक्सप्रेस हाईवे) में स्वीकृत है इसके आगे 6 किमी. एन.एच.-8 एक्सप्रेस हाईवे है तथा 1 किमी. 14/0 से 15/0 चन्दवाजी ग्राम की सम्पर्क सड़क है जिस पर वर्तमान में पेच मरम्मत कार्य पूर्ण करवा दिये गये हैं। सड़क की मरम्मत का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। महार से जाटावाली 7 किमी. एवं सम्पर्क सड़क चन्दवाजी 1 किमी. के नवीनीकरण का कार्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त जाटावाली से एन.एच.-8 एक्सप्रेस हाईवे तक पीपीपी प्रोजेक्ट (चौमूं से एन.एच.-8 एक्सप्रेस हाईवे) में स्वीकृत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई मुख्यालय पर सहायक निदेशक के कार्यालय का सृजन

309. श्री हीरालाल (निवाई): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई मुख्यालय पर सहायक निदेशक (कृषि) का कार्यालय सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र निवाई कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), टोंक के अन्तर्गत आता है। निवाई मुख्यालय पर सहायक कृषि अधिकारी तथा कृषि पर्यवेक्षक के कार्यालय संचालित है जिनके द्वारा कृषि तकनीकी विस्तार का कार्य किया जा रहा है। निवाई मुख्यालय पर कृषि विभाग का नवीन कार्यालय स्थापना का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

नवीन कार्यालय खोला जाना एक नीतिगत प्रकरण है जो गुणावगुण व संसाधनों की उपलब्धता एवं क्षेत्र की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

प्रदेश के आंगनबाडी केन्द्रों में संचालित विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित करने की योजना

310. श्री भंवरसिंह (कोलायत): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जिलेवार तथा पंचायत समिति क्षेत्रवार संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने वर्ष तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है तथा प्रत्येक बालक व बालिकाओं को केन्द्र में क्या आहार दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित करने का विचार रखती है?

(5) प्रदेश के कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन संचालित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवर सिंह)

(6) क्या यह सही है कि सरकार भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जाता है? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों का वेतन व भत्ते बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जिलेवार तथा पंचायत समिति क्षेत्रवार संचालित श्रेणीवार आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत कुपोषण की रोकथाम हेतु राज्य के समस्त आंगनबाडी केन्द्रों के समस्त इच्छुक पंजीकृत आयुवर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती-धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन विभागीय भवन, सरकारी भवन, सामुदायिक भवन, विधालयों एवं किराये के भवनों में किया जा रहा है। किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(6) किराये के भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है। वर्ष 2015-16 में 1385 भवनों एवं वर्ष 2016-17 में 1000 भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गयी है।

(7) प्रदेश में सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत मानदेय कर्मियों को दिये जाने वाले वर्तमान मानदेय का विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है। दिनांक 01.06.2016 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 400 रु. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 300 रु. एवं सहायिका, सहयोगिनी एवं साथिनों का 250 रु. प्रतिमाह मानदेय वृद्धि की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट घोषणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु वर्क परफोरमेन्स आधारित प्रोत्साहन हेतु पृथक से योजना बनाने की घोषणा की गयी थी। इस क्रम में योग्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑब्जेक्टिव मापदण्डों के आधार पर प्रतिमाह 250 से 500 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नियुक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक को नियमानुसार वेतन श्रृंखला 5200-20200 ग्रेड-पे 2400 के अन्तर्गत वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मकराना में असुरक्षित घोषित की गयी खानों में अवैध खनन पर कार्यवाही

311. श्री श्रीराम भींचर (मकराना): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मकराना विधान सभा क्षेत्र के बोरावड, बिदियाद, कोला डूंगरी व मोरेड में वर्तमान में कितनी खानों को क्वारी लाइसेंस जारी किये गये हैं तथा उक्त में से वर्तमान में कितनी मार्बल खानों में खनन कार्य हो रहा है? बापी खानों सहित क्वारी लाइसेंस धारकों के नाम, पते का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मार्बल खनन क्षेत्र में लाइसेंस जारी करते समय दो खानों के बीच में खानों की सुरक्षा हेतु सीमित क्षेत्र सुरक्षित रखे जाने का

(श्री श्रीराम भींचर)

प्रावधान था? यदि हां, तो कितना व अब तक जारी लाइसेंसों में किन-किन क्वारी लाइसेंस खानों में कितना-कितना स्थान सुरक्षित रखा गया? क्वारी लाइसेंस धारी के नाम, पते व रखे गये सुरक्षित स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में दों खानों के बीच में रखे सुरक्षित स्थान में संबंधित क्वारी लाइसेंस धारियों द्वारा अवैध खनन करने से मार्बल खानों के गिरने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है? यदि हां, तो ऐसी कितनी खाने हैं, जो गिरने की स्थिती में है एवं खनन करने के लायक नहीं हैं? क्वारी लाइसेंसधारियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विभाग के मकराना स्थित कार्यालय को अवैध खनन करने की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कितनी व अब तक अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? शिकायतकर्ता के नाम सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा गिरने की स्थिति में आने वाली खानों को असुरक्षित घोषित किया गया है? यदि हां, तो कितनी खानें असुरक्षित घोषित की गयी? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि असुरक्षित घोषित की गयी खानों में चोरी छिपे खनन कार्य किया जा रहा है? यदि हा, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में बोरावड में 92, बिदियाद में 17, कोला डुंगरी व मोरेड में 120 क्वारी लाइसेंस जारी किये हुये हैं। सूची परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है, वर्तमान में 213 खानों में खनन कार्य हो रहा है। बापी खानों सहित क्वारी लाइसेंस धारकों के नाम व पते परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है।

(2) मकराना क्षेत्र में मार्बल खनन रियासत काल से बापी खानों के रूप में संचालित था तथा बापी रजिस्टर अनुसार खानों के बीच सुरक्षा हेतु सीमित क्षेत्र रखे जाने की जानकारी नहीं है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत

(राज्य मंत्री, खान)

नियमों के तहत जो खानें सरकारी भूमि में आवंटित की गई है, उनमें से बोरावड कुमारी रेन्ज में कुछ खानों के मध्य एक छोटा क्षेत्रफल डाट के रूप में छोड़ा गया है, इसके अतिरिक्त अन्य रेन्जों में जो गेप क्षेत्र है वह रास्ते के रूप में है तथा रेवत डूंगरी रेन्ज में जो गेप क्षेत्र है वह रियासत काल से ही एक छोटी देवली (लोक देवता का स्थान) है। खानों का विवरण व डाट की साईज का विवरण परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में दो खानों के बीच में रखे सुरक्षित स्थान में संबंधित क्वारी लाइसेंस धारकों द्वारा अवैध खनन करने से मार्बल खानों के गिरने की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

(4) जी हां। खनिज विभाग मकराना में पिछले 3 वर्षो में अवैध खनन की 13 शिकायतें प्राप्त हुई है। विभाग द्वारा अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं शिकायतकर्ताओं के नाम सहित विवरण परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है।

(5) जी नहीं। विभाग द्वारा गिरने की स्थिति में आने वाली खानों को असुरक्षित घोषित नहीं किया गया है परन्तु खान सुरक्षा महानिदेशालय, अजमेर द्वारा खान अधिनियम 1952 एवं मैटेलीफोरिस माइन्स रेग्यूलेशन 1961 के तहत ऐसी खानों को असुरक्षित घोषित करने की कार्यवाही की जाती है। खान सुरक्षा महानिदेशालय, अजमेर के द्वारा बन्द कराई गई असुरक्षित खानों की सूची परिशिष्ट 5 पर उपलब्ध है।

(6) जी नहीं। खान सुरक्षा महानिदेशालय, अजमेर द्वारा बन्द कराई गई असुरक्षित खानों में वर्तमान में कोई अनाधिकृत खनन नहीं किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फलौदी में वनरोपण हेतु समितियों का गठन

312. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा वनरोपण के कार्य को संपादन हेतु ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया जाता है? यदि हां, तत्सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र फलौदी में ग्राम स्तर पर समितियों का गठन

(श्री पब्बाराम)

कर दिया गया है? यदि हां, तो ग्रामवार गठित की गयी समितियों के सदस्यों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वन विभाग द्वारा वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन तथा वन क्षेत्रों में व अन्य राजकीय भूमि पर वनारोपण कार्यों का संपादन राज्यादेश दिनांक 17.10.2000 (प्रति संलग्न परिशिष्ट-ए) द्वारा गठित ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से किया जाता है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा अधीनस्थ क्षेत्र में गठित ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का, कार्यकारणी के सदस्यों के नाम सहित, ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-बी अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीलीबंगा के गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या का समाधान

313. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के कई गांवों में वर्तमान में भी फ्लोराइडयुक्त पेयजल उपलब्ध हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? गांवों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त पेयजल से निजात दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के समेकित सूचना प्रबन्धन तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र, पीलीबंगा के किसी भी ग्राम के स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

सीमा से अधिक नहीं थी। आई.एम.आई.एस. की दिनांक 07.03.2017 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र के हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित 17 ग्रामों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक सीमा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है।

इन 17 ग्रामों में सतही जल स्रोत से क्षेत्रीय जल योजनाओं के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 8 योजनाओं के बनाये गये प्रस्तावों में से एक योजना (3 ग्राम सम्मिलित) के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर (विभागीय वित्त समिति) वर्तमान में तकनीकी परीक्षण में हैं। शेष 7 योजनाओं के प्रस्ताव (14 ग्राम सम्मिलित) दिनांक 1 मार्च, 2017 एवं 8 मार्च, 2017 को मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) कार्यालय में प्राप्त हुए हैं। इन योजनाओं का तकनीकी परीक्षण किया जाकर, परीक्षण में सही पाये जाने के उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

ग्रामवार वांछित विवरण परिशिष्ट - अ पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगनहर से खाटां माइनर निकालने की योजना

314. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार गंगनहर की लाइनिंग पक्की होने के बाद शेष पानी से खाटां माइनर निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नही। गंगनहर आधुनिकीकरण परियोजना अंतर्गत लाइनिंग करने के फलस्वरूप बचत के पानी का उपयोग उसी क्षेत्र में सिंचाई सघनता बढाने में किये जाने के प्रावधान अनुसार किये जाने से खाटा माइनर का कार्य विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के पंचायत मुख्यालयों पर खाद्य भण्डारों का निर्माण

315. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार सभी पंचायत मुख्यालयों पर खाद्य भण्डारों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किसी भी तरह के खाद्यान्न भण्डारों का निर्माण अभी नहीं करवाया जा रहा है तथा ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जालौर के मंदिरों को धार्मिक स्थल घोषित करने की योजना

316. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जालौर के सिरे मंदिर, माण्डवला जहाज मंदिर व भाण्डवपुर जैन मंदिर को धार्मिक स्थल घोषित कर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष सुविधाएं दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जालौर के सिरे मंदिर, माण्डवला जहाज मंदिर व भाण्डवपुर जैन मंदिर इस विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर नहीं है, न ही पंजीकृत प्रन्यास है। इन्हें धार्मिक स्थल घोषित कर राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष सुविधाएं दिलाने बाबत वर्तमान में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बस्सी में सड़कों का निर्माण

317. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्या सार्वननिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनवरी 2013 से जनवरी 2017 तक किस-किस योजना में किन-किन सड़कों का निर्माण कराया गया? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त सड़कों के निर्माण पर कुल कितना व्यय किया गया? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़कों की कोई शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां, तो कब व प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनवरी 2013 से जनवरी 2017 तक विभिन्न योजनाओं में निर्मित सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) सरकार द्वारा उक्त सड़कों के निर्माण पर कुल राशि रु. 2516.20 लाख का व्यय किया गया, योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। माननीय विधायिका बस्सी श्रीमती अंजू देवी खन्गवाल की गौरव पथ झर व पाटन के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसका परीक्षण करवाया गया तथा इसमें कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

वर्ल्ड बैंक द्वारा राजस्थान एग्रीकल्चर काम्पीटेटिव प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत राशि

318. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2012 में राजस्थान एग्रीकल्चर काम्पीटेटिव प्रोजेक्ट के लिए 832 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे? यदि हां, तो कितने वर्षों के लिए? प्रदेश के किसानों को उक्त प्रोजेक्ट के तहत क्या-क्या आर्थिक व तकनीकी सहायता किन-किन शर्तों व किन-किन विभाग को नोडल एजेन्सी बनाकर कितनी समय सीमा में दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम)

(2) उक्त प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2012 से 2016 तक कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? जिलेवार, विभागवार प्रोजेक्ट के तहत किये गये कार्यों व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि 832 करोड़ रुपये के उक्त प्रोजेक्ट में से लगभग 5 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी मात्र 3 से 4 प्रतिशत पैसा भी खर्च नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रोजेक्ट की अधिकतम बजट राशि लैप्स हो रही है तथा प्रोजेक्ट की कुल राशि के 70 प्रतिशत राशि पर सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक को ब्याज दिया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक वर्ल्ड बैंक को सरकार द्वारा ब्याज पेटे कितना भुगतान किया जा चुका है?

(5) उक्त प्रोजेक्ट राशि समय पर खर्च नहीं कर किसानों को प्रोजेक्ट के लाभ से वंचित रखने व वर्ल्ड बैंक को ब्याज के भुगतान के लिए सरकार ने किसकी जिम्मेदारी तय की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परियोजना 7 वर्ष के लिए स्वीकृत की गयी।

राज्य के कृषकों को नोडल विभाग कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, जलसंसाधन, जलग्रहण विकास एवं भू-जल विभाग के माध्यम से विभिन्न उन्नत तकनीक एवं गतिविधियों द्वारा जल बचत, उत्पादन/उत्पादकता बढाना, कृषक आमदनी/कृषक की कार्य क्षमता कुशलता में वृद्वि करने के प्रयोजनार्थ परियोजना सहायता का प्रावधान रखा गया है। विभागवार गतिविधियों पर प्रदत आर्थिक एवं तकनीकी सहायता का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। आर्थिक व तकनीकी सहायता परियोजना काल के दौरान वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार दिये जाने का प्रावधान है।

(2) परियोजना के तहत वर्ष 2012-13 से 2016-17 (फरवरी, 2017) तक 49889 किसानों का लाभान्वित किया गया। जिलेवार योजना के तहत किये गये कार्यो एवं खर्च राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) परियोजना के तहत माह फरवरी, 2017 तक 41.90 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है जो कि परियोजना राशि का 5.03 प्रतिशत है।

(कृषि मंत्री)

(4) परियोजना काल अप्रैल, 2019 तक है। अभी तक किसी प्रकार की बजट राशि लैप्स नही हुई है। वित्तीय अनुबन्ध के अनुसार 1.25 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय है। अभी तक ब्याज राशि का भुगतान नही किया गया है।

(5) मूल परियोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व ही परियोजना की समीक्षा का निर्णय माह मार्च, 2014 में लिये जाने के कारण परियोजना की वास्तविक शुरूआत समय पर नही हो पायी। तदोपरांत परियोजना की पुन- संरचना एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया माह जून, 2016 में पूर्ण होने के उपरात किसानो को लाभान्वित करने की प्रक्रिया प्रांरभ की जा चुकी है। अभी तक विश्व बैंक को किसी प्रकार की ब्याज राशि का भुगतान नही किया गया है। उक्त कारणों से कोई भी अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत साथिनों को देय मानदेय

319. श्री तरुण राय कागा (चौहटन): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिन तथा सहायिका को कितना-कितना मानदेय दिया जाता है तथा उनसे क्या-क्या सेवाएं ली जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त के द्वारा महिलाओं एवं बालकों के विकास के लिए बेसिक सेवाएं देने के उपरान्त भी योग्यजन को राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है तथा मानदेय में बढ़ोतरी भी नहीं की गयी? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त का मानदेय बढाने व राज्य कर्मचारी का दर्जा देन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगी, साथिन

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

तथा सहायिका को दिये जाने वाले वर्तमान मानदेय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त मानदेयकर्मियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिन को राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जा सकता क्योकिं यह मानदेय सेवा पर स्वेच्छिक सेवा भावना से समुदाय में सेवा करने वाली स्थानीय महिला होती है एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा सहयोगिनी का दैनिक कार्य 4 घंटे प्रति दिवस होता है। इस कार्य समय के उपरान्त ये किसी भी निजी कार्य हेतु स्वतंत्र रहती हैं।

इन पर राज्य सेवा के कार्मिकों की भांति नियम लागू नहीं है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 400 रु, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 300 रु. एवं सहायिका, सहयोगिनी एवं साथिनों का 250 रु. प्रतिमाह मानदेय में दिनांक 01.06.2016 से वृद्धि की गयी है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 के बजट में मानदेय के अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि 250 से 500 रुपये प्रतिमाह दिये जाने की घोषणा की गयी।

(3) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" में ही समाहित है। इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये पूर्णत: अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी हैं।

वर्ष 2016-17 के बजट में मानदेय के अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि 250 से 500 रुपये प्रतिमाह दिये जाने की घोषणा की गयी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नाथद्वारा में बजरी खनन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

320. श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में बजरी खनन के संबंध में सरकार को कब-कब, किस-किससे, क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में बजरी खनन के संबंध में जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को गत 3 वर्षों में सुगम/राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर 20 शिकायतें (परिशिष्ट-1), जिला कलक्टर, राजसमन्द को सीधे 23 शिकायतें (परिशिष्ट-2), उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को 12 (परिशिष्ट-3), तहसीलदार, नाथद्वारा को 6 (परिशिष्ट-4) एवं खनि अभियन्ता, राजसमन्द खण्ड-।। को सीधे ही 03 शिकायतें (परिशिष्ट-5) जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को 31 (परिशिष्ठ-6) एवं जिला परिवहन अधिकारी को 7 (परिशिष्ट-7) शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार कुल प्राप्त 102 शिकायतों का कार्यालयवार कार्यवाही का विवरण परिशिष्टों के रूप में उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ जिले में वानिकी पर्यटन के विकास की कार्ययोजना

321. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2013-14 से 31 जनवरी, 2017 तक वन संरक्षण के क्या-क्या कार्य किये गये? उक्त कार्यों पर कुल कितना व्यय किया गया एवं क्या-क्या भौतिक उपलब्धिया अर्जित हुईं? वर्षवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में वानिकी पर्यटन की क्या-क्या संभावना है एवं किन-किन क्षेत्रों में वानिकी पर्यटन विकसित किया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में उक्त जिले में वानिकी पर्यटन विकास के क्या-क्या कार्य किये गये एवं उक्त पर कितना-कितना व्यय किस-किस मद से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में वानिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वन विभाग द्वारा वन संरक्षण हेतु वर्ष 2013-14 से 31 जनवरी, 2017 तक कराये गये कार्यों एवं उन पर हुए व्यय का जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "ए" एवं "बी" अनुसार है।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में बस्सी अभयारण्य एवं सीतामाता अभयारण्य में पर्यटन विकास की संभावना होने से इन क्षेत्रों को वानिकी पर्यटन हेतु और विकसित किया जा सकता है।

(3) चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 2014-15 में बाडी मानसरोवर बांध पर राज्य आयोजना मद से 20 लाख रुपये व्यय किये जाकर ईको-ट्यूरिज्म साइट विकसित की गई है।

(4) चित्तौड़गढ़ जिले में वानिकी पर्यटन को बढावा देने के लिए बस्सी अभयारण्य हेतु 80 लाख रुपये एवं सीतामाता अभयारण्य हेतु 250 लाख रुपये के प्रस्ताव तैयार किये जाकर प्रक्रियाधीन हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हिण्डौली में नवीन नलकूप व हैंडपम्प लगाने के कार्य

322. श्री अशोक (हिण्डौली): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से जनवरी, 2017 तक बूंदी जिले में विधान सभा क्षेत्रवार कितने-कितने ट्यूबवेल एवं हैंडपंप स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में वर्ष 2014 से 2017 तक कोई हैंडपंप स्वीकृत नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नए नलकूप एवं हैंडपंप लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों के किस-किस ग्राम में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बूंदी जिले के तीन विधान सभा क्षेत्र क्रमश: बूंदी, केशोरायपाटन एवं हिण्डौली में पेयजल आपूर्ति सुचारू एवं सामान्य बनाये रखने हेतु माह

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

जनवरी, 2014 से जनवरी, 2017 की अवधि में 111 थ्री-फेज नलकूप, 118 सिंगल फेज नलकूप तथा 264 हैण्डपम्पों की स्वीकृति जारी की गयी। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जनवरी, 2014 से जनवरी, 2017 की अवधि में विधान सभा क्षेत्र, हिण्डौली में कुल 28 हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जाकर इनमें से 26 हैण्डपम्प निर्माण उपरांत चालू किये जा चुके हैं तथा 2 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है ।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, हिण्डोली में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16 थ्री-फेज नलकूप, आर.ओ. संयंत्र के निर्माण अंतर्गत 1 सिंगल फेज नलकूप एवं 12 हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गयी है । इस स्वीकृति के विरुद्ध 4 थ्री-फेज नलकूप एवं 10 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान हेतु भू-जल की उपलब्धता, पेयजल की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार जल योजनाओं के संवर्धन/पुनर्गठन अंतर्गत नलकूप एवं हैण्डपम्प का निर्माण कार्य सतत प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिद्धमुख सिंचाई परियोजना क्षेत्र में अस्थाई पाइप आउटलैट के स्थान पर A.P.M. लगाने का कार्य

323. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सिद्धमुख सिंचाई परियोजना क्षेत्र में कई चकों में अस्थाई पाइप आउटलैट द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? उक्त चकों व अस्थाई आउटलैट की सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या सरकार उक्त अस्थाई पाइप आउटलैट के स्थान पर A.P.M. लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 2 चकों में सीएडी द्वारा चक स्कीम को अंतिम रूप दिया जाना प्रक्रियाधीन होने तथा शेष 10 मोघों के स्थानों से संबंधित काश्तकारों में आपस में विवाद होने से अस्थाई आउटलैट के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है, सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। आपसी विवादों के निपटारे एवं चक स्कीम फाइनल होने पर अस्थाई आउटलैट के स्थान पर ए.पी.एम. लगाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 324

(स्थगित)

उदयपुर जिले में रिक्त राशन की दुकानें

325. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर जिले में वर्तमान में कितनी राशन की दुकानें संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितनी राशन की दुकानें रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त राशन डीलरों को नई राशन सामग्री आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में वर्तमान में 1135 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उदयपुर जिले में वर्तमान में 139 राशन की दुकानें रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश में उचित मूल्य दुकानदारों को पात्र उपभोक्ताओं को राशनकार्ड के आधार पर वितरित करने हेतु गेहूं, चीनी एवं केरोसीन का आवंटन किया जाता है। इसके

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

अतिरिक्त नई राशन सामग्री आवंटन करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बिलाड़ा के चारभुजा मन्दिर की भूमि को अतिक्रमियों से मुक्त कराने की कार्यवाही

326. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के हर्षादेवल मन्दिर, लाम्बा में महादेव मन्दिर, बुचकला में माताजी मन्दिर, बाणगंगा पर महादेव मन्दिर/गंगा मैया मन्दिर व डिगड़ी माता मन्दिर को धार्मिक स्थल घोषित कर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा विशेष पैकेज अंतर्गत उक्त स्थलों की मरम्मत कराने व अन्य सुविधायें दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या बिलाड़ा में चारभुजा मन्दिर की भूमि पर पुजारी द्वारा एकल ट्रस्टी बनकर कब्जा किये जाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो उक्त भूमि वर्तमान में किसके आधिपत्य में है? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमियों से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बिलाडा के हर्षादेवल मन्दिर, लाम्बा में महादेव मन्दिर, बुचकला में माताजी मन्दिर, बाणगंगा पर महादेव मन्दिर/गंगा मैया मन्दिर व डिगड़ी माता मन्दिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर नहीं है और न ही यह मंदिर राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास है। इन मंदिरों को धार्मिक स्थल घोषित कर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा विशेष पैकेज अंतर्गत उक्त स्थलों की मरम्मत कराने व अन्य सुविधाएं दिलाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

(2) जी हां। बिलाड़ा में स्थित मंदिर श्री चारभुजा जी बिलाड़ा का राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 20 के अन्तर्गत आयुक्त, देवस्थान विभाग के स्तर पर अपील संख्या 18/2015 विचाराधीन है। वर्तमान में उक्त भूमि ट्रस्ट के आधिपत्य में है।

(3) वर्तमान में प्रकरण अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया में अपील संख्या 18/2015 विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बिलाड़ा में मुख्यमंत्री नि:शुल्क पशु चिकित्सा योजनान्तर्गत वितरित दवाइयां

223. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री नि:शुल्क पशु चिकित्सा योजनान्तर्गत पशुओं के लिए नि:शुल्क दवाइयां दी जा रही हैं? यदि हां, तो कब से एवं इस हेतु कितनी-कितनी राशि फरवरी, 2017 तक आवंटित की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत फरवरी, 2017 तक बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में किस-किस चिकित्सालय/ पशु चिकित्सा उप केन्द्रों पर कितनी-कितनी राशि की कौन-कौनसी दवाइयां उपलब्ध करवाई गयी एवं कितनी-कितनी वितरित की गयी तथा इससे कितने पशुओं को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना (पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना) दिनांक 15 अगस्त 2012 को प्रारंभ की गयी है। इस योजना अन्तर्गत वर्षवार आवंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	**आवंटित राशि लाखों में (आयोजना एवं आर.के.वी.मद सहित)**
2012-13	4303.54
2013-14	5874.78
2014-15	5439.06
2015-16	3605.21
2016-17	5059.63

(2) पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की पशु चिकित्सा संस्थाओ को उपलब्ध करवाई गई औषधियां एवं उनकी राशि का विवरण परिशिष्ट- 1 पर संलग्न है।

(पशु पालन मंत्री)

पशु चिकित्सा संस्थाओं को उपलब्ध करवाई गयी औषधियों का उपयोग पशु चिकित्सा संस्थाओं एवं पशु चिकित्सा शिविरों में आने वाले बीमार पशुओं की पशु चिकित्सा हेतु आवश्यकता अनुसार किया जाता है।

विधानसभा क्षेत्र बिलाडा की पशु चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से की गयी पशु चिकित्सा से लाभान्वित पशुपालकों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा के भवन विहीन पशु चिकित्सालय

324. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के भवनहीन पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा के क्षतिग्रस्त पशु चिकित्सालय भवनों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के पशु चिकित्सालयों के भवन की स्थिति निम्नानुसार हैं:-

(अ) प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	**वर्तमान में भवन की स्थिति**
1 मालपुरा	राजकीय भवन
2 टोडारायसिंह	राजकीय भवन
3 डिग्गी	पंचायत भवन
4 लाम्बा हरिसिंह	पंचायत भवन
5 मोर	पंचायत भवन
6 उनियारा खुर्द	राजकीय भवन

(पशुपालन मंत्री)

(ब) पशु चिकित्सालय	वर्तमान में भवन की स्थिति
1 पचेवर	राजकीय भवन
2 लावा	राजकीय भवन
3 पारली	पंचायत भवन
4 टोरडी	पंचायत भवन
5 पंवालिया	पंचायत भवन
6 आवडा	पंचायत भवन
7 कलमण्डा	राजकीय भवन
8 नगर	पंचायत भवन

विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के समस्त पशु चिकित्सालय राजकीय/पंचायत भवन में संचालित हैं। पशु चिकित्सालय के नये भवन निर्माण विभाग के नाम भूमि के पट्टे एवं वित्तीय उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से करवाये जाते है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के क्षतिग्रस्त पशु चिकित्सालय के भवनों की मरम्मत वित्तीय उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से करवाई जाती है।

जोधपुर जिले में मृदा जांच हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना

325. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में प्रत्येक किसान के खेत की मृदा जांच करके मृदा कार्ड जारी किये जा रहे हैं? यदि हां, तो जोधपुर जिले में कितने किसानों को कार्ड जारी किये गये हैं व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में मृदा जांच हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो अब कब तक स्थापित कर दी जाएंगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा जारी नार्म्स के अनुसार सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रों में 2.5 हैक्टेयर तथा असिंचित क्षेत्रों में 10.00 हैक्टेयर इकाई क्षेत्र से एक-एक प्रतिनिधित्व नमूना एकत्रित किये जाकर, उस इकाई क्षेत्र की समस्त कृषि जोत को सॉयल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जोधपुर जिले में फरवरी, 2017 तक 01 लाख 10 हजार सॉयल हैल्थ कार्ड किसानों को नि:शुल्क वितरित किये गये।

(2) जोधपुर जिला मुख्यालय पर एक मृदा परीक्षण एवं एक क्षारीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त जोधपुर जिले में फलौदी तथा बिलाड़ा में नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं, जो कि आउट सोर्स के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस प्रकार जोधपुर जिले में कुल 04 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं ।

उदयपुर जिले में वनों को विकसित करने हेतु लगाये गये पौधे

326. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वनों को विकसित करने के लिये पौधे लगाये जातेम्स? यदि हां, तो गत 2 वर्षों में उदयपुर जिले में कितने पौधे कहां-कहां लगाये गये तथा उनमें से कितने पौधे वर्तमान में जीवित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। उदयपुर जिले में गत 2 वर्षों में लगाये गये पौधों एवं उनकी जीवितता संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट "ए" अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मण्डावर (दौसा) की वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

327. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले के ग्राम मण्डावर के वन क्षेत्र

(डा. किरोड़ी लाल)

भूमि के खसरा नं. 1 एम.ई. पर अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लिया है? यदि हां, तो किसने तथा कब?

(2) क्या यह भी सही है कि न्यायालय सहायक वन संरक्षक महवा द्वारा दिनांक 27.10.2016 को अपने निर्णय में वन भूमि से बेदखली के आदेश दिए है? यदि हां, तो अब तक उक्त भूमि से अतिक्रमियों को बेदखल नहीं किए जाने के क्या कारण है?

(3) क्या यह भी सही है कि वन भूमि के उक्त खसरे में एक ट्यूबवैल भी स्थापित कर दिया गया है, जिसे चोरी की बिजली से चलाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्यूबवैल को स्थाई रूप से बन्द कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम मण्डावर के वन क्षेत्र के खसरा नं. 1 एमई में लगभग 2 वर्ष पूर्व अतिक्रमण कर श्री सुरेश बागडी पुत्र श्री रामचरण मीणा निवासी मण्डावर द्वारा पक्का मकान बनाया गया।

(2) जी हां। न्यायालय सहायक वन संरक्षक, महवा में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 26.11.2015 को दर्ज प्रकरण में न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.10.16 में अतिक्रमी की वन भूमि से बेदखली व रु. 500/- शास्ति वसूली के आदेश दिये गये। अतिक्रमी द्वारा दायर एक वाद में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, महवा द्वारा दिनांक 10.11.16 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादियों को वादी की कब्जाशुदा आराजी के उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत आदेशित किया गया है इसलिए विभाग द्वारा अभी तक बेदखली की कार्यवाही नहीं की गयी है।

(3) वन क्षेत्र के उक्त खसरा में ग्राम पंचायत, मण्डावर द्वारा एकल बिन्दु योजना में ट्यूबवैल स्थापित किया गया है। उक्त ट्यूबवैल वर्तमान में बन्द है एवं इसका विद्युत संबंध जेवीवीएनएल से विच्छेदित करवा दिया गया है।

जयपुर जिला क्रीडा परिषद के आय-व्यय का विवरण

328. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला क्रीडा परिषद जयपुर सहकारी संस्था अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है? यदि हां, तो कब से? पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं क्रीडा परिषद के संविधान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्रीडा परिषद के कार्मिकों व सेवा निवृत्त सचिव/अधिकारियों/ कर्मचारियों को वेतन भत्ते/पेंशन/चिकित्सा पुनर्भरण आदि का भुगतान जिला क्रीडा परिषद द्वारा स्वयं के संसाधनों से अर्जित आय में से ही किया जाता है? यदि हां, तो जिला क्रीडा परिषद के गत पांच वर्षों के आय व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला क्रीडा परिषद जयपुर के जनवरी 2015 से जनवरी 2017 तक के रोकड़ बही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिला क्रीडा परिषद के सेवा निवृत्त सचिव को जनवरी 2016 व जुलाई 2016 में देय मंहगाई भत्ते का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व कितना व नहीं, तो क्यों तथा अब उक्त भत्ते का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

(5) क्या यह भी सही है कि जिला क्रीडा परिषद जयपुर के सेवा निवृत्त सचिव द्वारा परिषद में चिकित्सा पुनर्भरण के बिल प्रस्तुत किये गये है? यदि हां, तो कब- कब व कितनी-कितनी राशि के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि सेवा निवृत्त सचिव के उक्त चिकित्सा बिलों का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला क्रीडा परिषद, जयपुर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दिनांक 20 अगस्त 1991 से पंजीकृत है। पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं संविधान की प्रति परिशिष्ट क एवं ख पर संलग्न है।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

(2) जिला क्रीडा परिषद, जयपुर के नियमित कार्मिकों के वेतन, चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण का भुगतान एवं सेवानिवृत सचिव को पेंशन का भुगतान जिला क्रीडा परिषद, चौगान स्टेडियम की अर्जित आय से किया जा रहा है।

जिला क्रीडा परिषद, चौगान स्टेडियम, जयपुर की गत पांच वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की आय एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(3) जिला क्रीडा परिषद, जयपुर के जनवरी, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की रोकड बही की प्रतियां परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला क्रीडा परिषद, जयपुर के पत्रांक 66 दिनांक 10.03.2016 के द्वारा चौगान स्टेडियम की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए चौगान स्टेडियम की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के अधीन की गयी है। अत: दिनांक 01.04.2016 से चौगान स्टेडियम, जयपुर की अर्जित आय-व्यय का इन्द्राज जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, चौगान स्टेडियम, जयपुर की रोकड बही में किया जा रहा है।

(4) सेवानिवृत्त सचिव को माह जनवरी व जुलाई, 2016 के बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला क्रीडा परिषद, जयपुर के पत्रांक 66 दिनांक 10.03.2016 के द्वारा चौगान स्टेडियम की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए चौगान स्टेडियम की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के अधीन की गयी है।

(5) सेवानिवृत्त सचिव, जिला क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा स्वयं एवं पत्नी के राशि रुपये 1,22,664/- के चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये थे जिन्हें राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के सम्मुख भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये परन्तु राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद में सेवानिवृत्त कार्मिकों का चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण की सुविधा नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

(6) जी नहीं।

जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला क्रीडा परिषद, जयपुर के पत्रांक 66 दिनांक 10.03.2016 के द्वारा चौगान स्टेडियम की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए चौगान स्टेडियम की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के अधीन की गई है।

सेवानिवृत्त सचिव, जिला क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा स्वयं एवं पत्नी के राशि रुपये 1,22,664/- के चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये थे। जिन्हें राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के सम्मुख भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये, परन्तु राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद में सेवानिवृत्त कार्मिकों का चिकित्सा बिलो के पुनर्भरण की सुविधा नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा बाघ संरक्षण हेतु उपलब्ध कराई गयी राशि

329. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में केन्द्र सरकार द्वारा बाघ संरक्षण के लिए कितनी राशि राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई गयी एवं उसमें से कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा अपने कोष से कितनी राशि का प्रावधान वन्य जीव संरक्षण हेतु उपरोक्त वित्तीय वर्षों में किया गया एवं उसमें से कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य के अभयारण्यों में बाघों की मौत का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं सरकार बाघ संरक्षण हेतु क्या कारगर कदम कब तक उठायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में वर्ष 2011 से 2017 के मध्य कुल कितने बाघों की मौत हुई व उन मौतों के क्या कारण रहे तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा बाघ संरक्षण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में उपलब्ध कराई गई राशि एवं व्यय की गयी राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अपने कोष से वन्य जीव संरक्षण हेतु वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में क्रमशः 2733.36 व 3680.41 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गयी। वर्ष 2015-16 में इसमें से 2695.79 लाख रुपये तथा 2016-17 में फरवरी, 2017 तक 1402.01 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार बाघ संरक्षण हेतु सतत रूप से प्रयत्नशील है। बाघ परियोजना रणथम्भौर के लिए एक विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन किया जा चुका है। सरिस्का व मुकन्दरा के लिए भी विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(4) वर्ष 2011 से 2017 की अवधि में बाघों की मौत सबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है। प्रश्नगत अवधि में बाघों की मौत मुख्यत: प्राकृतिक कारणों से ही हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक से गलोद जाने वाले रास्ते पर क्षतिग्रस्त रपट का पुनर्निर्माण

330. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध से छोड़े गये वर्षा के पानी के कारण बनास नदी में टोंक से गलोद जाने वाले रास्ते पर बनाया गया रपट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है तथा लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक उक्त क्षतिग्रस्त रपट का पुनर्निर्माण करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि टोंक से खुरेड़ा एवं ढूंढ़िया से नाथड़ी तक की सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण आमजन को आवागमन में काफी परेशानी हो

(श्री अजीत सिंह)

रही है? यदि हां, तो उक्त सड़कों की मरम्मत कब तक करवा दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बीसलपुर बांध से छोड़े गये वर्षा के पानी के कारण टोंक से गलोद सड़क पर बनाया गया रपट क्षतिग्रस्त हो चुका है, विभाग द्वारा अस्थाई रूप से निर्माण कर, यातायात प्रारम्भ कर दिया है। स्थाई रपट का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) जी हां।

1. ढूंढ़िया से नाथड़ी 2 किमी. सड़क के नवीनीकरण हेतु आर.आई.डी.एफ.-22 में राशि रु. 40.00 लाख की स्वीकृति है। जिसकी निविदा प्राप्त कर कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। जो जून, 2017 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।
2. टोंक से गहलोद खूरेड़ा 10 किमी. सड़क क्षतिग्रस्त है। इसका पुनर्निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

बाड़ी पंचायत समिति के ग्राम दादुर से घड़ी खिराना तक सड़क का निर्माण

331. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की पंचायत समिति बाड़ी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम दादुर से घड़ी खिराना तक (लगभग 1 किमी) आवागमन हेतु कोई पक्का सड़क मार्ग नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार दादुर से घड़ी खिराना तक पक्की सड़क बनवाये जाने का विचार रखती हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की पंचायत समिति बाड़ी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम दादुर (840) व घड़ी खिराना (273) अन्य डामर सड़कों से जुड़े हुए हैं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इन दोनों गांवों को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

प्रदेश के डाक बंगलों को पी.पी.पी. मोड पर देने की योजना

332. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के डाक बंगलों को पी.पी.पी. मोड़ पर देने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रदेश के कौन-कौनसे डाक बंगलों को पी.पी.पी. मोड़ पर देने का निर्णय लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त डाक बंगलों को पी.पी.पी. मोड़ पर देने हेतु क्या शर्तें एवं अहर्ताएं निर्धारित की गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पी.पी.पी. मोड़ पर डाक बंगलें देने पर आम जन को भी डाक बंगलों में ठहरने की सुविधा दी जाएंगी? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डाक बंगलों का बेहतर संचालन व रखरखाव करने हेतु सा.नि.वि. द्वारा चुनिन्दा डाक बंगलों को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड़ पर देने का निर्णय किया गया है ताकि इनमें ठहरने वाले लोगों को समुचित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्न 11 डाक बंगलों को पीपीपी मोड पर देने का विचार रखती है:-

1. अजमेर 2. भीलवाड़ा 3. भरतपुर 4. बीकानेर 5. जयपुर 6. अलवर 7. जोधपुर 8. जैसलमेर 9. माउण्ट आबू (देलवाडा) 10. उदयपुर 11. नाथद्वारा (राजसमन्द)

(3) प्रथम चरण में अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, अलवर, जैसलमेर एवं नाथद्वारा के डाक बंगलों को पीपीपी मोड पर दिये जाने हेतु निविदाएं

आमंत्रित की गयी थीं। इन डाक बंगलों के शर्तें एवं अर्हताएं परिशिष्ट-1 से 6 पर संलग्न है।

(4) पीपीपी मोड पर डाक बंगले दिये जाने से आम जन को भी डाक बंगलों में ठहरने की सुविधा दी जाएगी। इसके अन्तर्गत पीपीपी मोड पर डाक बंगलों को लेने वाली रियायतीकार फर्म अपना पैसा खर्च कर डाक बंगलों में अतिरिक्त निर्माण/पुनरुद्धार एवं उनका संधारण करेगी जिसकी वसूली आम लोगों को डाक बंगलों में ठहरने की सुविधा प्रदान कर होने वाली आय से की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत के गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत सड़क से जोड़ने की योजना

333. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2013 से 2016 तक पाली जिले के सोजत व रायपुर में कौन-कौनसे गांवों को सड़कों से जोड़ा गया? सड़कवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत सोजत विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौनसे गांवों को सड़कों से जोडा़ गया? ग्रामवार सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कौनसी सड़कें हैं जो वर्तमान में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जोडा़ जाना प्रस्तावित हैं? सड़कवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की वंचित ग्राम पंचायतों को मुख्य सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में वर्ष 2013 से 2016 तक पाली जिले के सोजत तथा रायपुर में 14 गांवों को सड़क से

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जोड़ा गया है। सड़कवार सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) प्रधानमंत्री सड़क योजना में सोजत विधान सभा क्षेत्र में 9 गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा गया है। ग्रामवार सड़कों की सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) सोजत विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में वर्ष 2016-17 में 1 पात्रता रखने वाली सड़क प्रस्तावित होकर स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(4) सोजत विधान सभा क्षेत्र में कुल 50 ग्राम पंचायतें हैं, तथा सभी 50 ग्राम पंचायतें डामर सड़क से जुड़ी हुई हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नसीराबाद के निगम बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय

334. श्री रामनारायण (नसीराबाद): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो उक्त बस सेवा से वंचित हैं? सरकार द्वारा उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को कब तक यह सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण निगम सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को फिलहाल जोड़े जाने का कोई विचार नहीं है।

(परिवहन मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की निगम बस सेवा से जुड़ी एवं वंचित ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है:-

पंचायत समिति	कुल ग्राम पंचायत	निगम परिवहन सेवा से जुड़ी ग्राम पंचायत	निगम परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायत
पीसांगन	29	18	11
श्रीनगर	17	14	03
योग	46	32	14

निगम के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के निगम बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बृजवाटिका जगतपुरा (जयपुर) में पेयजल की व्यवस्था

335. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बृजवाटिका गोनेर रोड जगतपुरा जयपुर में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा ऐसी कालोनियों में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण टैंकरों द्वारा भी पानी सप्लाई किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त कालोनी में अब तक भी टैंकरों से पानी की आपूर्ति नहीं की गयी है? हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त कालोनी को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़कर पानी आपूर्ति कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

(4) क्या सरकार गर्मी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उक्त कालोनी में पानी की टंकियां रखकर टैंकरों से प्रतिदिन पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर के जगतपुरा क्षेत्र की गोनेर रोड स्थित बृजवाटिका कालोनी एवं इसके आस-पास क्षेत्र में पर्याप्त भू-जल की उपलब्धता नहीं होने के कारण वर्तमान में विभागीय पेयजल व्यवस्था नहीं है। उक्त कालोनी सहित जगतपुरा, प्रताप नगर एवं महल रोड के आस-पास के क्षेत्र को बीसलपुर पेयजल परियोजना से लाभान्वित करने के उद्देश्य से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु विभागीय नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 के द्वारा राशि रुपये 152.02 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी। इस स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य को तीन पैकेजों में विभक्त किया जाकर पैकेजवार प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) पैकेज संख्या 1:- जवाहर सर्किल पम्पिंग स्टेशन पर 3 पम्पिंग सैट्स बदलने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

(ब) पैकेज संख्या 2:- मुख्य परिवहन पाइप लाइन, राइजिंग मेन तथा परियोजना सीमा पर रिंग मेन पाइप लाइन बिछाने व जोड़ने के कार्य हेतु बनाये गये संशोधित तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व तकनीकी जांच प्रक्रिया में हैं।

(स) पैकेज संख्या 3:- पम्प हाऊस एवं विभिन्न जलाशयों के निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 14.08.2014 को राशि रुपये 48.99 करोड़ का जारी किया गया था परन्तु फर्म द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण कार्यादेश को दिनांक 12.10.2015 को निरस्त किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर खण्डपीठ द्वारा दिनांक 12.07.2016 को पारित निर्णय एवं विभागीय वित्त समिति की 713वीं बैठक दिनांक 21.12.2016 को लिये गये निर्णय की पालना में उक्त कार्य को प्रारम्भ करने हेतु

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

दिनांक 13.01.2017 को पूर्व में जारी कार्यादेश दिनांक 14.08.2014 को बहाल किया गया। इस पैकेज का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा यह कार्य दो वर्ष में पूर्ण करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में पेयजल वितरण तंत्र विकसित करने हेतु राशि रुपये 89.19 करोड़ की बनाई गयी योजना के प्रस्तावों पर विभागीय तकनीकी समिति की 649वीं बैठक दिनांक 08.02.2017 द्वारा तकनीकी सहमति जारी की गयी है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जाकर क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाएंगा।

(2) बृजवाटिका कालोनी एवं इसके आस-पास क्षेत्र के स्थानीय निवासियों द्वारा टैंकरों के माध्यम से जल परिवहन की विभाग से मांग नहीं किये जाने के कारण वर्तमान में विभागीय जल परिवहन द्वारा खुले जल वितरण का कार्य नहीं किया जा रहा है।

(3) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार।

(4) जी हां। जगतपुरा एवं आस-पास के क्षेत्र जो विभागीय पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से वर्तमान में जुड़े हुए नहीं हैं, में तात्कालिक उपायों के अन्तर्गत पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2000 लीटर जल भण्डारण क्षमता के 100 पी.वी.सी. टैंक के स्थापना कार्य हेतु दिनांक 28.06.2016 को राशि रुपये 39.83 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। इस कार्य के निष्पादन हेतु दिनांक 04.10.2016 को कार्यादेश जारी किया जाकर अब तक क्षेत्र में 23 टैंक स्थापित किये जा चुके हैं। बृजवाटिका कालोनी सहित जगतपुरा क्षेत्र के वार्ड संख्या 48 के कुछ स्थानों पर पी.वी.सी. टैंक के स्थापना कार्य हेतु स्थानीय विधायक के पत्र दिनांक 02.03.2017 द्वारा विभाग को प्रस्तुत मांग को दृष्टिगत रखकर फिजिबिलिटी के अनुसार टैंक स्थापना का कार्य शीघ्र पूर्ण करना अपेक्षित है।

सुशीलपुरा, अजमेर रोड, सोड़ाला को बीसलपुर योजना से जोड़ने की कार्यवाही

336. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर के अजमेर रोड, सोड़ाला में सरकार द्वारा किन-किन कालोनियों को बीसलपुर पेयजल योजना से पानी सप्लाई किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सुशीलपुरा (बड़ा गांव), अजमेर रोड, सोड़ाला को बीसलपुर पेयजल योजना से अब तक नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 में सुशीलपुरा कालोनी में पाइप लाइन डालकर बीसलपुर पेयजल योजना से पानी सप्लाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में अजमेर रोड स्थित सोड़ाला क्षेत्र में बीसलपुर पेयजल परियोजना से लाभान्वित कॉलोनियों संबंधी विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सोड़ाला रोड स्थित सुशीलपुरा कालोनी क्षेत्र बीसलपुर पेयजल परियोजना के तहत विभाग के शांतिनगर हैडवर्क्स स्थित उच्च जलाशय से वर्तमान में जुड़ा हुआ है। यह कालोनी उक्त उच्च जलाशय से दूरी लगभग 3.0 किलोमीटर है तथा अंतिम छोर पर स्थित होने के कारण इस उच्च जलाशय से इस कॉलोनी के आंशिक क्षेत्र में वर्तमान में कम दबाव से पेयजल आपूर्ति हो पाती है। इसके अतिरिक्त कालोनी में निर्मित 8 नलकूपों से उच्च जलाशय से पेयजल आपूर्ति के समय एवं इसके उपरान्त भी सीधे पेयजल भी आपूर्ति की जा रही है।

(3) बीसलपुर परियोजना अंतर्गत सुशीलपुरा कालोनी में सम्पूर्ण दबाव से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक पाइप लाइनें एवं नवीन

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

पम्पिंग मशीनरी का प्रावधान लेते हुए प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। सक्षम स्तर पर इन प्रस्तावों के प्राप्त होने एवं इनके तकनीकी परीक्षण उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृति पर विचार किया जाएंगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले के गांवों में पेयजल आपूर्ति की योजनाएं

337. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त योजनाओं पर किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नागौर जिले में वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही है तथा उक्त योजनाओं से कितने गांवों/ढाणियों को लाभांवित किया जा रहा है व गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निम्न मुख्य पेयजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण किया जा रहा है:-

(अ) पाइप्ड जल योजनाएं (वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 4000 से अधिक जनसंख्या हेतु)

(ब) क्षेत्रीय जल योजनाएं (दो या दो से अधिक गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों हेतु)

(स) पम्प एवं टैंक जल योजनाएं (वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 1500 से अधिक एवं 4000 तक की जनसंख्या हेतु) तथा

(द) हैण्डपम्प योजनाएं (वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 1500 तक की जनसंख्या हेतु)

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

प्रदेश में अब तक 53 वृहत् पेयजल परियोजनाएं पूर्ण की जाकर 24 शहर/कस्बों, 3181 ग्रामों तथा 1498 ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 54 प्रगतिरत वृहत् पेयजल परियोजनाओं से माह दिसम्बर, 2016 तक 22 शहरों, 1926 ग्रामों तथा 1741 ढाणियों को लाभान्वित किया गया है।

(2) वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 (माह फरवरी, 2017 तक) की अवधि में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं अंतर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) नागौर जिले में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 1575 ग्राम विभिन्न जल योजनाओं से लाभान्वित हैं। इसके अतिरिक्त जिले की 3216 चिन्हित ढाणियां को भी अब तक लाभान्वित किया गया है। योजनावार लाभान्वित ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 (माह फरवरी, 2017 तक) की अवधि में नागौर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं (वृहत् पेयजल परियोजना के अतिरिक्त अन्य योजनाएं) में पूंजीगत एवं संधारण मद में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त वृहत् पेयजल परियोजनाओं अंतर्गत नागौर लिफ्ट परियोजना के प्रथम चरण के आधारभूत संरचना कार्यों के पैकेज संख्या 1 तथा पैकेज संख्या 2 (नागौर जिले के 167 गांवों तथा नागौर एवं बासनी कस्बे को लाभान्वित करना) अंतर्गत योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनमें से 166 ग्राम तथा नागौर एवं बासनी कस्बे को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इस परियोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 (माह फरवरी, 2017 तक) की अवधि में पूंजीगत मद में रुपये 45.04 करोड़ एवं संचालन मद में रुपये 4.106 करोड़ की राशि व्यय हुई है।

साबरमती लघु सिंचाई परियोजना में अनुपयोगी व्यय पर कार्यवाही

338. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगसी राम)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उदयपुर जिले में 956.65 हैक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए साबरमती नदी पर लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 10.23 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2011 में जारी कर लगभग 9 करोड़ रुपये व्यय करने के उपरान्त भी उक्त योजना का लाभ अब तक किसानों को नहीं मिल सका है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बिना जमीन उपलब्धता के बनाई गई साबरमती लघु सिंचाई परियोजना में राशि रु. 9 करोड़ का अनुपयोगी व्यय करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सी. ए. जी. रिपोर्ट में भी सरकार द्वारा किए गये 9 करोड़ रु. के व्यय को सरकारी धन के अविवेकपूर्ण लोक महत्व में अनुपयोगी करार देते हुए, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की अभिशंसा की गयी है? यदि हां, तो सी.ए.जी. रिपोर्ट की प्रति व उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला उदयपुर में साबरमती नदी पर लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु राशि रुपये 10.23 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2001 के दौरान तथा संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 29.83 करोड़ की वर्ष 2011 के दौरान जारी की गयी। जारी संशोधित स्वीकृति के विरुद्ध मार्च 2014 तक परियोजना पर राशि रुपये 9.08 करोड़ का व्यय किया गया, जिसमें से बांध निर्माण पर संवेदक को राशि रुपये 3.89 करोड़ एवं 4.81 करोड़ मुआवजा का भुगतान किया गया था।

बांध पर किये गये राशि रुपये 9.08 करोड़ के व्यय के क्रम में ही बांध निर्माण पर कुल रुपये 17.58 करोड़ का व्यय कर कार्य नवम्बर 2015 के दौरान पूर्ण किया जाकर वर्ष 2015 एवं 2016 के दौरान पानी का संग्रहण कर अप्रत्यक्ष लाभ अर्जित किया गया है।

(2) साबरमती लघु सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु भूमि

(जल संसाधन मंत्री)

अवाप्ति संबंधित पारित अवार्ड राशि का भुगतान भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटड़ा को जुलाई, 2007 के दौरान ही किये जाने पर वर्ष 2009 के दौरान भूमि का नामान्तरण विभाग के नाम दर्ज किये जाने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित कर बांध निर्माण कार्य 28.11.2011 को प्रारम्भ कर 30.11.2015 को पूर्ण किया गया। योजना निर्माण में देरी के लिये अति. मुख्य अभियंता जल संसाधन, जोधपुर द्वारा जांच के आदेश जारी किये जा चुके है, रिपोर्ट प्राप्ति पर तदानुसार कार्यवाही की जाएंगी।

(3) सी.ए.जी.के वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.4 में फरवरी, 2013 से अधिकारीयों के विरुद्ध कार्यवाही की अभिशंसा नही की गयी। अपितु संवीक्षा टिप्पणी "कार्य आवंटन से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नही की गयी जिससे कार्य पूर्ण होने में देरी हुई तथा लाभार्थियों को सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ा" का उल्लेख किया गया है, सी.ए.जी. रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" एवं अनुपालना की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की नदियों को जोड़ने की कार्ययोजना

339. श्री नवीन पिलानिया (आमेर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी की स्थापना किस उद्देश्य से की गयी थी?

(2) क्या उक्त एजेन्सी ने जल बहुल नदी घाटियों का जल शुष्क क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से (नदियों को जोड़ने की योजना) राजस्थान से संबंधित कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना से राजस्थान को कितना जल उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा इससे किस-किस क्षेत्र में कितनी-कितनी भूमि सिंचित हो सकेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश से संबंधित नदियों को जोड़ने की योजना (राजस्थान एवं गुजरात लिंक) के लिए योजना का आकार समुचित बनाने तथा अधिक से अधिक जल

(श्री नवीन पिलानिया)

उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कब-कब क्या-क्या प्रयास किए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रदेश से संबंधित नदियों को जोड़ने की योजना को शीघ्र लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से कब-कब सम्पर्क कर क्या-क्या प्रयास किए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना 17 जुलाई, 1982 में भारत सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में जल संसाधन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए की गयी थी।

(2) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरंक्षण मंत्रालय के द्वारा तैयार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंर्तगत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 लिंकों (प्रायद्वीपीय घटक के अधीन 16 तथा हिमालय नदी विकास घटक के अधीन 14) की पहचान की गयी है| 30 लिंकों में राजस्थान से संबंधित हिमालय नदी विकास घटक के अधीन दो लिंक क्रमश: यमुना-राजस्थान लिंक एवं राजस्थान-साबरमती लिंक है तथा प्रायद्वीपीय घटक के अधीन एक पार्बती-कालीसिंध-चम्बल लिंक प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(3) प्रदेश में संबंधित योजना से परिकल्पित जल की मात्रा एवं लाभान्वित क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट-"अ" में अंकित है।

(4) शारदा नदी के पानी को लाभान्वित राज्यों तक शीघ्र पहुंचाने हेतु किये गये प्रयास के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा लिखे पत्र की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(5) प्रदेश से संबंधित नदियों को जोड़ने हेतु किये गये प्रयासों के अन्तर्गत भारत सरकार को पत्रों का विवरण परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कमाण्ड एरिया में राजस्व वसूली के नियम

340. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली 'उनियारा में कौन-कौनसे ग्राम कमाण्ड एरिया में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कमाण्ड एरिया में राजस्व वसूलने के क्या नियम निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा में कमाण्ड एरिया में आने वाले ग्रामों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कमाण्ड एरिया में राजस्व सिंचाई कर वसूलने संबंधी नियम, राजस्थान ईर्रिगेशन एण्ड ड्रेनेज एक्ट 1954 व राजस्थान सिंचाई एवं ड्रेनेज नियम 1955 के नियम 40-50 में वर्णित वसूली प्रक्रिया अनुसार समय-समय पर जारी सिंचाई दरों पर वसूला जाता है, नियम की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बून्दी जिले में अनुज्ञापत्रधारी राशन विक्रेता

341. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या खाद्‌य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बून्दी जिले में कुल कितने राशन विक्रेता अनुज्ञापत्रधारी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार एक अनुज्ञापत्रधारी के पास एक से अधिक अटैचमेन्ट हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले में वर्तमान में सभी अनुज्ञापत्रधारी पी.ओ.एस. मशीनों के माध्यम से ही राशन सामग्री का वितरण कर रहे हैं? यदि नहीं, तो योजना लागू होने के बाद इसके उल्लंघन के कितने प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में वर्तमान में 400 राशन विक्रेता अनुज्ञापत्रधारी है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 23.08.2016 के बिन्दु संख्या-3 में यह उल्लेख है कि जिले में किसी भी उचित मूल्य दुकान पर एक से अधिक उचित मूल्य दुकान को सम्बद्ध (अटैच) नहीं किया जाए। जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) बून्दी जिले में वर्तमान में 396 अनुज्ञापत्रधारी पास मशीन के माध्यम से राशन वितरण कर रहे है। 04 उचित मूल्य दुकान पर नैटवर्क की समस्या होने के कारण पास मशीन के स्थान पर रजिस्टर से वितरण किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकानदार का नाम
1.	हिण्डोली	आकोदा II	श्रीमती राधाबाई
2.	नैनवा	पीपल्या III	श्री रामस्वरूप मीणा, लुहारपुरा
3.	नैनवा	पीपल्या II	श्री धनपाल मीणा, मोतीपुरा
4.	नैनवा	पीपल्या I	ग्राम सेवा सहकारी समिति, पीपल्या

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 342

(स्थगित)

प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण

343. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक किस-किस जिला रसद अधिकारी द्वारा कब-कब, किस-किस उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में उक्त अवधि में निरीक्षण में किस-किस उचित मूल्य की

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

दुकान में क्या-क्या खामियां एवं अनियमितताएं पायी गयी व उक्त दुकानों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण के मापदण्ड निर्धारित किये हुए है। निर्धारित मापदण्डों के संबंध में आदेश दिनांक 14.10.2009 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में 01 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 जिला रसद अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के किये गये निरीक्षणों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में उक्त अवधि में उक्त निरीक्षणों में पाई गयी अनियमितताओं एवं दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 में सम्मिलित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत जारी गैस कनेक्शन

344. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में अब तक कुल कितने गैस कनेक्शन जारी किए गये एवं कितने शेष हैं? विधान सभा क्षेत्रवार लाभान्वितों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत पात्र परिवारों का चयन का आधार क्या रहा व चयन किस वर्ष किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पात्र चयनित परिवारों के अतिरिक्त अन्य परिवारों को भी उक्त योजनान्तर्गत गैस कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त सूचना

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

अनुसार अजमेर जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में कुल 36560 लोगों के केवाईसी फार्म रजिस्टर किए गये हैं, जिनमें से कुल 32550 लोग पात्र पाये गये है, जिनमें से कुल 20761 को गैस कनेक्शनों का वितरण किया जा चुका है एवं 11789 शेष हैं। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माह अगस्त, 2016 से अजमेर जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरण बन्द कर दिया गया है।

लाभान्वितों की संख्या सूची निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	**नाम क्षेत्र**	**प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत कुल जारी गैस कनेक्शनों की संख्या**			
		एचपीसी	**बीपीसी**	**आईओसी**	**कुल**
1.	अजमेर उत्तर	24	233	1431	1688
2.	पुष्कर	1106	0	749	1855
3.	ब्यावर	1	0	1344	1345
4.	किशनगढ़	1641	0	0	1641
5.	नसीराबाद	584	807	852	2243
6.	अजमेर दक्षिण	594	824	1214	2632
7.	मसूदा	168	2619	2433	5220
8.	केकडी	0	4137	0	4137
	कुल	**4118**	**8620**	**8023**	**20761**

(2) उक्त योजनान्तर्गत पात्र परिवारों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (SECC) 2011के आधार पर किया गया है। सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना, 2011 ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासीय एवं नगरीय गरीबी उन्मूलन विभाग, महापंजीयक एवं आयुक्त, जनगणना, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सहयोग के माध्यम से की गयी थी।

(3) कुछ ऐसे परिवार जो वास्तव में पात्रता रखते है, परन्तु किन्ही कारणों से उनका नाम पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गयी SECC लिस्ट में नहीं आ पाया है, तो उन्हें संबंधित जिला कलक्टर के कार्यालय में सम्पर्क करना

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

चाहिए। गैस वितरक द्वारा ऐसे प्रार्थियों का विवरण अपने डेटाबेस में "On hold" रखा जाएंगा, जब तक के वो SECC सूची में प्रतिबिम्बित नहीं होता।

परबतसर (नागौर) के तेजाजी मन्दिर के विकास हेतु आवंटित राशि

345. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि परबतसर (नागौर) में तेजाजी महाराज का मन्दिर स्थित है? यदि हां, तो क्या उक्त मन्दिर के पुन:निर्माण/पुनरूत्थान हेतु कोई मन्दिर विकास समिति बनी हुई है? हां, तो उक्त समिति में कौन-कौन सदस्य हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त मन्दिर के विकास के लिए राशि उपलब्ध करवा रही है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री वीर तेजाजी का मंदिर परबतसर, जिला-नागौर में स्थित है। यह मंदिर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत् पंजीकृत प्रन्यास है। मंदिर के निर्माण/पुनरूत्थान कार्य हेतु जिला कलेक्टर नागौर की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है जिसमें निम्न सदस्य हैं:-

I. उपाध्यक्ष- संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, क्षेत्र अजमेर पदेन अध्यक्ष

II. सदस्य सचिव- उपसहायक निदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामन सिटी, प्रदेन सदस्य /सचिव

III. कोषाध्यक्ष- उपकोषाधिकारी, परबतसर, पदेन कोषाध्यक्ष

IV. सदस्य:-

1. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. परबतसर
2. जिला पशुपालन अधिकारी, कुचामन सिटी,
3. सदस्य राजस्थान विधानसभा क्षेत्र परबतसर (विधायक)

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

4. अध्यक्ष, नगर पालिका, परबतसर

5. प्रधान, पंचायत समिति, परबतसर

(2) जी नहीं। श्री वीर तेजाजी का मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर नहीं होकर पंजीकृत प्रन्यास है। ट्रस्टों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

प्रदेश के लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों का पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों में क्रमोन्नयन

346. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्षों में प्रदेश के कितने लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों में क्रमोन्नत किया गया तथा इस हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित है?

(2) वर्तमान में प्रदेश में ऐसे कितने लघु आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनमें छात्र संख्या पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र के अनुरूप है, लेकिन उनको क्रमोन्नत किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तीन वर्षो में प्रदेश के एक भी लघु आंगनबाड़ी केन्द्र को पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों में क्रमोन्नत नहीं किया गया। जनसंख्या के मापदण्ड पूर्ण करने वाले लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्थान पर पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को पत्र लिखा गया है, जिसकी प्रति परिशष्ट "अ" पर संलग्न हैं। मिनी केन्द्रों आंगनबाड़ी केन्द्रों में क्रमोन्नत करने के लिए कोई मानदण्ड नहीं है। नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु मानदण्ड परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में प्रदेश में 566 लघु आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है जो जनसंख्या के आधार पर पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र की पात्रता रखते हैं, जिनको पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में स्वीकृति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

पत्र लिखा गया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा के नये वार्डों में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

347. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद क्षेत्र, दौसा एवं ग्रामीण क्षेत्र में वार्ड बन जाने के बाद वहां आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नए वार्डों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का मानदण्ड राजस्व ग्राम एवं वार्ड ना होकर जनसंख्या है। नगर परिषद दौसा में वर्तमान में 40 वार्ड हैं, जिनमें 40 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। नगर परिषद दौसा में पुनर्सीमांकन के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों को नामित किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में दौसा ग्रामीण क्षेत्र में 16 नवीन केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) मांग पर आधारित आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र एवं नोर्म्स के अनुसार प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली में आवंटित खनन पट्टे

348. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री दलीचन्द डांगी)

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में खान आवंटन हेतु नियम निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली में किस क्षेत्र में किस-किस खसरा नम्बर पर किस-किस को खनिज पट्टे कब-कब आवंटित किये गये हैं? मय आवंटितकर्ता नाम, क्षेत्रवार एवं वर्तमान स्थिति के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खनन लीज किन-किन को कितने-कितने समय तक की जारी की गयी? आदेशों की प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त खानों में ब्लास्टिंग किन नियमों व शर्तों के तहत व किन अधिकारी/कर्मचारी की निगरानी में किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में आवंटित माइन्स लीज तक जाने वाली अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में खान आवंटन हेतु नियम निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत प्रधान खनिजों का आवंटन खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 तथा अप्रधान खनिजों में खान आवंटन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के तहत किया जाता है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विधानसभा क्षेत्र मावली में स्वीकृत खनन पट्टों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) विधानसभा क्षेत्र मावली में जिन-जिन व्यक्तियों को खनन पट्टें जारी किये गये हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-2 में अंकित है। स्वीकृति आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, खान)

(4) खानों में ब्लास्टिंग का कार्य मेटेलिफेरस माइन्स रेग्युलेशन, 1961 के अध्याय XV में वर्णित प्रक्रिया अनुसार ब्लास्टर/मेट/फोरमेन/प्रबन्धक की योग्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। अध्याय XV की प्रति परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है।

(5) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मावली में आवंटित माइन्स लीज तक जाने वाली 8 सड़कें क्षतिग्रस्त है, जिसका विवरण परिशिष्ट 5 पर उपलब्ध है।

(6) वर्तमान में उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के अन्तर्गत खनन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क नवीनीकरण का कार्य ट्रस्ट की गवर्निंग काउन्सिल से अनुमोदन पश्चात् करवाया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में खातेदारी भूमि से जिप्सम निकालने हेतु लाइसेंस

349. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खातेदारी भूमि पर निकल रहे जिप्सम खुदाई हेतु लाइसेंस दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो इस हेतु क्या-क्या प्रावधान निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाड़मेर जिले में जिप्सम के व्यापारियों को खातेदारी भूमि पर लाइसेंस देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा किसानों को खातेदारी भूमि के सुधार हेतु दो मीटर की गहराई तक जिप्सम की परत हटाने हेतु परमिट जारी करने के संबंध में दिनांक 28.10.2016 से तत्समय प्रभावी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन करते हुए प्रावधान किया गया, जो वर्तमान में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम

(राज्य मंत्री, खान)

52(3) में निहित है, प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। परमिट जारी करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशालय द्वारा दिनांक 22.11.2016 को जारी किये गये हैं, प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) कोई भी खातेदार स्वयं की खातेदारी भूमि के सुधार हेतु दो मीटर की गहराई तक जिप्सम की परत हटाने हेतु परमिट प्राप्त कर सकता है। खातेदारी भूमि में यदि जिप्सम दो मीटर से अधिक गहराई तक उपलब्ध है तो खनन पट्टा ई-नीलामी के द्वारा संबंधित खातेदार को इंकार का प्रथम अधिकार प्रदत्त करते हुए स्वीकृत किया जा सकता है। बाड़मेर जिले में जिप्सम के परमिट हेतु अधीक्षण खनि अभियन्ता, जोधपुर द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 25.11.2016 से 15.01.2017 से ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गये थे, जिसके अंतर्गत कुल 65 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार गठित कमेटी से क्षेत्र का निरीक्षण करा परमिट जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)